खण्ड–495, अंक–6
सोमवार, 26 माघ, शक संवत् 1937
(15 फरवरी, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2016)

(खण्ड 495 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
प्रश्नोत्तर	6–39
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	39–40
जनपद बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में अरबन फीडर से विद्युत सप्लाई करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	40–41
जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा में किसानों को राहत राशि एवं पूर्व से लम्बित पड़े मुआवजों का अविलम्ब दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत इन्दारा राजवाहा को ग्राम सभा सुल्तानपुर से कोपवा बहादुरपुर तक पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	43
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मथुरा में एन0एच–2 पर प्रस्तावित बस स्टैण्ड और उसके साथ मल्टीप्लैक्स एवं शापिंग काम्पलेक्स बनाये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	43–44
जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र खड्डा में प्रमुख मार्गों का प्रभावित करने वाले दो आर0सी0सी0 पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	44
जनपद फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माइनरों/रजवाहों की सफाई कराने एवं बन्द पड़े कुलावे एवं क्षतिग्रस्त नालियां ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में एन0एच0 मार्ग–31 पर एकत्रित हुए गंगा नदी के जल खतरे को देखते हुए सिल्ट की	45
सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	45
जनपद वाराणसी उत्तरी के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पंचकोसी बधवा नाला मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	45

जनपद आगरा के विकास खण्ड खैरागढ़, गांव रिठौरी कटरा से नगला हरलाल तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 45–46

विषय	पृष्ठ–संख्या

जनपद बस्ती के ओपेक चिकित्सालय कैली में रखी फेको मशीन का लाभ आमजनों को दिलाने तथा फोल्डेबुल लेंस व कैसेट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 46

जनपद कानपुर महाराजगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांधी वार्ड में पटेल नगर मलिन बस्ती तथा बाईपास के किनारे सड़क एवं जल निकासी के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 46–47

गाजियाबाद के वार्ड–39 में जी0टी0 रोड से आर0के0 मैरिज हाल के बराबर वाली क्षतिग्रस्त सड़क जो श्री वेद मनमोहन के नाम पर है, की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 47

जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र खजनी में सिकरीगंज बेलाघाट कुटी मार्ग पर जल भराव के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 47

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता की ग्राम सभा गम्भीरा में पाइप पेयजल परियोजना कराये जाने विषयक श्री विनोद कुमार पटेल आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... 47–48

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता की ग्राम सभा सराय भूपति की बाजार कटरा गुलाब सिंह में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री शैलेन्द्र अग्रहरि आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 48

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सड़वा चन्दिका की ग्राम सभा कोड़रा मादूपुर में पाइप पेयजल प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री रामू वर्मा आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ... 48

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत जनहित में सुचारू आवागमन की व्यवस्था कराये जाने हेतु कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राकेश तिवारी आदि निवासीगण 48

जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत रुदौली नगर में स्थापित पुरानी पी0एच0सी0 की जगह पर नवीन महिला चिकित्सालय बनाये जाने विषयक श्री दुर्गेश श्रीवास्तव आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 48
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण विषयक प्रस्ताव ... 49–51

विषय	पृष्ठ–संख्या
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	51–130
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	130–131
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित) ...	131–138
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर व्यवस्था	138
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	138–139
जनपद महोबा समेत सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे के कारण अकाल की स्थिति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	139–143
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला में सूखा राहत राशि का वितरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	143–144
जनपद वाराणसी के बादशाह बाग में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत पानी की टंकियों के निर्माण में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र जायसवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ...	144–145
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद ईंट भट्ठों को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती सीमा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य...	146
जनपद सीतापुर के नगर क्षेत्र में 2013–14 में कम्पोजिट विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रण में बनाये जाने में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा	146–147

नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ... ...

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... 147–148

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद की ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में पानी की टूटी हुई पाइपों को पुनः डलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य 148–149

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जनपद आगरा में नारायण नगर वासन फैक्ट्री के सामने बिचपुरी रोड वोडला पर दो वर्ष से नाले टूटे होने से जलभराव के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य... 149–150

जनपद देवरिया के नगरपालिका परिषद् को पदेन सदस्य होने के बाद भी बैठक में न बुलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जन्मेजय सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य 150–151

यमुना एक्सप्रेस–वे के लिये जनपद आगरा व मथुरा के किसानों से अधिग्रहीत की गयी भूमि का 64.7 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान अभी तक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 151–152

नियम–56 की सूचना पर वक्तव्य की मांग 152

नत्थियां 153–156

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 15 फरवरी, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–270

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
10. अनीसुर्रहमान, श्री मुरादाबाद
11. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
12. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
13. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
14. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
15. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
16. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
17. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
18. अमित गौरव यादव, श्री एटा
19. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
20. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
21. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
22. अरुण कुमार, डा0 बरेली
23. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
24. अरुण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
25. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
26. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
27. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
29. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
30. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
31. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
32. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
33. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
34. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
35. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
36. इकबाल, श्री बिजनौर
37. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
38. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
39. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
40. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
41. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
42. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
43. उदयराज, श्री उन्नाव
44. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
45. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
46. उमाशंकर, श्री बलिया
47. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ

48. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
49. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
50. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
51. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
52. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
53. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
54. काली चरन सुमन, श्री आगरा
55. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
56. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
57. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
58. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
59. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
60. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
61. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
62. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
63. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
64. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
65. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
66. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
67. गोमती यादव, श्री लखनऊ
68. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
69. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
70. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
71. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
72. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
73. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
74. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
75. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
76. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
77. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
78. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
79. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
80. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
81. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
82. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
83. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
84. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
85. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
86. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
87. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
88. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
89. त्रिलोकी राम, श्री अलीगढ़
90. दलजीत सिंह, श्री बांदा
91. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
92. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
93. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
94. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
95. धर्मराज, श्री बाराबंकी
96. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
97. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
98. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
99. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
100. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
101. नारद राय, श्री बलिया
102. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
103. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
104. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
105. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
106. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
107. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल

108. पीतमराम, श्री पीलीभीत
109. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
110. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
111. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
112. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
113. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
114. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
115. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
116. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
117. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
118. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
119. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
120. बदलू खां, श्री उन्नाव
121. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
122. बाबू खां, श्री हरदोई
123. बावन सिंह, श्री गोण्डा
124. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
125. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
126. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
127. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
128. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
129. बैजनाथ, श्री मऊ
130. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
131. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
132. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
133. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
134. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
135. मनबोध, श्री देवरिया
136. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
137. मनीष रावत, श्री सीतापुर
138. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
139. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
140. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
141. महबूब अली, श्री अमरोहा
142. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
143. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
144. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
145. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
146. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
147. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
148. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
149. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
150. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
151. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
152. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
153. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
154. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
155. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
156. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
157. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
158. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
159. यासर शाह, श्री बहराइच
160. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
161. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
162. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
163. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
164. रणजीत सुमन, श्री एटा
165. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
166. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
167. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ

168. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
169. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
170. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
171. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
172. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
173. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
174. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
175. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
176. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
177. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
178. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
179. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
180. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
181. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
182. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
183. राधे श्याम, श्री अमेठी
184. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
185. राम करन आर्य, श्री बस्ती
186. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
187. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
188. राम गोविन्द, श्री बलिया
189. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
190. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
191. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
192. राम मगन, श्री बाराबंकी
193. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
194. राममूर्ति सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
195. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
196. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
197. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
198. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
199. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
200. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
201. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
202. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
203. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
204. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
205. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
206. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
207. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
208. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
209. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
210. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
211. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
212. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
213. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
214. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
215. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
216. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
217. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
218. विजय सिंह, श्री रामपुर
219. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
220. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
221. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
222. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
223. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
224. वीरपाल राठी, श्री बागपत
225. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
226. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकर नगर
227. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
228. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी

229. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
230. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
231. शाकिर अली, श्री देवरिया
232. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
233. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
234. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
235. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
236. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
237. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
238. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
239. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
240. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
241. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
242. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
243. संजय कपूर, श्री रामपुर
244. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
245. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
246. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
247. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
248. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
249. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
250. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
251. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
252. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
253. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
254. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
255. सियाराम सागर, डा0 बरेली
256. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
257. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
258. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
259. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
260. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
261. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
262. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
263. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
264. सुरेश राणा, श्री शामली
265. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
266. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
267. सुल्तान बेग, श्री बरेली
268. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
269. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
270. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर

नोट :– माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00, प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के विस्तार को रोकने हेतु सक्रिय कार्रवाई की मांग

''01—श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) तथा श्री अखिलेश प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में अलकायदा के जाल का विस्तार हो रहा है और माह दिसम्बर, 2015 में सम्भल जिले से एक अलकायदा माड्यूल की गिरफ्तारी के साथ अन्य जिलों में भी इनके सक्रिय होने का इनपुट मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे आतंकवादी संगठनों के विस्तार को रोकने हेतु कोई सक्रिय कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)—

राज्य के अन्य जिलों में अलकायदा के सक्रिय होने का इनपुट नहीं है परन्तु ऐसे आतंकवादी संगठनों के विस्तार को रोकने हेतु सभी संदिग्ध तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0—1 ।

(संसदीय कार्य मंत्री के उपस्थित न होने पर)

श्री सतीश महाना —

मान्यवर, यह गम्भीर बात है।

(इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री सदन में उपस्थित हो गये।)

श्री मोहम्मद आजम खां—

ज्यादा गम्भीर नहीं है, उतना गम्भीर नहीं है जितना कि आप गम्भीर हो गये। कभी—कभी हल्के भी रहा करें, हर वक्त जंग किये रहते हैं, वह बता नहीं रहे हैं कि गये क्यों थे पाकिस्तान, मैं चला आया तो बुरा मान रहे हो।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)—

मा0 अध्यक्ष जी, यह मामला बहुत गम्भीर है और सरकार उतने ही हल्केपन से इसको ले रही है। शायद वह इसके अंजाम से नावाकिफ है कि ऐसे लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं उनका कितना बड़ा नेटवर्क है और यह भी सुनिश्चित है कि उत्तर प्रदेश उनका एक सॉफ्ट टारगेट है। मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि इनपुट नहीं मिल रहे हैं, अगर इनपुट नहीं मिल रहे हैं उनकी इस बात को सत्य मान लिया जाए तो हरकत—उल—जिहादुल—इस्लामी के जो कई सदस्य एक बार अगस्त, 2008 में पेशी के लिए लखनऊ कोर्ट में लाये गये थे और कोर्ट रूम के बार उन्होंने पाकिस्तान जिन्दाबाद

और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाये। लेकिन दुःख की बात यह है कि जिस तरह से पैरवी होनी चाहिए थी ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोगों को सजा दिलाने के लिए, लचर पैरवी के कारण वह छूट गये और अभी–अभी अलकायदा के एक सदस्य जफर मसूद के रूप में गिरफ्तारी सम्भल जिले से हुई है और आपके ही अधिकारियों के अनुसार।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह सूचना ना तो सदन को देने की जरूरत है और ना सदन यह सूचना आपसे चाहता है, आपसे सदन प्रश्न चाहता है सूचना तो हम आपको देंगे अगर आप सूचना देंगे तो फिर सरकार क्या करेगी। अगर यह सारी सूचनाएं आपके पास हैं तो आप उनकी कोई वजह बताइये। यदि आप उनके इतने करीब हैं कि जो सूचना सरकार को नहीं है वह आपको है तो कुछ बताइये उनके बारे में, इसे आप प्रश्न के रूप में बताइये, जानकारी तो हम देंगे आपको।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

आप सुनने का माद्दा तो रखिये मा0 मंत्री जी, आप इतने अधैर्य क्यों हो रहे हैं, आप तो बड़े माद्दा वाले हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं चाहता हूं कि आप दिल खोल दें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, अब मा0 मंत्री जी कहेंगे कि जो सरकार को करना चाहिए, सरकार को सूचना देनी चाहिए वह आप देंगे तो सरकार क्या करेगी। मान्यवर, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि सरकार करे। सरकार ने कहा कि कोई इनपुट नहीं है, एन0आई0ए0 की इनपुट है, केन्द्र सरकार की इनपुट है कि यहां उत्तर प्रदेश में स्लीपिंग माड्यूल्स काम कर रहे हैं और अगर उनका मंसूबा पूरा हो गया तो किसी बहुत बड़ी दुर्घटना को ये अंजाम देंगे। इसलिए मैं चिंतित हूं एक साधारण नागरिक होने के नाते कि सरकार को जितना गम्भीर हो करके इस विषय पर उत्तर देना चाहिए था उस तरह से उत्तर नहीं दिया और उन्होंने कह दिया कि कोई इनपुट नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो एन0आई0ए0 ने आपको इनपुट दिया है, भारत सरकार की ओर से जो इनपुट आपको मिला है क्या उस इनपुट से आपको इनकार है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा उत्तर फिर भी यही होगा कि जो उत्तर दिया गया है कि हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है लेकिन सरकार पूरी तरह से सजग है किसी गुमान की बिना पर किसी वहम की बिना पर, किसी गलत सूचना की बिना पर सरकार प्रदेश का माहौल खराब करने के पक्ष में नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि यह विषय कोई राजनीति का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

जवाब तो पूरा आ गया कि कोई इस तरह का इनपुट नहीं है। बात खत्म हुई।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, लेकिन आपने उसके साथ यह जोड़ दिया कि ऐसा कुछ सरकार नहीं करेगी जिससे कि प्रदेश का माहौल खराब हो। मैं तो जो कह रहा हूं वह इसलिए कह रहा हूं कि माहौल खराब न हो, लोगों को उसका भुक्तभोगी न बनना पड़े, ऐसी कोई दुर्घटना न हो जाए इसलिए यहां का खुफिया तन्त्र, यहां का पुलिस प्रशासन इतना सक्रिय हो। आप कह रहे हैं कि अगर हम सक्रिय होंगे तो यहां का वातावरण बिगड़ जायेगा, यह मेरी समझ के बाहर है। तो आप यह बता दें कि कैसे माहौल बिगड़ जायेगा। अगर पूरे प्रदेश के लोग जो शान्तिप्रिय नागरिक हैं, उनके जानमाल की हिफाजत की जिम्मेदारी आपके ऊपर है यानि वर्तमान सरकार के ऊपर है, अगर उसमें वह फेल होती है तो कैसे माहौल खराब होगा। माहौल तो तब खराब होगा, जब आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। मुझे आप यह समझा दीजिये, मेरी समझ थोड़ी कम है। आपने तुरन्त उसको राजनीति की तरफ घुमा दिया कि इससे यहां का माहौल खराब हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें, हो गया।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो प्रश्न लगाया था, वह कुछ इससे मिलता जुलता था लेकिन इसी के साथ अटैच कर दिया गया, इसका तात्पर्य यह है कि उस प्रश्न का भी जवाब सरकार इसमें देना चाहती है। हम यह जानना चाहते हैं कि अभी कुछ दिनों में भारत की खुफिया एजेन्सियां और प्रदेश की पुलिस ने प्रदेश में कई ऐसे संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा संगठन है जिस पर आज की तारीख में बैन लगा है और क्या सिमी या आई0एस0आई0 के प्रदेश में सक्रिय होने की कोई सूचना प्रदेश सरकार को है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें ऐसा होता है कि अगर कहीं से कोई सूचना है या कोई वारंट वगैरह है, अरेस्ट है तो उसमें राज्य सरकार सहयोग देती है बाकी यहां कोई इस तरह का सक्रिय संगठन या कोई ऐसी सूचना नहीं है जिससे फौरी तौर पर कोई चिन्ता का विषय बनता हो। लेकिन क्योंकि पूरे देश में यह माहौल है और कहीं कुछ भी हो सकता है इसमें कोई दो राय नहीं है, तो सरकार किसी भी एतबार से इसमें किसी लीकेज के पक्ष में नहीं है। सभी तरफ नजर रखनी चाहिये और नजर रखनी होगी और उसमें जो बात आपको नागवार हुयी, यह अहसास भी न हो कि हम नजर रख रहे हैं और नजर भी रहे पूरी तरह हालात पर। इस समय पूरी तरह हालात काबू में हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं अगर बाहर से कोई गिरफ्तारी की जरूरत होती है या कहीं केन्द्र

सरकार की तरफ से या किसी एजेन्सी की तरफ से कोई बात होती है तो उसमें प्रदेश सरकार पूरा सहयोग देती है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मान्यवर बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि आतंकवादी संगठन अलकायदा जैसा कि विदेशी देशों से संचालित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह देश के लिये आज चिन्तनीय भी है और विदेशी शक्तियों के घुसपैठ से अनायास एक वर्ग समाज, धर्म विशेष के लोगों पर आशंका बरबस लोग ले जाने की कोशिश करते हैं तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहूंगा कि यह केवल राज्य की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्र की भी समस्या है और अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। तो क्या प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार इस घुसपैठ को रोकने के लिये कभी कोई बैठक किये हैं। चूंकि जब यह विदेशी आतंकवादी संगठन है तो स्वाभाविक रूप से इसका उद्भव स्थान प्रदेश नहीं है। ऐसे हालात में प्रदेश के बेकसूर लोगों को शक और शुबह की नीयत से इसलिये देखा जाता है कि उस वर्ग समाज, धर्म से ताल्लुकात रखने वाले कुछ एक–आध विदेशी आतंकवादी होते हैं तो इसके लिये मैं इतना जानना चाहता हूं चूंकि यह केन्द्र से सीधे जुड़ा मामला है तो प्रदेश सरकार ने इस मामले पर क्या केन्द्र सरकार से आपस में बातचीत करके कोई कार्य योजना तैयार की है। अगर बैठक की तो केन्द्र सरकार के साथ कितनी बैठकें की ? केन्द्र सरकार ने इनको रोकने के लिए क्या–क्या उपाय किये, उसको भी आप सदन को अवगत करायेंगे ? मान्यवर, अगर अभी तक कोई बैठकें नहीं हुई, कोई कार्ययोजना नहीं आयी और केन्द्र सरकार ने इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किये तो स्वाभाविक रूप से केन्द्र सरकार भी कहीं न कहीं आड़े आती है, उसकी मिलीभगत का भी अंदेशा होता है इसलिए इसका भी खुलासा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी करें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जिन संगठनों के नाम आये हैं या आते हैं वह हम सबके लिए इन्तहाई शर्मिन्दगी का बायस है और जो सवाल आपने किया है दरअसल यही हम सबका दर्द है। लेकिन हमारे अख्तियार से बाहर की बात है, हमारे वश के बाहर की बात है। आपने कहा कि जिन पर लोग उंगली उठाते हैं न उनका मजहब इसकी इजाजत देता है, न ही इंसानियत बल्कि हैवानियत भी जिसकी इज़ाजत नहीं देती, और मारे जाने वाले लोगों में वो यह पता नहीं चलाते हैं कि किसका धर्म क्या है, कौन कहां का रहने वाला है ? बल्कि खबर फैलाने और दहशत फैलाने के लिए जब वो मारते हैं तो वो अमानवीयता की तमाम हदों से पार हो जाते हैं। किसी भी तरह से दुनिया में कहीं भी उसको संरक्षण न मिला है, पूरा सऊदी अरब अगर मैं कहूं कि वहां, जहां से इस्लाम की पहली आवाज निकली उन्होंने बहुत मजबूती से इन तमाम चीजों को कण्डम किया है। किसी से किसी की नाराजगी का बदला किसी बेगुनाह से नहीं लिया जा सकता, उसे जितना भी गलत कहें वो कम है। लेकिन असल बात ये है कि उनके गुनाहों की सजा जब वो लोग पाते हैं जिनका उस गुनाह से कोई रिश्ता नहीं है तो जाहिर है बात अच्छी नहीं होती है और

हमारे यहां का माहौल हिन्दुस्तान का क्योंकि ऐतिहासिक रूप से बड़ा अजीबोगरीब रहा है रिश्तों का, वास्तों का, एक दूसरे से प्यार–मोहब्बत का। तो अगर यहां यह दाखिल होगा तो उसका सीधे नुकसान अकलियतों को और खासतौर से मुसलमानों को उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहले से ही नुकसान में हैं और बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान बंटवारे का नुकसान है। उसके बाद यह दूसरा बड़ा नुकसान हो रहा है जिसको रुकना चाहिए। हमारे जैसे लोगों की तरफ से अगर कहीं सुई के नुक्ते के बराबर भी कहीं भी सुभहा होता तो शायद मैं वो व्यक्ति होता जिसके बारे में कुतुबमीनार पर चढ़कर यह कहा गया होता कि मैं फलां आतंकवादी संगठन से ताल्लुक रखता हूं या हमदर्दी रखता हूं। मैं बहुत मुखालिफ हूं इसका और जितनी ताकत से इसे रोका जा सकता है, रोका जाये। राज्य सरकार इसमें इस बिना पर कि कौन यहां कुर्सी पर बैठा है, उसका नाम क्या है या राजनीतिक वास्तेदारियां किसकी क्या हैं इससे कोई रहम नहीं होना चाहिए, न है ऐसा। केन्द्र सरकार जहां–जहां मद्द चाहे वहां राज्य सरकार मद्द देती है और देगी। एन0आई0ए0 का ताल्लुक है तो जब उनकी तरफ से कोई बैठक होती है तो राज्य सरकार उसमें सहयोग देती है, आगे होगी, आगे सहयोग देगी। दरअसल इसका मुकाबला शायद हम आपस की खटास से नहीं जितना मजबूती से मुकाबला हम आपस की मुहब्बत से कर सकते हैं उतना मुकाबला हम नहीं कर सकते किसी और ताकत से। अगर हमारे अन्दर का भेद खत्म हो और हमारे दिलों में गुंजाइश हो और हमें बुरे को पकड़ना हो तो वक्त वो आना चाहिए कि न मक्का मस्जिद में बम फटे, न मंदिर में। हममें अगर कोई बुरा है तो हम पकड़कर दें और किसी और में कोई बुरा है तो वो पकड़कर दे, यही तो राष्ट्रीयता है। हम भी कहां जायेंगें, मैं तो बार–बार कहता हूं कि कौन ले लेगा, इतनी बड़ी आबादी को कौन ले लेगा ? कहां चले जायेंगें ये ? वतन से मुहब्बत न हो तो हमें यहां कौन भेज देता ? हमारे नेता जी तो बराबर कहते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन ये है कि हम जैसे लोग आज सरकारों में मंत्री और मुख्य मंत्री बने हुए हैं। यह लोकतंत्र की ही देन है कि आप वहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं। तो हमें इस लोकतंत्र को बचाकर रखना चाहिए न कि सब खत्म कर देना चाहिए। जिस देश का लोकतंत्र है, उस देश को बाकी रहना चाहिए या उस देश को कमजोर हो जाना चाहिए ? क्या यह हमारे हक में जाता है कि वतन कमजोर हो, क्या यह हक में जाता है कि यहां दंगे फसाद हों ? क्या यह हक में जाता है कि किसी बेगुनाह की जान चली जाय और किसी को ज़िल्लत का सामना करना पड़े, कोई शर्मिन्दा हो। हमें बड़ी शर्मिन्दगी होती है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल मजबूर–ए–महज हैं। हमारे पस–ए–कुदरत में नहीं है उन आतंकवादियों को रोकना। उन आतंकियों को रोकना हमारे कब्ज़े में नहीं है। अगर हमारे कब्ज़े में हो तो आप बतायें हम जातीय तौर पर भी उसके लिये तैयार हैं लेकिन फिर यही कहूंगा कि इसका मुकाबला हमारा आपसी एहतियाद, हमारा प्यार, हमारा मेल जो हमारी आम जिन्दगी में है। राजनैतिक माहौल से हम हटते हैं तो लगता है कि न हममें कोई हिन्दु न मुसलमान न सिक्ख। लेकिन जब हम सियासी माहौल में आते हैं तो म्यान से तलवारें बाहर आ जाती हैं। अब कोई भी ऐसे हालात होंगें

तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार उसमें कहीं किसी कोई कमजोरी से काम नहीं लेगी।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी ख प्रश्न सं0–1 पुकारे जाने पर माननीय नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, इस पर 20 मिनट हो गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट। मैं यह जानता हूं कि चूंकि यह राज्य सरकार का मामला नहीं है तो मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिये केन्द्र सरकार के साथ क्या प्रदेश सरकार की कोई बैठक हुई ?

श्री अध्यक्ष–

वह बता तो रहे हैं कि जब जरूरत होती है तो बैठक होती है। यह बताया तो।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

एन0आई0ए0 की तरफ से जब भी कोई बैठक होती है या कोई परामर्श चाहते हैं, या यहां से कोई सहयोग चाहते हैं तो होती रहती है। जल्द होती रहती है। लेकिन एक सुझाव आपकी तरफ से जो एक और है कि हमारे आपस में भी नेताओं के साथ बैठकर, आपके साथ, मुख्य मंत्री जी के साथ अगर कोई इस सिलसिले में बैठक हो और हम आपसी माहौल बनाने में कोई राय बनायें तो मेरे ख्याल से यह भी अच्छी बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आपके दिल एक रहें। कम से कम एक मामले पर तो हम एक रहें कि हम किसी अपने जातीय फायदे के लिये वह किसी भी तरह का हो हम उसके लिये मुल्क की साल्वियत को नुकसान नहीं पहुंचायेंगे, इस बात पर तो एक हो सकते हैं हमारे पास ऐसी एजेन्सियां हैं कि हम दिलों के अन्दर का हाल जान सकते हैं। हम उन एजेन्सियों का इस्तेमाल करें कि आखिर हममें से वह कौन ऐसे हैं जिनकी जबान पर कुछ है और दिल में कुछ है। अब ऐसी मशीनें भी हैं, ऐसे सवालात भी हैं कि अब लोग दिल छुपा नहीं सकते, दिल बाहर आ सकता है। तो दिलों को बाहर आना चाहिए। दिल एक हों तो कम से कम उत्तर प्रदेश महफूज रहेगा। क्योंकि यह देश का दिल है और इसकी हिफाज़त जरूरी है।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में सरकारी आई0टी0आई0 खोले जाने की मांग

'01–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के युवाओं को उद्यम परक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में सरकारी आई0टी0आई0 खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)–

जी नहीं।

प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–3477/89–व्या0शि0–2013–63(एम)/2013, दिनांक 06 सितम्बर, 2013 के द्वारा प्रदेश की असेवित तहसीलों तथा विकास खण्डों में नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु नीति निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सर्वप्रथम असेवित तहसीलों में और असेवित तहसीलों को संतृप्त किये जाने के उपरान्त असेवित विकास खण्डों में स्थापित किये जायेंगे।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं और साथ ही यह बात पहले मैं कहना चाहता हूं बिना शक कि जब से यह सरकार 2012 से शुरू हुई इस क्षेत्र में पीछे हुए काम से बढ़कर काम किया है। माननीय मंत्री जी अब इतने से काम नहीं चलेगा। पूरा सदन जानता है कि यह आई0टी0आई0 जो एक जमाने में माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार का काम माना जाता था कि जो बच्चे पढ़ते–लिखते नहीं हैं वह आई0टी0आई0 कर लें। वेल्डर फिटर बन जायं इसकी दृष्टि ठीक नहीं थी। लेकिन आज बदलाव आ गया है मॉल में, रिटेल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में माननीय अध्यक्ष जी, लाखों लोगों की आवश्यकता है। विदेशों में लाखों लोगों की आवश्यकता है। बेरोजगारी हम लेखपाल और सिपाहियों की भर्ती से तो दूर करने वाले नहीं हैं हम यहां पर...

श्री अध्यक्ष–

सवाल पूछिए ना।

श्री मनीष आसीजा–

मान्यवर, थोड़ा सा मैं माननीय सदन को भी यह बताना चाह रहा था, माननीय मुख्य मंत्री जी निवेश मेले लगा रहे हैं, इन्फ्रास्ट्रैक्चर खड़े कर रहे हैं औद्योगिक गलियारे बना रहे हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास प्रशिक्षित युवा नहीं होगा तो यह औद्योगीकरण किस काम का, कहीं यह सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 की तरह ढांचे तो खड़े नहीं रह जाएंगे, डाक्टर कमी होने के कारण, तो मैं आपके माध्यम से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने इसमें काम तो किया है लेकिन गम्भीरता से काम करने के लिए कोई गैप एनालेसिस किया है जिससे यह पता लग सके कि पूरे प्रदेश में कितना एच0आर0 आपके पास है कितना आई0टी0आई0 आपके पास है, कितना ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी स्थानीय जरूरतों से युवा रोजगार जुड़ सकता है, यह एक प्रश्न है गैप एनालेसिस किया है अगर नहीं, तो करा दें। दूसरा प्रश्न है आपने पी0पी0डी0 मॉडल में कुछ आई0टी0आई0 को सम्बद्ध किया है 115 में आपने किया है। इसमें मेरी जानकारी है आप भी पता कर लें इसमें ज्यादातर लोग सरकारी ठेके के स्वभाव के होते

हैं ट्रेडर्स, सबका मैं नहीं कहता हूं इसकी पुनः समीक्षा करके, अध्यक्ष जी व्यवस्था करा दें डा0 साहब तो हमारे अपने हैं।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन आप इतना घुमाकर क्यों पूछ रहे हैं कि डाक्टर साहब भी ऊब जाते हैं।

श्री मनीष आसीजा–

मान्यवर, जैसे फिरोजाबाद में कांच का काम होता है हमारे जिले में कोई राजकीय आई0टी0आई0 नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप पूछ क्या रहे हैं यह तो बतायें। इतनी देर से भाषण दे रहे हैं।

श्री मनीष आसीजा–

किसी भी मॉडल में स्थानीय जरूरतों के हिसाब से औद्योगिक पार्टनर्स आप बनायेंगे। तीसरा प्रश्न मेरा है, अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से तीसरा और अन्तिम प्रश्न पूछ रहा हूं कि मिशन मोड पर यह जो आई0टी0आई0 है मेरी जो जानकारी है लगभग हमें 1200 से ऊपर आई0टी0आई0 की आवश्यकता है आप साल में बीस लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल तो पूछिए।

श्री मनीष आसीजा–

क्या प्रत्येक जिले में आई0टी0आई0 की स्थापना करेंगे ?

श्री अभिषेक मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य का इन्टेंशन है जो मंशा है वह बिल्कुल अच्छा है। समाजवादी सरकार ने आज तक, मुझे कहते हुए खुशी है कि मा0 श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य इस क्षेत्र में किया है आज तक किसी भी चार साल में जितने आई0टी0आईज बने हैं आज तक हमने उनसे ज्यादा अच्छे और ज्यादा आई0टी0आईज बना करके पांच सालों में तकरीबन पचास हजार बच्चे हम ऐड करने जा रहे हैं हमारी भी मंशा है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें, सख्त जरूरत है इसकी, इन्फ्रास्ट्रैक्चर डेवलप्मेंट के लिए, इन्डस्ट्रीलाइजेशन के लिए, उसमें हमने लगातार काम किया है, मैंने बता दिया जैसे ही हमारी तहसीलें संतृप्त हो जाएंगी वैसे ही हम ब्लाक भी टेकअप करेंगे।

श्री मनीष आसीजा–

आप गैप एनालेसिस करायेंगे ? आप बगैर गैप एनालेसिस कराये 20 आई0टी0आई0 खोलकर कैसे टारगेट पूरा करेंगे। आप गैप एनालेसिस के बारे में बता दें।

श्री अभिषेक मिश्र–

सवाल में गैप एनालेसिस का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने पूछा है और मुझे जानकारी है मुझे बताते खुशी है कि हमने स्किल गैप एनालेसिस पूरे प्रदेश की कराई है उसका डेटा एबिलेविल है उसके साथ–साथ हमने

इसको भी आइडेन्टिफाइड किया है जैसे लखनऊ की चिकनकारी है वाराणसी में साड़ी का काम है, इस तरह से टाटा इन्सटीट्यूट ऑफ सोशल साइसेंस से उसके अलग से कोर्स बना करके, उनको एप्रूव कराकर उसको भी चलाने का काम कर रहे हैं। सारे सेक्टर में एबिलेविल है मैं भिजवा दूंगा।

प्रदेश में जनगणना, मतदाता सूची सर्वे आदि कार्य करने हेतु सांख्यिकी सेवक की नियुक्ति करने की मांग

'02—डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनगणना, मतदाता सूची सर्वे आदि विभिन्न कार्य करने के लिए सांख्यिकी सेवक की नियुक्ति करने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई')—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल—

मान्यवर, जवाब से कोई बहुत बड़ी असहमति नहीं है क्योंकि यह पहली बार प्रश्न है और जब ऐसे सैद्धान्तिक प्रश्न आते हैं तो व्यवस्था इसको स्वीकार नहीं करती है प्रश्न का आधार यह है कि शिक्षक शिक्षणेत्तर कार्यों में लगातार लगा हुआ है मतदाता सूची हो, चाहे चुनाव ड्यूटी हो, चाहे जितने प्रकार के सर्वे वह डेली हेल्थ सर्वे हो सोशियो इकोनामिक सर्वे हो, जाति गणना हो, विभिन्न प्रकार के फिजिकल एसेट्स की उपलब्धि परिवारों में हो यह जितने सर्वे होते हैं इन सर्वे के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है जब भी यह सर्वे आते हैं तो या तो यह कागजों पर हो जाते हैं या अल्टीमेटली शिक्षक बलि का बकरा बनता है। जिसको यह काम सौंप दिया जाता है यह प्रश्न लेकर आने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यह जो इस प्रकार के कार्य हैं बी0एल0ओ0 की ड्यूटी है, चुनाव की ड्यूटी है मतदाता सूची है डेली हेल्थ सर्वे है सोशियो इकोनामिक सर्वेज हैं हमें क्या यह महसूस नहीं होता कि इन कामों के लिए जब हम इतने सारे लोगों को इम्प्लाई कर रहे हैं इतनी सारी चीजें चला रहे हैं तो इन कामों के लिए हम अलग से लोग रख लें जो इसको प्रमाणिकता और ईमानदारी के साथ करें अपने इस सवाल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो काम जिसका है उससे लिया जाय यह शिक्षक का काम नहीं है यह काम जो इस काम को करें उनका है क्या सरकार यह मानती है कि शिक्षक से यह काम नहीं कराया जाना चाहिए और अध्यक्ष महोदय मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात होगी अनुपूरक जवाब दिए गए होंगे मा0 उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि इस प्रकार के काम शिक्षकों से न कराए जाएं सरकार कह सकती है कि हम यह नहीं कराएंगे जो चल रहा है वह चलेगा लेकिन मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूं चूंकि लोकतंत्र में चुनाव सबसे

महत्वपूर्ण चीज है और मतदाता सूची अगर ठीक नहीं है तो चुनाव कभी ठीक नहीं होगा क्या सरकार यह महसूस करती है कि इसकी प्रमाणिकता को बनाए रखने के लिए हम पूर्णकालिक सेवकों की नियुक्ति कर लें जो इस काम को ईमानदारी के साथ निभाएं मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जनगणना का कार्य प्रत्येक 10 वर्ष के अन्तराल पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एवं जनगणना कार्य निदेशालय भारत सरकार के उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहयोग से सम्पादित होता है। प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी नागरिकता अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार एवं नागरिकता पंजीयन नामित हैं। जिलाधिकारी जिला रजिस्ट्रार द्वारा अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले सामान्य निवासियों की गणना का कार्य कराया जाता है। जनगणना कार्य हेतु राज्य सरकार के स्तर से किसी कार्मिक की अलग से नियुक्तियां नहीं की जाती हैं न ही वर्तमान में ऐसी कोई नियुक्ति की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है जनगणना कार्य भारत सरकार के निदेशालय की इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेकिन उनके स्तर से यदि कोई नियुक्तियां की जाती हैं तो इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है न ही हमें कोई आपत्ति है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

इसीलिए तो मैं इस सवाल को लेकर आया हूं आपकी वर्तमान नीति में नहीं है कोई बात नहीं क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि मतगणना काम हो चाहे जनगणना का काम हो डी0एम0 खुद तो करता नहीं है डी0एम0 तो आपने एक अधिकारी नियुक्त किया है नीचे काम करने वाले लोग तो वही हैं और यह वह लोग हैं जो अपना मूल काम छोड़कर इस काम को करते हैं। क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि हमें शिक्षा का स्तर बेहतर करना चाहिए शिक्षकों का सम्मान बढ़ाना चाहिए जो शिक्षकों का काम है वह उनसे करवाया जाय बनिस्बत इन सारे कामों के जनगणना हो, मतगणना हो, सर्वे हो डी0एम0 कहीं नहीं जाता है अल्टीमेटली जाते यही लोग हैं मेरा प्रश्न इतना है कि जब आप सारे सिस्टम को जान रहे हैं भारत सरकार इसमें कोई नियुक्ति नहीं करने जा रही है क्योंकि यह राज्य सरकार का दायित्व है जनगणना भारत सरकार कराती जरूर है लेकिन दायित्व राज्य सरकार का होता है मतदाता सूची चुनाव आयोग बनवाता जरूर है लेकिन दायित्व राज्य सरकार का होता है तो जब राज्य सरकार के दायित्वों में यह सारी चीजें आती हैं और हम देख रहे हैं कि इस व्यवस्था के नाते हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था तबाह हो रही है और जितने आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं सब फर्जी आते हैं कागजी आते हैं मुझे तो नहीं मालूम कि इतने सालों में कोई कभी हमारे घर यह पूछने आया हो और आपको भी नहीं मालूम होगा कि आपके घर कितने लोग रहते हैं उनको क्या बीमारी हुई घर में पंखा है बिजली है ए0सी0 है ट्यूबवेल है कोई जानकारी लेने कहीं कोई नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष–

सवाल कीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मेरा सवाल इतना ही है कि इसमें प्रमाणिकता स्थापित हो यह सर्वे ईमानदारी के साथ किए जाएं इसके लिए हमें तंत्र चाहिए और क्या सरकार यह तंत्र नियुक्त करेगी मेरा प्रश्न इतना ही है।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कह दिया नहीं करेगी।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

इसमें स्पष्ट उत्तर आ गया है। मैं समझता हूं कि अब किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में वर्तमान विधवा पेंशन नीति की जानकारी तथा जनपद इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी में वर्ष 2012 से 31 अक्टूबर, 2015 तक विधवा पेंशन हेतु आवेदन एवं उनकी स्वीकृति का विवरण

'03–श्री अनुग्रह नारायण सिंह, डा0 अरुण कुमार तथा श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में विधवा हो रही महिलाओं को पेंशन देने की क्या नीति है ? क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी में वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 31 अक्टूबर, 2015 तक कुल कितनी विधवाओं ने पेंशन हेतु आवेदन किया और उसमें से कितनी को विधवा पेंशन स्वीकृत की गई तथा शेष को कब तक पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा)–

पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला अनुदान योजना के अन्तर्गत 18 से 60 वर्ष की ऐसी महिलायें जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रही हों जिनका पुत्र नाबालिग हो अथवा बालिग होने के बावजूद उनका भरण–पोषण करने में असमर्थ हो उन्हें रु0 300/– प्रतिमाह भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 31 अक्टूबर, 2015 तक कुल 5079 आवेदन प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 2178 लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है।

जनपद प्रतापगढ़ में 5544 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 4679 को पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है।

जनपद फतेहपुर में 2178 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 2056 को पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है।

जनपद कौशाम्बी में 1854 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 464 को पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है।

जनपद इलाहाबाद 2901 लाभार्थियों के, प्रतापगढ़ में 865 लाभार्थियों के, फतेहपुर में 122 लाभार्थियों के, कौशाम्बी में 1390 लाभार्थियों के आवेदन–पत्र आनलाइन फीड कराये जा रहे हैं। पी0एफ0एम0एस0 से सत्यापित व जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा पुनः सत्यापित होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था वह इससे थोड़ा अलग था, लेकिन इसको उसमें जोड़ दिया गया है। हम यह चाहते हैं कि जो निराश्रित विधवा हैं, उनको 300 रुपया प्रतिमाह पेंशन मिलती है। कोई निराश्रित विधवा अपने पूरे परिवार का पालन–पोषण 300 रुपये में नहीं कर सकती है। यह 300 रुपया पेंशन बहुत अपर्याप्त है। यह पेंशन राशि बढ़ाई जाये और जो फर्जी पेंशन मिल रही है उसकी जांच कराई जाये जिससे सही लोगों को पेंशन मिले।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल–

मान्यवर, यह प्रश्न सत्ता पक्ष से आया है इसलिये हम इसे नकार नहीं सकते हैं। शासन में बैठे हुये लोग शासकीय नीतियों से अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 300 रुपया पेंशन बहुत कम है। इसको गम्भीरता से लेने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष–

वह नीतियों से असहमति नहीं व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि वह कह रहे हैं कि इसे बढ़ाया जाये। असहमति तो तब होती जब वह मानते नहीं, यह असहमति नहीं है।

(सदस्य श्री मनीष असीजा जी के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपने अपना प्रश्न कर लिया है, अब आप बैठ जाइये।

डा0 अरूण कुमार–

मान्यवर, मासिक पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 1000 रुपये की जानी चाहिये और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि बी0पी0एल0 यानी बिलो पॉवर्टी लाइन की लिमिट शहर के अन्दर 25,446 से बढ़ाकर 56,460 कर दी गयी है। जो लोग अब इस 25,446 से 56,460 की लिमिट में आते हैं क्या उनको भी सरकार इस वर्ष में पेंशन देगी ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

मा0 अध्यक्ष जी, पेंशन की राशि बढ़ाने के लिये विचार किया जा रहा है और जो आपने कहा कि उसकी सीमा बढ़ा दी गयी है तो इस बार यह निर्णय किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 और शहरी क्षेत्र में 56,460 की जो सीमा बढ़ाई गयी है, इसके अन्दर जो भी लोग आते हैं उन सबको इसके लाभ से आच्छादित किया जायेगा।

डा0 अरूण कुमार–

मान्यवर, जो लोग मार्च तक अप्लाई कर देंगे क्या उनको भी लाभान्वित किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये, आपकी बात आ गई है।

जनपद शामली सहित प्रदेश में बाल पुष्टाहार वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु प्रभावी योजना तैयार करने की मांग

'04–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली सहित प्रदेश में बाल पुष्टाहार वितरण में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुष्टाहार वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए कोई प्रभावी योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

जी नहीं।

विभागीय योजनाओं के संचालन/बाल पुष्टाहार वितरण सम्बन्धी जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं इनकी जांच करायी जाती है तथा गुण–दोष के आधार पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्रवाई की जाती है। विभिन्न शिकायतों की जांच में दोषी पाये गये 62 कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक/विभागीय कार्रवाई की गयी है।

विभाग के उद्देश्य पूर्ति तथा योजनाओं के सुचारु संचालन एवं पुष्टाहार वितरण हेतु विभाग में पारदर्शी व्यवस्था की गयी है।

विवरण सामग्री के रूप में संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। कोई आरोप–प्रत्यारोप का विषय नहीं है लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि पिछले वर्षों में इस बाल पुष्टाहार की व्यवस्था के चलते हुए भी लगातार चाहे शिशु मृत्यु दर हो, चाहे कुपोषण का मामला हो, लगातार बढ़ रहा है। शिशु मृत्यु दर में भी उत्तर प्रदेश भारत में पहला स्थान बनाये हुए है। तो मेरा इसमें एक सामान्य सा प्रश्न यह है कि जिस सामग्री के वितरण से, जिस पुष्टाहार के वितरण करने के बाद भी कुपोषण समाप्त नहीं हो रहा है, यहां पर बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधि जानते हैं कि इस पुष्टाहार की जो वितरण प्रणाली है, यदि मैं एक ब्लाक की बात करूं तो जहां

---

† ¼nsf[k;s uRFkh ^^d** vkxs i`"B 153&154 ij½

एक ब्लाक में 8 से 10 पोस्ट हैं, जो कहीं न कहीं सुपरवाइजर के रूप में इसकी निगरानी करें, 8 में से 2 हैं या 3 हैं तो क्या इस सारी अव्यवस्था को देखते हुए सरकार इस प्रकार की व्यवस्था बनाने पर विचार करेगी कि कोई निगरानी समिति जिला स्तर पर गठित की जाए कि इसके वितरण में जो धांधली है, जो गड़बड़ी है, उसमें निगरानी रख सके, ऐसी कोई निगरानी समिति जिला स्तर पर सरकार तैयार करेगी ? मान्यवर, भ्रष्टाचार के विषय में कहा गया है कि बहुत सारी कार्रवाई हुई है, तो वैसे तो बहुत सारे प्रकरण हैं लेकिन सिद्धार्थनगर का एक प्रकरण है, वहां सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा शिकायत हुई, वह निलम्बित कर दिए गए, पुनः उसी जनपद में फिर बहाल कर दिए गए। यह कार्रवाई किस प्रकार की है ? यह समझ से परे है। मान्यवर, यह मैं सीधे रूप से कहना चाहता हूं कि जो सामग्री पुष्टाहार के रूप में दी जा रही है, क्या उसकी मेडिकल जांच करा करके विधिवत् उस सामगी को परिवर्तित करने पर सरकार विचार करेगी और क्या इसमें भ्रष्टाचार को देखते हुए जनपद स्तर पर इसके बंटवारे को समुचित करने के लिए कोई निगरानी समिति का गठन करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बलराम यादव–

महोदय, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है और तहसील स्तर पर इस पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी है, जो इसके पारदर्शी ढंग से वितरण की व्यवस्था की देखभाल करती है। जहां तक इस अनुपूरक पौष्टिक आहार से मैं समझता हूं कि इससे गर्भवती माताओं, धात्री महिलाओं और बच्चों को काफी लाभ मिला है और अगर इसके सम्बन्ध में कोई सुझाव आप दें कि इसमें और कौन–कौन सी चीजें जोड़ दी जायें तो उन्हें भी देख लिया जायेगा।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मेरा इतना आग्रह था, मा0 मंत्री जी ने सुझाव की बात कही है, पिछले चार सालों में मा0 मंत्री जी इतना ही बता दें कि क्या प्रदेश की कुपोषण दर घटी है, क्या शिशु मृत्यु दर घटी है ? मान्यवर, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है क्योंकि लगातार कुपोषण की दर बढ़ रही है तो इस योजना का कितना लाभ हो रहा है, यह अपने आप स्पष्ट हो जाता है।

श्री दलवीर सिंह–

अध्यक्ष जी, यह सर्वविदित है, जितने भी हम लोग यहां बैठे हैं, जानते हैं, इस योजना से न कोई लाभ है, न इसका सही क्रियान्वयन हो रहा है और न होने की सम्भावना है। इसमें जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी श्रम कर रहे हैं, उनका भी श्रम व्यर्थ है। इसमें जो पैसे का निवेश लगाया जा रहा है, वह भी व्यर्थ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, क्या इस योजना को खत्म करके किन्हीं सड़क आदि के विकास कार्यों में इस धन का प्रयोग किया जा सकता है, यदि किया जा सकता है, तो किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह कैसा सवाल है, इसे छोड़िये।

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण तथा सैनिक कल्याण मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार और मा0 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चल रहा है, मा0 सुप्रीम कोर्ट का सीधे इसमें निर्देश है कि हर कुपोषित बच्चे को, हर गरीबी रेखा के नीचे के बच्चे को पुष्टाहार दे करके उसको कुपोषण से बचाया जाय। मा0 सदस्य ने जो कहा है, तो मैं बता दूं, कुपोषण में भी कमी आई है और बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी आई है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

राजकीय सेवा में सेवारत पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराये भत्ते की अनुमन्यता विषयक जानकारी

'05–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1/2015/जी–1–01/10–2015–226/2008 टी0सी0 2, दिनांक 11–2–2015 के तहत राजकीय सेवा में सेवारत पति तथा पत्नी दोनों को एक ही किराये के अथवा अपने आवास में रहने की स्थिति में दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य है किन्तु एक ही सरकारी आवास में रह रहे पति तथा पत्नी को नहीं मिल पाने के कारण शासनादेश की मूल भावना की पूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार समान न्याय के सिद्धांत के आधार पर एक ही सरकारी आवास में रह रहे पति तथा पत्नी में से जिनके नाम सरकारी आवास नहीं है को भी मकान किराया भत्ता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता विषयक पूर्व निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पति और पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने एवं एक ही किराये के अथवा निजी आवास में रहने की स्थिति में एक को ही कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया गया था। पति तथा पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने तथा एक को सरकारी आवास आवंटित होने तथा दूसरे सरकारी सेवक द्वारा उसी आवास में अध्यासन करने पर दूसरे को मकान किराया भत्ता अनुमन्य नहीं किया गया था।

उपरोक्त व्यवस्था में संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या–1/2015/जी–1–01/ दस–2015–226/2008, टी0सी0–प्प्ए दिनांक 11 फरवरी, 2015 द्वारा राजकीय सेवा में पति तथा पत्नी दोनों के कार्यरत होने एवं एक ही किराये के अथवा अपने आवास में रहने पर दोनों को उनकी देयता के अनुसार मकान किराये भत्ते की नियमानुसार देय धनराशि प्रदान की गयी है।

पूर्व निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार पति तथा पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने तथा एक को सरकारी आवास आवंटित होने तथा दूसरे सरकारी सेवक द्वारा उसी आवास में अध्यासन करने पर दूसरे को मकान किराया भत्ता अनुमन्य नहीं है। इस प्रकार शासनादेश दिनांक 11 फरवरी, 2015 की मूल भावना की पूर्ति हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पति तथा पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने तथा एक को सरकारी आवास आवंटित होने तथा दूसरे सरकारी सेवक द्वारा उसी आवास में अध्यासन करने पर दूसरे को मकान किराया भत्ता अनुमन्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप हैं ?

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, इसमें मेरी रुचि है।

श्री अध्यक्ष–

रुचि है तो प्रश्न खत्म हो जाय, उसके बाद लेते हैं।

श्री अध्यक्ष–

श्री अवस्थी बाला प्रसाद हैं ?

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकरण में कुछ लोग कोर्ट गये और कोर्ट ने स्टे दे दिया कुछ लोगों को, जिन लोगों को स्टे दे दिया वह तो अभी भी पुराना लाभ पा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने स्टे नहीं लिया, उनसे यह धनराशि वसूल ली गई और उनको यह लाभ नहीं मिल रहा है। छोटा सा अनुपूरक हमारा यही था कि जिन लोगों ने स्टे नहीं लिया था या नहीं लिया है, उन्हें भी स्टे लेने वालों को जो सुविधा मिल रही है या जिनसे वसूली नहीं हो रही है या उनकी वसूली नहीं हुई, वह सुविधा मिलेगी या उनको वह धनराशि वापस करने पर विचार करेगी सरकार।

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में हम जानकारी करके मा0 सदस्य महोदय को अवगत करा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। अब प्रश्न समाप्त हो गए।

भारत सरकार के मृतक सेवकों के आश्रितों की पारिवारिक पेंशन में मंहगाई भत्ते की धनराशि सम्मिलित कर भुगतान करने की मांग

'06–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के मृतक सेवकों के आश्रितों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में महंगाई भत्ते की धनराशि सम्मिलित कर पेंशन दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य सरकार के मृतक आश्रितों को यह लाभ नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार भारत सरकार की भांति राज्य सरकार के मृतक आश्रित सेवकों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में भी मंहगाई भत्ते की धनराशि सम्मिलित कर भुगतान कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

राज्य सरकार के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को स्वीकृत पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है। परन्तु मृतक सरकारी सेवक के ऐसे आश्रित जो सेवायोजित है, को स्वीकृत पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान सम्प्रति अनुमन्य नहीं है।

कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के शहरों में होटलों, तीर्थ स्थलों आदि पर महिला एवं बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु सरकारी योजना बनाये जाने की मांग

01–श्री सुदेश शर्मा–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों के बड़े चौराहों, होटलों एवं तीर्थ स्थलों पर दिन प्रतिदिन महिला एवं बाल भिक्षावृत्ति में निरन्तर वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या इसको रोकने हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

महिला कल्याण विभाग द्वारा निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों के लिए पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के गृह संचालित किये जा रहे हैं, जहां पर सभी निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों के खाने, पीने एवं रहने का समुचित प्रबन्ध किया जाता है।

अतः बड़े चौराहों, होटलों एवं तीर्थ स्थलों पर महिला एवं बाल भिक्षावृत्ति में वृद्धि होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

कूड़ा बीनने वाले, घर से भागे हुए बच्चों, भीख मांगने वाले बच्चे, सड़क पर तमाशा दिखाने वाले बच्चे, होटल में काम करने वाले बच्चे आदि को आश्रय प्रदान करने हेतु समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से खुले आश्रय गृह भी संचालित हैं। साथ ही महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से 10 जनपदों में शरणालय भी संचालित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में जानकारी

02—श्री मनीष असीजा—

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसी कितनी विधवा महिलायें हैं, जिनके विधवा पेंशन के आवेदन—पत्र पात्रता श्रेणी में स्वीकृत होने के बावजूद बजट अभाव में उनको पेंशन प्राप्त नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार इन सभी पात्रता श्रेणी की विधवा महिलाओं को पेंशन की सुविधा प्रदान करने हेतु बजट में प्रावधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा—

पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा एकीकृत पेंशन पोर्टल पर अपलोड डाटा एवं पी0एफ0एम0एस0 से सत्यापित तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर से लाक किए गये समस्त पात्र लाभार्थियों को उक्त योजना के अन्तर्गत वितरित किया जा रहा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के कारण निराश्रित विधवाओं की पेंशन राशि बढ़ाने सम्बन्धी जानकारी

03—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को देखते हुए निराश्रित विधवाओं की पेंशन राशि 300 रु0 को बढ़ाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

04—श्री जय प्रकाश निषाद—

खदिनांक 11—02—2016 को अता0प्र0सं0—145 द्वारा उत्तरित,

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर कोहडा तथा शंकरपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यकत्री के रिक्त पदों को भरे जान की मांग

05—श्री संजय प्रताप जयसवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के कोहडा तथा शंकरपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र व टेढ़ीकुइंया मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यकत्री के पद रिक्त है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि रामनगर ब्लाक के ही ग्राम भानपुर तथा ब्लाक सल्टौआ के गंधरिया गजराज में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सहायिकाओं का चयन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

जनपद बस्ती के रामनगर ब्लाक अन्तर्गत ग्राम भानपुर में आंगनबाड़ी सहायिका का 01 पद रिक्त है, जिस पर चयन नहीं हुआ है। ग्राम गंधरिया गजराज विकास खण्ड सल्टौआ में न होकर विकास खण्ड साऊंघाट में स्थित है। ग्राम गंधरिया गजराज में आंगनबाड़ी सहायिका का पद रिक्त है।

जी हां।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं के चयन का मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय से अनुतोष प्राप्त होते ही आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं के रिक्त पदों के भरने की कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री के अशासकीय पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

06—श्री राधेश्याम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री का अ0शा0 पत्रांक—593/बे0शि0—बा0वि0पु0/20, दि0 16—04—15 जोकि निदेशक, बाल विकास को सम्बोधित एवं ग्राम रायपुर सदरा, पो0 सरई गुदौली, विकास खण्ड गोसाईगंज, जिला लखनऊ में आंगनबाड़ी केन्द्र की बिल्डिंग बनवाये जाने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

वर्तमान में उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक विद्यालय में संचालित है। आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि के चयन सम्बन्धी ग्रामसभा का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव को आई0पी0पी0ई0 (इंटैंसिन पार्टी सिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज) ब्लाक/परियोजना में मनरेगा कर्न्वजेन्स के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन सूची में सम्मिलित कर लियाा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के ब्लाक सेवरही में आई0टी0आई0 स्कूल खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

07–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के ब्लाक सेवरही में आई0टी0आई0 स्कूल खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10684051/2015, प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद कुशीनगर के ब्लाक सेवरही में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा चुकी है एवं भवन निर्माण का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। जनपद कुशीनगर में वर्तमान में 06 राजकीय तथा 05 निजी इस प्रकार कुल 11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु नीति के अन्तर्गत सर्वप्रथम असेवित तहसीलों में तदोपरान्त असेवित विकास खण्डों में खोले जायेंगे। नीति के क्रम में जनपद कुशीनगर की विधान सभा सेवरही में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सेवरही स्थापित है, जो वर्तमान में पूर्व से ही संचालित है।

इस प्रकार जनपद में व्यवसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों पर दबंगों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की मांग

08–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों पर दबंगों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

जी हां।

महिला कल्याण विभाग महिलाओं के उत्पीड़न के प्रभावी रोकथाम के लिये शासनादेश संख्या–1मु0मं0/60–3–14–13(7)/14, दिनांक 09–06–2014 द्वारा प्रत्येक

कार्यालय में उत्पीड़न कमेटी गठित कर कामकाजी महिलाओं के उत्पीड़न के सम्बन्ध में प्रत्येक माह अनुश्रवण किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार दहेज से पीड़ित सामान्य महिलाओं एवं घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के उत्पीड़न पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु शासन के पत्र संख्या–250भास0/60/3–06–3(22)06, दिनांक 02–11–2006 द्वारा प्रत्येक जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी को संरक्षण अधिकारी नामित किया गया है।

इसके अतिरिक्त बच्चों के दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न की रोकथाम हेतु अपाक्सो एक्ट 2012 प्रदेश में प्रभावी है। बच्चों के उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय बालगृह लखनऊ में तैनात कतिपय कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के गायब होने विषयक प्रमुख सचिव महिला कल्याण को प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

09–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालगृह ख्बालक, लखनऊ में तैनात कतिपय कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के गायब होने एवं संस्था अध्यक्ष व संस्था लिपिक द्वारा संस्था में मारपीट करने के विरुद्ध मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर सं0–पी0जी0–05694519 एवं मा0 सदस्य, विधान सभा श्रीमती चन्द्रा रावत व श्री विजय यादव द्वारा भी तत्सम्बन्धी पत्र जो कम्प्यूटर सं0–डी0जी0–10693506/15 में दर्ज है, प्रमुख सचिव, महिला कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

जी हां, श्री उदय शंकर मालवीय, सहायक अधीक्षक एवं श्री दिनेश चन्द्र रावत, व्यायाम प्रशिक्षक, राजकीय बाल गृह बालक, लखनऊ की सेवा पुस्तिका संस्था से जिला प्रोबेशन कार्यालय लखनऊ ले जाते समय कहीं गिर गयी जो पुनः तैयार कर ली गयी है। संस्था में मारपीट की कोई घटना घटित नहीं हुयी है। मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर सं0–पी0जी0 05694519 प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय की वेबसाइट से सूची प्राप्त की गयी, जो श्री शिवाकर बाजपेई, क्राफ्ट प्रशिक्षक के सेवा देयकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है। उनके वांछित देयकों का भुगतान नियमानुसार कर दिया गया है।

(2) मा0 सदस्य विधान सभा में श्रीमती चन्द्रा रावत व श्री विजय यादव द्वारा तत्सम्बन्धी पत्र जो कम्प्यूटर सं0–डी0जी0 10693506/15 में दर्ज है, निदेशालय को प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा लाभार्थियों हेतु निर्धारित धनराशि के गबन करने के विरुद्ध मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

10—श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)—

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2011—12 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा 20751 लाभार्थियों हेतु निर्धारित रु0 4951800.00 की धनराशि से सुनियोजित तरीके से गबन करने के विरुद्ध मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर सं0—पी0जी0—05599752, दिनांक 30—03—15, पी0जी0—05607639, दिनांक 15—04—15, पी0जी0—05613260, दिनांक 28—04—15, पी0जी0—05620229, दिनांक 13—05—15 एवं माननीय विधायक श्री सुधाकर सिंह का पत्र दिनांक 24—03—15 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा—

जी हां। जिला प्रोबेशन अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा 20751 लाभार्थियों हेतु रु0 4951800/— की धनराशि से सुनियोजित तरीके से गबन करने के विरुद्ध मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर सं0—पी0जी0 505599752, दिनांक 30—03—15 एवं मा0 विधायक श्री सुधाकर सिंह का पत्र दिनांक 24—03—2015 प्राप्त हुये है तथा मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या—पी0जी0—05607639, दिनांक 15—04—15, पी0जी0—05613260, दिनांक 28—04—15, पी0जी0—05620229, दिनांक 13—05—15 प्राप्त नहीं हुये हैं।

मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर सं0 पी0जी0—505599752, दिनांक 30—03—15 एवं मा0 विधायक सुधाकर सिंह के पत्र दिनांक 24—03—2015 के सन्दर्भ में प्रश्नगत प्रकरण में विभागीय जांच की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर के पेंशन प्रकरण की विशेष आडिट सम्प्रीक्षा भी प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में होमगार्ड्स के जवान कुशल मजदूरों के मानदेय के सम्बन्ध में जानकारी

11—श्री सुदेश शर्मा—

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होमगार्ड्स के जवान कुशल मजदूरों की श्रेणी में पंजीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि इनको मिलने वाला मानदेय केन्द्र/प्रदेश सरकार द्वारा कुशल मजदूरों हेतु अनुमन्य मानदेय के बराबर नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

होमगार्ड्स प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

प्रदेश में होमगार्ड के जवान कुशल मजदूरों की श्रेणी में पंजीकृत नहीं है।

होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 की धारा—3 के अनुसार एक स्वयंसेवक दल के रूप में होमगार्ड्स का गठन किया गया है। अधिनियम, 1963 की धारा—11 (4) में प्राविधानित है कि काम के लिए बुलाए गये होमगार्डों को ऐसा दैनिक भत्ता दिया जाएगा जो नियत

किया जाय। वर्तमान में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को रु0 225/– प्रति होमगार्ड्स प्रतिदिन दैनिक भत्ता अनुमन्य किया गया है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 द्वारा इटावा के सैफई महोत्सव तथा लखनऊ महोत्सव में गत विगत वर्षों में किये गये व्यय का विवरण तथा इलाहाबाद में प्रयाग महोत्सव का भी आयोजन शासकीय सहायता द्वारा किये जाने की मांग

12–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 द्वारा इटावा के सैफई महोत्सव तथा लखनऊ महोत्सव में वर्ष 2013–14, 2014–15 तक कितना–कितना रुपया व्यय किया तथा इसमें कौन–कौन से प्रमुख कलाकारों ने भाग लिया एवं उनको इस हेतु कितना–कितना भुगतान किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त की भांति संपूर्ण प्रदेश में धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक, शैक्षिक क्षेत्र में अग्रणी प्रयाग, इलाहाबाद में प्रयाग महोत्सव का भी आयोजन शासकीय सहायता से कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरुण कुमार कोरी)–

सैफई महोत्सव–2013–14 के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संस्कृति विभाग द्वारा की गयी सहभागिता के अन्तर्गत रु0 96,59,007.00 (रुपये छियान्नवे लाख उनसठ हजार सात मात्र) का वास्तविक व्यय किया गया। उक्त महोत्सव के अन्तर्गत प्रमुख रूप से श्री राजू श्रीवास्तव, मुम्बई, श्री जावेद अली, मुम्बई, श्री हेमन्त बृजवासी, मुम्बई, श्री शाबरी ब्रदर्स, जयपुर, श्री रूप सिंह शेखावत, राजस्थान, श्री हेमन्त बृजवासी, मुम्बई श्री शाबरी ब्रदर्स, जयपुर, श्री रूप सिंह शेखावत, राजस्थान, श्री लखवीर सिंह लक्खा, श्री रामभारती, कला केन्द्र, नई दिल्ली एवं देश के विभिन्न प्रान्तों के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां करायी गयी।

सैफई महोत्सव–2014–15 के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संस्कृति विभाग द्वारा की गयी सहभागिता के अन्तर्गत रु0 95,29,185.00 (रुपये पच्चानवे लाख उनतीस हजार एक सौ पच्चासी मात्र) का वास्तविक व्यय किया गया। उक्त महोत्सव के अन्तर्गत प्रमुख रूप से माहुरी (फायर नृत्य) न्यूजीलैण्ड, ड्रेगन व लॉयन नृत्य, चाईनीज, पश्चिम बंगाल, श्री राजू सर्वेन्ट, श्री दीपक राजा एवं श्री राजीव ठाकुर, श्री कोहिनूर लंगा, श्री मुरारी लाल शर्मा, मथुरा, सुश्री मालिनी अवस्थी एवं देश के विभिन्न प्रान्तों के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां करायी गयी।

लखनऊ महोत्सव में संस्कृति विभाग द्वारा कोई धनराशि नहीं व्यय की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत इलाहाबाद में प्रयाग महोत्सव हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कोई योजना नहीं है। भारत सरकार के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा इलाहाबाद में वर्षपर्यन्त अनेक कार्यक्रम होते रहते है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व0 वीनेश कुमारी मृतक मुख्य सेविका बाल विकास एवं पुष्टाहार जनपद अलीगढ़ के बकाया देयकों के भुगतान उनके आश्रित पुत्र श्री भाष्कर चौहान को करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

13—श्री दलवीर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वीनेश कुमारी मृतक मुख्य सेविका बाल विकास एवं पुष्टाहार, निवासी जवा, जनपद अलीगढ़ के बकाया देयकों के भुगतान उनके आश्रित पुत्र श्री भाष्कर चौहान को करने सम्बन्धी, प्रश्नकर्ता के पत्र सं0—सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0—10639155/ 2015, दिनांक 18—06—2015 पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

श्री भाष्कर चौहान, मृतका स्व0 वीनेश कुमारी के अभिलेखों में विधिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं है। विधिक उत्तराधिकारी घोषित न होने के फलस्वरूप उनको लम्बित देयकों का भुगतान नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

श्री भाष्कर चौहान जनपद अलीगढ़ के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में मृतक आश्रित के रूप में नौकरी सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

14—श्री दलवीर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर आपके आदेश सं0—सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0—10639096/2015, दिनांक 18—06—2015 जो श्री भाष्कर चौहान जनपद अलीगढ़ को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में मृतक आश्रित के रूप में नौकरी सम्बन्धी है, पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

श्री भाष्कर चौहान, मृतका स्व0 वीनेश कुमारी की बहन के पौत्र है को उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में निहित प्राविधानों के अनुसार ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत न आने के फलस्वरूप नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित नहीं किया गया।

उपरोक्तानुसार।

15—श्री रविदास मेहरोत्रा—

ख्दिनांक 09—02—2016 को अता0प्र0सं0—198 द्वारा उत्तरित,

युवकों के उत्थान हेतु जौनपुर में कौशल विकास केन्द्र के स्थापना की योजना

16—श्री नदीम जावेद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कौशल विकास पर हो रहे कार्यक्रम के अन्तर्गत युवकों के उत्थान के लिये जौनपुर में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से अनुबन्धित 8 निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं एक फ्लैक्सी एम0ओ0यू0 प्रशिक्षण प्रदाता को जनपद जौनपुर आवंटित किया गया है। इन प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा जनपद जौनपुर में 57 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हिन्दी भाषा जागरूकता समारोह के आयोजन की मांग

17–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी भाषा जागरूकता समारोहों का आयोजन सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

हिन्दी भाषी प्रदेश होने के कारण उत्तर प्रदेश में इसकी आवश्यकता नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद में विधवा महिलाओं के पेंशन सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी जानकारी

18–श्री मनीष असीजा–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में ऐसी कितनी विधवा महिलायें हैं जिनके पेंशन के आवेदन–पत्र पात्रता श्रेणी में स्वीकृत होने के बावजूद बजट के अभाव में उनको पेंशन प्राप्त नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार इन सभी पात्रता श्रेणी की विधवा महिलाओं को पेंशन की सुविधा प्रदान करने हेतु बजटीय प्राविधान कर धनराशि आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

जनपद फिरोजाबाद में अब तक 6128 विधवा पेंशन के पात्र लाभार्थियों के आवेदन फार्म कार्यालय में प्राप्त हुये हैं। सभी लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृति करते हुये जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा फार्म पी0एफ0एम0एस0 पर अपलोड करा दिये गये है।

जी हां।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, फिरोजाबाद, द्वारा पेंशन स्वीकृत करते हुए फार्म पी0एफ0एम0एस0 पर अपलोड करा दिये गये है। पी0एफ0एम0एस0 से सत्यापित तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर से लाक किये गये समस्त पात्र लाभार्थियों को उक्त योजना के अन्तर्गत पेंशन वितरित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बालिग बच्चों की विधवा माताओं को प्रदान की जाने वाली पेंशन एवं निर्धारित नीति की जानकारी

19—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उन विधवाओं को पेंशन नहीं दी जाती है जिनका बच्चा बालिग होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन विधवाओं को पेंशन स्वीकृत नहीं की गयी है उसका बालिग लड़का अपनी विधवा मां को घर से अलग कर देता है ऐसी स्थिति में क्या सरकार उनकी सहायतार्थ कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सैय्यद शादाब फातिमा—

शासनादेश सं0—1408/60—1—15—1—13(72)/06, दिनांक 13 अगस्त, 2015 में यह व्यवस्था है कि पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना में ऐसी महिलायें जिनके बच्चे बालिग होने पर भी यदि भरण पोषण करने में असमर्थ है और वह महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है तो पात्रता की श्रेणी में आती है।

नियमों के अन्तर्गत पात्रता के आधार पर उक्त योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत व वितरित की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

20—श्री त्रिभुवन राम—

ख्विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त,

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र भेलसर रूदौली बाबा बाजार उमापुर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

21—श्री रामचन्द्र यादव—

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत भेलसर रूदौली बाबा बाजार उमापुर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के बाद बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को स्वीकृति के बाद भी निर्मित न करने के कारणों की जांच कराकर निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)—

निर्माण कार्य बन्द नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—2 के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 31—8—2015 से प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है। अतएव प्रश्नगत मार्ग को निर्मित न कराने के कारणों की जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

22—श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या—वि0प0/ज0हि0/2015—16/क—5न0—368615/8979, दिनांक 16—11—2015 मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर यथोचित निर्णय लेने हेतु पत्रावली लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

23—श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के डामरीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या—वि0प0/ज0हि0/2015—16/क—5न0—368614/8981, दिनांक 16—11—2015 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं है।

24—श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप —

ख्2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0—196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

25—श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप—

ख्ले बुधवार के अता0प्र0सं0–196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

26–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

ख्ले बुधवार के अता0प्र0सं0–197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

27–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

ख्ले बुधवार के अता0प्र0सं0–198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

जनपद इलाहाबाद तहसील फूलपुर ग्राम सभा झूंसी कोहना में उल्टा किला की मरम्मत कराये जाने की मांग

28–श्री दीपक पटेल–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील–फूलपुर के ग्राम सभा झूंसी कोहना में ऐतिहासिक, पौराणिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण उल्टा किला रख–रखाव एवं मरम्मतीकरण के अभाव में ध्वस्त होने के कगार पर है, जिससे इसके वजूद पर संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किले की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमार कोरी–

संस्कृति विभाग के उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य संरक्षित स्मारकों के मरम्मत आदि की कार्रवाई की जाती है। यह स्मारक उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

29–श्री अनीसुर्ररहमान–

खदिनांक 09–02–2016 के अता0प्र0सं0–194 द्वारा उत्तरित,

जनपद इलाहाबाद में मार्च, 2014 से मार्च, 2015 तक प्राप्त विधवा पेंशन हेतु आवेदन पत्रों की जानकारी

30–श्री दीपक पटेल–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में मार्च, 2014 से मार्च, 2015 तक विधवा पेंशन हेतु कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुये, उनमें से कितनी पात्र विधवाओं को पेंशन प्रदान की गयी एवं कितनी शेष हैं ? क्या सरकार शेष पात्र लाभार्थियों को विधवा पेंशन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

जनपद इलाहाबाद में मार्च, 2014 से मार्च, 2015 तक विधवा पेंशन हेतु कुल 1344 आवेदन–पत्र प्राप्त हुये। उक्त समस्त पात्र आवेदन पत्रों को आनलाइन फीड कराकर पेंशन प्रदान किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट की स्थापना कराने की मांग

31–श्री मनीष असीजा–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट की स्थापना करने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

जी नहीं।

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 तत्सम्बन्धी नियमावली, 2007 के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक जनपद में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाना है। जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट का नहीं।

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 एवं नियमावली, 2007 के प्राविधानों के अनुसार चयन समिति द्वारा प्रत्येक जनपद के लिये बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के चयन की कार्रवाई गतिमान है।

32–प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

ख्2सरे मंगलवार के अता0प्र0सं0–64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

जनपद मथुरा ब्लाक राया, करह आदि में पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत विगत पांच वर्षों में जर्जर सड़कों की मरम्मत एवं नवनिर्माण कराये जाने की मांग

33–श्री पूरन प्रकाश–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में ब्लाक राया, फरह एवं बल्देव में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों में कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया ? क्या यह सही है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत तीनों ब्लाकों में निर्मित सड़कें रख–रखाव के अभाव में जर्जर हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सड़कों की मरम्मत/नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव–

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा जनपद मथुरा के ब्लाक राया, फरह एवं बल्देव में पिछले 5 वर्षों में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत किसी सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत होमगार्ड्स का मानदेय बढ़ाये जाने की मांग

34—श्री नदीम जावेद—

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत लगभग 1,20,000 होमगार्ड्स को रु0 225/—प्रतिदिन मानदेय के अतिरिक्त किसी अन्य भत्ते व सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्रदेश में कार्यरत होमगार्ड्स का मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

वर्तमान में 1,18,348 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की संख्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित है जिन्हें मानदेय के रूप में रुपये 225/— प्रतिदिन देय है। ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को अन्तरजनपदीय ड्यूटी पर रुपये 30/— अतिरिक्त, विभिन्न संस्थाओं की कामर्शियल ड्यूटी पर रुपये 10/— का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु अथवा घायल होने पर बीमा योजना का लाभ, होमगार्ड्स कल्याणकोष से आर्थिक सहायता, अनुकम्पा के आधार पर पात्र आश्रितों को सेवायोजित करने का प्राविधान है।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए समय—समय पर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के मानदेय में वृद्धि की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में वर्ष 2015—16 हेतु योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में आवंटित धनराशि का क्रमवार विवरण

35—श्री रामचन्द्र यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में वर्ष 2015—16 में समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायत कांदा खुलाशा, हरिहरपुर का स्थान, रतनपुर, रानीमऊ, दशरथमऊ सहित विधान सभा क्षेत्र रूदौली में कुल कितनी— कितनी धनराशि अब तक आवंटित की गयी ? क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में वर्ष 2015—16 हेतु योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में आवंटित धनराशि का कार्यक्रमवार विवरण संलग्न है।[†]

योजनान्तर्गत चयनित ग्राम टांडा खुलासा, हरिहरपुर कायस्थान, रतनपुर, रानीमऊ व दशरथमऊ में स्वच्छ पेयजल हेतु हैण्डपम्प की स्थापना एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि आवंटित न होने तथा स्वच्छ शौचालय का

---

† ¼nsf[k;s uRFkh ^^[k** vkxs i`"B 155&156 ij½

निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम रतनपुर एवं रानीमऊ में जनपद स्तर पर राज्यांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण उक्त ग्रामों में कार्य नहीं कराया जा सका है। इन कार्यक्रमों को छोड़कर उक्त ग्राम अन्य सभी कार्यक्रमों से संतृप्त हैं। उक्त ग्रामों के अवशेष कार्यक्रमों का निर्माण कार्य धनराशि की उपलब्धता पर कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

36–श्री नदीम जावेद–

ख्2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

प्रदेश में महिलाओं/बच्चों के प्रति घटित यौन अपराधों के रोकथाम के मांग

37–श्री मनीष असीजा–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिलाओं के प्रति यौन अपराधों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को रोकने के लिये बने नये कानून क्रिमनल ला अमेण्डमेंट एक्ट–2013–पोक्सों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिये प्रदेश में थाने स्तर पर इसको सूचना पट्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने तथा सामाजिक रूप से विभिन्न समूहों, महिला कालेजों आदि में बैठकें कर साहित्य उपलब्ध कराकर वृहद् जन जागरूकता अभियान चलाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सैय्यदा शादाव फातिमा–

जी हां।

सूच्य है कि महिलाओं/बच्चों के प्रति घटित होने वाले यौन अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस विभाग के पत्र संख्या–डीजी–सात–एस–3(23)/2012, दिनांक 13–01–2013 एवं डीजी परिपत्र संख्या–16/2013, दिनांक 29–04–2013 के माध्यम से प्रोटेशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल एसाल्ट एक्ट–2012 तथा क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट ऐक्ट–2013 के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार कराये जाने के लिये प्रत्येक थाने में सूचना पट्ट पर चस्पा कराये जाने के आदेश निर्गत हैं।

इसके अतिरिक्त प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल एसाल्ट ऐक्ट–2012 व क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट ऐक्ट–2013 के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न समूहों, महिला कालेजों में साहित्य उपलब्ध कराकर जागरूकता की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही साथ महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के नियंत्रण हेतु वूमेन पॉवर लाइन 1090 का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात में वर्ष 2015–16 में लोहिया ग्राम के रूप में चयनित गांवों के सम्बन्ध में जानकारी

38–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात में वर्ष 2015–16 में कितने गांव लोहिया ग्राम के रूप में चयनित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार लोहिया ग्राम के रूप में सिकन्दरा विधान सभा क्षेत्र के गांवों को भी चयनित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

इस विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015–16 में कोई भी लोहिया ग्राम चयनित नहीं किया गया है।

शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2013 द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन हेतु शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2012 के प्रस्तर–2 (4) में निमनानुसार आंशिक संशोधन करते हुए मा0 सदस्य विधान सभा एवं विधान परिषद् की सहभागिता सुनिश्चित किए जाने हेतु यह व्यवस्था की गई है कि प्राप्त तीन गुना संख्या के राजस्व ग्रामों की सूची जिलाधिकारी द्वारा जनपद के मा0 जिला प्रभारी मंत्री जी को चयन हेतु उपलब्ध करायी जाए। इस सूची के आधार पर जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा जनपद के समस्त मा0 सदस्य विधान सभा एवं मा0 सदस्य विधान परिषद् में विचार–विमर्स करते हुए वर्षवार ग्रामों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार शासनादेश में विहित उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत चयन की कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा–वृन्दावन के बीच में एक वातानुकूलित ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

39–श्री प्रदीप माथुर–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री द्वारा सितम्बर, 2012 में वृन्दावन आगमन पर मथुरा–वृन्दावन के बीच में एक वातानुकूलित ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा की गयी थी तथा इसके लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में 5 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित भी की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राविधानित धनराशि रु0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्रवाई गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली के डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने जाने की मांग

40–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015–16 में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित विधान सभा क्षेत्र रूदौली, जनपद फैजाबाद के ग्रामों में होने वाले कार्यों की कार्ययोजना के आधार पर धन आवंटन में

कटौती की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार चयनित गांव पंचायतों में कराये गये अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु धन आवंटित कर समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में चयनित समग्र ग्रामों में होने वाले कार्यों के सापेक्ष धनराशि की कटौती नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012 से 2015 तक विधवा पेंशन के लम्बित आवेदन–पत्रों के निस्तारण की मांग

41–श्री दीपक पटेल–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 में प्राप्त विधवा पेंशन के कितने आवेदन–पत्र अनिस्तारित पड़ें हैं ? क्या सरकार सभी लम्बित आवेदन–पत्रों का निस्तारण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 में कुल 4073 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए। समस्त आवेदन पत्रों की पेंशन स्वीकृत करते हुए पी0एफ0एम0एस0 पर आनलाइन फीड कराकर पेंशन दिये जाने की कार्रवाई की गई, कोई भी पात्र आवेदन–पत्र निस्तारण हेतु अवशेष नहीं है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद बी0एस0एन0एल0 के सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत रक्षकों के बकाये मानदेय/वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में

42–श्री दीपक पटेल–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद में विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बी0एस0एन0एल0 में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्य कर रहे प्रान्तीय रक्षक दल के 62 जवानों को 11 महीनों से मानदेय/वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रान्तीय रक्षक दल के इन जवानों को बकाये मानदेय/वेतन दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां। बी0एस0एन0एल0 की मांग पर प्रान्तीय रक्षक दल के 42 जवानों की ड्यूटी दूरभाष केन्द्रों की सुरक्षा में लगाई गई है। इन जवानों का माह सितम्बर, 2014 एवं अक्टूबर, 2014 तथा माह–मार्च, 2015 से अक्टूबर, 2015 तक का बिल भुगतान हेतु महाप्रबन्धक, दूरसंचार, इलाहाबाद के यहां प्रस्तुत है, जिसका भुगतान अप्राप्त है। माह नवम्बर, 2015 एवं दिसम्बर, 2015 तक के बिल जनपद के विभिन्न दूरभाष केन्द्रों के अभियन्ताओं से प्रमाणित होकर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

जी हां।

बी0एस0एन0एल0 से भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त जवानों का भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात, ब्लाक झींझक अन्तर्गत ग्राम जजमुइया का सम्पूर्ण विकास कराये जाने की मांग

43–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के ब्लाक झींझक के अन्तर्गत आने वाले ग्राम जजमुइया को पिछले वर्ष लोहिया ग्राम घोषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम का सम्पूर्ण विकास कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड झींझक के ग्राम जजमुइया का चयन किया गया है।

उक्त ग्राम का योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रमों से सम्पूर्ण विकास कराया जायेगा।

योजनान्तर्गत अनुमन्य समस्त कार्य 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के विकास खण्ड सरसौल अन्तर्गत करदी गांव एवं उसके मजरे बगेचा और गडेजन पुरवा के विकास कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

44–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–कानपुर के विकास खण्ड–सरसौल के अन्तर्गत करदी गांव लोहिया ग्राम में चयनित हुआ था ? यदि हां, तो

क्या राजस्व ग्राम करदी सहित उसके मजरे बगेचा और गडेजन पुरवा में सभी अनुमन्य विकास कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। जनपद कानपुर के विकास खण्ड–सरसौल के अन्तर्गत करवी गांव एवं उसके मजरे गड़रियन पुरवा तथा सलेम बगीचा को वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत चयनित किया गया है।

उक्त ग्राम व उसके मजरें में निर्धारित मानक के अनुरूप सभी अनुमन्य विकास कार्य कराये जा रहे है।

योजनान्तर्गत अनुमन्य समस्त कार्य 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

45–श्री दलवीर सिंह–

ख्दिनांक 11–02–2016 को अता0प्र0सं0–57 द्वारा उत्तरित,

प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने हेतु लघु उद्योगों का प्रशिक्षण दिलाकर लोगों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

46–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने हेतु क्या सरकार लघु उद्योगों से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिलाकर लोगों को रोजगार दिलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमशील मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कौशल में वृद्धि कराते हुए रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त करने योग्य बनाया जाता है। इन पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत लघु, मध्यम तथा भारी उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न व्यावसायिक कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों को शासन द्वारा प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश देने का प्राविधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को 39 सेक्टर के 292 कोर्सेज में अल्पकालीन रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें लघु उद्योगों से सम्बन्धित प्रशिक्षण भी शामिल है। युवाओं को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें रोजगार प्रदान कराने में मिशन द्वारा हर सम्भव सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

ख1.48, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब हम नियम–301 की सूचनायें लेते हैं। आज दिनांक 15–02–2016 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें से 15 सूचनाएं स्वीकृत की गयीं।

पहली सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

दूसरी सूचना श्री रविन्द्र भड़ाना की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

तीसरी सूचना डा0 अरुण कुमार की जनपद बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में अरवन फीडर से विद्युत सप्लाई करने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

पांचवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर अन्तर्गत कतिपय संपर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में किसानों को राहत राशि एवं पूर्व से लंबित पड़े मुआवजों को अविलम्ब दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री उमाशंकर की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत इन्दारा रजवाहा को ग्राम सभा सुल्तानपुर से कोपवां बहादुरपुर तक पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

नौवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मथुरा में एन0एस0–2 पर प्रस्तावित बस स्टैण्ड और उसके साथ मल्टीप्लैक्स एवं शापिंग काम्प्लेक्स बनाये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे की जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र खड्डा में प्रमुख मार्गों को प्रभावित करने वाले दो आर0 सी0 सी0 पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव जनपद फैजाबाद के रूदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माइनरों/रजवाहों की सफाई कराने एवं बन्द पड़े कुलाबे एवं क्षतिग्रस्त नालियां ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री सुदेश शर्मा की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

चौदहवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

पन्द्रहवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में एन0एच0 मार्ग–31 पर एकत्रित हुये गंगा नदी के जल से खतरे को देखते हुये सिल्ट की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं वे क्रमशः श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री सन्त प्रसाद, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री गजराज सिंह, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री सुरेश बंसल, श्री काली चरन सुमन, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री ममतेश शाक्य तथा श्री सतीश महाना।

माननीय सदस्य श्री मुकुट बिहारी वर्मा के अनुपस्थित होने पर श्री रवीन्द्र जायसवाल की सूचना ली जाती है। श्री रवीन्द्र भड़ाना के अनुपस्थित होने पर श्री भगवान सिंह कुशवाहा की सूचना ली जाती है। श्री पंकज कुमार मलिक के अनुपस्थित होने पर श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री कुलदीप सिंह सेंगर के अनुपस्थित होने पर श्री सतीश महाना, श्री सुदेश शर्मा, की जगह पर श्री सुरेश बंसल और श्री अनीसुर्रहमान की जगह पर श्री सन्त प्रसाद की सूचनाएं स्वीकार की जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में अरबन फीडर से विद्युत सप्लाई करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार–

ख्महोदय, बरेली महानगर (शहर विधान सभा) क्षेत्र में गांव खड़उवा, टियूलिया, पस्तोर, सरनियां, नदौसी, बण्डिया, रामलीला गोंटिया, समाधि गोंटिया, सेवाधाम, आलोक नगर, डिफेन्स कालोनी, सिद्धार्थ नगर (परतापुर), रामनगर कालोनी, बसन्त विहार तथा वीर सावरकर नगर लगभग 25 साल पहले महानगर से जुड़े। इन सबको ग्रामीण फीडर से विद्युत सप्लाई होती थी जो 25 साल व्यतीत हो जाने के बाद आज भी ग्रामीण फीडर से सप्लाई होती है तथा बिजली महानगर के मुकाबले कम देर मिलती है। इन क्षेत्रों में बिजली का विकास कार्य कोई खास नहीं हुआ है। शहरी विद्युत विभाग ने इनको शहर नहीं माना क्योंकि इनको ग्रामीण फीडर से सप्लाई होती है। ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं यहां इसलिये नहीं लागू कीं क्योंकि ग्रामीण विद्युत विभाग ने इनको महानगर का हिस्सा माना और महानगर विद्युत सप्लाई ने इन्हें ग्रामीण क्षेत्र का माना। मैं चाहता हूं कि उक्त क्षेत्रों को भी शहरी विद्युत फीडर से सप्लाई की जाय।

---

uksV %& [ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।,

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

ख्अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद–चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के अन्तर्गत निम्न सम्पर्क मार्गों के अभाव में बीहड़ एवं दस्यु प्रभावित क्षेत्र में बसे हुए लोगों को आवागमन एवं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से कुछ सम्पर्क मार्ग ऐसे हैं जो आधे अधूरे बने हैं किन्तु वन विभाग के आपत्ति के कारण नहीं बन पा रहे हैं।

1–विकास खण्ड मानिकपुर में ग्राम कल्याणपुर स्थित बरदहा नाला रपटा से धारकुण्डी गौशाला आश्रम होते हुए म0प्र0 की सीमा तक सम्पर्क मार्ग।

2–विकास खण्ड मऊ में प्रधानमंत्री सड़क मऊ नीबी ग्राम से दानूबाबा के आगे लपांव सम्पर्क मार्ग जोड़ने तक।

3–विकास खण्ड मानिकपुर में मारकुण्डी से ददरीमाफी मडैयन होते हुए ग्राम बहिलपुरवा तक सम्पर्क मार्ग।

4–विकास खण्ड मानिकपुर में ददरीमाफी से अनुसुइया आश्रम तक सीधी सम्पर्क मार्ग।

5–विकास खण्ड मानिकपुर में ग्राम जमुनिहाई से अमरावती आश्रम होते हुए सती अनुसुइया आश्रम सम्पर्क मार्ग।

6–विकास खण्ड मऊ में बरगढ़ मोड़ से परानू बाबा होते हुए ग्राम परदवां तक सम्पर्क मार्ग।

7–विकास खण्ड मऊ में हनुमानगंज मजरा लौरी से कोटा कदैंला पक्का सम्पर्क मार्ग।

8–विकास खण्ड मानिकपुर में मानिकपुर बाजार तिराहा से ग्राम चुरेह केशरुवा अनुसूचित जाति बस्ती के आगे म0प्र0 सीमा तक सम्पर्क मार्ग।

उक्त विकास खण्ड के मार्गों का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे उक्त स्थानीय/क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः महोदय इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में यथाशीघ्र **जनपद–चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर व वि0ख0 मऊ, मानिकपुर के निम्न सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्यों में वन**

---

uksV %& [ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

विभाग द्वारा की जा रही आपत्ति को समाप्त करवाकर सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य की कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के किसानों को राहत राशि एवं पूर्व से लम्बित पड़े मुआवजों को अविलम्ब दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में ओलावृष्टि होने के कारण क्षेत्रीय किसानों को अत्यधिक क्षति हुई थी, जनपद–गोरखपुर में ओलावृष्टि आदि से किसानों की फसल नष्ट हो जाने के कारण क्षेत्रीय किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं। सरकार द्वारा भी क्षेत्र का सर्वे कराकर प्राकृतिक आपदा ग्रस्त घोषित किया था। किसानों को गत वर्ष के प्राकृतिक आपदा राहत राशि अभी तक शत प्रतिशत उपलब्ध नहीं की जा सकी एवं इस वर्ष भी राहत राशि वितरित नहीं हुई है। ओलावृष्टि से किसानों की फसल के नुकसान का सही सर्वे नहीं किया गया और न ही आज तक किसानों को सही राहत राशि उपलब्ध करायी गयी। राज्य सरकार से किसानों को नई व पुरानी सूखा राहत राशि व किसानों के पूर्व से लम्बित पड़े राहत राशि को अविलम्ब भुगतान कराने हेतु सम्बन्धित विभागों को अपने स्तर पर कार्रवाई करने हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा अनुरोध किया गया है, परन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त राहत राशि के भुगतान हेतु कोई प्रयास नहीं किये जाने से क्षेत्र के किसानों में शासन के प्रति अत्यधिक रोष व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से जनपद–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के किसानों को राहत राशि एवं पूर्व से लम्बित पड़े मुआवजों को अविलम्ब दिलाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत इन्दारा रजवाहा को ग्राम सभा सुल्तानपुर से कोपवा बहादुरपुर तक पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर–

ख्मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा रसड़ा अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड–32 से निकलने वाली इन्दारा रजवाहा ग्राम सभा सुल्तानपुर से लेकर कोपवां बहादुरपुर तक वाया रामनगर, संवरा, उचेड़ा, डुमरी अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण प्रतिवर्ष इससे हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो

---

uksV %& [ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जाती है जिससे किसानों को अत्यधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है तथा गरीब किसान लाचार अवस्था में केवल अपनी फसलों की बर्बादी पर आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा अन्तर्गत पड़ने वाली इन्दारा रजवाहा को ग्राम सभा सुल्तानपुर से कोपवां बहादुरपुर तक पक्का कराये जाने हेतु शासन से कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर–

ख्मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं यह तहसील उत्तरांचल राज्य की सीमा पर उपस्थित है तथा यह तहसील राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पर स्थित है तथा यह उत्तरांचल राज्य के नैनीताल, अल्मोड़ा आदि पर्यटक स्थलों का प्रमुख मार्ग है तथा पड़ोसी जनपद रुद्रपुर (उत्तरांचल) के सिडकुल है जिसमें 600 से अधिक फैक्ट्रियां स्थित हैं जिसका आवागमन भी इसी तहसील से होकर जाता है तथा यहां पर अक्सर जाम लगा रहता है जिसके कारण सवारियों को उतरने व चढ़ने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा अक्सर दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। यहां पर रोडवेज का बस अड्डा खोले जाने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है तथा सरकार का बहुत लम्बे समये से यहां पर रोडवेज का बस अड्डा खोले जाने का आश्वासन भी है। यह तहसील व्यापारिक दृष्टिकोण से भी परिवहन विभाग के लिए लाभदायक है। यहां पर रोडवेज बस अड्डा न खोले जाने से क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है, जिसके कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मथुरा में एन0एच0–2 पर प्रस्तावित बस स्टैण्ड और उसके साथ मल्टीप्लैक्स एवं शापिंग काम्प्लेक्स बनाये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में
नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर–

ख्लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मथुरा में एन0एच0–2 पर स्थित पराग डेरी परिसर में 5 एकड़ भूमि पर परिवहन बस स्टैण्ड स्थापित किये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी के हस्तक्षेप से उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा दुग्ध विकास संघ को 15 करोड़ रुपये का

---

uksV %& [ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

भुगतान कर उनसे लीज पर भूमि आवंटित करा लिया गया है। किन्तु उक्त भूमि आवंटित होने के बावजूद भी अभी तक परिवहन विभाग द्वारा नये बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है। परिवहन विभाग द्वारा यहां पर पी0पी0पी0 मॉडल पर बस स्टैण्ड और उसके साथ मल्टीप्लेक्स और शापिंग काम्प्लेक्स बनाया जाना प्रस्तावित है उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा उक्त भूमि 62 वर्ष की लीज पर आवंटित किये जाने के कारण कोई भी प्राइवेट कम्पनी पी0पी0पी0 मॉडल पर उक्त बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। यदि पी0पी0पी0 मॉडल पर बस स्टैण्ड की प्रतिस्थापना के लिए शासन द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता है तो तत्काल प्रभाव से उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम उक्त बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य शुरू करे, जिससे वर्तमान में शहर के बीचोबीच स्थित पुराने बस स्टैण्ड के पास लगने वाले जबर्दस्त जाम से यहां के निवासियों को राहत मिल सके तथा बाहर से आये यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। इसलिये शीघ्र एन0एच0–2 पर स्थित पराग डेरी परिसर में लीज पर आवंटित 5 एकड़ भूमि पर परिवहन निगम द्वारा नया बस स्टैण्ड प्रतिस्थापित किया जाना अति–आवश्यक है। प्रकरण तात्कालिक, जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मथुरा में एन0एच0–2 पर स्थित पराग डेरी परिकर में लीज पर आवंटित 5 एकड़ भूमि पर नये बस स्टैण्ड का निर्माण परिवहन विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र खड्डा में प्रमुख मार्गों को प्रभावित करने वाले दो आर0 सी0 सी0 पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दुबे–

ख्महोदय, विधान सभा 329 खड्डा, जिला कुशीनगर में दो बड़े पुल के निर्माण न हो सकने से वर्ष के 6 माह से प्रमुख मार्ग से जनता का आवागमन बन्द हो जाता है। निम्न आर0सी0सी0 पुल का निर्माण जनहित के दृष्टिगत अति आवश्यक है।

1–ग्राम सभा–अहिरौली के मनमन टोले में रंजीता नाले पर 20 मीटर आर0सी0सी0 पुल निर्माण।

2–मकनहीं घाट पर 15 मीटर आर0सी0सी0 पुल निर्माण।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद फैजाबाद के रूदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माइनरों/रजवाहों की सफाई कराने एवं बन्द पड़े कुलाबे एवं क्षतिग्रस्त नालियां ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

---

uksV %& [ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्री राम चन्द्र यादव–

ख्महोदय, जनपद फैजाबाद विधान सभा रुदौली अन्तर्गत माइनरों/रजवाहों की सफाई का कार्य विगत कई वर्षों से नहीं किया गया जिसके कारण किसानों की खरीफ की फसल चौपट हुई। वित्तीय वर्ष के 11 माह बीत चुके हैं इस वर्ष भी सफाई का कार्य अभी तक नहीं किया गया। परिणामस्वरूप रबी की फसल का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। सुल्तानपुर शाखा नहर व फैजाबाद शाखा नहर के सभी गुलावे बंद पड़े हैं, नालियां क्षतिग्रस्त पड़ी हैं उपरोक्त दोनों नहरों से क्षेत्र के सुलेमानपुर गांव के पास सीवन बाधितपुर माइनर कट जाने से सैकड़ों किसानों की जमीन जलमग्न हो गयी। रौजा गांव इलाके में यह माइनर तीन बार कट चुकी हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की घोर लापरवाही से पूरे क्षेत्र के किसानों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के तात्कालिक विषय पर सरकार से कार्रवाई करने की मांग करता हूं।,

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में एन0एच0 मार्ग–31 पर एकत्रित हुये गंगा नदी के जल से खतरे को देखते हुये सिल्ट की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया के गंगा नदी में स्टोर हो जाने के कारण नेशनल हाईवे–31 पर पानी का दबाव काफी बढ़ गया है जिससे वहां एन0एच0 मार्ग–31 पर खतरा बढ़ गया है। बरसात के समय तो कभी भी टूटने का अन्देशा बना रहता है जिससे पचासों गांव विलुप्त होने की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं। पहले एन0एच0 मार्ग कई बार टूट चुका है जिससे काफी गांव प्रभावित हो चुके हैं। यह पिछड़ा क्षेत्र है। जनहित में उक्त नदी की सिल्ट की सफाई कराये जाने की आवश्यकता है जिससे पानी का फैलाव दूर तक हो जायेगा और एन0एच0–31 पर उक्त पानी का बदाव कम हो जायेगा और आम जनमानस को इससे राहत मिलेगी। यह जनहित का विषय है।

अतः इस पर शासन से तत्काल त्वरित कार्रवाई किये जाने व प्रकरण का निराकरण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद वाराणसी उत्तरी के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पंचकोसी बघवा नाला मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र वाराणसी उत्तरी के अन्तर्गत पंचकोसी–बघवा नाला मार्ग विगत कई सालों से क्षतिग्रस्त है। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। इस महत्वपूर्ण मार्ग के निर्माण हेतु जिले के सम्बन्धित

---

uksV %& [ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अधिकारियों को अवगत कराया गया परन्तु अभी तक इस मार्ग के निर्माण/मरम्मत हेतु कोई कार्रवाई न किये जाने से जनमानस में हताशा एवं निराशा व्याप्त है। जनहित में इस मार्ग का निर्माण अविलम्ब कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा के विकास खण्ड खैरागढ़, गांव रिठौरी कटरा से नगला हरलाल तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे जनपद आगरा के विकास खण्ड खैरागढ़ में गांव रिठौरी कटरा से नगला हरलाल तक मार्ग जिसकी ल0 लगभग 3.50 किमी0 है, जो काफी वर्षों पहले पत्थरों के खण्डों से बना हुआ था। जोकि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जिसके कारण छात्र–छात्राओं को स्कूल जाने एवं क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे सरकार के प्रति क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मार्ग को सरकार द्वारा चलायी जा रही त्वरित योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए पक्की सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बस्ती के ओपेक चिकित्सालय कैली में रखी फेको मशीन का लाभ आमजनों को दिलाने तथा फोल्डेबुल लेंस व कैसेट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल–

ख्महोदय, मानव जीवन के लिए अन्धता अभिशाप माना जाता है, जिसके निवारण के लिए केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारें अति गम्भीर हैं। अत्याधुनिक विधि से आंखों के आपरेशन के लिए मरीजों को दूसरे जनपदों में जाना पड़ता है। सुविधा होने के बावजूद इसका लाभ निजी संस्थायें उठाती हैं, गलती का ठीकरा फूटता है स्वास्थ्य विभाग पर।

ज्ञात हो कि 04 वर्ष पूर्व से जनपद–बस्ती के ओपेक चिकित्सालय कैली में रखी फेको मशीन ताले में बन्द है। फोल्डेबुल लेन्स व कैसेट की कमी के चलते लाखों रुपये की मशीन अनुपयोगी बनी हुई है। वर्तमान में विशेषज्ञ डाक्टर सामान्य ढंग से ही आंखों का आपरेशन कर रहे हैं, जबकि वर्ष 2011 में ही मिनी पी0जी0आई0 के नाम से विख्यात ओपेक चिकित्सालय कैली में सरकार ने अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत फेको मशीन उपलब्ध करा दी थी। चूंकि चिकित्सालय में कुशल प्रशिक्षित विशेषज्ञ डाक्टर न होने के कारण उक्त मशीन उपेक्षित पड़ी रही। माह जुलाई वर्ष 2015 में चिकित्सालय में फेको मशीन से प्रशिक्षित चिकित्सक की तैनाती शासन द्वारा की गयी, लेकिन फेको

---

uksV %& [ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

मशीन के लिए आवश्यक फोल्डेबुल लेन्स कैसेट की चिकित्सक द्वारा मांग किये जाने पर चिकित्सालय प्रशासन द्वारा बताया गया कि मशीन के साथ उपरोक्त उपकरण आये ही नहीं थे। शासन से जब चिकित्सालय प्रशासन ने उक्त सम्बन्ध में वार्ता किया तो शासन द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त दोनों उपकरण अनुमन्य ही नहीं हैं, जबकि आपरेशन के दौरान उक्त दोनों उपकरणों का होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि फोल्डेबुल लेन्स के माध्यम से ही आपरेशन के दौरान आंखों में लेन्स डाला जाता है तथा कैसेट का उपयोग भी आपरेशन के दौरान किया जाता है। एक कैसेट का उपयोग मशीन में एक ही बार किया जाता है दूसरे दिन यह बेकार हो जाता है। उपकरण के न होने से लाखों रुपया खर्च करके सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी अत्याधुनिक फेको मशीन अनुपयोगी साबित हो रही है। फेको मशीन का लाभ आमजन को मिल सके इसके लिए फोल्डेबुल लेन्स व कैसेट उपलब्ध कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण अति लोकमहत्व का है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद कानपुर महाराजगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांधी वार्ड में पटेल नगर मलिन बस्ती तथा बाईपास के किनारे सड़क एवं जल निकासी के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना–

ख्महोदय, कानपुर महाराजगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गांधी ग्राम वार्ड में पटेल नगर मलिन बस्ती की मुख्य मार्ग एवं इसी वार्ड के अन्तर्गत गांधी ग्राम में बाई पास के किनारे सड़क एवं जल निकासी न हाने के कारण सारे स्थानीय निवासियों को भीषण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जल भराव के भीषण बीमारियों के फैलने का गम्भीर खतरा पड़ रहा है। स्थानीय जिला प्रशासन की इस निष्क्रियता के कारण जनमानस में निराशा एवं आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जल निकासी की व्यवस्था एवं मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

गाजियाबाद के वार्ड–39 में जी0टी0 रोड से आर0के0 मैरिज हाल के बराबर वाली गली क्षतिग्रस्त सड़क जो श्री वेद मनमोहन के नाम पर है, की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल–

ख्महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड नंबर 39 में एक मुख्य सड़क जो जी0टी0 रोड से आर0के0 मैरिज हॉल के बराबर में है जो श्री वेद मनमोहन मार्ग के नाम पर है, पूर्णतयः क्षतिग्रस्त है। यह एक मुख्य सड़क है, जिसमें काफी संख्या में लोगों/वाहनों का आवागमन रहता है, इस सड़क पर जगह–जगह गड्ढे हो चुके हैं व

---

uksV %& [ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

बरसात के दिनों में गन्दा पानी भरा रहता है जिसके कारण यहां के निवासियों को बड़ी असुविधा है व गंभीर बीमारी फैलने का भी भय रहता है।

अतः जनहित में, जिस सड़क पर चलना भी दूभर है, की मरम्मत कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र खजनी में सिकरीगंज–बेलघाट–कुरी मार्ग पर जल भराव के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद–

ख्महोदय, सिकरीगंज–बेलघाट–कुरी मार्ग का उच्चीकरण होने से सड़कों की ऊंचाई बढ़ जाने के कारण बेलघाट–शंकरपुर–कुरी आदि चौराहों पर पानी भर जाता है जिससे जल जनित बीमारियां फैल रही हैं तथा आवागमन में भी कठिनाई हो रही है। जनहित में जल निकासी के लिए नाली का निर्माण अविलम्ब किया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सिकरीगंज, बेलघाट, कुरी आदि चौराहों पर जल निकासी हेतु तत्काल नाली का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–03 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–04।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता की ग्राम सभा गम्भीरा में पाइप पेयजल परियोजना कराये जाने विषयक श्री विनोद कुमार पटेल आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 आर0के0 वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता की ग्राम सभा गम्भीरा में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री विनोद कुमार पटेल व श्री इन्द्रजीत पटेल निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता की ग्राम सभा सराय भूपति की बाजार कटरा गुलाब सिंह में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री शैलेन्द्र अग्रहरि आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता की ग्राम सभा सराय भूपति की बाजार कटरा गुलाब सिंह में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री शैलेन्द्र अग्रहरि व श्री कमलेश अग्रहरि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

ख11.50, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सड़वा चन्दिका की ग्राम सभा कोड़रा मादूपुर में पाइप पेयजल प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री रामू वर्मा आदि निवासीगण जनपद

प्रतापगढ़ द्वारा
हस्ताक्षरित याचिका

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सड़वा चन्दिका की ग्राम सभा कोड़रा मादूपुर में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री रामू वर्मा व श्री विनोद कुमार एडवोकेट निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत जनहित में सुचारू आवागमन की व्यवस्था कराये जाने हेतु कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राकेश तिवारी आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत जनहित में सुचारु आवागमन की व्यवस्था कराये जाने हेतु कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राकेश तिवारी एवं श्री वीरेन्द्र शर्मा निवासीगण फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत रुदौली नगर में स्थापित पुरानी पी0एच0सी0 की जगह पर नवीन महिला चिकित्सालय बनाये जाने विषयक श्री दुर्गेश श्रीवास्तव आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत रुदौली नगर में स्थापित पुरानी पी0एच0सी0 की जगह पर नवीन महिला चिकित्सालय बनाये जाने विषयक श्री दुर्गेश श्रीवास्तव व श्री राजेश गुप्ता निवासीगण फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–7

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 फरवरी, 2016 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 13 फरवरी, 2016 से दिनांक 11 मार्च, 2016 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 15 फरवरी, 2016 को उत्तर प्रदेष कृषि उत्पादन मण्डी (संषोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं उसके पारण की मदें ली जायं।

2–दिनांक 15 व 16 फरवरी, 2016 को भी श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो।

3–दिनांक 17, 18, 19, 22 तथा 23 फरवरी, 2016 को वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा हो।

4–दिनांक 19 फरवरी, 2016 का असरकारी दिवस दिनांक 26 फरवरी, 2016 को लिया जाय।

5–तद्नुसार 13 फरवरी, 2016 से 11 मार्च, 2016 तक के उपवेषनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

फरवरी, 2016

13 शनिवार 14 रविवार	बैठक नहीं होगी।
15 सोमवार	1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं उसका पारण।
16 मंगलवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
17 बुधवार 18 गुरुवार 19 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा।
20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी।
22 सोमवार 23 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा।
24 बुधवार 25 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
26 शुक्रवार	असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन) (दिनांक 12 फरवरी एवं 19 फरवरी, 2016 के स्थान पर)।
27 शनिवार 28 रविवार	बैठक नहीं होगी।
29 सोमवार	

मार्च, 2016	
01 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
02 बुधवार	
03 गुरुवार	
04 शुक्रवार	असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन) (दिनांक 26 फरवरी, 2016 के स्थान पर)।
05 शनिवार 06 रविवार 07 सोमवार (महाशिवरात्रि अवकाश)	बैठक नहीं होगी।
08 मंगलवार 09 बुधवार 10 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
11 शुक्रवार	1–वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। **2–3.00 बजे अपराह्न** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख11ण45, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव‡

श्री अध्यक्ष–

‡ fnukad 09 Qjojh] 2016 dh dk;Zokgh ls A

मद संख्या–8 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–9 पांच–पांच मिनट बोलिएगा, अब चर्चा के लिए दो दिन बचे हैं।

'श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया, जिसका प्रस्ताव श्री गुलाम मौहम्मद जी ने रखा था और हमारे दल के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी नेता विरोधी दल ने जो उसमें संसोधन रखा उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं और अध्यक्ष जी यह कहना चाहता हूं कि इस राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र नहीं किया गया। किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, गरीब महिलाओं, पेंशन की बात, शादी अनुदान की बात इन सब चीजों को जिक्र अध्यक्ष जी, उसमें नहीं मिलता है। जहां तक किसानों की बात है, किसानों के डीजल पर अनुदान नहीं दिया जा रहा है, वहीं मिल मालिकों को डीजल पर अनुदान दिया जा रहा है। आज किसान को उनकी उपज की लागत नहीं मिल पा रही है। अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़ आदि भिन्न समस्याओं से किसान को रूबरू होना पड़ रहा है, लेकिन जो उनको सरकारी सहायता मिल रही है, जो उनको सरकारी सहायता देने की बात की गई है और दी गई है, उसमें बहुत ही ज्यादा पक्षपात किया गया है। अध्यक्ष जी, हम लोगों द्वारा बार–बार यहां नियमों में उठाये जाने के बाद भी, यहां की चर्चाओं में लाने के बाद भी जिले के अधिकारियों द्वारा वहां पर बहुत ज्यादा भेद किया गया है। उन्हीं गांवों में अतिवृष्टि का पैसा बंटा है, जो एक विशेष दल से सम्बद्ध थे, जो एक विशेष दल के कृपापात्र थे, उन्हीं लोगों को मिला। हम लोगों ने बताया, सर्वे कराया, अधिकारियों से कहा, यहां पर भी बताया, लेकिन उन लोगों को कोई अनुदान नहीं मिला। बाढ़ राहत में भी उनको कोई सुविधा नहीं मिली। हमारे यहां हजारों लोग कटान में बेघर हो गए उनको बसने के लिए जमीन भी नहीं मुहैया कराई गई और सूखा राहत की चेकें भी जिन लोगों को मिली हैं, बहुत कम–कम की चेकें मिलीं हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गन्ना किसानों की समस्याओं को ध्यान देना चाहिए। हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने जहां गन्ने के रेट वर्ष 2007 में जब उनको 125 रुपये मिले थे, उसको बढ़ाकर 250 रुपये तक पहुंचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार गन्ना किसानों को बकाये पर ब्याज दिलाने का काम किया। आज राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो बातें आई हैं, उसमें गन्ना किसानों के लिए कुछ नहीं है। आज उनको 230 रुपये में गन्ना का भुगतान मिल रहा है, पिछले साल का बकाया भुगतान भी उनको नहीं मिला है। इस साल 230 रुपये में 50 रुपये की चेक कब मिलेगी, इसका जिक्र कहीं कुछ नहीं किया गया है। पिछले वर्ष राज्य सरकार की तरफ से मिल मालिकों को 40 रुपये का अनुदान दिया गया, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी यह कहने में बड़ा दुख होता है कि अगर गरीबों को मिलने वाली दाल पर अगर 40 और 50 रुपये का अनुदान राज्य सरकार दे

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

देती तो यह कहा जाता कि गरीबों की थाली में दाल जो नहीं आ पा रही है, उसके बारे में चिन्तित है। इसलिए यह सरकार किसानों के लिए चिन्तित नहीं है, गरीब की थाली से दाल गायब है और वहां पर बैठी केन्द्र की सरकार वह भी कोई ऐसी योजना नहीं बना रही है। डेढ़–दो साल हो गए हैं, दाल के रेट 150–200 रुपये से कम नहीं हुये हैं, चाहते तो आस्ट्रेलिया और अमेरिका से दाल आ सकती थी, लेकिन आज गरीब बेचारा बेबस है, लाचार है अपनी बात को कहे तो किससे कहे। जैसे झूठ बोलकर, असत्य बोलकर, लोक–लुभावन बातें करके यह सरकार आई है, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, कर्ज माफ, नहरों की सिंचाई, किसानों को उनकी लागत पर 50 परसेन्ट का लाभ देने की बात कही, साड़ी देने की बात कही, कम्बल देने की बात कही, इस सरकार ने युवाओं का ज्यादातर वोट लिया किसानों का वोट लिया, लेकिन उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। वहीं केन्द्र में आने वाली सरकार ने उत्तर प्रदेश में 73 की 73 सीटें जीती हैं, लेकिन कोई काम नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि 15 लाख रुपये देंगे। हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपये जाएंगे। इन्होंने 15 लाख तो दूर 15 रुपये भेजने का काम नहीं किया है। गरीब हजारों–हजार खाते खुलवाने के लिए दौड़कर जा रहा है लेकिन दो सालों में मायूस होकर बैठा है और उसको एक रुपया नहीं मिला है तो इन दो सरकारों ने गरीबों का शोषण किया है। गरीबों की भलाई का कुछ ध्यान नहीं दिया है। काननू–व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अक्लीयत के भाई चैन व अमन से नहीं रह पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा से ज्यादा दंगे हो चुके हैं। काननू–व्यवस्था की स्थिति यह है कि सी0ओ0 और सब इन्सपेक्टर मारे जा रहे हैं, कहीं पुलिसवाले के बच्चों का अपहरण हो रहा है। हमारे लखीमपुर खीरी में तीन सगी बहनों का अपहरण हुआ, फिरौती देने के बाद वह छूटीं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेचैन है। आज याद कर रहे हैं लोग बहन कुमारी मायावती जी के उस शासन को, जिसमें किसी ने कानून तोड़ने की बात की तो चाहे वह मंत्री रहा, एम0पी0 रहा या एम0एल0ए0 रहा, चाहे वह कितना बड़ा अधिकारी रहा, गरीबों के हित के लिए उसको जेल की हवा खिलाने में दो मिनट नहीं लगे। उसके विरुद्ध कानून ने अपना काम किया तो उत्तर प्रदेश की जनता आज बहन कुमारी मायावती जी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है कि कब चुनाव आये, कब चुनाव की बेला हो और कितनी जल्दी से जल्दी वे चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी को 2017 मे विधान सभा में बैठायें। अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं का ध्यान मैं आपकी तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं गन्ना विभाग के द्वारा सड़कों के पुनर्निर्माण की व्यवस्था अब तक नही थी। हमारे यहां सरईंयां से लगाकर जेठरा सिंगावर होते हुए ग्राम कतौली तक गन्ने की सड़क 30 साल से बनी हुई जर्जर हालत में है। मै चाहता हूं कि उस गन्ने की सड़क का पुनर्निर्माण कराया जाये। हमारे यहां सुजईकुण्ड जाने वाले मार्ग पर पुल नहीं बना हुआ है, उस पर पुल बनाया जाये। हमारे यहां आई0टी0आई की स्थापना की जाये। हमारी विधान सभा में महिला डिग्री कालेज नहीं है, महिला डिग्री कालेज बनाया जाये। ईसानगर में, खमरिया में, कटौली में, कफारा मे विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की जाये। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये और

किसानों को उनके बकाया का भुगतान दिया जाये। अध्यक्ष जी, मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि इन सब चीजों का जिक्र राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में नहीं किया। हम अपने नेता प्रतिपक्ष जी के बात का समर्थन करते हुए उनसे अपने आपको जोड़ते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

'पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति सिंह वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के आम आवाम के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है आज तक जितनी भी हुकूमतें रही हैं किसी भी सरकार ने इतना संतुलित बजट कभी भी नहीं दिया। महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है और सरकार की नीतियों का जो बखान किया है, पहली दफा उत्तर प्रदेश के विधान भवन में किसी भी राज्यपाल द्वारा अपनी सरकार के बारे में जो टिप्पणी की गयी उससे साफ यह जाहिर होता है कि हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय राज्यपाल जी की सहमति से उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो भी नीतियां बनाने का काम किया जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य जी बोल रहे थे हमने किसानों को पहली दफा इस देश में, उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है जिसने अपने सरकारी खजाने से 40 रुपया प्रति कुंटल किसानों का नुकसान न होने पाये इसलिए मिल मालिकों को देकर गन्ने के दाम को गिरने नहीं दिया, उसको नुकसान से बचाने का काम किया। हमने शिक्षा जगत में ग्रामीण, गांव, खेत, खलिहान किसान के लोगों को भी तकनीकि शिक्षा हासिल हो, जो हमारे कान्वेन्ट स्कूल हैं, गांव देहात के जो स्कूल हैं इन दोनों के छात्रों में तकनीकि ज्ञान का फासला न हो इसके लिए लाखों की संख्या में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश मे लैपटाप देने का काम किया जिससे शहरी और ग्रामीण शिक्षा में कोई फर्क न होने पाये। उत्तर प्रदेश के लोग स्वस्थ्य रह सकें, सुखी रह सकें इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 108 और 102 एम्बुलेन्स चलाया और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को हम सभी ने सुना है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर देश में यह पहला राज्य है जिसमें दुग्ध विकास के क्षेत्र में सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है और आई0आई0एम0 की स्टडी के आधार पर पूरे प्रदेश के अन्दर सभी मुख्यालय पर आधुनिक डेरी प्लांटों की स्थापना करके जो गांव में खेत खलिहान के लोग हैं जो एक लीटर, दो लीटर दूध बेचकर अपने बच्चों का भरण–पोषण करने का काम करते हैं। उनके साथ कोई लूट खसोट न हो, बेइमानी न हो सके इस दिशा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहल करते हुए एक बड़ी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है जिससे उत्तर प्रदेश देश के अन्दर सर्वांगीण, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश है। हम यह चाहते हैं कि हिन्दोस्तान के अन्दर उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच पर आधारित जो हमारे मंडल मुख्यालय पर आधुनिक प्लांट लग रहे हैं इससे पूरे देश के अन्दर हमारे किसानों को लाभ मिलेगा, इससे बीमारों को शुद्ध दूध

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

मिलेगा, बच्चों को शुद्ध दूध मिलेगा जिससे उत्तर प्रदेश के लोग स्वस्थ्य रह सकेंगे। नौकरी देने के नाम पर उत्तर प्रदेश के अन्दर, आप पिछली सरकारों में देखते रहे तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं लेकिन हमारी सरकार के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी की पालिसी के अनुरूप कोई भी व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर यह नहीं कह सकता है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की भर्ती में उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई हो। अभी हम लोगों ने सिपाहियों की भर्ती किया फिर आगे सिपाहियों की भर्ती हो रही है। जो बेरोजगार है, दौड़ ले गया, स्वस्थ्य रहा वह सिपाही हो जायेगा। अभी आप देख रहे हैं कि लेखपालों की भर्ती हो रही है पूरी पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश के अन्दर रहने वाले सभी वर्गो के लिए किसानों को मुफ्त सिंचाई का प्रबन्ध। पूरे देश में किसी सरकार ने ऐसा करने का काम नहीं किया है न ही गन्ने पर सरकारी खजाने से कोई भी राज्य सरकार पूरे हिन्दोस्तान के अन्दर पैसा देकर के किसानों को नुकसान न हो इसकी भरपाई करने का काम किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं और उनके अभिभाषण से जो नई नीतियां बनी हैं इससे उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा और माननीय मुख्य मंत्री जी का जो स्वप्न है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में विकसित करने का वह निश्चित रूप से सफल होगा।

'श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो कटौती का प्रस्ताव माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखा उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ा जाता है सरकार की नीतियों को बिना मन से पढ़ा हुआ एक बात और मन से की हुई दूसरी बात इन दोनों में अन्तर होता है। मन से जितनी भी बाते कही हैं उसका हमेशा विरोध माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया है पूर्व में पढ़े गये विरोध का अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो हम उसके विरोध में यहां खड़े हुए हैं। मान्यवर, इस बात की शुरूआत अगर करें तो पहले पेज के ऊपर यह लिखा गया है कि सभी वायदे पूरे किये और इसके बारे में हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। मान्यवर, कथनी और करनी में फर्क है कि नहीं है यह समाजवादी पार्टी अपने मैनिफिस्टों को सामने रखकर अगर इसके ऊपर भाषण देती तब माना जाता। शायद उसमें कहा गया था कि प्रदेश में प्रत्येक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा है कि नहीं है यह प्रश्न मान्यवर, इनके सामने खड़ा हुआ है, लैपटाप दिया जायेगा, टेबलेट दिया जायेगा है कि नहीं है, एक बात मान्यवर, जरूर है जो समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका हम सब बहुत सम्मान करते हैं आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो बात कहीं है एक बार नहीं कई बार कही है और साल डेढ़ साल से कह रहे हैं कि उनको पता है कि सरकार में बैठे हुए मंत्री कौन–कौन से मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको पता है कि कौन कौन से खनन का काम कर रहे हैं, उनको पता है कि अबकी बार यह जीतकर आने वाले नहीं है। यह मेरा भाषण नहीं है

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

यह आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी का कथन है। माननीय अध्यक्ष जी, कहा जाता है न कि छेड़ा कहीं जाता है और दर्द कहीं और होता है। जो बात माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कही है, जो अखबारों में छपी है और जिसमें किसी भी प्रकार का खण्डन माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार के द्वारा नहीं आया है, मैं उस बात को कह रहा हूं। क्या आपने अपने घोषणा पत्र में यही कहा था कि प्रदेश के अन्तर्गत चारों ओर जिस समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पंचायतों के चुनाव होंगे उस समय जनता के द्वारा चुने हुये लोगों को बन्धक बनाकर उनसे जबर्दस्ती वोट लिये जायेंगे। क्या यह कहा गया था कि चारों ओर अपराध को संरक्षण दिया जायेगा, शह दी जायेगी। मान्यवर, यह अखबार में छपा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेते हुये यह कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थानों में दलाली बन्द कर दें। इसका मतलब वह थानों में दलाली कर रहे थे, तभी तो कहा गया कि वह बंद कर दें और उनके यह कहने के बाद उन पर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, यह हम रोज अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं। मेरे पास बहुत सारी कटिंग्स हैं, अब आप कहेंगे कि समाचार पत्रों की कटिंग्स हम यहां पर लगा नहीं सकते हैं, लेकिन यह सच है कि प्रदेश में जिस प्रकार से अत्याचार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से गुण्डाराज बढ़ रहा है। अपनी पीठ स्वयं थपथपा लेने की बात कोई समझ में नहीं आती है। अभी जिस समय बजट के ऊपर चर्चा होगी, जैसे अभी यह कहा गया कि उस समय यह क्या कर रहे थे, तो यह और वह दोनों बराबर कर रहे थे। उसके ऊपर बहुत सारे सदस्य यह कहेंगे कि हमारे यहां यह समस्या है, हमारे यहां यह समस्या है। एक राजा ने अपने मंत्री को कुछ अशर्फियां दी और पूछा कि राज्य में प्रजा कैसे है, तो मंत्री ने कहा बड़ी खुशहाल है और जब वह अशर्फियां खत्म हो गई और दो–तीन महीने बाद राजा ने फिर पूछा कि अब राज्य में प्रजा कैसी है, तो उसने कहा प्रजा बड़ी दुखी है। मान्यवर, हमारे जो सरकार में बैठे हुये वरिष्ठ माननीय नेतागण हैं, उनके क्षेत्र में हो सकता है कि कुछ विकास काम हो भी रहा हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को रामपुर से फुर्सत नहीं है और वहां पर सारे काम सही तरीके से हो रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि पूरा प्रदेश सही तरीके से चल रहा है। उन पांच लोकसभा क्षेत्रों में जहां से समाजवादी पार्टी के कुछ नेतागण जीत सके, वहां पर भी लोगों को लगता है कि बहुत कुछ अच्छा है। मान्यवर, शास्वत सत्य है और यह हमारे ग्रन्थों में कहा गया है कि **"सचिव बैद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस। राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास।।** तो मान्यवर, बड़ी तेजी से विनाश हो रहा है। यह सच है कुछ अधिकारियों के कहने पर कि सब कुछ बढ़िया है, तो फिर विनाश ही होना है। अगर लखनऊ को ही ठीक करने से, पूरे उत्तर प्रदेश को आप ठीक मान लेते हैं, तो

(इस समय 12 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री जियाउद्दीन रिजवी पीठासीन हुए)

हमारे इधर बैठे हुये पड़ोसियों ने भी लखनऊ में बहुत कुछ बनाया था, लेकिन लखनऊ की एक भी सीट इनको नहीं मिली। मान्यवर, पूरे प्रदेश को छोड़िये, इन्हें पूरे प्रदेश से तो जाना ही पड़ा, लखनऊ की एक भी सीट पर यह कब्जा नहीं कर सके। पूरा प्रदेश लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से लेकर चारबाग स्टेशन तक नहीं है। पांच–छह किलोमीटर का पूरा प्रदेश नहीं है। माननीय मंत्री आजम खां जी जिस बात को कहते हैं

बड़ी संजीदगी से कहते हैं और मैं उस बात को बहुत प्रशंसात्मक रूप से लेता हूं। मैं इस बात को कहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप सबसे महत्वपूर्ण मंत्री है, वैसे तो सभी लोग महत्वपूर्ण हैं मैं किसी के महत्व को अधिक बताकर एक–दूसरे से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह पांचवा बजट है और मेरा आपसे सुझाव भी है, सलाह भी है कि एक बार तो नगर विकास विभाग का बजट रखकर यहां पर माननीय सदस्यों से चर्चा करा लीजिये। आप आखिरी दिन इसके लिए रखते हैं और आपको पता होता है कि आखिरी दिन नहीं आ रहा है और हमको भी मालूम होता है कि इसके उपर कभी चर्चा नहीं होनी है। तो चार बजट में एक बार भी नगर विकास विभाग के बजट के ऊपर आपने चर्चा नहीं कराई है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

कानपुर को नगर विकास विभाग के बजट में बहुत मिलता है, इसके ऊपर कटौती करनी पड़ेगी।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जिस समय मैं कटौती का प्रस्ताव रखूंगा तो उस समय आप वह भी कर दीजियेगा। अगर आप मेरे को यह अवसर देंगे, तो आप वह भी कर लीजियेगा, लेकिन आप उसको रखिये। थोड़ी सी उस पर चर्चा हो। मान्यवर, जब आप बजट रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप कानपुर को अलग से देंगे यह मुझे मालूम है। इसीलिये तो मैं ऐसा कह रहा हूं। मेरा कहने का भाव यही है, आप हर चीज को नेगेटिव में ले जाते हैं। देखिये जिस समय जिस चीज की बात हो, उस समय उस बात की चर्चा की जाये तो यह रेलेवेण्ट चर्चा होगी। यह सामयिक चर्चा है। असामयिक चर्चा दो परिस्थितियों में होती है। एक परिस्थिति वह कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हो, तो उसकी हर समय आप चर्चा करने का प्रयास करते हो और एक समय वह, जिसका डर हो दिमाग में, उसकी चर्चा भी असामायिक होती है। तो सरकार केवल केन्द्र सरकार में आदरणीय मोदी जी की चर्चा विषय हो या न हो, हर समय हर विषय में उनको लाकर खड़ा कर देना चाहती है। तो मोहब्बत तो इनको होगी नहीं, डर इनको जरूर है जो इनको सताता रहता है, इसीलिये यह मोदी जी की चर्चा करते रहते हैं। मान्यवर, चर्चा सामयिक होनी चाहिये। हम पूछते हैं कि प्रदेश में नदियों का क्या हो रहा है तो आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी, हम कहते हैं कि पेंशन के लिये आप क्या कर रहे हो तो आप कहते हो प्रधानमंत्री जी, हम एन0एच0आर0एम0 के बारे में पूछते हैं तो आप कहते हो प्रधानमंत्री जी। आपके बजट में आपने जिस–जिस मद में अपनी तारीफ की है, उसमें आपने यह लिखा है चाहे एम्बुलेन्स की तारीफ करो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ करो तो आप भारत सरकार द्वारा एन0एच0आर0एम0 में दिये गये पैसे की ही आप तारीफ करते हो। जिसमें गर्वन्मेंट आफ इंडिया पैसे नहीं देती, उसमें आप कहते हो कि हम फेल हैं। आज आपके पास कहने को केवल इतना ही है, जिसमें भारत सरकार आपको सहयोग कर रही है, बाकी आपके पास क्या है। मान्यवर, जिस समय बजट के ऊपर बात आयेगी तो फिर मैं मदवाइज भी बताऊंगा कि किस–किस मद में कितना पैसा दिया गया है। मान्यवर, ऐसी परिस्थितियों में जिस समय आप कहते हैं कि सरकार बहुत विकास के काम कर रही है,

इस विधान सभा में सारे माननीय सदस्य पिछले चार साल से गला फाड़–फाड़कर बोल रहे हैं कि पीने का पानी नहीं है। सबसे बड़ी आवश्यकता पीने के पानी की है और सबसे न्यूनतम राशि आपने जिसमें उपलब्ध कराई है वह है हैण्डपम्प। हैण्डपम्प आपने दिये नहीं और आप कह रहे हो कि बहुत विकास के काम करा रहे हैं और पीने का पानी दे नहीं पा रहे हो। मान्यवर, यह आपका विकास है, अगर आप इंडस्ट्रियल विकास की बात करते हो तो पिछले चार साल में चार इंडस्ट्रियल समिट किये हैं आपने। आज से तीन साल पहले आगरा में किया था, दो साल पहले दिल्ली में किया था, अभी आपने तीसरा या चौथा फिर किया। आप समीक्षा तो करिये कि आप क्या लाये हैं। जिस समय आप उन आडम्बरों से हटकर, उन अधिकारियों द्वारा कहे गये मधुर वचनों के बिना अपनी समीक्षा करना प्रारम्भ कर देंगे तो सही बात पता लगेगी। मान्यवर, वह मधुर वचन कान में सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अंततोगत्वा हश्र वही होता है जो इनका हुआ, मेरा मंत्री जी आपसे सुझाव है कि वास्तविकता को आप जानिये। जमीनी हकीकत को पहचानिये। लोहिया ग्राम आपने लिख दिया, बहुत अच्छे हैं। लोहिया ग्राम से संबंधित किसी क्षेत्र में चार गांव माननीय विधायकों के द्वारा देखें, उसमें भी आपने कटौती कर दी। यहां पर विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा कहा जाता है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि यह करेंगे, वह भी नहीं करते। आप जो कहते हो वह तो करो। आप जो कहते हैं, वह नहीं करते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसमें मैं इन बॉतों को जरूर कहूंगा कि आपने युवाओं के लिये जितने भी सपने दिखाये थे, आज की तारीख में आप एक के ऊपर भी नहीं टिके हुये हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर–व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां पर यह बात कहनी चाहिये, वहां पर इनके पास कोई बोलने वाला नहीं है। इसीलिये मैनें कहा कि जहां जो मर्जी आये वह कह दो। जो मैं कह रहा हूं वही यह कर रहे हैं। वहां प्रंशसा करते हैं कि बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत अच्छा है। यहां पर जो चीज बैठकर बोलनी चाहिये, आज यह उस स्थिति में नहीं हैं। हम चर्चा यहां करेंगे तो यह बतायेंगे कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। मेरा मान्यवर, कहना यही है कि आप अपनी चर्चा करिये कि आप क्या कर रहे हैं। आपको अवसर मिलेगा तो उसके ऊपर भी बोलियेगा। यहीं पर अभी आपको कुछ न कुछ बोलने का अवसर मिलेगा, यहीं बोल लीजिएगा। मान्यवर, आज बिजली पर बहुत बड़ी–बड़ी बातें की जा रही हैं, आज से लगभग दो साल पहले जब केन्द्र में यू0पी0ए0 की सरकार थी उस समय उत्तर प्रदेश नें थोड़ी सी बिजली ज्यादा ले ली थी तो पूरा नार्दन ग्रिड फेल हो गया था और पूरा नार्थ इंडिया दो दिन अंधेरे में रहा था। आज मान्यवर, भारत सरकार की नीतियों के कारण बिजली उपलब्ध है लेकिन फिर भी आप नहीं दे पा रहे हैं। आज की तारीख में ग्रामीणों को चार घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इन पांच सदस्यों और रामपुर के मा0 मंत्री जी को छोड़कर अन्य मा0 सदस्य जो कहें उनके क्षेत्र की जनता को जरूर बतायें कि यहां पर हकीकत यह है और वहां बोल कुछ और रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, आपकी मुस्कराहट बता रही है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह 100

प्रतिशत सही है, कोई इसका प्रतीकात्मक विरोध नहीं है। मा0 अधिष्ठाता जी, आज इस अवसर पर जब श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद देने की बात हो रही है तो मान्यवर, धन्यवाद दिया जा सकता था अगर यह जमीनी हकीकत देखते तो। मान्यवर, यहां से अधिकारी जाते हैं जो मैंने कहा कि अधिकारियों की निगाह से देखते हैं यहां से एक अधिकारी गये किसी का नाम नहीं लूंगा, अखबारों में छपा कि मुख्य मंत्री जी के दूत आ रहे हैं जानकारी करके हकीकत बताने के लिए। मैंने भी अखबार में पढ़ा मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज दूत आ रहे हैं, दूत का बड़ा महत्व है भारतीय संस्कृति में, मैंने उनका फोन नम्बर ढूंढ करके उनको फोन किया कि आज आप आये हैं चलिये मैं आपको क्षेत्र में दिखाता हूं तो उन्होंने कहा कि नहीं वह तो अधिकारियों ने तय कर दिया है। मान्यवर, आप क्या उम्मीद करते हैं जो वहां जिले का अधिकारी होगा वह क्या उस जगह आपको ले जायेगा जहां पर पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, जहां पर लोहिया ग्रामों में भ्रष्टाचार हुआ है क्या वह वहां पर आपको ले जायेगा। वह आपको जहां ले जायेगा आप वहां जाने के लिए तैयार हैं और जो वह देख करके आता है और आपको बताता है उसे आप अभिभाषण में लिख देते हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि आप जमीनी हकीकत को पहचानो। जमीनी हकीकत को पहचान कर जिस समय आप अपनी नीतियां बनायेंगे, आप सच को सच और झूठ को झूठ मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए तो आप व्यवस्था के अन्दर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पायेंगे। परिवर्तन आप तब कर पायेंगे जब आप जमीनी हकीकत को पहचानेंगे। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होता है क्योंकि हम भी सरकार में रहे हैं और फिर आगे आने वाले हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि आप उस जमीनी लेबल के ऊपर किसी अच्छे काम करने वाले की प्रशंसा करेंगे तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा लेकिन अगर आप उनके भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास करेंगे तो उसके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जिम्मेवारी कोई मिनिस्टर नहीं ले सकता, सरकार को उसे अपने ऊपर ओढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। लाखों कर्मचारियों के अन्तर्गत अगर श्रीमान अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री बन जायें या कोई भी मुख्य मंत्री बन जाये तो सारे के सारे कह देंगे कि अब वह बन गया है अब हम सारे ईमानदार हो गये हैं, इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं तो इस बात से पीड़ित हूं कि विधान सभा में यदि किसी भ्रष्टाचार का प्रश्न लगाया जाता है तो उस पर उसकी मुहर लग जाती है यहां पर कह दिया जाता है कि उसने भ्रष्टाचार किया है लेकिन अगर भ्रष्टाचार करने के बाद भी यह मुहर लग रही है कि उसने नहीं किया है तो आप क्यों उसको छिपाना चाहते हो, क्यों आप उसको दण्डित नहीं करना चाहते हो। आप उसको दण्डित कीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, यदि कोई किसी भी विभाग का मंत्री हो तो वह क्या अपने सारे कर्मचारियों की जिम्मेदारी ले लेगा क्या ? मान्यवर, नहीं ले पायेगा, इसलिए नहीं ले पायेगा क्योंकि वह वहां तक पहुंच नहीं पायेगा लेकिन हां अगर आप उसके भ्रष्टाचार को संरक्षण दे देंगे तो बहुत बुरा होगा। मान्यवर, आतंकवाद पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद पर कोई

समर्थन नहीं है लेकिन अगर जे0एन0यू0 में भारत विरोधी नारे लगाये जाते हैं और उनके समर्थन में जो भी खड़ा होता है वह देशद्रोही है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए चाहे वह कोई भी हो। वहां पर आप उसके समर्थन में चले जाते हैं जिसको टेलीविजन में दिखाया जा रहा है कि इसने यह भाषण दिया, यह व्यक्ति यह बोल रहा है, जो टेलीविजन की डिबेट में आकर उसको संरक्षण देने का काम करते हैं, अगर आप उनके समर्थन में खड़े होते हैं तो क्या यह नहीं माना जायेगा कि आप आतंकवादियों के संरक्षण में खड़े हैं। मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखकर सरकार को हर बात की चिन्ता करनी चाहिए। आपका दिया हुआ एक–एक बयान आतंकवादियों, उन अराजक तत्वों को, उन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है। मान्यवर, कहा उधर जा रहा है मिर्ची इधर लग रही है।

(ब0स0पा0 के कुछ सदस्यों द्वारा श्री अधिष्ठाता को महाना जी का समय समाप्त होने का इशारा करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करिये।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, ये माननीय सदस्य आपको निर्देश देंगे, मा0 अधिष्ठाता को निर्देश देने का काम करेंगे, यह तो पीठ की अवमानना है। यह आपको बतायेंगें कि इतना समय दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

महाना जी, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सतीश महाना–

ठीक है, मान्यवर, उन सुझावों के साथ कि हकीकत को पहचानने का प्रयास करो तब कुछ परिवर्तन ला पाओगे। इसी के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बल देता हूं।

'श्री संजय कपूर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने नेता प्रतिपक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मौजूदा सरकार द्वारा जो बखान राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है मैं समझता हूं कि वह सच्चाई से बहुत परे है। आज किसान बहुत परेशान है, किसान को बहुत अपेक्षायें थीं, उम्मीदें थी कि यह सरकार बनेगी तो उसके गन्ने के मूल्य का भुगतान ठीक से होगा, उसे इसका लाभ पहुंचेगा, विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा, किसानों को लाभ पहुंचेगा लेकिन आज हालात यह है कि किसान बद से बदतर हालत में है। न उसे गन्ना मूल्य का भुगतान सही समय पर मिल रहा है, न सही रेट मिल रहा है जिसकी वह अपेक्षा करता था, न ही देहात के क्षेत्रों में 4, 6 या 8 घण्टे से ज्यादा विद्युत की आपूर्ति हो पा रही है। यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़े परेशानी की बात है कि

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

उत्तर प्रदेश एक किसान प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जब सरकार बनी थी तो किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, नौजवानों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को बहुत अपेक्षायें थी। मैं समझता हूं कि उस पर यह सरकार पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है जिससे नौजवान भी बहुत परेशान है, अपने आपको असहज महसूस कर रहा है। आज हालात यह है कि चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो, चाहे वो महाविद्यालय हो कहा तो यह जाता है कि हमने बहुत सारे बेसिक स्कूल खोल दिये, बहुत सारे राजकीय महाविद्यालय खोल दिये मगर हालात यह है कि वहां पढ़ाने के लिए टीचर नहीं हैं और बच्चे शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं उनके सामने बहुत बड़ा भविष्य का संकट खड़ा हुआ है। कानून–व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, कानून–व्यवस्था के मामले में कोई पुरसाहाल नहीं है, पुलिस निरंकुश हो गयी है और जितना गुण्डा एलीमेंट है वो सड़कों पर ऐसे घूम रहा है जैसे उसने सरकार को खरीद रखा हो, सरकार उसके मातहत हो। जिस तरीके से हालत है मैं समझता हूं कि आने वाले भविष्य के लिए कोई अच्छे दिन नहीं हैं। सरकारें तो आती–जाती रहती हैं, मगर जिस सरकार को जनता ने चुनकर भेजा है उससे बहुत अपेक्षायें होती हैं और हमें भी बहुत अपेक्षायें माननीय मुख्य मंत्री जी से थी, वह नौजवान थे उनसे यह अपेक्षा थी कि जब वह आयेंगें तो यकीनन नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को लाभ पहुंचेगा। बहुत से वायदे यहां पर मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा किये गये थे। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि विधायकों को जनेश्वर मिश्र और लोहिया गांव में हिस्सा दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि हम इधर बैठे हैं, हो सकता है कि उधर के कुछ लोगों से इस पर राय ली गयी हो। बहरहाल हम लोग तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि न जनेश्वर मिश्र में कहीं पर हमसे पूछा जा रहा है न लोहिया गांव में पूछा जा रहा है। आज इसकी बहुत आवश्यकता है। सब लोग मिलकर काम करेंगें तभी इस प्रदेश का विकास हो सकेगा और जो मुख्य मंत्री जी की सोच है वह भी कामयाब हो पायेगी, जब सबका सहयोग साथ में शामिल होगा। आज हालत यह है कि सड़कों का बुरा हाल है, सड़कों पर पैसा पहले से बेहतर देने का प्रयास किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जबसे सरकार आयी है सड़कों पर पैसा भी दिया गया है और काम करने का प्रयास भी किया गया है। मगर मेरे यहां सरकार के पैसा देने के बावजूद भी, सरकार द्वारा इसमें धनावंटित किये जाने के बावजूद भी आज अधिकारियों का हाल यह है कि एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है मेरे क्षेत्र की एक सड़क है बिलासपुर एहरेसीजगढ़ मार्ग एक वर्ष पैसा आवंटित किये हुए हो गया है मगर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उसमें आजतक टेण्डर नहीं हो पा रहा है। हालात यह है कि एक बिलासपुर–स्वार रोड है उस पर काम 4 साल से चल रहा है पूरा नहीं हो पा रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि यहां जो धनावंटित भी हो रहा है सरकार का जो खजाना खर्च किया जा रहा है उसका भी सही तरीके से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। नीचे लेबिल पर जो अधिकारी हैं वह अपने बड़े अधिकारियों की बात, मंत्रियों की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कोई मानने को तैयार नहीं है। आज हालात यह है कि

जिस तरीके से इन कामों को रोका जा रहा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर यह चाहते हैं कि वाकई में प्रदेश का विकास हो, प्रदेश का चौमुखी विकास हो जो सोच माननीय मुख्य मंत्री जी की है जो सोच माननीय शिवपाल जी की है उस पर वाकई में अगर काम करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे की धरातल की जो हकीकत है उन लोगों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अगर अंकुश नहीं लगायेंगे तो यकीयन इस प्रदेश का हाल भी और प्रदेशों से ज्यादा बदत्तर हो जायेगा जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। आज हालत यह है कि मेरे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन पर मैंने पिछली बार महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव के जरिये अपनी बातों को रखा था और आज भी रखा है लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन पर जो उम्मीद थी उस तरह की कार्यवाही आज तक नहीं हो पाई। मेरे यहां एक दिबदिबा गांव है जो उत्तराखंड के बार्डर पर पड़ता है। चूंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र है वह उत्तराखंड के बार्डर पर है। दिबदिबा में जमीन भी सस्ती है और वहां बहुत सारी कालोनियां बन रही हैं। ग्राम सभा है वहां पर टाउन एरिया की मांग चली आ रही है। वहां पर इतना पैसा नहीं है, इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि लोगों को बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था हो सके तो मैंने इसकी मांग करी है कि वहां पर टाउन एरिया बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जनता को उसका लाभ पहुंच सके। मगर इस पर आज भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पिछले लगभग 4 साढ़े 4 वर्षों से बिलासपुर तहसील में मुन्सिफ कोर्ट की मांग करता चला आ रहा हूं लेकिन उसमें आज तक अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके अलावा माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिलासपुर में रोडवेज बस अड्डे के लिये पिछली बार जब मैं विधायक था तब से मैं प्रयास करता चला आ रहा हूं। जगह भी चिन्हित कर ली गई लेकिन हालात यह है कि मुझे 9 साल विधायक बने हुए हो गये, आज तक वह रोडवेज का बस अड्डा नहीं बन पाया। बराबर प्रयास कर रहा हूं। वहां पर नेशनल हाई वे पर बिलासपुर है आज तक उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। सरकार ने जगह चिन्हित कर ली उसके बाद आज तक पैसा देकर रोडवेज का बस अड्डा नहीं बन पाया तो जनता यह जानना चाहती है कि खाली झूठे वायदों से, इतना बड़ा पुलिन्दा बनाने से प्रदेश का विकास नहीं होगा। प्रदेश का विकास तब होगा जब सोच हमारी यह हो कि जो जन प्रतिनिधि चुनकर आया है चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर जनता के हित की बात करता हो तो उसकी बात पर अमल किया जाना चाहिए। यह सोचकर उसे अलग नहीं कर दिया जाना चाहिए कि वह सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है। सत्ता तो आती जाती चीज है, यह तो आज किसी के पास है कल किसी और के पास होगी लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनहित के जो काम हैं चाहे वह सड़कों के काम हों। विकास तो तब ही हो पायेगा प्रदेश का जब सड़कें होंगीं, बिजली होगी, चिकित्सा होगी, शिक्षा होगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक केन्द्रीय टाउन एरिया है जिसकी लगभग 50 हजार से ज्यादा आबादी है और उसमें 90 प्रतिशत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के लोग रहते हैं और कहा जाता है कि यह सरकार अल्पसंख्यकों की बहुत हितैषी है। बीस किलोमीटर दूर तक कोई

मेडिकल फैसिलिटी वहां पर नहीं है। वहां पर एकमात्र पी0एच0सी0 है जहां मात्र एक डाक्टर रहता है। और वहां 700–800 पेशेन्ट रोज आते हैं। मैं पिछले 4/5 साल से वहां पर 30 बेड के अस्पताल के लिये प्रयास कर रहा हूं। बराबर हर नियम में इसको लगाता हूं। रोज माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि वहां पर बहुत आवश्यक है। वायदा भी कर लिया गया लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर वहां की हफ्ते की ऐवरेज डेथ की चेक कराई जाय तो वह दो तीन लोग खाली मेडिकल एड न मिलने की वजह से मृत्यु होती है। आज हालात यह हैं, अगर इन हालातों से हमें बचना है, इन हालातों में हमें सुधार करना है, प्रदेश को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा। जो जनहित के काम हैं उनको मैं समझता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा और यह सोचना पड़ेगा जिससे जनता को लाभ पहुंच सके। अगर यह 30 बेड का अस्पताल बन जाय। केन्द्रीय में उप मंडी की बात चल रही है, अगर केन्द्रीय में उपमंडी बन जायेगी या वहां पर महिला डिग्री कालेज की बात चल रही है अगर वह बन जायेगा तो यकीनन उस क्षेत्र की जनता को फायदा पहुंचेगा। अल्टीमेटली फायदा उसे पहुंचेगा जिसकी सरकार होगी। यह कह सकते हैं। वहां हमारा पत्थर तो लगता नहीं है। मैं इत्तेफाक से उत्तराखंड में कार्यकर्ता हूं, छोटा सा पार्टी का सिपाही हूं प्रभारी के नाते। वहां अगर विधायक या कोई माननीय मंत्री जाता है या माननीय मुख्य मंत्री जाते हैं तो वहां पर सत्ता का हो या विपक्ष का, वहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक हमारे साथ बैठता है। यहां हालात यह है कि अगर पत्थर पर हमारे नाम लिख जायं, पहले तो नाम लिखा ही नहीं जायेगा। अगर जुगाड़ से किसी विधायक ने लिखवा भी लिया तो शाम को तोड़ देंगें उस पत्थर को कि इस विपक्ष वाले का नाम कैसे आ गया। तो सत्ता विपक्ष तो आती जाती रहती है मगर जनता के हितों के कामों को नहीं रोकना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री संजय कपूर–

अगर हमें प्रदेश का विकास करना है, प्रदेश को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, आगे बढ़ना है तो इन सब बातों को देखना होगा। मान्यवर, एक दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा क्षेत्र कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। जहां पर अग्निशमन केन्द्र की बात चल रही है। पिछले 5 साल से प्रयास कर रहा हूं। वहां पर अग्निशमन केन्द्र नहीं होने की वजह से गेहूं की जो फसल होती है गर्मी के दिनों में कहीं आग लग जाती है खेत में तो 35–40 किलोमीटर दूर शहर है वहां से जब तक फायर बिग्रेड की गाड़ी आती है तब तक ध्वस्त हो चुकता है। हर साल 2–4 करोड़ का गेहूं जलता है। मेरा प्रयास बराबर है लेकिन मेरे सत्ता का विधायक न होने के नाते यह काम नहीं हो पा रहा है। यह किसी पार्टी विशेष का नहीं है, किसान किसी पार्टी का नहीं है, किसान तो किसान है, चाहे स0पा0 की सरकार हो, भा0ज0पा0 की सरकार हो, चाहे ब0स0पा0 की

सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसान चाहता है कि उसकी मदद हो, तो मैं चाहता हूं कि उस पर काम होना चाहिए। जहां कानून–व्यवस्था का सवाल है रठौंडा, एक जगह है मिलख में, उसमें लगभग बीस किलोमीटर दूर पर एक थाना बनाये जाने की मांग चल रही है लेकिन उसमें भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो बातें हैं, सरकार किसी की हो यह सबके हित की बातें हैं, इन बातों पर मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि अमल हो तभी एक अच्छा सुशासन होगा, और तभी अखिलेश यादव जी की और मा0 सदस्यों की मंशा पूरी भी तभी हो पाएगी जब हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

'श्रीमती रुबी प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद सबसे पहले हमारी सरकार ने जहां किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं की बढ़ोत्तरी और विकास के लिए उदारतापूर्ण काम किया, वहीं साथ ही साथ 2012 में मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो अपने घोषणा–पत्र में जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करने का काम किया। हमारी सरकार किसानों की सरकार है। मजदूरों की सरकार है। उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए कुक्कुट मिनी कामधेनू ,कामधेनू योजना देने का काम किया, साथ ही साथ जब हमारे किसान प्राकृतिक आपदा से हमारे प्रदेश के किसान, कई जिलों में सूखे और कई जिलों में ओलावृष्टि के कारण आंसू बहा रहे थे, तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने सभी को चेक देकर उनके आंसू पोंछने का काम किया। निश्चित तौर पर युवाओं का विकास उनको रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास योजना संचालित कर लाखों युवाओं को ट्रेनिंग कराकर विभिन्न क्षेत्रों में युवक और युवतियों को रोजगार देने का काम किया। छोटे–छोटे उद्योगों में निश्चित तौर से हमारी महिलाओं के लिए उनके सर्वांगीण विकास और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, 1090 और 102 एम्बुलेंस को, जहां नजदीक के अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को गर्भ धारण से लेकर जब तक उनको बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तब तक उन्हें ले जाने और ले आने का काम 102 एम्बुलेंस करती है। साथ ही साथ हमारी लाखों बहनें जो उत्पीड़ित आए दिन होती रहती हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए 1090 भारत का पहला प्रदेश है जहां यह लागू किया गया। साथ ही साथ उन महिलाओं को जिनको समाज में तेजाब से पीड़ित और उत्पीड़ित होने के कारण अपमान सहना पड़ता था उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना की, और उन महिला पीड़ितों को सम्मान देने का काम किया साथ ही साथ अगर हम सड़क की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमारा जनपद सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का सबसे अन्तिम जनपद है और हमारा अन्तिम विधान सभा है वाराणसी शक्ति नगर राजमार्ग, अभी हमारे यहां से विधान सभा की समिति गई थी, जब वह सड़क पर चल रहे

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

थे तो देखकर आश्चर्य चकित हुए कि वह विदेशों की सड़क पर चल रहे हैं या उत्तर प्रदेश की सड़क पर चल रहे हैं इतनी अच्छी सड़क उन्होंने, जीरो डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा जाता है नक्सल प्रभावी क्षेत्र जिसको कहा जाता है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने देने का काम किया। वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग जो बनकर पूरा तैयार है। साथ ही साथ हमारे ही जनपद में जो सिंचाई परियोजना 38 वर्षों से लम्बित पड़ी हुई थी करहर सिंचाई परियोजना और बहुत सारे पार्टियों के मुख्य मंत्रियों के शिलापट्ट वहां पर 1968 से लगे पड़े थे पर किसी ने बनवाने का काम नहीं किया, मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 सिंचाई मंत्री जी को हम इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जहां किसान भगवान भरोसे खेती करते थे उन्होंने 22 अरब देकर योजना शुरुवात करवाने का काम किया जिससे 108 गांव और दो ब्लॉकों के किसान सिंचित होंगे। साथ ही साथ हमारे पड़ोस के प्रदेश झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के भी दो–चार गांव लाभान्वित हुए हैं। निश्चित तौर पर चाहे वह सिंचाई का क्षेत्र हो चाहे वह सुरक्षा का हो या हम कहें मजदूरों का। मजदूर उत्तर प्रदेश कर्मकार बोर्ड के माध्यम से लाखों मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ हम अपने जनपद की बात कह रहे हैं हमने अपनी दुद्धी विधान सभा में लगभग 20 हजार मजदूरों को साइकिल एवं सौर ऊर्जा देने का काम किया माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से उन समाज के अन्तिम व्यक्ति के आंसू पोछने का काम किया गया। क्योंकि उनका मानना है कि समाज का सबसे अन्तिम व्यक्ति जब तक खुशहाल नहीं होगा हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता। माननीय अधिष्ठाता महोदय चूंकि हम लोगों के लिए साइकिल बहुत बड़ी चीज नहीं होती लेकिन मजदूरों के लिए साइकिल चार पहिया वाहन के बराबर काम करता है। वह नजदीक में चाहे वह स्कूल कालेज हो, चाहे वह हास्पिटल हो हमने अपने क्षेत्र में अपनी आंखों से देखा कि हमारी आदिवासी महिलाएं जिनको 10 कि0मी0 5 कि0मी0 पर मजदूरी करने जाना पड़ता है चाहे हास्पिटल जाना पड़ता है स्वयं साइकिल चलाकर, बैठकर बच्चों के साथ वह चली जाती हैं। निश्चित तौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी वर्गों का चाहे वह कन्या विद्याधन हो लैपटाप हो सबसे अहम बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के विकास में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है जब तक बिजली नहीं होगी उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं होगा लेकिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण सोनभद्र का अनपरा डी जिसका माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने शिलान्यास किया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका उद्घाटन/लोकार्पण किया। जहां एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन अनपरा डी के माध्यम से होता है। निश्चित तौर पर हमारे जनपद सोनभद्र में उन्होंने इंजीनियरिंग कालेज, बगल के जनपद मिर्जापुर में भी इंजीनियरिंग कालेज और बगल के जनपद चंदौली में भी उन्होंने मेडिकल कालेज देने का काम किया। निश्चित तौर पर ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने चाहे रोजा पावर प्लांट हो बारा पावर प्लांट इलाहाबाद हो या जनपद सोनभद्र का अनपरा डी प्लांट हो उन्होंने इसको चालू करके ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने काम किया। क्योंकि बिजली ही हमारे विकास की अहम कड़ी है जब हमारे छोटे और लघु किसान खेती करते हैं तो वह छोटे से अपने पम्प चलाकर किसान खेती करते हैं। हमारी

सरकार ने एक ही वाट में दो दो वाट फ्री करने का काम किया साथ ही प्रत्येक तहसील में 33/11 के0वी0 का उन्होंने फीडर सेपरेशन का काम किया। हमें लगता है कि 75 जिलों में 33/11 बनवाने का उन्होंने काम किया ताकि कम से कम इस प्रदेशवासियों को अच्छे से बिजली मिल सके और साथ ही साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे यहां जो महिलाएं बच्चे हमारे यहां ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाएं और बच्चे कुपोषण का शिकार होते थे उन्होंने कुपोषण का राज्य मिशन स्थापित किया ताकि उन बच्चों और महिलाओं के बेहतर भविष्य के लिए काम किया जा सके। निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में चाहें वह डिग्री कालेज हों महिला डिग्री कालेज हों इंजीनियरिंग कालेज हों उन्होंने बहुत सारे जिलों में इसकी स्थापना करवाई ताकि जो गरीब अल्पसंख्यक, किसान मजदूर, दलित आदिवासी, महिलाएं जो उच्च शिक्षा से चाहे वह युवा हो या युवती हो जो उच्च शिक्षा से वंचित रहते थे और प्राइवेट कालेजों में हायर फीस न दे पाने की वजह से हायर शिक्षा टेक्निकल शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे इनकी स्थापना से इनको बेहतर भविष्य का नया आयाम मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्रीमती रूबी प्रसाद–

साथ ही साथ लैपटाप देकर उन्होंने यह सोचा कि यदि हमारे बगल में पड़ोस में एक अमीर व्यक्ति का बच्चा लैपटाप चलाता रहे और एक किसान मजदूर का बेटा देखता रहे और उसके मन में हीन भावना आए इसकी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने लैपटाप देने का काम किया ताकि गरीब के बच्चे भी लैपटाप चलाएं और यह सोचें कि अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होता यह हमारी सोच है, माननीय मुख्य मंत्री और हमारी सोच है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। हमारे मा0 नेता ने यूं तो अपनी बात को बहुत विस्तार से कह दिया है, इसलिये मैं उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अपने क्षेत्र की मात्र दो–तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुये हमारे भाई श्री गुलाम मौहम्मद जी ने जोर देकर कहा कि प्रदेश की स0पा0 सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। विकास कार्य बहुत जोरों पर चल रहा है, साथ ही साथ लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, उनकी बात सुनकर मुझे मुनव्वर राणा साहब की एक बात याद आ गई कि 'मेरे सोहबत में भेजो ताकि उनका डर निकल जाये, बहुत सहमी हुई दरबार में सच्चाई रहती है।' सच तो यह

है कि पूरे प्रदेश में विकास का काम ठप्प है और लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति यह है कि हर तरफ लूट, डकैती, हत्या, बहू–बेटियों की इज्जत आबरू पर हमले और सांप्रदायिक हमलों की बाढ़ इस सरकार में आई हुयी है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने सबसे पहले अपने विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर की एक समस्या रखना चाहता हूं। मेरी मुबारकपुर विधान सभा की नगर पालिका में लगभग डेढ़ साल से ई0ओ0 नहीं है, जिसका चार्ज जिला मुख्यालय के ए0डी0एम0 महोदय को दे दिया गया है। इस वजह से वहां के लोग इतने परेशान हैं कि अक्सर नगर पालिका का घेराव करते हैं, रोड जाम करते हैं, क्योंकि ए0डी0एम0 महोदय जिला मुख्यालय पर बैठते हैं। वहां के गरीब आदमी को अपने रोजमर्रा के छोटे–मोटे कामों के लिये जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। जब वह लोग वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ए0डी0एम0 महोदय किसी मीटिंग में गये हुये हैं, कहीं दौरे पर गये हुये हैं। अब उस गरीब आदमी के पास सिर्फ दो विकल्प बचते हैं कि या तो वह अपने पूरे दिन का काम छोड़कर वहां बैठकर उनके वापस आने का इंतजार करे अथवा अपनी रोजी–रोटी की मजबूरी में वह वापस चला जाये। इस सन्दर्भ में चूंकि वहां पर अक्सर रोड जाम, धरना–प्रदर्शन, लॉ एण्ड आर्डर की प्रॉब्लम होती है, इसलिये मैंने जिलाधिकारी से मिलकर उनसे अनुरोध किया। मा0 नगर विकास मंत्री जी से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया और मुझे अच्छा लगा कि मा0 मंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया कि आपका पत्र कार्रवाई के लिये प्रमुख सचिव के पास भेज दिया गया है, इस पर कार्यवाही हो जायेगी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार की कार्यशैली यह है कि आठ महीने गुजर जाने के बाद और मा0 मंत्री जी के पत्र देने के बाद आज तक वहां पर ई0ओ0 नहीं आया है। इसलिये मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्रता के साथ सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया करके वहां पर ई0ओ0 की पोस्टिंग कर दी जाये। दूसरी बात, मैंने अभिभाषण में देखा कि मुबारकपुर में एक विपणन केन्द्र का जिक्र है। सरकार वहां पर साढ़े ग्यारह करोड़ रुपया खर्च करके एक विपणन केन्द्र बनाना चाहती है। मुबारकपुर बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। मुबारकपुर, अमिलो, इब्राहिमपुर, जहानागंज को यदि मिला दिया जाये तो लगभग एक लाख की आबादी है। जब भी मुझे मौका मिला है मैंने इस सदन में सरकार के संज्ञान में लाने की कोशिश की कि यह जो बुनकर समाज है इसकी रोजी–रोटी बिजली सप्लाई पर निर्भर करती है और सत्यता यह है कि सरकार चाहे कितनी भी डींग मारे, मगर इतना अनुरोध करने के बाद आज भी स्थिति यह है कि वहां पर 6–7 घंटे से ज्यादा इफेक्टिव लाईट नहीं मिलती है। इसलिये मा0 अधिष्ठाता महोदय, ठीक है, जो अच्छी बात है उसको अच्छा भी कहा जाये। आपने विपणन केन्द्र बनाये, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद देता हूं और इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अगर विपणन केन्द्र में आखिर लोग क्या ले जाकर रखेंगे ? अपना जो प्रोडक्शन करेगा, बुनकर, जो बनायेगा, वही वहां ले जाकर बेचेगा। तो बनायेगा तब, जब महोदय, उसको लाइट मिलेगी। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से एक बार पुनः

यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह मुबारकपुर को, इस बेल्ट को चूंकि बुनकर बहुल क्षेत्र है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

नहीं, महोदय, यह तो मेरे साथ बड़ी ज्यादती है, अभी तो एक सदस्य आधा घण्टा बोल कर गए हैं, बहन जी ने भी 15 मिनट बोला है, महोदय, 2–4 मिनट तो दीजिए। महोदय, मैं आपसे माध्यम से सरकार से दोबारा अनुरोध करता हूं कि मेरे क्षेत्र को इन्डस्ट्रियल बेल्ट घोषित कर दें और कम से कम उन्हें 20 घण्टा बिजली दें। महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं चूंकि हमारे भाई ने यह बात कही और चूंकि मैं यहां बैठा था, इसलिए मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि जब आप अपनी बात कह रहे थे, तब आपने बहुत जोर देकर कहा कि हमारे नेता की किसी सी0डी0 का भी जिक्र किया कि मेरठ में यह सी0डी0 बोली जो मुस्लिम विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोला कि ये लोग साम्प्रदायिकता बढ़ाते हैं और यह भी बोला कि हमारे नेता ही सही मायने में सेकुलर नेता हैं। ठीक है, आपने बोला, मगर मेरे भाई, जब आप इसका जिक्र करते हैं तो आपको बिहार के असेम्बली इलेक्शन का भी जिक्र करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

मान्यवर, प्लीज 02 मिनट और दें। आपके नेता ने ही वहां गठबन्धन बनाया था और इस नाते बनाया था और यह कह कर बनाया था।

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति सिंह वर्मा)–

विषय पर आइये।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

विषय पर ही बोल रहा हूं, मान्यवर, कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम एक महागठबन्धन बना लें ताकि वह रुक जायें। फिर आपके उस सेकुलर नेता के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गयी कि भाग खड़े हुए और भागे ही नहीं बल्कि प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में चीख–चीख कर कहने लगे कि इस देश में सबसे अच्छे नेता मोदी हैं और यही नहीं वहां भाजपा की लहर आ रही है और भाजपा की ही सरकार बनना चाहिए।

श्री राममूर्ति सिंह वर्मा–

राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे हैं कि पूरे देश पर बोल रहे हैं?

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

महोदय, मैं सिर्फ वही बोल रहा हूं, जिन बिन्दुओं को हमारे भाई ने बोला। हमारे भाई ने इखलाक का भी जिक्र किया, गौतमबुद्ध नगर दादरी हत्याकाण्ड में, मैं

पूछता हूं कि आपके सेकुलर नेता, जिनको आप सेकुलर कहते हैं और हमारे हितैषी हैं, हत्यारों को जानते हैं, कहते भी हैं कि मोदी जी पूछें तो मैं बता दूं तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, उसके सामने कि वह हत्यारों को बचा रहे हैं। जबकि सारे लोग जानते हैं कि वह कहीं ने कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब वीरपाल राठी जी बोलें।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

महोदय, सच तो यह है कि आप और बीजेपी दोनों मिलकर इस प्रदेश में दंगा कराते हैं और लाशों के ढेर पर आप और आपके नेता अपनी कुर्सी को रखकर सत्ता हथियाने के लिए बेकसूर हिन्दू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका लिखा नहीं जायेगा।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

महोदय, आपने मेरे साथ ज्यादती कर दिया, धन्यवाद।

'श्री वीरपाल राठी–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा रखे गए अभिभाषण पर उसके विरोध में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही एक निवेदन भी करना चाहूंगा। अधिष्ठाता महोदय, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिन पर राज्यपाल महोदय ने यहां पर चर्चा नहीं की है, जिन पर चर्चा की जानी बहुत आवश्यक थी। मान्यवर, गन्ना पर अभी एक माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि हमारी सरकार ने 40 रुपये गन्ने का पेमेण्ट दिया लेकिन साथ ही वह यह बात भूल गए होंगे कि उन्होंने यह तो चर्चा की लेकिन यह चर्चा नहीं की कि गन्ने का ब्याज जो था, किसानों की जेब में जो जाना था, उसे किसानों की जेब से निकाल करके गन्ना मिल मालिकों की जेब में दे दिया, यह चर्चा उन्होंने नहीं की। साथ ही मैं एक और निवेदन करूंगा कि बहुत सुविधाएं दी गन्ना फैक्ट्रियों को इस सरकार ने, चार साल हो चुके हैं, चार साल में एक रुपया भी इस सरकार ने नहीं बढ़ाया और आज किसान भूख की कगार पर है जो गन्ना किसान है, दो–दो साल हो चुके हैं, उनके गन्ने का पेमेण्ट नहीं हुआ है। आप जा करके देखिए मलकपुर गन्ना मिल, इसकी चर्चा नहीं की गई। मान्यवर, यह बहुत समस्या है, प्रदेश की अहम् समस्या है। मान्यवर, एक चर्चा और करूंगा आपके सामने, सन् 1990 के अन्तर्गत पानी का बॅटवारा हुआ था और पानी के बटवारे में हरियाणा और दिल्ली को पानी दे दिया गया। और जो आज मौजूदा सरकार है उस वक्त भी वही सरकार थी। उस सरकार ने गलती की है उत्तर प्रदेश के साथ। आप देखें कि पानी के बटवारे में अगर पानी सबसे कम मिला है तो वह उत्तर प्रदेश को मिला

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

है। और मान्यवर, भविष्य में अगर विश्वयुद्ध होगा तो पानी के बटवारे को लेकर होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसानों की बेल्ट है। जहां सबसे ज्यादा खेती होती है। उसमें आज पानी की मारामारी है। वहां सारा डार्क जोन है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय को यह समीक्षा करनी चाहिए थी कि जब पानी के बटवारे के साथ मौजूदा सरकार ने अन्याय किया था तो उस पर समीक्षा होनी चाहिए। मान्यवर, आज प्रदेश के अंदर जितने भी विद्युत के बिल थे उन बिलों पर 180 रुपये प्रति कनेक्शन उपभोक्ता पर पड़ता था। लेकिन आज 180 रुपये प्रति किलोवाट यानी दोगुना कर दिया गया। गांव के लोगों को जहां सुविधा देने की बात समाजवादी पार्टी के लोगों ने घोषणा पत्र में रखी थी कि हम सुविधा मुहैया करायेंगे उल्टा उन पर दण्ड कर दिया गया। इतना बोझ उन उपभोक्ताओं पर पड़ा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मान्यवर, अभी मा0 नेता श्री मुलायम सिंह जी की चर्चा कर रहे थे। मा0 मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि आधे से अधिक भ्रष्ट मंत्री हैं मेरी सरकार में, यह उनका बयान आया। सतीश महाना जी कह रहे थे। इसके साथ यह भी सच है कि मैं मानता हूं कि प्रदेश के अंदर जो प्रदेश के नेता मुलायम सिंह जी हैं वह आज देश की पहली पंक्ति में खड़े हुए हैं। इतना बड़ा उनका कद है। और इतने बड़े कद के साथ उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आधे से अधिक मंत्री भ्रष्ट, हमें नजर नहीं आते विपक्ष के लोगों को, कि यहां कोई मंत्री भ्रष्ट होगा। अगर इस भ्रष्टता की श्रेणी में देखा जाये तो यह भी देख लिया जाये कि पद किसके पास ज्यादा हैं। पद की संख्या आधे से अधिक मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 श्री शिवपाल सिंह यादव जी के पास है। और मंत्री के पास तो एक छोटा पद है। मान्यवर, मैं आपके सामने एक और निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर रमाला मिल का प्रस्ताव आया था। दोगुना करने का, बड़ा करने का। लेकिन पैसा नहीं दिया गया। राजकीय कालेज थे उनको हमने डिग्री कालेज कराने की बात कई बार लिखी। चार साल हो गये। हम प्रस्ताव करते रहे कि डहा के अंदर डिग्री कालेज बनाया जाये। लेकिन सरकार ने लिख दिया कि धन का अभाव है इसलिए पैसा नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो आज जर्जर हैं, चार साल हो गये। टूटी पड़ी हैं। पुल की व्यवस्था तो ऐसी है कि जहां हमने डिमाण्ड की कि हमें इस क्षेत्र में पुल दे दिया जाये लेकिन एक भी पुल नहीं दिया गया। मान्यवर, मैं आपके सामने निवेदन करूंगा और बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि मा0 मुलायम सिंह जी एक बात और बोलते हैं कि हमारी सरकार समाजवादी की सरकार है। मा0 मुलायम सिंह जी कहते हैं कि हमारी सरकार धर्मनिरपेक्षता की सरकार है। और मैं यहां पर घोषणा करना चाहता हूं कि अगर यहां पर धर्मनिरपेक्षता की सरकार है और यहां पर मा0 आजम खां जी इस सदन में सबसे अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे और समझदार हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं, सदन से, तमाम विपक्ष लोग चाहे बसपा के हों, चाहे लोक दल के हों चाहे सपा के हों आज तक इस प्रदेश के अंदर कोई मुस्लिम मुख्य मंत्री क्यों नहीं है। जो प्रदेश के अंदर धर्मनिरपेक्षता का हंगामा मारते हैं। बनाइये किसी मुस्लिम को। बनाईये,

आजम खां जी को बनाइये। और हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं अगर मुलायम सिंह जी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बीच में बोलने का प्रयास करने पर)

बी0जे0पी0 की बात नहीं करता हम केवल अपनी बात करते हैं। हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। हम उस सिद्धांत की बात करते हैं जो चौधरी चरण सिंह जी ने सिद्धांत दिये थे। चौधरी चरण सिंह जी जो कहा करते थे वह करते थे। और तुम्हारे घोषणा–पत्र में क्या वायदे थे। और उस घोषणा पत्र के क्या वायदे पूरे हुये हैं। आप कहा करते थे कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और वही बात भारतीय जनता पार्टी बोलती थी। मान्यवर, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बहुत बड़े पेड़ पर एक व्यक्ति चढ़ गया। जब उसने नीचे देखा कि अगर तू नीचे जाएगा तो मर जाएगा, नहीं उतर पायेगा तो उसने घोषणा कर दी कि मैं 100 ब्राह्मण को जिवाउंगा अगर आज इस पेड़ से नीचे उतर जाऊं। जब वह बीच में आया तो वह पचास पर आ गया और जब और नीचे आया तो वह 25 पर, फिर दस पर आया और उसके बाद कूद गया और कूदने के बाद बोला कि एक ब्राह्मण को भी नहीं जिवाउंगा। वह हाल इन्होंने बेरोजगारी के सवाल पर किया है। कि सिर्फ घोषणा करते थे, बेरोजगारी दूर नहीं हुई, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जाय, अब आपका लिखा नहीं जायेगा।

श्री वीरपाल राठी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद्, जय हिन्द, जय भारत।

डा0 आर0के0 वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2016 पर श्री राज्यपाल महोदय के द्वारा दिये गये अभिभाषण पर चर्चा के अवसर पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं अपने आप को नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लाये गये संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में सम्बद्ध करते हुए, उस पर बल देते हुए मैं आपके माध्यम से सदन को यह बात अवगत कराना चाहता हूं कि मान्यवर, श्रीमान राज्यपाल महोदय के द्वारा लाये गये अभिभाषण में, उनकी अभिभाषण पुस्तिका में कई जगहों पर कथनी–करनी में एक की बात कही गई और हमारे इस सदन में बैठे हुए बहुत सारे नेताओं के द्वारा भी बार–बार यह बात कही गई है कि सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। मान्यवर जब हम पूरे प्रदेश को एक समान नजरिये से देखते हैं, विकास के पैमाने की ओर नजर डालते हैं विकास की योजनाओं के परिणाम एवं पारदर्शिता पर नजर डालते है और गरीबों के आसुंओं की ओर नजर डालते हैं, जब यहां की कानून–व्यवस्था पर नजर डालते हैं, तो मान्यवर, हमें दिखाई पड़ता है कि सरकार की कथनी–करनी में एक नहीं, अन्तर नहीं बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कथनी और करनी में तलाक हो चुका है। मान्यवर, सरकार की कथनी और करनी में तलाक हो चुका

है। मान्यवर, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पुस्तिका के पेज नम्बर तीन का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जिस पर लिखा है कि सरकार ने किसानों की सिंचाई मुफ्त करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, वहीं दूसरी ओर सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करके और नए ट्यूबवेल चला कर के, नहरों की सिल्ट की सफाई करा करके, किसानों की सिंचाई करा करके किसानों के चेहरों पर खुशहाली लाने का प्रयास किया। मान्यवर, यह बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ हुआ है, सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार की कथनी और करनी में एकता नहीं बल्कि तलाक हो चुका है। मान्यवर, हमारे जनपद प्रतापगढ़ का यह आंकड़ा है, यह सिंचाई विभाग के द्वारा समय सारणी बनाई गई है, मान्यवर इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए, हमारे प्रतापगढ़ को 1150 क्यूसेक लीटर पानी प्रतातगढ़ जल शाखा शीर्ष से आता है, मान्यवर उसकी जो क्षमता है 1150 क्यूसेक लीटर की है, लेकिन सरकार ने जो तय किया है, यह सारणी आप देख लें, मेरा एक भी वक्तव्य झूठा नहीं है, केवल 800 क्यूसेक लीटर पानी की व्यवस्था सरकार ने देने का काम किया है, लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना इस बात की है कि सरकार ने जो झूठीं बातें, झूठे वायदे, खोखले वायदे करके जनता को गुमराह करने का काम किया है, आज प्रतापगढ़ जल शाखा शीर्ष में बड़े पैमाने पर सिल्ट जमा है और वहां पर जल शाखा शीर्ष से प्रतापगढ़ को मात्र साढ़े पांच सौ क्यूसेक लीटर पानी मुहैया होता है, यह आपके सरकारी विभाग का आंकड़ा है, इसमें पूरी की पूरी सच्चाई है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब आप समाप्त करें।

डा0 आर0के0 वर्मा–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह के झूठे बयान सरकार की तरफ से अगर श्री राज्यपाल महोदय उनको पढ़ने का काम करेंगे, तो हम जैसे लोग संशोधन के पक्ष में बल देने के लिए खड़े होने का काम करेंगे। मान्यवर, दूसरी बात मैं आपसे अपने विधान सभा क्षेत्र की कहना चाहता हूं, सरकार ने डा0 लोहिया समग्र ग्राम योजना के बारे में चर्चा की, निश्चितरूप से मैं स्वागत करता हूं कि निश्चितरूप से वह एक अच्छी सोंच रही है, जिसमें गरीबों, कमजोरों, मजदूरों के बारे में सोंचा गया, लेकिन मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी की पूरा यह योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है, गरीबों को लाभ नहीं हुआ है, जो गरीब पात्र हुआ करता था, उसको योजनाओं का पात्र नहीं बनाया गया है, मान्यवर, मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूंगा, कुछ ग्राम सभाओं के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख लें, मान्यवर, हमारी विधान सभा में राजापुर ग्राम सभा है जो डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित हुआ है, मान्यवर उस गांव में जिन लोगों के पास नौकरी है, श्रीमती मालती देवी वाईफ आफ लालता प्रसाद, इनके घर में नौकरी है, इनको लोहिया आवास मिला है, दूसरी तरफ वहीं अनारा देवी वाईफ आफ बाबू लाल इनके घर में नौकरी है,

इनको आवास मिला है, वहीं पर कुछ ऐसे विकलांग लोग हैं, निराश्रित लोग हैं, जिनका कोई परिवार न उनको आवास मिला है, न उनके लिए पेंशन मुहैया करायी गयी है। बंशी लाल नाम का एक विकलांग है उसको वहां के लोगों ने पेंशन तक दिलाने का काम नहीं किया है, आवास तो बहुत दूर की बात रही है। मान्यवर, अगर यह सदन गंभीर है, अगर सरकार गंभीर है तो इस चीज को संज्ञान में लेते हुए जिम्मेदार और जवाबदेह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का वायदा करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

चलिए अब समाप्त करें।

डा0 आर0के0वर्मा–

मान्यवर, मैंने बहुत कम वक्त लिया, मुझे दो मिनट का समय चाहिए। मैं अपनी पार्टी का इकलौता विधायक हूं अगर पूरी बात भी नहीं आएगी तो बात नहीं बनेगी। तीसरी बात मैं कानून–व्यवस्था के नाम पर आपसे कहना चाहता हूं। 100 नम्बर को छोड़ दीजिए, मैं आपको 05 दिसम्बर, 2015 की घटना के बारे में बताना चाहूंगा। शराब के माफियाओं की वजह से हमारे प्रतापगढ़ की बदनामी हमेशा से होती रही है। जब मेरे संज्ञान में यह आया कि 05 दिसम्बर, 2015 की शाम को 5 बजे प्रतापगढ़ से बड़े पैमाने पर शराब सोरांव थानान्तर्गत लायी गयी है, तो मैंने अपने सी0यू0जी0 नम्बर से 876595 से 4713 थाना प्रभारी सोराव को कॉल किया। मेरे कार्यालय और सोरांव थाने के बीच में मात्र 200 मी0 का अंतर है। मैंने कम से कम 15 बार सोरांव थाने के एस0ओ0 को फोन किया। आप मेरे सी0यू0जी0 नम्बर की कॉल डिटेल निकलवा करके जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। मैंने डी0आई0जी0 महोदय को जानकारी दी कि मान्यवर, आपका इंस्पेक्टर बात नहीं कर रहा है गम्भीर अपराध की सूचना देती है। बड़े पैमाने पर अनियमितताएं संज्ञान में आयी हैं। बड़े पैमाने पर शराब की हमें सूचना यहां पर दी गयी है, उसकी बरामदगी होनी चाहिए। उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। डी0आई0जी0 ने कहां मैं 30 सोराव को कहता हूं फोन उठाकार बात कर किन्तु 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैंने 20 बार फोन लगाया लेकिन इंस्पेक्टर का फोन नहीं उठा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एक विधायक को आपके द्वारा प्रदान किया गया सी0यू0जी0 नम्बर, अगर इंस्पेक्टर के द्वारा नहीं उठाए जाते तो आम नागरिक अगर 1090 पर जब कॉल करता होगा या 100 पर कॉल करता होगा तो उसका फोन कैसे उठता होगा? उसकी समस्याओं का समाधान कैसे होता होगा ? मान्यवर, इस अभिभाषण का विरोध मैं इसलिए भी करता हूं कि आज जो बढ़ती हुयी लागत को देखते हुए किसानों की उपज का उनको लाभांश दिए जाने पर राज्यपाल महोदय जी ने कोई चर्चा नहीं की है। मैं किसानों को फसल की लागत के लाभ में 50ः लाभांश दिये जाने की मांग करता हूं। अधिष्ठाता महोदय जी आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें। अब कुछ लिखा नहीं जायेगा। कोई मतलब नहीं है। दूसरे सदस्य बोल रहे हैं।

श्री मौ0 इरफान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। माननीय हमारे साथी गुलाम मौहम्मद साहब ने गर्वनर साहब के बारे में जो अपने विचार रखे उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं और मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि जितना इससे पूर्व सरकारों का इतिहास रहा है उसमें सबसे बेहतर इस चार साल की सरकार की कार्यदायगी रही है। हमारे विपक्षी साथी को पता नहीं उन्हें कुछ शब्द रट गए हैं, भ्रष्टाचार या इस तरह के शब्द वह कभी इस पर गौर नहीं करते कि हमारी सरकार ने जितने काम किए हैं, जो समाजवादी सरकार ने काम किए हैं, जो समाजवादी सोच ने काम किए हैं, उसमें आज प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। तमाम विदेशी हमारे यहां अपनी योजनाओं के लिए दौड़ लगा रहे हैं। हमारे देश में जितना ज्यादा विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है उसका उदाहरण किसी और प्रदेश में नहीं मिलता है। समाजवादी पेंशन योजना जो सीधे–सीधे 45 लाख लोगों के खातों में जाती है। यह इतना बड़ा काम है और उसमें 10 प्रतिशत इजाफा होना एक और बहुत बड़ा काम है जो अब तक किसी सरकार की सोच से भी ऊपर है। जो हमारी सरकार ने कर के दिखाया है। मैं पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति, पूर्वदशम् छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति इस तरह की जो योजनाएं हैं उसको सीधे–सीधे उन बच्चों को जो गरीब हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और किसी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, सीधे–सीधे सरकार ने उनकी मदद की है। विशेष तौर पर अल्पसंख्यक विभाग को जो सरकार के द्वारा राशि जारी की गयी है। जिसमें बच्चों के लिए या उनकी योजनाओं के लिए मैं कब्रिस्तान की बाउॅण्ड्री के लिए जो एक सराहनीय काम किया है, वह ऐसा काम है जिसमें माननीय अधिष्ठाता महोदय जी कहना चाहूॅगा कि नगर विकास मंत्रालय की जानिब से कि जो अल्पसंख्यक बॉउण्ड्री उन गांव में कब्रिस्तानों के बारे में हुई है वह इतना बड़ा काम है कि जो माफिया उस पर कब्जा किए हुए थे, उन तमाम को कब्जामुक्त कराकर एक ऐसा संदेश भेजने का काम किया है जो हर गांव में चमक रहा है और जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारी समाजवादी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में जो काम किया है, बिजली की व्यवस्था इतनी दुरुस्त की गई है जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुई है। उन नगर पालिका परिषदों को भी जहां की वसूली अच्छी है उनको 20 घण्टे बिजली सप्लाई दिया जाना, कुछ शहरों को 24 घण्टे बिजली दिया जाना, कुछ को 22 घण्टे बिजली दिया जाना और देहात में 12 घण्टे बिजली सप्लाई दिया जाना एक बहुत बड़ा काम है। सोलर सिस्टम के जरिए तमाम बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना बहुत बड़ा सराहनीय काम है। हमारी सरकार ने किसानों को सीधे–सीधे जो मूल्य का अन्तर था, जो गन्ना मूल्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को यह दिक्कत आ रही थी। चूंकि चीनी का मूल्य बाजार में बहुत घट गया था उसकी वजह से किसान मालिक अपनी

असमर्थता जता रहे थे तो 28 रुपये 60 पैसे प्रति कुण्टल की दर से प्रत्येक किसान के खाते में पैसा भेजना, इससे पहले कभी सम्भव नहीं हो पाया था और करोड़ों रुपया सरकार ने दिया है। ये सीधे–सीधे किसानों को फायदा पहुंचा है। कामधेनु योजना और कुक्कुट पालन योजना इस तरह की योजनाएं जो ब्याज माफी वाली योजनाएं सरकार के द्वारा चालू की गई हैं, गवर्नर महोदय ने उसका जिक्र अपने अभिभाषण में किया है। मैं यकीनी तौर पर उसकी प्रशंसा करता हूं, उसके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को मेट्रो का उपहार दिया गया है। जो इतने बड़े प्रदेश को हमारी समाजवादी सरकार की जानिब से दिया गया है। यह एक ऐसा उपहार है कि जो कभी कल्पना था और अब वह साकार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस वर्ष के और इससे पिछले वर्ष में पूरी तौर पर मैं इस बात की जानकारी देना चाहूंगा कि इस साल किसी भी किसान को बुआई के समय खाद और बीज का संकट पैदा नहीं होने दिया गया है। यह पहली बार हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ है। हमारे साथी गुलाम मोहम्मद साहब ने गवर्नर साहब के अभिभाषण के समर्थन में जो अपनी बात कही थी मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। मैं कहना चाहता हूं कि नगर विकास में जितना काम हमारे मा0 मोहम्मद आजम खां साहब जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं उनके विभागों का विशेष तौर पर कार्य किया गया है कि कोई शहर, कोई गांव, कोई नगर निगम, कोई नगर पंचायत, आज 14 नगर निगम हैं, इतना काम हुआ है जो पूरी तौर पर दिखाई दे रहा है। 194 नगर पालिका परिषद हैं और 427 नगर पंचायत हैं। जो नई नगर पंचायतें बनाई गईं हैं तो कहीं भी ऐसा दिखाई देता है किसी भी शहर में, किसी भी गांव पंचायत में, किसी भी न्याय पंचायत में कि सड़कों का जाल बिछ गया है। अब ये ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सी सड़कें और रह गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक कल्याण के जो सराहनीय कार्य हैं वे पूरी तौर पर चाहे मदरसा अनुदान है जो इससे पहले कभी नहीं किया गया था। कोचिंग व्यवस्था जिसमें गरीब मुस्लिम बच्चों के लिए, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, यह कार्य सराहनीय है। मैं अपनी तरफ से यह और कहना चाहूंगा कि उपभोक्ता सेवा केन्द्र जो बिजली विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसमें ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 01 लाख 73 हजार ग्रामों को बिजली दिया जाना कोई मामूली काम नहीं है। उन गांवों का विद्युतीकरण कराना जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी, यह काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। सरकार द्वारा पहली बार धर्मार्थ कार्य में समाजवादी श्रवण योजना शुरु की गई है जो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इस तरह की योजनाएँ हमारी सरकार द्वारा चालू की गई हैं। कृषि, शिक्षा सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। अभी हमारे एक साथी ने एक शब्द कहा, बार–बार भ्रष्टाचार का शब्द कहा। पता नहीं कहां से इनको भ्रष्टाचार याद आता है। ये अगर भ्रष्टाचारी रहे होंगे तो इनको खुद ही अपना याद होगा क्योंकि आईने में अपनी तस्वीर नजर आती है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ी है। हमारी सरकार जो पुरानी भ्रष्ट व्यवस्थाएं थीं, उन पुरानी व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और हम सब मिलकर हमेशा इस तरह की बात करें। यह

सरकार जो मौजूदा सरकार चल रही है, ये लोग हमेशा सरकार के निगेटिव में बात न किया करें उसके पॉजिटिव पर भी चर्चा किया करें। मैं अपने सामने वाले साथियों से यह कहना चाहूंगा कि किस तरह से आपके सामने योजनाएं लगातार आ रही हैं। आपने तो बस आरोप लगा दिया और लोहिया ग्रामों की बात कर दी। लोहिया ग्रामों की लिस्ट जो गांव पहले से बैकवर्ड, पिछड़े हैं उनके अंकों के आधार पर तय की गई है और प्रत्येक जिले में मौजूद है। उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। वहां के जिलाधिकारी से हर बार रिपोर्ट मांगी गई है और उन्हीं गांवों में से चयन करके लोहिया गांवों का चयन किया गया है। किसी के साथ बेइंसाफी नहीं हुई है। अन्त में अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने मुझे गवर्नर साहब के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, आपका शुक्रिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अब्दुल मशहूद खां–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री गुलाम मौहम्मद जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। अधिष्ठाता महोदय जो विपक्ष में हमारे साथी बैठे हैं, चूंकि विरोध करना उनका फर्ज है इसलिए वह विरोध करते हैं, वरना वह यह भी जानते हैं कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। आज मैं तो सुबह से बैठा देख रहा था 12 बजकर 20 मिनट तक प्रश्नकाल का समय होता है, लेकिन विपक्ष के पास सवाल 11 बजकर 55 मिनट पर ही खत्म हो गया। यह बात साबित करती है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और विपक्ष के पास सवाल नहीं रह गये हैं, यह इस बात को साबित करता है और जहां तक सवाल है कि किसी प्रदेश या देश की तरक्की मुख्य 5 चीजों पर आंकी जाती है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा अगर ईमानदारी से हमारे विपक्ष के साथी आंकड़ा उठाकर देखें तो पिछली जितनी सरकारें आईं उनकी तुलना के हिसाब से सन् 2012 से लेकर आज तक इन चार सालों में इन पांचों क्षेत्रों में सबसे बेहतर काम हुआ। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र से ही शुरू करूं तो जो पुल आजादी के इतने दिन बाद भी नहीं बन पाया था, आदरणीय शिवपाल जी ने सरकारी हेलीकाप्टर ले जाकर उतारा और डेढ़ साल के अंदर वह पुल बनकर तैयार हो गया और उससे कम से कम दो लाख लोगों को फायदा हुआ, जिनको करीब 100 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था, उससे भी ज्यादा घूमकर जाना पड़ता था, उनको फायदा हुआ। 30 किलोमीटर की सड़क जिस पर हमें जाने में ढाई घंटे लगते थे, उस सड़क को इस सरकार ने बना दिया। अब उस सड़क पर हम 30 मिनट में पहुंच जाते हैं, 30 मिनट में पहुंच जाते हैं, इसी तरह पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया। हमारे क्षेत्र में जो हिमालय की तलहटी में बसा हुआ क्षेत्र है, तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र, जहां पर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ, देवीपाटन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस सूबे में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही है। हिमालय की तलहटी में लोग मिट्टी में चोड़ा खोदकर, जिसको लोग कुआं बोलते हैं, उसे खोदकर गंदा पानी पीने को मजबूर थे, लेकिन हमारी सरकार

ने गहरे हैण्डपम्प देकर, डीप हैण्डपम्प जिसके एक–एक नल की कीमत साढ़े पांच लाख रुपये हैं, उसे देकर उनको स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी तरह बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाईं गईं, जिसका सीधा–सीधा किसानों को, गरीबों को, मजलूमों को, मजदूरों को, सबको इसका लाभ मिला है। श्रमिक बीमा योजना के अंतर्गत तमाम साइकिलें बांटी गईं। श्रमिकों का बीमा कराया गया, उसका लाभ उनको मिल रहा है। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी दवाई के लिए उसका लाभ मिल रहा है। क्लीन यू0पी0, ग्रीन यू0पी0 के तहत रिकार्ड वृक्षारोपण किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकार्ड दर्ज हुआ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतने पौधे एक दिन में लगाये गए, किसी प्रदेश की किसी सरकार ने लगाये हों तो बता दीजिए।

(विपक्ष से आवाज आई, पौधे सूख गए हैं।)

उस पर काम हो रहा है, जो लगाये जाएंगे, उसमें कुछ सूखेंगे भी लेकिन उसमें काम हो रहा है, हरियाली आएगी। आपने जो स्वच्छता मिशन चलाया था उसमें अच्छे–अच्छे को आपने झाड़ू पकड़ा दिया लेकिन आज भी हिन्दुस्तान साफ नहीं हुआ। हिन्दुस्तान का कचरा साफ नहीं हुआ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य बोल रहे थे, आदरणीय नेताजी के बारे में। एक देहाती कहावत है कि ''सूप बोले तो सूप, चलनी क्या बोले, जिकरे बहत्तर छेद,'' ये भूल गये कि इनके नेता ने बाबरी मस्जिद के बारे में क्या कहा था ? कहा था कि वहां सुलभ शौचालय बना देना चाहिए। ये मुसलमानों का बड़ा हितैषी बनने के लिए कह रहे थे। मैं मुसलमान हूं, मैं महसूस कर सकता हूं कि कौन मुसलमानों का कितना हितैषी है। मुसलमानों के हितैषी सिर्फ समाजवादी सरकार है, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल बनाकर यह साबित कर दिया कि मुसलमानों तुम्हारे जो लोग मुर्दा हो गए हैं, जो कब्रों में चले गए हैं, हम उनकी भी हिफाजत करना जानते हैं और अन्तेष्टि स्थलों का भी इन्होंने बनवाया। इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और पहली बार हमने देखा कि राज्यपाल महोदय जो दृढ़निश्चयी हैं, पूरा अभिभाषण पढ़कर गए, विपक्ष के लोग हल्ला मचाते रहे, कागज का गोला फेंकते रहे लेकिन राज्यपाल महोदय पूरा अभिभाषण पढ़ कर गए। इससे यह भी साबित होता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और सरकार के कार्यों से वह प्रभावित हैं इसलिए वह पूरा पढ़कर गए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः धन्यवाद देते हुए और समर्थन पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रोशन लाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हमने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण व बजट पुस्तिका पर बहुत ही अध्ययन किया उसमें एक–एक पन्ना पढ़कर देखा इसमे पृष्ठ संख्या–38 एक लगायत 346, जो समस्यायें हमारी विधान सभा क्षेत्र की थीं अगर

बिन्दुवार इसको हम पढ़ना चाहेंगे तो शायद एक–डेढ़ घण्टा निकल जायेगा। मैं कुछ अपनी विधान सभा की मुख्य जनहित के विकास कार्यों की समस्या रखना चाहता हूं कि अभी 2012–13 में इसी सरकार में हमारे विधान सभा क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई थी और तिलहर तहसील जाने के लिए लगभग 150 गांव का एक मात्र रास्ता है। तिलहर निगोही मार्ग पर लगभग 150 मीटर जो पी0डब्लू0डी0 से सड़क बनाई गयी थी वह भयंकर बाढ़ से कट गई थी। आज 15 किलोमीटर के बजाये 40 किलोमीटर शाहजहांपुर होकर जाना पड़ता है, जबकि इसी सरकार में वह सड़क कटी थी अभी हमारे माननीय सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि पूरे विधान सभा, पूरे प्रदेश में विकास हुआ है, चार साल लगातार मैंने नियमों के तहत जब–जब मौका मिला नियम–301 में और नियम–51 में भी लगाया लेकिन उस सड़क का अभी तक कोई समाधान नहीं कराया गया। इसी प्रकार अभी विधवा पेन्शन की बात हो रही थी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोग, सरकार एक टीम गठित करा दे जनपद शाहजहांपुर में जो गरीब, निर्धन, असहाय, जिनका कोई नही कई हजार की संख्या में उनकी विधवा पेन्शन काट दी गयी और माफियाओं व संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत द्वारा उनको बन्द करके नई पेन्शन बांध कर उनका पैसा निकाल लिया गया। अगर मैं इसमे एक भी बात गलत कह रहा हूं मैंने जिलाधिकारी जी से, सम्बन्धित अधिकारियों से भी बात रखी लेकिन उस बात पर कोई अमल नहीं किया गया। मै कोई आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं जिनका कोई नहीं, उनसे गरीब कौन हो सकता है, ऐसे लोगों की पेन्शन काट दी गयी और मैं सारे सदन के सामने दावे के साथ कहता हूं अगर मेरी बात झूठ निकल जाये तो मैं यहां पर अपना इस्तीफा देकर हाउस से बाहर चला जाऊंगा, अगर मेरी बात गलत हो। मान्यवर इसी प्रकार हमारे यहां पूरे प्रदेश में सरकार कह रही थी कि गरीबों के लिए काम हो रहा है, सत्ता पक्ष के भी लोगों के शायद ईंट भट्ठे होंगे, विपक्ष के भी होंगे, प्रति एक भट्ठा पर लगभग 200 से 250 मजदूर काम करते हैं और हमारे जनपद शाहजहांपुर में ही अकेले 200 से ऊपर भट्ठे हैं और उसमें 200 से और 250 प्रत्येक भट्ठा पर जो बेचारे मजदूर काम करते हैं इसी प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में 18 हजार ईट भट्ठे हैं। 18 हजार ईट भट्टों पर 70 से 80 लाख परिवार के मुखिया काम करते हैं। इस प्रकार दो करोड़ लोग अपनी रोजी–रोटी पर भुखमरी की कगार पर आ रहे हैं, यहां का अपना प्रदेश छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हैं।

श्री रोशन लाल वर्मा–

ऐसी स्थिति में मैं सरकार से चाहता हूं कि इसमें उन गरीबों की रोजी–रोटी जुड़ी है और लगभग एक हजार करोड़ का इसमें सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है ईंट भट्ठा न चलने के कारण। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि ऐसे गरीबों के हित में ईंट भट्ठे चलाये जायें। सरकार कोई न कोई कदम जरूर उठाये जिससे उन गरीबों की रोजी–रोटी चल सके। मान्यवर, हम लोगों को जो अभी 25 लाख रुपये गरीब, निर्धन, बेसहारा जो लोग हैं

उनके इलाज हेतु जो गरीबों को पैसा देने का अधिकार दिया है। मान्यवर, जब हम लोग जनपद में किसी सम्बन्धित अधिकारी को चिट्ठी लिखते हैं किसी गरीब के इलाज के लिए तो उसमें उस चिट्ठी को हमारी इतना उलझा दिया जाता है, इतना उसे तोड़–मरोड़ दिया जाता है कि उनका पैसा समय से रिलीज नहीं होता तब तक उन गरीब बेचारे की इलाज के अभाव में जान चली जाती है कई बार मैंने चिट्ठियां लिखीं लेकिन वह पैसा जारी नहीं किया गया। हमारा इसमें एक सुझाव है कि जब हम किसी गरीब के लिए अगर उसका दो लाख रुपया लगना है, या एक लाख रुपया लगना है या 50 हजार लगना है उसको लम–सम हम लोग चिट्ठी लिख दें और वह पैसा सीधे पीजीआई को भेज दिया जाय जिससे उस गरीब का समय से इलाज हो सके और अगर वहां पर उस इलाज से ज्यादा पैसा बचता है तो वह पैसा वापस फिर सरकार में आ जाय ऐसा हमारा अनुरोध है। इसी प्रकार अभी हमारे सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि किसानो के हित में बहुत कार्य किये। गत वर्ष में बेमौसम बारिस, ओलावृष्टि हुई इससे तो किसानों का वह हाल हुआ है इस सरकार में कि बरसात में जलता हुआ घर देख रहे हो। ''बरसात में जलता हुआ घर देख रहे हो और सरकार इधर देखो किधर देख रहे हो।'' गत वर्ष बरसात में ओलावृष्टि में इस कदर किसानों की हानि हुई अभी हमारे विधान सभा क्षेत्र में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं सच कह रहा हूं कि जो किसानों की फसल बरबाद हुई उसमें बड़े पैमाने पर पक्षपात हुआ है बहुत ज्यादा से ज्यादा 25 प्रतिशत लोगों को मुआवजा मिला बाकी सारे गरीब बेचारे आज भी तहसील में चिट्ठी लिखा–लिखा के ले जाते हैं लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

माननीय अधिष्ठता महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर पूरे प्रदेश में विकास कार्य की बड़ी बातें हमारे साथी लोगों ने कही हैं और जो आने वाला समय है उसमें हम अपनी दो बातें कहना चाहता हूं–

''हम अगर चांद नहीं है तो सितारे ही सही,
रात अंधेरी हो तो तारे भी सिफा देते हैं।
और इससे पहले फलख से कोई बिजली टूटे,
आग हम खुद ही नशेमन में लगा लेते हैं।
नाखुदा होश में आ देख हवा के झोंके,
आने वाले 2017 के चुनाव में किसी तूफां का पता देते हैं।।''

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का कोई जवाब नहीं, इनके सामने तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता लेकिन यह हल्की बात जरूर कर देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है,
(आपके लिए जहां कह रहा हूं आप समझते होंगे)
''तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है।

हाथ रख लेती है कानों पे तेरे नाम के साथ।।''

'श्री मनीष असीजा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल जी के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूं कि इस बार का जो बजट है वह प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा बजट तीन लाख छियालिस हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और जाहिर है कि हम सब लोग समझते हैं कि इतना बड़ा पैसा अगर इसमें दिया गया है तो प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही होगा। कमोवेश जब से विधान सभा में मुझे आने का अवसर मिला है, चाहे सत्तापक्ष हो, चाहे विपक्ष के सभी दल के लोग हों, हम सबके भाषण का जो विषय है वह गरीब और कमजोर है। किसी के मुंह से मैंने आज तक नहीं सुना कि ताकतवर के लिए कुछ बोला गया है, सब कमजोर के लिए ही बोला गया है। मैं आपके माध्यम से सदन में यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि हम लोग अपने दिल पर हाथ रखकर देंखे कि जितनी योजनायें बन रही हैं, अभिभाषण में सरकार का जितना पक्ष रखा गया है, जो भी योजनाओं के प्रति उत्साह दिखाया गया है, जमीनी स्तर पर उसकी क्या स्थिति है ? तो कहीं न कहीं हमें महसूस होगा कि भले ही बहुत अच्छी भावना के साथ, बहुत सच्चे उद्देश्य के साथ हमने योजनायें बनाई होंगी, लेकिन वह गरीब तक नहीं पहुंच रही हैं। मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं कि अभी 01 जनवरी, 2016 से 28 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया है, 20–21 करोड़ की आबादी का हमारा प्रदेश है, लगभग 15 करोड़ के ऊपर हमारे राशन उपभोक्ता इसमें कवर होंगे। आप यकीन मानिये कि हमारे यहां पर जो नगर आयुक्त हैं, जो एस0डी0एम0 हैं, उनके एन0एफ0एस0ए0 के राशन के कार्ड बन गये हैं दो रुपये किलो गेहूं, तीन रुपये किलो चावल प्राप्त करने के लिए और गरीब आदमी भटक रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को जानकर आश्चर्य होगा कि नगर आयुक्त जैसे पी0सी0एस0 सेवा के व्यक्ति का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में बना है। उन्होंने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन वह पुरानी सूची है, कहीं डोर–टू–डोर सर्वे नहीं हुआ, किसी गरीब आदमी को देखा नहीं गया और नतीजा यह कि जिसको सस्ता आनाज चाहिये वो अभी भी राशन कार्ड से महरूम है। इसी तरीके से मैं लगातार चार साल से इस सदन में सरकार से यह बात कह रहा हूं कि फिरोजाबाद का जो कांच–चूड़ी उद्योग है, जिसमें मेहनतकश हिन्दू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सभी वर्गों के मेहनतकश मजदूर अपना खून–पसीना बहाता है, अपनी रोजी–रोटी कमाता है, उसके लिए भी कुछ सोच लिया जाये। उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार कुछ कर दे, उनके आवासीय क्षेत्र जिस प्रकार से है अवस्थापना सुविधाओं से विहीन होकर वह निवास कर रहे हैं, साक्षात नारकीय जीवन व्यतीत करने को वह मजबूर हैं। उनके लिए कोई बड़ी आवासीय योजना बन जाये, लेकिन पिछले चार साल से हम कहते–कहते थक रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इण्डस्ट्रियल स्टेट भाऊ के नगला में पिछले तीस वर्षों से सरकारी

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

भूमि निष्प्रयोज्य पड़ी है, वहां काम करने वाले हजारों श्रमिक भाइयों के लिए एक रैन बसेरा, सुलभ शौचालय, ठण्डा पानी पीने की मशीन का निर्माण कराने की बात भी पिछले चार सालों से लगातार उठा रहा हूं। इसी तरीके से हमारे फिरोजाबाद में औद्योगिक शहर होने के नाते बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियां संचालित होती हैं। अभी हम लोगों ने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे बनाया है, साढ़े सोलह हजार करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क का, यह एक बहुत बड़ा उद्देश्य बताया जाता है कि इसमें उद्योगों को प्रगति मिलेगी और फिरोजाबाद शहर का जो उद्योग है उसकी तरफ भी मैं कई बार सरकार का ध्यान दिला चुका हूं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। आगरा–लखनऊ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे के सहारे एक ग्लास एक्सो मार्ट खोलना फिरोजाबाद के कांच उद्योग को नई संजीवनी देने का कार्य करेगा। जनपद में 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति के आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय के हैं, परन्तु विद्युत आपूर्ति घण्टों बाधित रहती है। मैं कोई बहुत बड़ी मांग भी नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि पिछले सौ साल से ऊपर कांच–चूड़ी का जो उद्योग फिरोजाबाद में चल रहा है, सरकार एक अलग नजरिये से वहां पर एक जांच दल भेजकर वहां के लोगों की, वहां के मजदूरों की, वहां के कर्मचारियों की, वहां के उद्योगपतियों की, वहां के आयात–निर्यात की संभावनाओं की एक ठीक प्रकार से एनालिसिस करने का काम तो कर सकती है। इसके बाद अब आप ही फैसला करिये कि आपको आगे क्या करना है। मैं आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, आपकी न्यायप्रियता का मैं कायल हूं। मैं आपसे आज एक और निवेदन करना चाहता हूं। नगर निगम, फिरोजाबाद के अन्तर्गत इस वक्त जो भवन स्वामी है, उनके साथ यह नगर निगम बहुत बड़ा उत्पीड़न का काम कर रहा है और वह इस मामले में बहुत सेकुलर भी है और बहुत दल निरपेक्ष भी है। वह न तो सरस्वतीनगर देख रहा है और न हाजीपुरा देख रहा है, न वह हुमायूंपुर देख रहा है और न वह कश्मीरी गेट देख रहा है। उसने इस मामले में बहुत अच्छा उदाहरण बनाया है। चार–पांच गुर्गे जाते हैं किसी के मकान पर, उसको एक लाख रुपये का नोटिस दे देते हैं। ऐसे मेरे पास 50 नोटिस इकट्ठे हैं, इन्हें देख सामने वाले के होश फाख्ता हो जाते हैं। सौदा हो जाय तो बेहतर है अगर वह मेरे पास आ जाते हैं तो मैं उस नोटिस की कापी लगाकर नगर आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय को दे देता हूं और उनसे एक बात कहता हूं कि भई अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है और किसी के घर का अगर एक रुपया टैक्स है तो आप उसके दरवाजे पर जाकर 90 पैसे का टैक्स लगा दो, एक रुपये दस पैसे का टैक्स लगा दो, यह तो जायज बात है। लेकिन एक रुपया टैक्स में आप उसको 20 रुपये टैक्स की नोटिस थमा दो तो उसकी क्या हालत होगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात आ गयी है, इसका मुझे बड़ा सन्तोष है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपने पहले भी बताया था।

श्री मनीष असीजा–

लेकिन इसमें सुधार नहीं हुआ। मैं एक बात और अनुरोध करना चाहता हूं। आपकी गरीबों के प्रति दिल में जो कसक थी, वह शायद बहुत सारे लोगों की रही होगी कि जो मेहनतकश खून पसीना बहाकर रिक्शा चलाता है, उसको आपने बैटरीचालित रिक्शा देने की बात कही थी। अनफारचुनेटली मेरे फिरोजाबाद में पिछले चार साल में एक भी रिक्शाचालक इस योजना से लाभान्वित नहीं हो सका। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके ध्यान में यह बात अवश्य होगी।

'श्री मोहम्मद आजम खां–

असीजा जी, उसमें दरअसल कई दुश्वारियां आईं। एक तो अधिकारियों के स्तर पर, फिर बनाने वालों के स्तर पर, कई–कई बार कम्पनीज को बुलाया गया, जिस तरह की रिक्शा हम चाहते थे, उस तरह की रिक्शा नहीं मिल पा रही थी। फिर एक सुझाव यह आया कि चाइना से हम रिक्शा खरीद लें तो उनकी क्वालिटी उस काबिल नहीं थी। तो गत दिनों हमने काइनेटिक वालों से कुछ रिक्शा खरीदी थी, लखनऊ में तकसीम की हैं और बड़ी तादाद में और होना है, फिरोजाबाद भी आपका उस लिस्ट में है, वहां भी आयेंगे। वहां रिक्शे देंगे आपको, जितने दे सकते हैं इस चुनाव तक, उतने देंगे और बड़ी तादाद में देंगे।

श्री मनीष असीजा–

बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। एक बात और है, आपके पास मैंने पहले भी इस बात के लिये निवेदन किया था कि कांच की चूड़ी का गड्डा बाजार करके फिरोजाबाद में सभी धर्म जाति वर्ग के लोग काम करते हैं। हिन्दू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं। वह लोग खुले में सवेरे 4 या 5 बजे आकर ठेलों में या डलियों में चूड़ी बेचते हैं सवेरे 10–11 बजे तक। अब जब दिन सर्दी के होते हैं, फिर भी रोजी–रोटी के लिये वह नागा नहीं करते। जब यह लू–लपट के दिन होते हैं तो भी वह 11 बजे तक लपटें झेलते हैं और जब बरसात होती है तो वह प्लास्टिक की बोरियां अपने सिर पर रख कर इस काम को करते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री मनीष असीजा–

ऐसे लाखों लोग हैं इनके लिये अगर एक सुविधायुक्त शेड बन जाये तो इसके लिये माननीय मंत्री जी आपका इनीशियेटिव ही होगा क्योंकि आपने कई बार भूमि के लिये प्रस्ताव मांगा है, लेकिन दुनिया जहां के काम हो रहे हैं, हवाई अड्डों की बात हो रही है, एक्सप्रेस–वे की बात हो रही है और लाख दो लाख गरीब आदमी हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है। मन में कसक आती है इसलिये साढ़े 3 लाख करोड़ के बजट के साथ अपना मन भरता नहीं दिखता यह मैं आपसे कहना चाहता था।

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक दो बिन्दु और हैं, उन्हें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे यहां जो यमुना के घाट हैं वहां पर प्राचीन शनिवार जी के जैन मंदिर, प्राचीन सूफी साहब का मजार और श्री हनुमान जी का प्राचीन मंदिर स्थित है और यहां पर प्रतिवर्ष बहुत बड़े मेले लगते हैं। सूफी साहब के मेले में लाखों लोग शिरकत करते हैं, हनुमान जयन्ती पर लाखों लोग वहां आते हैं और जैन धर्म के भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अगर उन घाटों को भी पक्का कर दिया जाय तो बहुत अच्छी बात होगी। फिरोजाबाद की वह एक सांस्कृतिक ऐसी पहचान है और यमुना जी का वह घाट है तो मैं समझता हूं कि सबको यह सुकून देने वाला रहेगा, यह राजनीति से अलग विषय है।

इसके अलावा दो–तीन मॉगे मेरी और हैं जिस पर आपका ध्यान चाहूंगा। हमारे यहां इंडस्ट्रियल स्टेट भाऊ का नगला की सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें बनवाया जाय। इसके अलावा नगर निगम, फिरोजाबाद के क्षेत्र में सैकड़ों मोहल्ले अनुसूचित बाहुल्य, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं, वहां सड़कें, नाली न होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को नारकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर होना पड़ रहा है, इन्हें तत्काल बनवाया जाय। इसके अलावा जनपद फिरोजाबाद में आलू की पैदावार को देखते हुये एक आलू आधारित उद्योग तथा आलू शोध संस्थान का निर्माण कराया जाय। इसके अलावा जिला हेड क्वार्टर पर एक राजकीय आई0टी0आई0 खोला जाये और 160 एम0वी0ए0 का दूसरा ट्रांसफारमर आफसाबाद बिजलीघर में तत्काल स्थापित कराया जाये।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, ई0एस0आई0 हास्पिटल गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सैंक्शन पड़ा हुआ है राज्य सरकार उसके लिए भूमि दे दे मैं इसकी अपेक्षा करता हूं। 400 केवीए बिजली घर के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मेरे द्वारा दिया गया है यह भूमि उपलब्ध करा दी जाए एवं मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए प्रस्तावित राजस्व विभाग की भूमि तत्काल प्रभाव से चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित की जाए। सुभाष तिराहे से दबरई जिला मुख्यालय तक नागरिकों की सुविधा के लिए सिटी बस सर्विस चलाई जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

कुंवर कौशल सिंह –

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, हम अभिभाषण की तो नहीं, राज्यपाल जी के क्रिया–कलापों की आलोचना करते हैं। अभी यहां चार साल बीत रहा है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर तो चर्चा हो सकती है लेकिन उनके क्रिया–कलापों पर टिप्पणी करने का विधान सभा को अधिकार नहीं है। आपसे निवेदन है कि इसको दिखवा लिया जाए क्योंकि अभिभाषण पर तो चर्चा हो सकती है लेकिन क्रिया–कलापों पर नहीं।

कुंवर कौशल सिंह–

मान्यवर, मेरा आशय बातों के क्रिया–कलापों से था। मैं महाना जी की ओर ही जा रहा हूं। अभी बात हो रही थी लैपटॉप और बिजली की, जब इसी सदन के अन्दर दो साल पहले लैपटॉप का वितरण चल रहा था तो यह कहा जा रहा था कि झुनझुना बांटा जा रहा है। जब इस देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो गोरखपुर के मानरेला की रैली में जा करके उन्होंने भाषण दिया और कहा कि यदि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो इस प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का काम करूंगा और इसे बिहार की जनता ने भी बखूबी सुना। इसके बाद जब वह प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार गये तो वहां भी कहा कि अगर मुख्य मंत्री हमारा बना तो 24 घंटे बिजली दूंगा और लैपटॉप बांटूंगा। तो यहां के नेता कहते हैं कि यह सरकार बुरी है और दिल्ली से चलकर नेता जी आते हैं तो कहते हैं लैपटॉप देना जरूरी है और जब लैपटॉप बांटा जाता है तो उस पर झुनझुना आ जाता है। चार साल का समय बीत गया, वहां से कहा जाता है कि किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर)

हम उस बात को बता रहे हैं आपको, आप सुनने की कुव्वत रखो, इधर से उधर जाने की प्रक्रिया आपके ही जमाने में अपनाई गई, जब कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, अभी बता देता हूं पैसे वाले दल में नहीं हूं पैसा दे करके टिकट नहीं खरीदता हूं और चप्पल उतार करके किसी के घर में नहीं जाता हूं और माथा टेक करके किसी को नमस्ते नहीं करता हूं मैं उस दल में हूं बस इतना जान लीजिए, विधायकी रहे चाहे जाए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, बात कीजिए, हम क्यों शब्दों को वापस लेंगे, आपके कहने से वापस लेंगे। बात होनी चाहिए मा0 अधिष्ठाता महोदय, जिसको तर्क करना है तर्क करके देख ले, इसी उत्तर प्रदेश के अन्दर 24 शुगर मिलों को बेचा गया था और इसी उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अन्दर यह कहा जाता है कि हम किसान विरोधी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप बात करके देखो, यहां महाना साहब बैठे हैं, किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाया जा रहा है। इस देश के प्रधान मंत्री ने बाहर से चीनी मंगा करके उत्तर प्रदेश के किसानों की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, मैं यह बताने के लिए आया हूं। बात की जाए तार्किक, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और उस समय अम्बेडकर योजना चलाई जाती थी, अम्बेडकर योजना के तहत इसी उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष की मंडी में काम किया जाता था आज गांवों को लोहिया ग्राम से जोड़ करके उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हर जाति विशेष को सुसज्जित करने का काम किया है। कहा जाता है कि मेरे यहां नहीं होता है, मैं कांग्रेस से विधायक हूं मेरे जिले में बहुजन समाज पार्टी से जी0एम0 सिंह विधायक हैं हर जगह आप जा करके देख लो कोई भी विधान सभा अगर लोहिया ग्राम से वंचित होगी तो राजनीति और विधायकी से इस्तीफा देने का काम करूंगा। मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं मैं बाहर की बात नहीं जानता हूं लेकिन बात तार्किक होनी चाहिए। हो क्या रहा है, कानून–व्यवस्था पर बात हो रही है, दिगही में 11 ब्राह्मणों को, आप गोरखपुर में हो मैं

महाराजगंज में हूं जय प्रकाश जी, मान्यवर, दिगही में 11 ब्राह्मणों को जिन्दा जला दिया गया और ये कहते हैं कि कानून–व्यवस्था कमजोर है। एस0एस0पी0 खड़ा रहा, पी0ए0सी0 खड़ी रही। लोग आग में झोंके जाते रहे। कल्याण सिंह जी की हुकुमत थी, मऊ के अंदर एक लड़के को जबरन वसूली के लिए डंडे से मारा गया और उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया गया था, यही मेरे बड़े भाई कुंवर अखिलेश सिंह विधायक थे मैं वहां बैठ करके उनका भाषण सुन रहा था। यह आपको बताना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय कि यह एक दूसरे पर कटाक्ष करने की बात नहीं है, कटाक्ष नहीं होना चाहिए, बात समाज को आगे ले जाने की होनी चाहिए। मैं इस बात पर सहमत हूं कि समाज को आगे ले जाया कैसे जाये ? समाज को आगे ले जाने के लिए उत्साह चाहिए, ज्ञान चाहिए, पैसे पर टिकट नहीं चाहिए। आदमी के अंदर यह भावना होनी चाहिए कि हम कैसे प्रदेश को आगे ले जायं ? हुआ यह, हम पूछते हैं यहीं पर लोग बैठे हुए हैं, पानी की बात की जा रही है, पानी नहीं मिल रहा है, हमको हैण्डपम्प नहीं मिल रहा है। भा0ज0पा0 की सरकार है हमारी ही सरकार केन्द्र में थी तो मैंने दिग्विजय सिंह जी से कहा कि आपके यहां खनन विभाग है आप चाहो तो हम लोगों को हैण्डपम्प दे सकते हो। महाना साहब हैण्डपम्प का रोना रो रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में भा0ज0पा0 की सरकार है, खनन विभाग के बजट का जो पैसा आता है उसका दो प्रतिशत आपदा के लिए कटता है और उस पैसे से चाहें तो महाना जी हम सबको हैण्डपम्प दिलवा सकते हैं लेकिन हर आदमी एक दूसरे पर आक्षेप करने की बात करता है। उस पैसे से चाहें तो सौर ऊर्जा हम लोगों को भी दिलवा सकते हैं लेकिन बात इसकी है कि हम दूसरे का विरोध करके उसके ऊपर सीढ़ी से चढ़ना चाहते हैं, यह हमारी परिपाटी बन चुकी है इस परिपाटी को खत्म किया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

कौशल जी, आपका समय समाप्त हुआ।

कुंवर कौशल सिंह–

जनता अच्छी तरह से जान रही है कि क्या होने वाला है ? हर आदमी एक दूसरे से कह रहा है कि हम भी राजकुमार हैं, हमारी सरकार आने वाली है, किसकी सरकार आयेगी, यह 2017 बतायेगा। लेकिन अधिष्ठाता जी, मेरा आपसे यह कहना है कि इस झगड़े को समाप्त किया जाए। एक प्रार्थना मेरा अधिष्ठाता जी, आपसे है कि हम लोग आखिरी वर्ष में जा रहे हैं, हर विभाग के बजट पर हर सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाय यह मेरा आपसे व्यक्तिगत सिफारिश है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

'श्री पूर्णमासी देहाती–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, श्री गुलाम

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

मोहम्मद साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उन्होंने हर बात पर प्रकाश डाला है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय कौशल किशोर सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सबको विकास की बात करनी चाहिए। मिलें तो बंद हुई, क्योंकि आज मिलों के बंद होने से किसान भी दुर्दशा झेल रहा है और मजदूर तो बेघर हो गये। मान्यवर, अभिभाषण में उत्तर प्रदेश सरकार की विकासोन्मुखी सभी बिन्दुओं को इंगित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जो विकास का काम कर रही है। जहां तक उन्होंने लोहिया ग्राम की बात कही है तो लोहिया ग्राम सबको दिये जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नारा है कि–'सबका साथ और अपना विकास'। तो उन्होंने सही कहा मा0 प्रधानमंत्री जी ने पड़रौना में भाषण दिया था कि मेरी सरकार बनेगी उसके दूसरे दिन पड़रौना चीनी मिल चलनी शुरू हो जायेगी यह प्रधानमंत्री जी ने कहा था लेकिन उसकी नीलामी की नोटिस टंग गयी है। वह तो हम लोगों ने किसी तरह से हटवाया है। तो हम निवेदन करेंगे भारतीय जनता पार्टी वालों से कि प्रधानमंत्री जी को यह याद दिला दें कि दूसरे दिन तो नहीं एक साल से ऊपर हो गया, अब तो वह मिल चल जाये और वह मिल भारत सरकार की है। कुशीनगर में दो मिलें थी कटकुइयां और पड़रौना। ये दोनों बी0आई0सी0 की मिलें हैं और कानपुर में शायद कपड़ा मिल भी उसका था मैं इसलिए कह रहा हूं कि राज्य सरकार ने कई मिलों को चलाने का काम किया है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। जबकि पड़रौना जिला मुख्यालय है और बहुत अधिक उसका एरिया है। तो साथियों चूंकि सभी लोगों ने इस पर चर्चा किया है और वह स्मार्ट शहर बना रहे हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम स्मार्ट गांव बनायेंगे। यह सही है कि गांवों से ही शहर बनता है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इधर गन्ना मूल्य का भुगतान काफी हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है तो हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में उसका भी प्राविधान किया है और उसका भी भुगतान हो जायेगा। सड़कें बन रही हैं, लेकिन जो हम लोगों को प्रधानमंत्री सड़कें मिलती थीं वह पता चला है कि अभी केन्द्र ने उसमें बजट नहीं दिया इसलिये उन सड़कों का प्राविधान इस साल नहीं हुआ तो मैं अपने साथियों से कहूंगा कि यह बात सबके लिये है और कौशल किशोर जी ने सही बात कही अगर भारत सरकार से कुछ आ जाय तो वह सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सभी का साथ और अपना विकास तो अगर बजट आ जाय तो सबका विकास हो जायेगा। क्योंकि उन्होंने सही बात कहा कि हम लोग आखिरी वर्ष में चल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री पूर्णमासी देहाती–

तो मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, हमने आपका ज्यादा समय नहीं लिया। इसी के साथ माननीय गुलाम मोहम्मद जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री उमेश पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता विरोधी दल माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा रखे गये संशोधन भाषण से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए अपनी बात आगे रखना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 110 पृष्ठों का यह सरकारी दस्तावेज मैंने पढ़ने का काम किया है, सिर्फ झूठ का पुलिन्दा इस सरकारी दस्तावेज में है। अधिष्ठाता महोदय, किसानों की हितैषी कही जाने वाली यह सरकार, आज किसानों के बारे में कितना चिन्तित है और इस वर्ष को किसान वर्ष के रूप में लेने का कार्य किया है। अभी हमारे भाई हमारे बगल के क्षेत्र के रहने वाले हैं और संयोग से वहां से विधायक हैं। बड़े ओजस्वी अंदाज में अपनी बात कह रहे थे, मैं जानता हूं अच्छी तरह से, मेरे बड़े भाई हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा–पत्रों में लिखा गया था कि जब हम सत्ता में आयेंगे तो किसानों का 50 हजार तक का कर्जा माफ करेंगे। (व्यवधान) मेरी बात सुन तो लीजिये, किया है आपने, तो मैं बता रहा हूं। मेरी बात तो सुनिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 50 हजार तक का कर्जा माफ करने की बात कही थी, किस बैंक का ? भूमि विकास बैंक का। मेरे पूर्वांचल से आप भी आते हैं। पूर्वांचल से मैं भी आता हूं। पूर्वांचल के भूमि विकास बैंक की दशा क्या है ? यह आपसे छिपी नहीं है। जिन परिस्थितयों में कर्जा माफ हुआ। हमारे किसान नेशनलाइज बैंकों से कर्जा लेने का काम किये थे उन नेशनलाइज्ड बैंकों से कर्जा लेने वाले किसानों का एक रुपया कर्जा माफ नहीं हुआ। यह किसानों के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है। मैंने क्यों कहा कि यह झूठ का पुलिन्दा है। इसी बात के लिये कहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे साथी ने कहा है किसानों की बात। गन्ना किसानों के साथ क्या हो रहा है, उनका भुगतान हो गया। किसानों को उनकी उपज का मूल्य उनके पास सही ढंग से पहुंच गया ? माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो सूबे में सरकार चल रही है उनको अपना विकास दिखाई दे रहा है। इटावा, मैनपुरी, सैफई, रामपुर, कन्नौज इसके अलावा और कहीं धरातल पर विकास शून्य है और ढोल पीट रहे हैं अपने हाथों अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। समय करीब आ रहा है, अन्तिम वर्ष है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने कहा था कि हम खेतों पर पानी पहुंचाने का काम करेंगे अपने घोषणा–पत्र मे, मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे, क्या किसानों को बिजली मिली ? क्या सही समय पर उनको उनकी उपज का मूल्य मिला ? क्या सही समय पर खाद बीज मिला, नहीं मिला, उनको लाठियां मिलीं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मैं फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज अभी भी वक्त है जो हमारे किसान पचास हजार का कर्जा नेशनलाइज्ड बैंकों से लिए हैं किसान आज इंतजार कर रहा है कि शायद सरकार इस अन्तिम वर्ष में हमारे हक में फैसला ले, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, किसानों का पचास हजार का कर्जा इस अन्तिम वर्ष में माफ किया जाए। माननीय अधिष्ठता महोदय, हमारे भाई ने, मा0 सदस्य गुलाम

मोहम्मद साहब ने कहा कि कानून का राज्य चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य कायम है और पूरा उत्तर प्रदेश अमन चैन से है। पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर शान्ति है माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अन्दर भय और आतंक का वातावरण बना हुआ है पूरा हिन्दुस्तान जान रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। आज मेरे भाइयों मेरे सम्मानित सदस्य, अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ किस अन्दाज में हुआ, आप सबको पता है अभी ब्लाक प्रमुख का चुनाव हुआ माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे पर बीती है मैं जानता हूं। ब्लाक प्रमुख के चुनाव में डी0एम0 से ले करके, एस0डी0एम0 से ले करके कोतवाल से लेकर के, डी0पी0आर0ओ0 से लेकर के अगर कहीं कोई कर्मचारी का रिश्तेदार क्षेत्र पंचायत का सदस्य था तो वहां दबाव बना करके..

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री उमेश पाण्डेय–

और प्रधानों द्वारा दबाव बनाकर के क्षेत्र पंचायत के सदस्य को दहशत में डालने का काम किया और अपने प्रत्याशी को जिताने का काम किया। इस तरह से दहशत बनाई जाती है और कहते हैं कि कानून का राज्य स्थापित है। मान्यवर, जिस तरह से यह सरकार चल रही है तो वह दिन दूर नहीं, आज लोहिया के नाम पर ढिंढोरा पीटते हैं लोहिया वादी बनते हैं लेकिन अगर आज लोहिया जी होते तो उनकी आत्मा रोती। मान्यवर, आज यह सरकार हर मुद्दे पर फेल है मैं अपनी बहन नेता कुमारी मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं। 2007 से लेकर 2012 तक उनकी सरकार बनी तो सदियों से मुरझाये हुए चेहरों पर मुस्कान लाने का काम हमारी नेता ने किया।.....

श्री अधिष्ठाता–

लिखा नहीं जाएगा।

श्री उमेश पाण्डेय–

ख्ा ग ग,

श्री अधिष्ठाता–

अब लिखा नहीं जाएगा।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन पर दो मिनट बोलना चाहती हूं महामहिम राज्यपाल ने अपनी सरकार की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि हम सबका विकास चाहते हैं विकास तो तब होगा जब उत्पादित माल में सबको हिस्सा मिले। जब रोजगार में वृद्धि हो दुःख के साथ कहना पड़ता है उत्तर प्रदेश में न कोई बड़ा उद्योग स्थापित हुआ है न आगे स्थापित होने का कोई अवसर दिखाई दे रहा है। यह सही है कि यह सरकार निवेश का

---

uksV %& [x x x] ;g va'k Jh vf/k"Bkrk ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

महौल बनाने में लगी हुई है छोटे–मोटे निवेश आ भी रहे हैं लेकिन ऐसा कोई निवेश नहीं है कि हम बड़े रोजगार की आशा लगाएं। सरकार के पास न तो कोई बेरोजगारी का आंकड़ा है न तो उसका कोई हिसाब–किताब है कि एक साल के अन्दर कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। राम भरोसे इसको छोड़ दिया गया है जितने लोगों को काम मिल जाएगा सरकार अपनी पीठ ठोंकेगी कि मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया है। खुद सरकार की ओर से रोजगार की कोई योजना इसमें दिखाई नहीं दे रही है। इसमें महिला सम्मान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है यह प्रशंसनीय काम है महिला प्रकोष्ठ योजना चाहिए खासतौर से जो तेजाब से पीड़ित महिलाओं को सहायता चाहिये। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि महिलाएं पीड़ित होती क्यों हैं और महिलाओं को पीड़ित करने वाले को क्या दण्ड मिलता है। अभी–अभी पता चला है कि एक पांच बच्चों की मां को घर में घुसकर दबंगों ने जिन्दा जला दिया। अभी दो दिन की बात है कि एक महिला जिसका 3.30 बजे आपरेशन होकर डिलीवरी हुई है उसको एक आदमी घुसकर सुबह के 6 बजे रेप कर देता है आई0सी0यू0 में घुसकर न कोई डर है न कोई भय है और अगर यह पकड़ा भी जाय तो आरोपी के विरुद्ध कोई गवाह नहीं मिलेगा जेल जाएगा भी तो छूट जाएगा और वह फिर अपनी राह चल देगा। ऐसा कोई माहौल नहीं बन रहा है जिससे दबंगों और बदमाशों में डर पैदा हो और वह समझें कि अगर हम यह करेंगे तो यह दण्ड भोगेंगे और इस प्रकार के बदमाशों के लिए न तो कोई गवाही होनी चाहिए न केस चलना चाहिए सीधे खुले सड़क पर उसको हैंग कर देना चाहिए। लेकिन कोई डर भय न होने के कारण लाख सरकार चिल्लाए कानून–व्यवस्था कायम करेंगे लेकिन कानून–व्यवस्था नाम की चीज उत्तर प्रदेश में नहीं है। सबसे ज्यादा पीड़ित यह महिलाएं हैं न यह घर में सुरक्षित हैं न बाहर सुरक्षित हैं। महिला समृद्धि योजना पेश की गई है महिलाओं के बारे में इतनी चिन्ता की गई है कि उनको तीन प्रतिशत पर ब्याज दिया जाय लेकिन हम पूछते हैं कि अगर हमीं को कोई लाख दो लाख रुपया दे तो हमारी समझ में यह नहीं आएगा कि हम इसको पूंजी के रूप में कैसे कन्वर्ट करें। किसमें लगाएं कहां पर लगाएं, जिससे हम उत्पादन कर सकें हम उत्पादित माल को कहां बेचेंगे यह दिशा–निर्देश चाहिए ऐसी कोई कमेटी ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि महिलाओं कों न केवल कर्ज दिया जाय बल्कि वह स्वावलम्बी बन सकें कोई उद्योग शुरू कर सकें देश की क्या मांग है बाजार की इस समय क्या च्वाइश है किस प्रकार की मांग चल रही है किस प्रकार की रुचि घूम रही है यह जानकारी दी जाए और उत्पादन सम्बन्धी उनको आवश्यक जानकारी दी जाय और उत्पादित माल के बिक्री की भी व्यवस्था की जाय क्योंकि महिलाएं यह काम स्वयं नहीं कर सकेंगी। सरकार ने स्वीकार किया है कि 166. 23 लाख हेक्टेएयर जमीन पर उत्तर प्रदेश में खेती होती है और जिसमें से 79 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित है और 47.80 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचन की क्षमता पैदा की जाएगी अगर सरकार की योजना शत प्रतिशत पूरी हो जाए तो भी उत्तर प्रदेश में 40 से 50 लाख हेक्टेयर जमीन असिंचित रह जाएगी और इसमें भी सबसे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि इस पर ध्यान इस प्रस्ताव में नहीं दिया गया है कि किस प्रकार से अनुर्वर

जमीन बढ़ती जा रही है। बनारस के आराजी लाइन और सेवापुरी ब्लाक डार्क जोन घोषित हो गया है काशी विद्यापीठ ब्लाक पर भी तलवार लटक रही है कारण क्या है कि विदेशी शीतल पेयजल कम्पनियों ने भू–गर्भ जल का इतना दोहन कर रही हैं कि पूरा का पूरा क्षेत्र अनुर्वर होता जा रहा है। केवल इसी दो ब्लाक में दो सौ बीघा जमीन अनुर्वर हो गई है। जिस दिन सरकार ने इसको डार्क जोन घोषित किया तीन चार साल हो गया तब से लेकर अभी तक कोई यहां नहर नहीं खोली गई न कोई उसकी शाखा लाई गई न कोई यहां हैण्ड पम्प लगा सकता है न कोई यहां ट्यूबवेल खोद सकता है सिंचाई के कोई साधन नहीं यहां तक कि पेयजल का साधन भी प्रतिबंधित हो गया है। लेकिन इन सब विषयों पर इस सरकार के कार्यक्रम में कोई गम्भीर चिन्तन नहीं किया गया है। सरकार द्वारा खाद उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है यहां फिर कहना पड़ता है कि सरकार इसके आंकड़े पेश कर रही है लेकिन केवल नाइट्रोजन खाद बढ़ रही है और फास्फेट और पोटैशियम के खाद वितरण में हम बहुत पीछे जा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसी तरह से उत्पादन के मामले में भी एकपक्षीय निर्णय हो रहा है उत्पादन वृद्धि होगा किस चीज का दाल का चावल का गेहूं का लेकिन गन्ने का नहीं। गन्ने का ग्रोथ रेट निगेटिव जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के लिये बहुत चिन्ता की बात है और सरकार के इस कार्यक्रम में इस पर भी चिन्ता नहीं प्रकट की गयी है। इस कार्यक्रम में सबसे उपेक्षित वर्ग यदि कोई है तो वह नगर विकास है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने नगरों को सरकारी कोटे से हटाकर केन्द्रीय सरकार के जिम्मे डाल दिया है। इस समय नगरों की हालत बहुत खराब है। वाराणसी में कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में चार वार्डों में गन्दा पानी आता था, जो पीने लायक तो दूर, नहाने लायक भी नहीं है। हम लोग उस पानी को बोतलों में भरकर जलकल विभाग के महाप्रबन्धक के कार्यालय में रख आये, लेकिन उन्होंने खारिज कर दिया कि सब ठीक है, टेस्ट में सब ठीक पाया गया है। आज वह बढ़कर 12 वार्डों में लगातार गन्दा और दुगर्न्धयुक्त पीला पानी आ रहा है, लेकिन इस बात को जब उठाया जाता है तो हमारे समक्ष 15 वर्षीय जल स्वच्छ करने की योजना पेश कर दी जाती है। 15 वर्षों में 05 वर्ष कहते–कहते बीत गये हैं और 10 वर्ष रह गये हैं अर्थात् 10 वर्ष बाद आने वाली नयी पीढ़ी को शायद स्वच्छ जल मिल जाये। इस समय तो सम्पूर्ण क्षेत्र पेट जनित रोगों से ग्रस्त होता जा रहा है, क्योंकि नलों में बहुत ही गन्दा पानी आ रहा है। स्वच्छ जल की व्यवस्था की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। वर्तमान में बनारस की जो सड़कें हैं वह इस समय टूटी–फूटी हैं। सीवर लाइन बजबजा रही हैं, सड़कों पर सीवर लाइन का पानी बह रहा है। सफाई और स्वच्छता की बहुत बुरी हालत है। इस कार्यक्रम में न तो सीवर लाइन बनाये जाने की कोई योजना है और न ही स्वच्छ जलकल की कोई योजना है। महामहिम श्री राज्यपाल ने इस सरकार के कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुये बताया है कि उनका उद्देश्य प्रदेश का विकास है। वित्तीय साधन विकास का एक बहुत बड़ा साधन होता है। वित्तीय व्यवस्था के द्वारा ही विकास की ओर बढ़ जाता है लेकिन सरकार केवल विभिन्न विभागों को रुपया बांटने में लगी है, सरकार वित्तीय साधनों के बंटवारे में इतनी उलझी हुयी है कि अपने लक्ष्य से

भटक गयी है। हमें दिखायी दे रहा है कि आने वाले दिनों में एक पक्षीय विकास होगा। यह विकास असंतुलित होगा, क्षेत्र में भी असंतुलित होगा, उद्योगों में भी असंतुलित होगा। समय रहते हमें चेत जाना चाहिये।

'श्री दिलनवाज खान–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं पठानों के पठान मा0 मंत्री जी श्री मोहम्मद आजम खां साहब को कि उन्होंने हमारे विधान सभा क्षेत्र में बुगरासी नगर पंचायत, खानपुर नगर पंचायत, बीबीनगर नगर पंचायत और स्याना नगर पालिका में कोई ऐसी सड़क नहीं बची है जो पक्की न हुई हो। मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देता हूं कि नगर विकास विभाग के माध्यम से हमारी नगर पंचायतों में काफी काम हुये हैं। हमारे स्याना विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसे कब्रिस्तान थे जहां गरीब मुसलमान सोच नहीं सकते थे कि वहां बाउण्ड्री हो सकती है, लेकिन हमारे पठानों के पठान मा0 आजम खां साहब ने वह बाउण्ड्रीवॉल करवायी है, जिसके लिये मैं इन्हें बधाई देता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीबीनगर–स्याना–बुगरासी मार्ग के चौड़ीकरण व निर्माण हेतु 37 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है और लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है, लेकिन प्राक्कलन–पत्र में जे0एस0बी0 सामग्री का प्राविधान है, जबकि जे0एस0बी0 सामग्री की जगह आर0बी0एम0 सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिसकी दर में लगभग ढाई गुना का अन्तर है। आर0बी0एम0 में लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक मिट्टी का भाग है, जिसके कारण सड़क का निर्माण घटिया मैटीरियल इस्तेमाल कर किया जा रहा है। इसलिये मेरी मा0 मंत्री जी से यह दरख्वास्त है कि जब आप इतनी धनराशि प्रदान करते हैं तो सड़क का निर्माण सही तरह से होना चाहिये ताकि सड़क 05 या 10 साल चल जाये, जिससे सरकार की भी तारीफ हो।

मान्यवर, एक और बात से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। जनपद बुलन्दशहर में जिला प्रशासन के द्वारा दिनांक 02–02–2016 को कमालपुर के युवक फराज, निवासी थाना कोतवाली देहात, जनपद बुलन्दशहर को धारा–151 में जेल भेजा गया था। जिसको आरोपित किया गया था, उस युवक फराज ने जिलाधिकारी, बुलन्दशहर की बिना मर्जी से उसकी सेल्फी ली थी। मैं भी इस बात को कहता हूं कि यह उस लड़के ने गलत काम किया था। लेकिन उसके बाद एक पत्रकार ने जिलाधिकारी महोदया को फोन किया और उन्होंने यह कहा कि मैडम, ऐसा–ऐसा प्रकरण हुआ है तो आपका क्या कहना है ? जो जिले की मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जो कि निन्दनीय है। उन्होंने यह कहा कि मेरे पास ऐसे लोग हैं कि मैं वहां जाकर तुम्हारी मां और बहनों की फोटो खिंचवा सकती हूं। अगर कोई एक पत्रकार सीधा सा सवाल पूछ रहा है तो उन्हें सीधा सा जवाब देना चाहिए था। मैं आपसे एक और बात

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

कहना चाहता हूं कि जिला प्रशासन द्वारा एक जनमत संग्रह करवाया गया, अगले दिन और यह कहा गया कि हंड्रेड परसेण्ट जनमत संग्रह में लोग हमारे साथ हैं। लेकिन मान्यवर, जनमत संग्रह में जो लोग आए थे, वह शहर के ज्वैलर्स थे, पेट्रोल पम्प के मालिक थे और कई ऐसे लोग थे जो जिला प्रशासन के साथ चलने का काम करते हैं। फिर वहां पर ए0डी0एम0 (प्रशासन) द्वारा कहा गया कि कैंडिल मार्च का जुलूस निकाला जायेगा। फिर वह कैंडिल मार्च का जुलूस निकाला गया और उसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि बुलन्दशहर में धारा–144 लगी हुई थी, उसमें ए0डी0एम0 (प्रशासन) भी कैंडिल लिए हुए वहां पर मौजूद थे, उस जुलूस में और मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, यह दैनिक जागरण का आफिस था, वहां पर दो ट्रक कूड़े के डलवा दिए गए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

देखिए, जब इनकी सेहत इससे कहीं ज्यादा अच्छी थी, अब तो इन्होंने वजन कम किया है। जब यह मोटे–ताजे थे और अब से ज्यादा सुन्दर लगते थे, तब इनके जिलाधिकारी से बहुत अच्छे रिश्ते–ताल्लुक थे। ये दुबले क्या हुए कि रिश्ते भी जाते रहे।

श्री दिलनवाज खान–

मान्यवर, मैं भी पठान का बच्चा हूं, तो सच के सिवाय कुछ नहीं बोलता हूं, जो मुझे सही लगा, वह मैं बोल रहा हूं। दफा–144 लगी हुई थी, जिला प्रशासन ने कैसे जुलूस निकलवाया और ए0डी0एम0 (प्रशासन) कैसे जुलूस में शामिल हुए और जो पत्रकारों के ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है, मैं आपसे मांग करता हूं, वह वापस होनी चाहिए और मैं इसके लिए मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, धन्यवाद।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, आपने मुझको महामहिम राज्यपाल जी द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर अपना भाषण देने के लिए कहा है। प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी जो आपातकाल के लोकतंत्र सेनानी थे, जो सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, उनको 15 हजार रुपया मासिक सम्मान राशि देने का एलान किया है। जब इस देश में आपातकाल लगा था, पूरा देश जेलखाना बना दिया गया था, जो अत्याचार और अन्याय की सारी सीमाएं तोड़ दी गयी थीं और उस समय हम लोग 20 महीने आपातकाल में जेल के अन्दर बन्द रहे थे। पत्रकारों को अपनी बात कहने पर रोक लगा दी गयी थी और पूरे मीडिया पर बैन लगा दिया गया था। 40 सालों के बाद प्रदेश सरकार ने जो आपातकाल के सेनानी हैं, उनको 15 हजार रुपये मासिक पेन्शन देने का काम किया है। मान्यवर, ऐसे ही जो समाज के सबसे गरीब, निराश्रित, बेसहारा, असहाय महिलाएं हैं उनके जीवन यापन के लिए बड़े प्रयास की आवश्यकता है।

उनको पेंशन मिले उसके लिए समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत उनको पेंशन मिलने का काम हो रहा है और उनकी संख्या बढ़ाकर 40 लाख से 45 लाख की गयी थी और अब 55 लाख की घोषणा की गयी है। आपके माध्यम से यह अनुरोध करना है कि जो घोषणा की गयी है उतनी पेंशन निराश्रित महिलाओं को मिले इसके लिए भी

आपकी पीठ से ऐसे आदेश होने चाहिए। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध है कि जो कोटा पिछले वर्ष तय हुआ था 45 लाख का वह कोटा अभी तक पूरा नहीं हुआ। उस कोटे को पूरा करने का काम कराया जाये। दूसरी बात यह है कि जो निराश्रित विधवा हैं उनमें 16 लाख लोगों को पेंशन देने की घोषणा की गयी है। ऐसे ही जो निराश्रित वृद्धा हैं उनको 39 लाख को पेंशन देने की घोषणा की गयी है और 08 लाख विकलांग लोगों को पेंशन देने की घोषणा की गयी है लेकिन मान्यवर, यह अनुरोध है कि जो निराश्रित विधवा, वृद्धा और विकलांग लोग हैं उनको 300 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। 300 रुपये में कोई निराश्रित विधवा, असहाय महिला कोई अपाहिज विकलांग अपने पूरे परिवार का पेट नहीं पाल सकता है। यह पेंशन राशि 300 से बढ़ाकर कम से कम 1000 रुपये करने का काम हो। मान्यवर, कई और जनहित की घोषणायें की गयी हैं। मान्यवर, हम लोगों का यह प्रयास है कि प्रदेश में पूरी तरह कानून का राज कायम हो। लेकिन कुछ स्थानों पर ऐसी घटनायें होती हैं जिन्हें रोके जाने की आवश्यकता है। अभी 13 तारीख को अम्बेडकरनगर में जन संदेश टाइम के ब्यूरो चीफ करूण मिश्रा की दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी। अभी तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुये हैं। वह हत्यारे गिरफ्तार हों उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा हो। उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले। मान्यवर, ऐसे ही लखनऊ शहर में अभी–अभी एक महिला बेटी का पांच दिन पहले अपहरण हुआ। हम लोगों ने यह कहा कि उस बेटी का अपहरण हुआ है पता लगाया जाये लेकिन पांच दिन पहले उसका अपहरण करने के बाद बलात्कार हो गया, लेकिन पुलिस द्वारा उसका पता नहीं लगाया गया। अभी–अभी खबर मिली है कि उस बेटी की लाश बरामद हो गयी है। तो जो ऐसे अपराधी लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो पुलिस के लोग लापरवाही करने का काम करते हैं उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे प्रदेश में पूरी तरह कानून का राज कायम रहे ताकि जनता पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, हम लोग यह चाहते हैं कि अगर हमारी बेटी और बहन के साथ कोई दुराचार करने, दुस्साहस करने का काम करे तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो उन्नति बेटी का अभी–अभी शव मिला है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो लोग उसके बलात्कार और हत्या के दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, आज प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में शहरों में 24 घण्टे तथा गांवों में 18 घण्टे बिजली मिलने का काम हो। कानून–व्यवस्था में सुधार के लिए भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है इसके लिए और तेज प्रयास किये जायें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका लिखा नहीं जाएगा।

(इस बीच श्री जय प्रकाश निषाद और श्री रविदास मेहरोत्रा दोनों सदस्य एक साथ बोलते रहे। इस बीच श्री रविदास मेहरोत्रा जी का माइक आफ होने के कारण उनका भाषण सुना नहीं जा सका।)

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका नहीं लिखा जायेगा। श्री जय प्रकाश जी आप बोलें।

'श्री जय प्रकाश निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मा0 नेता प्रतिपक्ष जी के संशोधन पर बल देते हुए अपनी बात रखता हूं। मान्यवर, आज इस सदन में इस बात को सुनकर बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सत्तापक्ष के हमारे मा0 सदस्य महोदय अपना रोना रो रहे हैं। लगता है कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार बिलकुल सो गयी है और बहरी गूंगी हो गयी है। यह बहुत गंभीर प्रश्न है। हमारे सत्तापक्ष के मा0 विधायक महोदय श्री रविदास मेहरोत्रा साहब बड़े दुःख के साथ अपनी बात रख रहे थे और यह जाहिर करता है कि इस प्रदेश में सरकार की हालत बहुत खराब है, हमारे इस प्रदेश के जहां मुखिया रहते हों, मुखिया के बगल में एक गरीब परिवार की बेटी की हत्या हो जाती है, लाश कई दिन तक ढूंढी जाती है और इतने बड़े सूबे का जो शहर हो, उत्तर प्रदेश जो भारत का एक सबसे बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश की राजधानी में और इस प्रदेश के मुखिया के घर के बगल में किसी एक गरीब परिवार के बेटी की लाश मिलती है और उस पर कार्यवाही नहीं होती है और इसका इजहार सत्ता पक्ष के मा0 विधायक करते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि इस प्रदेश की कानून–व्यवस्था पूरी तरह से लचर और चरमरा गई है। उस व्यवस्था पर हम लोगों को लानत है, हमारे बीच में आज कई सदस्य इस बात को कह रहे थे, आज हमारे बीच में हमारे सदस्य विपक्ष के श्री कौशिल किशोर जी बोल रहे थे, अभी यहां मौजूद नहीं हैं, मैं जानता हूं, हमारे बगल में महराजगंज है, इनके एक सगे भाई समाजवादी पार्टी की नुमाइन्दगी करते हैं और यह स्वयं कांग्रेस की नुमाइन्दगी करते हैं, लेकिन यह बात वहां साबित होती है कि करते तो कांग्रेस की है, लेकिन इनकी गाड़ी में झण्डा किसका लगता है, वह मैं नहीं बताऊंगा, वह खुद जानते हैं। जीतते किससे हैं और तरफदारी किसकी करते हैं। मान्यवर, हम इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं, हमें भी दुःख हुआ, मेहरोत्रा साहब की बात पर, मैं चाहूंगा हमारे सरकार के भारी–भरकम और एक प्रभावशाली मंत्री

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

जिनकी एक इमेज है, ऐसे एक मा0 मंत्री हम लोगों के बीच में इस सदन को सम्भालने का काम करते हैं, सदन को समझने का भी काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति यहां मौजूद हैं, उनके कानों में यह बात जरूर गई होगी, मैं चाहूंगा कि उनकी बात का निस्तारण तत्काल कराया जाय और अंकुश लगाकर के ऐसे अपराधियों को तत्काल जो भी समुचित सजा हो, वह सजा दिलाने का सरकार प्रयास करे। आज हम नेता प्रतिपक्ष के इस प्रस्ताव पर बल देते हुए तमाम बातें सरकार की बताना चाहूंगा, प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी, तो आज इस सूबे के जो मुखिया हैं, इन्होंने घूम–घूम कर पूरे प्रदेश में अपनी बात का ऐलान किया और कहा उस बात को हर गरीब परिवार के लोग आज टकटकी निगाह से बैठे देख रहे हैं, आज चार साल हो गये, लेकिन उस पर जरा सा भी अमल नहीं हुआ। अमल की बातें अगर करें तो तमाम ऐसे समुदाय के लोग हैं, जिनके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ने की बात कही थी और जिनके लिए कुछ करने की बात कही थी, लेकिन आज तक पटल के ऊपर उन्हें नहीं लाये, उनके प्रति इस तरह की सम्वेदना जताया था और वह पूरा समुदाय एक तरफ टकटकी लगाये बैठा है, 17 जातियों को इन्होंने कहा था, ऐलान करके कहा था पूरे प्रदेश में, जब मेरी सरकार आयेगी, यह सरकार आपकी विरोधी है, जब मेरी सरकार आयेगी तो 17 जातियों को मैं अनुसूचित जाति में शामिल कराने का काम करूंगा, लेकिन जब इस सदन में मैंने सवाल लगा कर के पूछा तो सवाल के जवाब में आया कि यह काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती है, इस देश की सरकार कर सकती है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, जब ऐसी बात थी तो एक समाज को गुमराह करने का काम नहीं करना चाहिए, उसको सही रास्ता बताना चाहिए और सही रास्तों पर चलना चाहिए। मा0 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनकी नीतियों पर बहुजन समाज पार्टी चलती है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उसकी बदौलत आज इस सदन तक पहुंचने का मौका मिला और यह गरीब समुदाय के लोग हर वर्ग के लोग आ करके यहां अपनी बात रखने का काम करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत सी बातें ऐसी नहीं कही गईं जिससे आज इस सूबे का गरीब तबका, निचले तबके के लोगों के लिए कोई फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रही हो, भारी पैमाने पर उस गरीब, दबे–कुचले समाज के लोगों को किसी तरह रोजी–रोजगार मिला और उनको अपनी नौकरी में जाकर के प्रमोशन कर के आगे बढ़ कर के काम करने का अवसर मिला था और उन लोगों को भारी पैमाने पर कई लाख लोगों को डिमोशन कर के और नीचे ला दिया गया और उनके आगे बढ़ने का, उनके अच्छे कार्य करने की जो भी बातें थीं उसमें उनको संकुचित कर दिया गया। उनकी रोजी–रोटी, उनके आगे बढ़ने का, उनके अच्छे कार्य करने का जो भी बातें थीं उसमें उनको संकुचित कर दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, अभी हमने पांच मिनट भी नहीं बोला है। सिर्फ दो मिनट बोला है, आप देख लें। अगर कहें तो मैं बैठ जाता हूं। कोई ऐसी बातें नहीं है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज पूरे प्रदेश में तमाम ऐसी बातें हैं, जो संशोधन प्रस्ताव में होना चाहिए, वह नहीं है। जो चौरी–चौरा क्षेत्र में दिया हुआ फाटक है वहां पर हमने संशोधन के लिए चार साल लिख कर दिया लेकिन अभी तक नहीं हुआ और उसमें रेलवे क्रासिंग है। क्रासिंग पर आए दिन वहां घटनाएं घटती रहती हैं। वहां पर बहुत–सी घटनायें घट गयी। कई बार तो उसमें जीप में दस–दस लोग एक साथ एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन सरकार ने उनको मुआवजा तक नहीं दिया। उस पर उपरिगामी पुल बनाने की मैंने कई बार बात कही लेकिन आज तक सरकार ने वहां जरा–सा भी कुछ सोचने का काम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं उस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा सहभागिता रही है। पांच बार लगातार वहां की विधायक रही हैं लेकिन वहां पर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आज तक नहीं हो पायी वह कछार क्षेत्र कहा जाता है। जब वहां पर बाढ़ आती है तो बाढ़ के कहर से उस दोआबा क्षेत्र के लोग प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने पर उनको वह सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाती है। बन्धे सभी जर्जर हो गए हैं। सिंचाई विभाग पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री जय प्रकाश निषाद–

महोदय, मैं अपने क्षेत्र की समस्या रखना चाहता हूं इसको जरा सुन लें। उसके बाद अगर इसमें भी नहीं बोलने देंगे तो हम लोगों को कब अवसर मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

पहले आपको अपने क्षेत्र के बारे में बोलना चाहिए था। चलिए खत्म करिए।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जितने बन्धे हैं सारे जर्जर हो चुके हैं। एक तरफ से राप्ती नदी है और दूसरी तरफ से गुर्रा नदी है और एक तरफ से बड़ी नदी आती है। तीन–चार नदियों का आपस में दोआबा है, इसमें जितने बन्धे हैं, सारे बन्धे जर्जर हो गए हैं चार साल में बन्धों का अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। यह बन्धे जब भी बाढ़ आएगी टूट जाएंगे। बहुत भारी पैमाने पर जनहानि हो सकती है। आखिरी बात रखना चाहता हूं कि मधुवा थाने में 17 तारीख को एक घटना होती है जिसमें अपराध संख्या–98/16 धारा 436, 427, 504, 506 एस0सी0, एस0टी0 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन पर आपने हमको बोलने के लिए मौका दिया गया इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। मान्यवर, हर सरकार अपने को जन कल्याणकारी सरकार कहने की कोशिश करती है और इस विषय को रखती है। यदि इस सरकार को कोई नाम देना हो तो नाम देना पड़ेगा, चिढ़ने वाली सरकार, चिढ़ाने वाली सरकार, बदला लेने वाली सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार। और यदि आपको इसका उदाहरण तलाशना हो तो कहीं दूर नहीं जाना है। इस विधान सभा के बहुत ही सम्मानित आदरणीय सदस्य, जिनको सारे लोग बड़े आदर से देखते हैं उनके सामने अभी चार दिन पहले इसी विधान सभा में जब विपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी वेदना कह रहे थे, उपयुक्त हो या अनुपयुक्त हो, आप स्वीकार करें या न करें यह अलग बात है लेकिन उनको सुनकर उनके साथ सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बजाए चिढ़ाने का काम हो रहा था उनके पास, जिसके पास गार्जियनशिप की कुर्सी है। जिनके पास यह कलेजा होना चाहिए कि पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है इसलिए सबको सुनेंगे, समझेंगे। सुनना–समझना तो दूर वह चिढ़ा रहे थे, और कहो और नारा लगाओ। क्या है, कौन कह रहा है सरकार की उस कुर्सी पर बैठा हुआ सम्मानित व्यक्ति जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी गार्जियन की है। वह गार्जियनशिप का निर्वाह न करके चिढ़ा रहे थे। इस सरकार की नियति चिढ़ाने की बन गयी है।

मान्यवर, अभी हमने महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ा। उसमें केन्द्र सरकार के कृत्यों को अपने खाते में जोड़ना और असहयोग की बात को लेकर रोना। रोना ही प्रमुख है। आप पूरे अभिभाषण को पढ़ लें, कम से कम चार–पांच बार इसका उल्लेख किया गया कि केन्द्र सरकार ने यह नहीं किया, केन्द्र सरकार वह नहीं किया। जो किया उसको तो आप अपने खाते में जोड़ ले रहे हैं लेकिन जो नहीं किया या जो किसी कारण से टल रहा है। उसमें यह नहीं किया, वह नहीं किया, दूसरे के खाते में डालने का काम हो रहा है। अभी हम इनकी यह पुस्तक पढ़ रहे थे। इसमें इन्होंने पृष्ठ–5 पर एक चीज कही कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को हमने सड़क से जोड़ दिया है, जोड़ने की हमारी योजना है। मैं इस पर दो निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, नितिन गडकरी जी बाराबंकी में आए थे। हमारे जिले बहराइच का यह सौभाग्य है कि हमारे यहां से दो–दो मंत्री हैं और पहले जरवल से लेकर नेपालगंज तक जाने में 4 घण्टे लगते थे। 10 साल तक एन0एच0 और एस0एच0 का झगड़ा लटका रहा। आज एक ही वर्ष में वह सड़क ऐसी हो गई है कि ठीक दो घण्टे में 150 कि0मी0 की यात्रा पूरी हो जाती है। इसको ये यहां भले न स्वीकार करें लेकिन हमारे दोनों मंत्रियों को मानना पड़ेगा कि जो यहां इस राज्य सरकार में हैं कि अगर यह सड़क न बनी होती तो उनको यहां आने में बड़ी दिक्कत होती। पहले बड़ी दिक्कत थी। मान्यवर, यह सब किया लेकिन उसी समय हम लोगों ने एक सड़क की घोषणा कराई थी। जरवल से गोण्डा होते हुए बलरामपुर से उतरौला और कहा था कि इसकी एक बार एन0ओ0सी0 मिल जाए। जैसे ही हम लोगों ने एन0ओ0सी0 का जिक्र किया, एक घोषणा हो गई कि इसको हम फोर लेन बनाएँगे।

कब बनाएँगे 2017 आ रहा है, तब तक तो नहीं शुरु होने वाली है, शुरू करने की नौबत तो आयी नहीं। किसी चीज को जो कर रहे हैं, उसको टांग अड़ा कर रोकना, यह विकास की बात कहां है। आप नहीं कर पा रहे थे, दूसरा करने की घोषणा कर रहा था, करने तो देते। एक बार मौका मिल गया, आप देख रहे हैं जरवल से नेपालगंज तक जाने की जो सड़क है उसको देखकर आप आश्चर्यचकित होंगे। अभी एक सत्ता पक्ष के मेरे मित्र कह रहे थे, एक सज्जन कर रहे थे कि हमारे यहां कोई सड़क बाकी ही नहीं है, सड़क के लिए जगह तलाशनी पड़ती है। मैं अपने यहां गारण्टी से कह सकता हूं कि 10–10 कि0मी0 सड़क, धूल उड़ाती हुई सड़क हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर हालत में हम लोगों की लिखी हुई कोई सड़क आज तक हुई नहीं। जनेश्वर मिश्र योजना की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सूची से लिया जाता है। सूची से तो लिया जाता है लेकिन सूची में वे गांव लिए जाते हैं जिनको हमने न लिखा हो। चाहे वह जनेश्वर मिश्र योजना हो, चाहे लोहिया योजना हो। 4 साल हो गए, कम से कम 4 बार लिखा होगा लेकिन एक भी सड़क, एक भी जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में, एक भी लोहिया ग्राम में लिया गया हो, एक सिंगिल भी लिया गया हो तो मैं उदाहरण दे सकता। मैं यह मानने के लिए तैयार हो जाऊँगा कि यह सरकार कम से कम सबकी सुन रही है। एक भी नहीं लिया गया है। मान्यवर, कहां से मैं इस बात को मान लूँ कि ये सबकी सरकार है, सबको सुनने वाली सरकार है। ये पृष्ठ–9 पर सबकी सुरक्षा की भावना की बात कर रहे हैं लेकिन वह सुरक्षा भावना की स्थिति तो आपने देख ली। अभी हमारे आदरणीय रविदास मेहरोत्रा जी जिक्र कर रहे थे अम्बेडकर नगर का। अभी जिक्र कर रहे थे लखनऊ प्रॉपर का। इन सारी वेदनाओं में वह वेदना छिपी नहीं है क्या ? क्या नहीं दिख रहा है कि कितनी असुरक्षा भरी पड़ी है ? ये किसान की बात करते हैं। बहराइच में कोई किसान धान क्रय केन्द्र खुला क्या? धान की खरीद हो गई, पूरी हो गई, कोटा पूरा हो गया। एक भी कॉटा नहीं खुला, कोई कॉटे पर किसान नहीं गया, कोई बैलगाड़ी नहीं गई और ताले लटके रहे। अखबारों ने छापा कि क्रय केन्द्रों पर ताले लटके हैं, कॉटे हैं लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं। इसके बावजूद धान की खरीदारी का सब पूरा हो गया। ये हमारी स्थिति है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि कल से हमारे यहां बरबलिया गांव के 5 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं इसलिए आमरण अनशन पर बैठे हैं क्योंकि उनके घर जल गए और उनको कुछ भी मुआवजा नहीं मिला। हमने पता किया, कल मैं उस आमरण अनशन पर गया और पता किया कि क्या बात है तो उसकी अगुवाई कर रहे हैं गौतम जी। कहा कि गौतम अगुवाई करेगा उसके बाद में सहायता मिल जाएगी। माने, यदि कोई गौतम है तो क्या वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं है। उसकी अगुवाई में सहायता आन्दोलन चलेगा तो नहीं मिलेगा घर जल गया तो जल जाने दो। यह स्थिति है चिढ़ने और वेदना की। मान्यवर, किसी भी तरह से इस सरकार में जनता के हित की बात नहीं कही जा सकती। एक चीज की मैं जरूर सराहना करना चाहूंगा आपातकाल में जिन लोगों को जेल हुई उनके लिए जो किया गया है। भले आपातकाल में मेरा पूरा घर गिरा दिया गया था, पूरा गिरा दिया गया था,

मैं जेल नहीं जा पाया, इसलिए मैं उस केटेगरी में नहीं हूं, लेकिन पूरी दीवार गिराकर हम लोगों के घर को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन उस आपात काल के लिए जो 15 हजार की धनराशि दी है, इसके लिए मैं इस सरकार के खाते में धन्यवाद की बात रखूँगा लेकिन बाकी हर कदम पर फेल, किसान के लिए फेल, सुरक्षा के लिए फेल, दुर्भावना की पराकाष्ठा। सरकार गार्जियन की भूमिका में आए और पूरे उत्तर प्रदेश को एक साथ देखे और इस तरह में अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, सरकार की इतनी सक्रियता और इतना विश्वास है कि 10 प्रतिशत कोरम विधान सभा में नहीं है। या तो आप कोरम की घंटी बजवा दीजिए। आपसे मेरा निवेदन है कि 40 लोग भी नहीं हैं, अभी मैंने गिना है। कोरम पूरा नहीं है, या तो आप कोरम की घंटी बजवा दीजिए ताकि सरकार के कानों में उसकी बात चली जाए। सरकार के लोग ही सरकार की बात नहीं सुनना चाहते, यहां पर तो फिर भी लोग ज्यादा हैं।

श्री अधिष्ठाता–

पीछे बैठे हैं लोग आगे आ जाएं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, पीछे बैठे लोगों को माना नहीं जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

हॉ, बुला रहे हैं, बुला रहे हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, अभी भी नहीं हैं, मैंने गिन लिये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आ रहे हैं, आ रहे हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, अभी भी नहीं हैं, कुछ और को बुलवा लीजिए। दो–चार पांच सदस्यों को और बुलवा लीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

अब आ गए हैं, कालीचरन सुमन जी आप बोलें।

श्री काली चरन सुमन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं हमारे विपक्ष के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देने के लिए मैं आपके बीच खड़ा हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2012 समाजवादी पार्टी के

नेतृत्व में यह कहकर सरकार बनी थी कि हम इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, इस प्रदेश को हम खुशहाल प्रदेश बनाएंगे, इस प्रदेश को हम विकासयुक्त प्रदेश बनाएंगे। यह कहकर यह नारा देकर यह सरकार बनी। इस प्रदेश के मुखिया देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस प्रदेश के मुखिया देखने में बड़े भोले–भाले लगते हैं। इस प्रदेश के मुखिया देखने में तो बड़े स्वभाव वाले लगते हैं, परन्तु जब से प्रदेश में इनके नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से दिन–प्रतिदिन इस सरकार का ही नहीं इस प्रदेश का जो विकास की गति होनी चाहिए थी, जो उन्नति की गति होनी चाहिए थी, वह निम्न स्तर पर जा रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो बातें रह गई हैं, उनके सम्बन्ध में मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, चार–पांच बिन्दु हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगा कि मुफ्त पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई और दवाई इस सरकार का नारा था। जब पढ़ाई स्कूलों में हो ही नहीं रही है, किस बात की मुफ्त पढ़ाई है। जब अस्पतालों में दवाई मुफ्त मिल ही नहीं रही है तो किस बात का यह नारा है। जब नहरों में पानी नहीं है, नहरों में पानी टेल तक पहुंचता ही नहीं है, तो किस बात का यह सिंचाई मुफ्त का नारा है। इसीलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार का केवल ढोकला है, यह सरकार का झूठ का पुलिन्दा है। यह माननीय राज्यपाल का अभिभाषण है, निराधार और असत्य है, इसलिए हम इसकी आलोचना करते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोहिया ग्राम के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। मैं लोहिया ग्राम के बारे में कहना चाहता हूं कि यह समाजवादी पार्टी की सरकार वाले लोहिया जी को तो मानते हैं, पर लोहिया जी की बात को नहीं मानते हैं। लोहिया जी ने कहा था कि हर व्यक्ति का समान अधिकार होना चाहिए। हर व्यक्ति को समान विकास का अधिकार होना चाहिए। मेरे क्षेत्र में दो लोहिया ग्राम चयनित किये गये थे, वह भी अधूरे छोड़ दिये गये हैं। एक लोहिया ग्राम सरनखेड़ा जो बरौलीअहिर के अंतर्गत आता है वह मेन रोड से लेकर के एक वेदूराम के घर तक सी0सी0 काम अधूरा छोड़ दिया है। हम उन दिनों की याद दिलाना चाहते हैं जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, उस समय अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत गांवों के नाम चयन किये जाते थे। चाहे किसी भी व्यक्ति के घर से लेकर, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो उस ग्राम का पूरा विकास होता था। परन्तु आज लोहिया के नाम पर खानापूर्ति करके यह सरकार लोहिया जी का अपमान करने का काम कर रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय समाजवादी पेंशन के सम्बन्ध में कहना है कि यह सरकार नकल करने में बहुत माहिर है। जो योजना बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने महामाया पेंशन योजना के नाम से लागू की थी, उसी का स्वरूप लेकर समाजवादी पेंशन योजना लागू कर दी। एक साल तो यह कहकर टाल दिया गया था कि इसका स्वरूप बना रहे हैं। एक साल यह कहकर टाल दिया था कि हम चयन कर रहे हैं। वास्तविकता, हकीकत यह है कि आज तक उन गरीब महिलाओं को जो पेन्शन मिलती थी उनके खाते में नहीं जाती है। अधिष्ठाता महोदय, कहनी कुछ है और करनी कुछ। कृषि विपणन, कृषि के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में, कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, ग्रामीण अन्चल आता है और किसान लोग अपनी मण्डियों में जाते हैं, मेरे क्षेत्र की तमाम ऐसी सड़के हैं जो मण्डी परिषद द्वारा बनाई है,

आज उनकी हालत इतनी खराब हैं कि किसान लोग चल नहीं सकते हैं। एक सड़क है कबूलपुर से लेकर नगलाशासिया ककरारी तक मैने तमाम योजनाओं मे नियमों के अन्तर्गत दिया था कि इस सड़क का निर्माण कराया जाये परन्तु अधिष्ठाता महोदय एक तरफ सरकार कहती है कि संसाधनों की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है जब हम नियम–51 और 301 लिख कर देते हैं जवाब मिलता है कि संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है, संसाधन हो जायेंगे तब बनेगी। अधिष्ठाता महोदय, यहां कथनी और करनी में अन्तर नहीं तो और क्या है ? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना का अभिभाषण में जिक्र किया गया है। हमारी बाईं तरफ लोग बैठे हैं, यह कहते थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में सरकार आयेगी हम अच्छे दिन लायेंगे, इनके तो अच्छे दिन नहीं आये। आज करीब दो साल उस सरकार को बने हुए हो गये और चार साल इस सरकार को बने हुए हो गये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जो सड़के चयनित हुईं हैं उन पर एक ढेले का काम नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र मे दो सड़के थी, शमसाबाद रोड से अकबरपुर बुढेरा तक दूसरी रोहता ग्वालियर रोड से लेकर बहमरौली अहीद तक आज तक उसमे ढ़ेले का काम नहीं हुआ, गड्ढे बने हुए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार जो कहती थी, अच्छे दिन आयेंगे उनके अच्छे दिन नही आये और चार साल में इनका भी वादा पूरा नहीं हुआ। अधिष्ठाता महोदय मै निवेदन करना चाहता हूं कि इसको अमल किया जाये इसमें कार्यवाही की जाये। अधिष्ठाता महोदय पेयजल ग्रामीण योजना महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर यह ग्रामीण पेयजल योजना का जिक्र किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 241 टी0टी0एस0पी0 की टंकिया स्थायी रूप से खराब पड़ी हुई हैं। आज चार साल हो गये एक भी टंकी चालू करने का काम नहीं हुआ। 125 टी0टी0एस0पी0 टंकिया जो सरकार मे स्वीकृत हैं पर आज तक नही लग पाई हैं, मै निवेदन करना चाहता हूं कि 125 टी0टी0एस0पी0 टंकिया जो स्वीकृत हैं जिसका पैसा जिला स्तर पर है, चालू कराईं जायें। माननीय अधिष्ठाता महोदय लोक निर्माण विभाग के मामले में कहना चाहता हूं। लोक निर्माण विभाग मे 250 से लेकर 500 तक जो गांव, बसावटें थी उनको जोड़ा जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं 2013–14 मे एक सड़क स्वीकृत हुई थी, जिसका नाम था बुड़ाना मुस्तकल से लेकर नंगला जाटव तक उसका पैसा भी स्वीकृत हो गया था 2013–14 मे, 10 लाख रुपये के करीब वहां पहुंच भी गया था परन्तु आज तक वह सड़क नहीं बन पायी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कहां कमी होती है, नौकरशाही सुनती नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस पर कार्यवाही की जाये। अधिष्ठाता महोदय कानून–व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा कि आज यह विकराल समस्या है। कानून–व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं यह पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार ढेर हो चुकी है और समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं भी आप पता कर ले, किसी भी जगह पता कर ले, चाय की दुकान में पता कर ले, रेलवे में पता कर लें, सारे लोग कह रहे है यह पहली ऐसी सरकार है जिसमें जो थाने मे रिपोर्ट लिखाने जाता है, वही थाने में बन्द होता है, उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है इसलिए अधिष्ठाता महोदय बहन कुमारी मायावती की सरकार मे कानून–व्यवस्था का राज

था, कानून की देवी थी। हम कहना चाहते हैं इस सरकार का समापन हो रहा है और 2017 मे पुनः मायावती की सरकार आयेगी। धन्यवाद।

'श्री रविन्द्र भडाना–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, श्री राज्यपाल के अभिभाषण में जिस तरह की चर्चाएं आई हैं जो विषय आया है वह बड़ा ही ऐसा हास्यास्पद लगता है कि जैसे दोहरी तिहरी बाते हों। सरकार को जो करना चाहिए बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा उसके नाम पर अगर सरकार को बताना शुरू करें तो बिजली नाम की चीज नहीं है देहात के अन्दर बिजली कितनी आती है वह भी ट्रिपिंग के साथ, पानी के लिए बिजली के कनेक्शन नहीं हैं ट्यूबवेल के, डार्क जोन बना रखें हैं किसान से कहते हैं कि पैदा करो, पैदा काहे में करेगा जब सिंचाई के लिए पानी नहीं है, कनेक्शन उसको नहीं है। शिक्षा की बात करते हैं विद्यालय नहीं है और सड़कों की बात करें तो मैं तो अपनी विधान सभा की बात करूंगा सारी सड़के उधड़ कर, टूटकर नष्ट हो चुकी हैं। बार बार लिखकर देते हैं 301 में 51 में भी और प्रश्नों के माध्यम से भी लेकिन आज तक सड़कों का निर्माण नहीं कराया गया। मान्यवर, यह सरकार कर तो रही है उसका मैं विवरण बताता हूं कटान पशुओं का कटान गोकशी, गाड़ियों का कटान। मेरठ के अन्दर गाड़ियों के कटान का ऐसा सेन्टर बन गया है, दिल्ली, एन0सी0आर0 और चारों तरफ के कमिश्नरी से गाड़ियां लाकर के काटी जाती हैं कई बार पकड़ी गयी हैं, मौके से लोग पकड़े गये हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है। मान्यवर, मेरठ के अन्दर, मैं पहले भी विषय उठा चुका, शुक्रवार के दिन चोर बाजार लगता है वहां चोर बाजार के नाम से जो चोरी की गयी चीजें हैं उसका बाजार लगता है खुलेआम वह चीजें बिकती है लेकिन आज तक कोई उस पर कार्रवाई की बात ही नहीं है और आप ही के बहुत बड़े बड़े व्यक्ति वहीं पास में ही रहते हैं वह रोज वहां से निकलते होंगे लेकिन उसके बाद भी वह चोर बाजार नहीं रुक रहा है। मान्यवर, यह तो सब चीजे है ही इसके अलावा लूट, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार हत्याएं, रोज हत्याएं हो रही हैं कानून–व्यवस्था के नाम पर एक ऐसा मजाक हो रहा है पूरे प्रदेश के अन्दर मेरठ में तो मैं रोज रोज देखता हूं कभी कहीं कुछ होता है कभी कहीं कुछ घटनायें होती हैं। लगातार कानून–व्यवस्था का मजाक सा बनकर रह गया है। मान्यवर, विकास की बात करें तो सरकार भेदभाव के आधार पर काम कर रही है, कर तो रही है लेकिन भेदभाव के आधार पर। सरकार के ढिंढोरा पीटने वाले बहुत सारे लोगों ने ढिंढोरा पीटा कि हम कब्रिस्तान की चहारदीवारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है हम उसको मना नहीं कर रहे हैं लेकिन इसी प्रदेश में क्या दूसरा वर्ग नहीं है आप वर्ग के आधार पर भेद करेंगे उनके शमशान घाटों का, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है उसकी भी चहारदीवारियां हों, उनकी भी वहां शेड्स आदि बने तो उसके लिए भी व्यवस्था हो। मान्यवर, मैं भेदभाव की बात कर रहा हूं आप कर रहे होंगे कहां

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

कर रहे हो पता नहीं। आप सड़क भी बना रहे होंगे लेकिन मेरे यहां तो नहीं बनी एक भी। मान्यवर, सड़कों के निर्माण में भेदभाव बरता जाता है पी0डब्लू0डी0 विभाग सड़कों के लिए प्रस्ताव मांगता है उस प्रस्ताव के अन्तर्गत हमारे क्षेत्र में सड़के नहीं बनाई जाती। मान्यवर, बराबर में हम दूसरी विधान सभाओं के अन्दर देखते हैं वहां पी0डब्लू0डी0 भी सड़के बनाता है। मान्यवर, एम0डी0ए0 जो मेरठ विकास प्राधिकरण है उसके क्षेत्र के अन्दर एम0डी0ए0 के द्वारा विकास कार्य होने चाहिए लेकिन एम0डी0ए0 की अवस्थापना से दूर जाकर के ग्रामीण अंचलों में लोग काम करा रहे हैं। यह भेदभाव नहीं तो और क्या है ? आवास विकास, आवास विकास की अवस्थापना से जो वहां उसका पैसा आता है रजिस्ट्री आदि का उसके आधार पर उसकी अवस्थापना से शहर के अन्दर उसका निर्माण होना चाहिए सड़कों का और विकास कार्यों का लेकिन वहां न होकर के शहर के दूरदराज क्षेत्रों में होता है। मान्यवर, यह भेदभाव नहीं तो और क्या है ? हर चीज के अन्दर भेदभाव, शादी होगी तो भेदभाव, कोई भी अनुदान मिलेगा तो भेदभाव और अगर छात्रवृत्ति की बात करें तो छात्रवृत्ति में घोटाले, मान्यवर, स्कूलों की जांच करा लें ऐसे ऐसे घोटाले मिलेंगे उन स्कूलों के अन्दर विद्यार्थी हैं नहीं उनके नाम चढ़ाकर के और कहां–कहां से उसकी छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। मेरठ के एक समाज कल्याण अधिकारी उसमें जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी वहां पर बाज नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों के अन्दर छात्रवृत्ति के बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। इसी तरह से पेंशन की बात है, आप कहते हैं कि हम पेंशन दे रहे हैं, माना कि आप पेंशन दे रहे होंगे, लेकिन भेदभाव के आधार पर पेंशन देने का काम किया जा रहा है। शादी अनुदान की बात करें तो शादी अनुदान के अन्दर भी भेदभाव किया जा रहा है। यह सरकार भेदभाव के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर काम करने का काम कर रही है। पश्चिमी क्षेत्र को बिल्कुल उपेक्षित रखा गया है। मान्यवर, अगर पश्चिम में गन्ने की बात करें तो चाहे वह पूर्ववर्ती वाले हो, चाहे वर्तमान वाले हों, गन्ने के ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। चाहे किसान की बात करें, किसान के अनुदान की बात करें, ओलावष्टि हुई उसमें किसान के साथ धोखा हुआ और मजाक हुआ। किसान की पीड़ा सुनने को यह सरकार तैयार नहीं है। चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात करें तो अस्पताल नहीं हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी लैपटाप वितरण के लिए गये थे तो वह ट्रामा सेण्टर की घोषणा करके आये थे, लेकिन आज तक उस ट्रामा सेण्टर की शुरूआत भी नहीं हुई है। मेरठ के अंदर जाम की भयावह स्थिति है। जो मूलभूत सुविधायें होनी चाहिये, वह नहीं हैं। इनर रिंग रोड और आऊटर रिंग रोड जो महायोजना में प्रस्तावित हैं, तो 10–12 साल हो गये। आज तक इनर रिंग रोड पर काम नहीं और आऊटर रिंगरोड पर काम नहीं। यह तो इस सरकार के विकास की बात है। मान्यवर, पूरा मेरठ हाहाकार कर रहा है। सारी सड़कें टूटी–फूटी पड़ी हुई हैं। वहां पर सफाई नहीं है, पानी का निकास नहीं है। मेरे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, जहां पर पानी निकासी की समस्या है। आज तक उन क्षेत्रों में नाले नहीं बनाये गये हैं। बहुत बड़ी समस्याओं से जूझता मेरठ और यातायात की व्यवस्था से जूझता मेरठ। इस सरकार को ध्यान देना चाहिये और राज्यपाल के

अभिभाषण में यह सम्मिलित किया जाना चाहिये था। सरकार इस बात की चिंता करती कि मेरठ के अंदर शिक्षा हो, मूलभूत सुविधायें हों, लेकिन उनको नहीं रखा गया है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।

'श्री सुरेश बंसल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं इसका आभारी हूँ। मैं अपने नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी से अपने को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहूँगा कि महामहिम राज्यपाल ने महानगरों की जो मुख्य समस्यायें हैं उनके विषय में अभिभाषण में नहीं कहा है। सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है, दूसरी समस्या शुद्ध पानी की है, तीसरी समस्या शिक्षा की है, चौथी समस्या इन्क्रोचमेण्ट की है। मैं इन्हीं समस्याओं के संदर्भ में अपने क्षेत्र गाजियाबाद की बात करना चाहूंगा। मैं अपने यहां की एक प्रमुख समस्या की ओर बताना चाहता हूं, जो प्रदूषण से संबंधित है। मेन जी0टी0 रोड पर एक सड़क जो भाटिया मोड़ से गुलमोहर तक जाती है, पचास हजार मीटर का एक प्लाट है, उसको नगर निगम ने कूड़े से भर दिया है और अब मरे हुये जानवर भी उस पर डाले जा रहे हैं और उसमें आग भी लगा दी जाती है जिससे बहुत प्रदूषण होता है। उसके चारों तरफ आबादी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। बहुत बार प्रयास किया, नगर निगम और डी0एम0 से बात की, लेकिन आज तक उस समस्या का कुछ निदान नहीं हो सका है। वहां के नागरिकों ने धरना–प्रदर्शन भी किये हैं, परन्तु वह समस्या बनी हुई है। मेरा शासन से अनुरोध है कि इस कूड़े के ढ़ेर को तुरन्त उठवाया जाये। दूसरी समस्या पानी की है। हमारे गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो एन0एच0–24 और नोएडा के बीच में आता है, जिसमें नगर निगम के तीन वार्ड हैं, जिसकी आबादी एक लाख तीस हजार के करीब है, वहां पर पानी की सप्लाई नहीं है। वहां पर सरकार की तरफ से पानी की लाइन नहीं है। पानी हैण्डपम्पों से मिलता है और वह भी पीला पानी आता है जिससे कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। वहां पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। तीसरी समस्या शिक्षा की है, आप कहते हैं कि सबको शिक्षा मिले। हमारे यहां माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए क्रमशः इण्टर कालेज और डिग्री कालेज नये नहीं बन रहे हैं और आबादी बढ़ रही है। मेरा यह कहना है कि केलाभट्टा जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें लाखों की आबादी है, उसमें एक जूनियर हाई स्कूल है जहां पर जगह भी बहुत है, उसके बारे में मैं पिछले चार साल से लगातार कह रहा हूं कि उसमें आप एक इण्टर कालेज बनवा दीजिये, परन्तु आज तक वहां पर कोई इण्टर कालेज नहीं बना है। इसके साथ ही जो विजय नगर क्षेत्र है, जिसकी आबादी पांच लाख के करीब है, उसमें छात्रों के लिए एक भी इण्टर कालेज और डिग्री कालेज नहीं है, उसको तत्काल बनवाया जाये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि इतना इनक्रोचमेंट शहर

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

में है कि एक तो वाहन और इनक्रोचमेंट इतना है जिसकी वजह से आम आदमी को निकलना दूभर है। एक योजना थी विजय नगर को शहर से जोड़ने के लिये एक आर0ओ0बी0 बनना था, वह सन् 2012 से पेडिंग है और जो माननीय मंत्री जी हमारे जिले के प्रभारी हैं, माननीय आजम खां साहब, इन्होंने कई बार जिला योजना की बैठक में वहां आश्वासन दिया है कि आर0ओ0बी0 बनेगा, परन्तु आज तक उस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुयी है। इसी प्रकार जो विजय नगर क्षेत्र है उसमें शिक्षा के साथ–साथ चिकित्सा की भी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां अस्पताल भी नहीं है, इतना बड़ा क्षेत्र और अस्पताल न हो तो गरीब आदमी कहां जायेंगे। गाजियाबाद शहर में महानगर की सड़कों पर आपको हजारों लोग खुले आसमान के नीचे सोते मिलेंगे, जिनको कोई जनसुविधा नहीं है, मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके लिये कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। समस्या इतनी है और हम अपने नगर के विकास के लिये नियम–301 में सूचना तथा सवाल आदि लगाते हैं, पिछले चार वर्षो से मेरी 6–7 नियम–301 की सूचनायें पेडिंग पड़ी हैं और उसमें लिखकर आ जाता है प्रक्रियात्मक विलम्ब। तीन साल पहले जो हमने 301 डाली थी, उस पर भी आप प्रक्रियात्मक विलम्ब लिखोगे तो कैसे विकास होगा। मेरा शासन के लोगों से अनुरोध है कि भई हमारा भी कुछ काम करा दीजिये। जो नियम–301 है, बड़ी मुश्किल से हम लोगों की मंजूर होती है, उन पर यदि हमारे नगर में काम नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा । शहर में इस कदर इनक्रोचमेंट है कि चौराहे व्यस्त रहते हैं, घंटो–घंटो ट्रैफिक जाम रहता है, पुलिस की व्यवस्था नहीं है, रोज चोरी डकैती होती है, यह सब क्या है। सी0सी0 कैमरे नहीं लगे हुये हैं, गाजियाबाद जैसे महानगर में रोजाना डकैतियां हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, इसलिये कानून–व्यवस्था पर भी शासन को ध्यान देना चाहिये। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र की जितनी भी समस्यायें हैं आप उन पर कार्रवाई करें, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्रीमती विमला बाथम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले चूंकि नोएडा औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिये उद्योग से जुड़ी समस्याओं की चर्चा करूंगी। एक तो जो वैट वहां लागू है जो मशीनरी आती है सेम स्टेट से, यू0पी0 टू यू0पी0, उसमें साढ़े 14 प्रतिशत वैट है, जबकि हम दिल्ली से अगर मशीन खरीदते हैं तो 2 प्रतिशत सी0एस0टी0 पर मशीन आ जाती है अब आप ही निर्णय करिये कि कोई क्यों यू0पी0 से खरीदेगा, सब दिल्ली से ही खरीदेंगे। यह बहुत बड़ा अंतर है जिसकी वजह से सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले भी मैंने यह समस्या उठाई थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। बिजली की दरें अनाप–शनाप बढ़ाई जा रही हैं, अभी रेजीडेन्शियल एरिया में साढ़े 6 रुपये और इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 9 रुपये प्रति यूनिट बिजली के रेट हो

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

गये हैं, इस प्रकार लगभग 25 परसेंट दरें अचानक बढ़ा दी गयी है, इससे भी उद्योगों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नोएडा जहां से पूरे यू0पी0 का 6 परसेंट आमदनी सरकार को होती है रेवन्यू से, लेकिन वहां पर अगर आप सुविधायें नहीं देंगे तो यह उद्योग नहीं चल सकते। इसी तरह वहां पर जो प्रवेश कर है जो यू0पी0 से यू0पी0 में जो चीजें हम खरीदते हैं, उन पर एक से लेकर पांच परसेंट तक प्रवेश कर लगा हुआ है जैसे स्टील के आइटम पर एक परसेंट, पेपर पर दो परसेंट और डीजल पर 5 परसेंट प्रवेश कर है। तो आप बताइये कि इन चीजों को आदमी यू0पी0 से यू0पी0 क्यों खरीदेगा। लोग दिल्ली जाकर डीजल भरवाते हैं, इससे सरकार का नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी इस पर समानता लाने के लिये कोई नहीं सोच रहा है। दिल्ली चूँकि नोएडा से लगा हुआ है तो दिल्ली और नोएडा के रेटों में समानता होनी चाहिये। पानी जो बहुत बेसिक चीज है और हमारा बेसिक अधिकार है और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सबको शुद्व पेयजल दे। लेकिन नोएडा का पानी इतना खराब है कि पानी की टोटी आप खोलिये तो कीचड़ से भरा हुआ पानी मिलता है। इस पानी को पीना तो दूर, इससे नहाना भी मुहाल है। इसके लिये हमारी नोएडा के अधिकारियों से बात हुयी तो पता चला कि वहां 35–40 साल पहले लाइनें पड़ी थीं, वह सब जर्जर हो गयी हैं, उनमें जंग लग गयी है और बहुत सारी सिल्ट जमा हो गयी है, जिस वजह से यह दिक्कत आ रही है। नोएडा अगर महानगर है और इंडस्ट्रियल हब वहॉ पर है तो इसका मतलब है कि वहां जो निवेश आयेगा वह पानी बिजली जैसी मूलभूत समस्या के आधार पर ही आता है, जब पानी ही नहीं है तो निवेश कैसे आयेगा इसके लिए एक मेरा सुझाव है कि वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लाण्ट अगर लगा दिये जाएं, जहां से पानी की सप्लाई शुरू होती है तो यह एक बहुत बड़ी राहत हो जायेगी। गंगा वाटर की हम बात करते हैं, गंगा वाटर एक सपना लगता है कहीं पता नहीं चलता है कि कब गंगा वाटर आया और कब बन्द हो गया। इसी तरह से कानून व्यवस्था पर मैं फिर आपसे बताना चाहती हूं कि नौएडा एक इंडस्ट्रियल शहर है और यहां देश और विदेश से लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं यह एक बहुत ही हाईटेक सिटी है लेकिन अगर हाईटेक सिटी में दिन–दहाड़े लोगों की चेन छिन जाए, गुंडागर्दी खुले आम हो, अवैध कब्जे हो जाएं, अभी मैं कल का ही एक उदाहरण देती हूं मेरी पार्टी के लोगों ने मेरे पोस्टर लगाये और वह पोस्टर उसी समय फाड़ दिये गये, किसने फाड़े आप समझ सकते हैं, सत्ताधारी पार्टी ने फड़वाये। इतना अंधेर और इतना बड़ा अपमान कैसे हम लोग झेलते हैं, हमें पता है कि किस हद तक गुंडागर्दी होती है और उसके बाद फिर सत्ताधारी पार्टी समझती है कि वोट क्यों नहीं जनता देती है। गुंडागर्दी करके कभी भी वोट हासिल नहीं हो सकता है इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि गुंडागर्दी वहां पर कम करें और अवैध कब्जे कम करायें। खुलेआम यह सब नंगा नाच हो रहा है और प्रशासन कुछ नहीं कहता है क्योंकि प्रशासन आपकी कठपुतली है इसलिए प्रशासन क्या बोलेगा, प्रशासन के लोग तो हर समय सत्ताधारी पार्टी का ही साथ देते हैं चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो। यह हमारी बहुत बड़ी तकलीफ है और यह हमारी ही नहीं पूरे नौएडा की तकलीफ है। एक मैंने अभी क्वैश्चन यहां पर

भेजा था कि जो बोर्ड बैठक वहां पर होती है उसमें किसी जनप्रतिनिधि को शामिल किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, जहां का मामला हो वहां का जनप्रतिनिधि वहां हो क्योंकि क्षेत्र की समस्या को वही रख सकता है। जो आई0ए0एस0 अधिकारी आते हैं उन्हें क्या पता कि हमारे क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ जब बोर्ड की बैठक में जनप्रतिनिधियों को नामित किया गया हो जबकि एक बार जब आपकी सरकार थी पिछले टर्म में तो हमारे अमर सिंह जी ने अपना एक प्रतिनिधि, एक सी0ए0 वहां नामित किया था, वह भी गलत था अगर कोई नहीं हो सकता तो फिर वह कैसे था लेकिन उसके बाद से कोई भी नामित नहीं हुआ। इसलिए मेरी मा0 अध्यक्ष महोदय से गुजारिश है कि नौएडा में जब भी बोर्ड की बैठक हो तो वहां जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो उसे जरूर शामिल किया जाए, उसकी राय जरूर ली जाए ताकि वह क्षेत्र की समस्या को अच्छी तरह से उठा सके। वहां पर कुछ किसानों की

(इस समय 03 बजकर 02 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

समस्याएं हैं, 1979 में जिनकी भूमि अर्जित की गई थी उनको 1997 तक किसानों को कुछ नहीं मिला, 10 साल जो भूमि अर्जन का काल था उनको मात्र दो–ढाई रुपए प्रति मीटर या गज के हिसाब से मुआवजा मिला। उसके बाद मुआवजा बढ़ा, अभी हाल में 64.7 प्रतिशत मुआवजा दिया गया तो उन किसानों का क्या गुनाह है जिनको यह मुआवजा नहीं मिला। अभी कोर्ट ने भी यह कहा है कि जितनी भूमि उनकी गई है उसकी 10 प्रतिशत भूमि उनको आबादी के लिए छोड़ी जाए लेकिन एथारिटी उन्हें वह भी मुहैया नहीं करा रही है बल्कि 5 प्रतिशत के प्लाट भी नहीं दिये जाते हैं और एथारिटी में जो पैसा देता है उसको मिल जाते हैं और जो ज्यादा पैसा देता है उसको और अच्छी लोकेशन में मिल जाता है, इतना भ्रष्टाचार एथारिटी में फैला हुआ है। एक और किसानों की समस्या है कि बिना बताये भूमि अर्जित कर लेते हैं और कह देते हैं कि मुआवजा आपने नहीं उठाया तो इसमें मेरी क्या गलती है। किसान सोचता है कि मैंने मुआवजा उठाया नहीं इसलिए जमीन मेरी है लेकिन वहॉ पता चलता है कि सारी जमीन एथारिटी के रिकार्ड में दर्ज हो गई और किसान खाली हो गया। यह इस तरह का अंधेर है और बाद में बिल्डर कब्जा लेने के लिए चले जाते हैं और जे0सी0बी0 मशीन उनको धंसाने के लिए चली जाती है, बहुत से गांव के गांव इससे पीड़ित हैं जो कि सौ–सौ साल पुराने गांव हैं। हैण्डपम्प के लिए मैंने बहुत बार मा0 अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट की थी, संसदीय कार्य मंत्री जी से भी बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में 100 हैण्डपम्प देने की कृपा करें क्योंकि मा0 मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट सत्र के आखिरी दिन यह घोषणा की थी कि नगरीय क्षेत्रों को हैण्डपम्प मिलेंगे लेकिन नौएडा ने क्या गुनाह किया कि वहां ये धनराशि नहीं गई वहां से हमें लेटर आ गया कि धनराशि नहीं आवंटित हुई इसलिए आपको नहीं मिल सकते हैं। मेरी आपसे बहुत गुजारिश है कि आप हमारे क्षेत्र को 100 हैण्डपम्प की सौगात दे दें ताकि मैं अपने लोगों से आंख मिलाकर बात कर सकूं। जिस तरह से एक अराजकता का माहौल नौएडा में बना हुआ है विशेष रूप से

इण्डस्ट्री के क्षेत्र में जो उगाही होती है जिस तरह से इण्डस्ट्री चलने नहीं दी जा रही है उससे किसी का नुकसान नहीं है मात्र सत्ताधारी पार्टी का नुकसान है क्योंकि ऐसा होने से सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलता है और जब रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो सरकार आप कैसे चलायेंगे। इस बात को मैं कई बार चर्चा में लायी हूँ कि रेवेन्यू के लिए उद्योगों को आप सहायता दीजिए, उद्योग चलाईये। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने बहुत सारी स्कीम्स चलायी हैं लेकिन वे सारी स्कीम्स कागजों पर हैं, धरातल पर नहीं हैं। उन स्कीम्स को धरातल पर उतारिये। जो बजट आया है हम कह सकते हैं कि उसमें चाहे कुछ भी न हो किसी के लिए लेकिन फिर भी अगर उस बजट पर काम हो, उस बजट को अमलीजामा पहनाया जाये तो शायद कुछ कारगर रिजल्ट निकलेगा और हम सब लोग जब चुनाव में जायें तो अपनी–अपनी बात कह सकें। इसलिए नोएडा एक स्पेशल क्षेत्र है, स्पेशल जोन है जहां दुनिया की नजरें हैं। वर्ल्ड मैप पर नोएडा है। हाईटैक सिटी नोएडा है, वहां और क्षेत्रों से अधिक सुविधायें दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये।

श्रीमती विमला बाथम–

नोएडा यू0पी0 की शान है, यू0पी0 की नाक है उस शान को, उस नाक को बचाईये और नोएडा को विशेष दर्जा दिलवाईये तभी हम लोग उस नोएडा को बचा सकेंगे, बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष–

सत्तापक्ष की तरफ से कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेगा ? (प्रतिपक्ष की तरफ से कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने के लिए हाथ उठाने पर) इसके बाद आप लोग बोलिये, आज 10 बजे तक बोलिये, सबको मौका मिलेगा।

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे भाई गुलाम मौहम्मद जी ने श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, सामने बैठे हुए एक साथी ने हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर इस तरह से गंदे अल्फाज यूज करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जितना मुसलमानों का काम किया उतना शायद आज तक हिन्दुस्तान में किसी ने काम नहीं किया है और उनके पैरों की धूल नहीं हो सकते आपके नेता। आप बार–बार लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हैं, आप किससे असुरक्षित महसूस कर रहे थे, यहॉ बैठे हुए पत्रकार बंधुओं की सारी गैलरियां शीशे से ढ़क दी गयी थी, इतना अच्छा प्रशासन और

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

शासन चल रहा था कि डर हो गयी थी कि हमारे पत्रकार बंधु भी कहीं इनके ऊपर हमला न बोल दें। और सारी तरफ से पूरी विधान सभा घेरी गयी थी लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे मुख्य मंत्री हैं उन्होंने ये सारी दीवारें हटवायीं और आज जो चाहे जहॉ जा सकता है इस तरह की व्यवस्था करने का काम किया। पांच कालिदास मार्ग पर क्या था कि वहां पर कौआ भी नहीं बोल सकता था। कौआ बोलता था तो सिपाही दौड़ा दिये जाते थे कि कहीं कौआ कोई बम न गिरा दे। इसलिए कौए के ऊपर भी हमला कर दिया जाता था। हमारे मुबारकपुर के साथी चले गये, वो मुसलमानों के ऊपर बोलने का काम कर रहे थे। मुबारकपुर में भी जो उनकी विधान सभा है, हमने भेदभाव नहीं किया, हमारी सरकार ने कहीं भेदभाव नहीं किया। मा0 अध्यक्ष जी, विपणन केन्द्र तो देने का काम किया ही किया, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल उन्हीं की क्षेत्र में देने का काम किया गया। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उसको बेचने का काम कर रही थी। यह किसान की हितैषी सरकार है, पहली को–आपरेटिव मिल, उत्तर प्रदेश में नहीं, हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि एशिया में सबसे बड़ी चीनी मिल आपके यहां लग रही है उसके बारे में आपने एक बार भी जिक्र करने का काम नहीं किया। उनको याद नहीं होगा, पिछली बार उनकी सरकार थी, उनके मंत्री भी थे जो जेल में कई सालों तक बंद रहे। वहां भी कोई काम नहीं किया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आयी तो विपणन केन्द्र दिया, इससे पहले जब सरकार थी और मा0 बलराम यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो वहां भी हास्पिटल देने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया। इन बातों पर चर्चा नहीं की। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की बात बता दूं जब हम वोट मॉगने जा रहे थे तो सारे गरीब–गुर्बा बार–बार यही कह रहे थे कि हमारी पेंशन छीन ली गयी जो मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने देने का काम किया था। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पेंशन 45 लाख से बढ़ाकर 55 लाख अर्थात 10 लाख बढ़ाने का काम किया है। इस पर चर्चा नहीं हो रही है कि जिला पंचायत के चुनावों में और ब्लाक प्रमुख के चुनावों में बड़ी धांधलीबाजी हुई। मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के नेता मौजूद नहीं हैं। हमारी विधान सभा में, महाराजगंज में जिसे आपने कन्डीडेट दिया है कहा जाता है कि छोटे भाई कहीं है बड़े भाई कहीं हैं। यह मेरे खिलाफ लड़ने जा रहे हैं जिसको आपने कैन्डीडेट बनाया है जो ब्लाक प्रमुख हुआ है। मिलेगा तो उससे पूछिये कि वह किसका भाई है और किस पार्टी से ब्लाक प्रमुख हुआ है। हमारे यहां ब्लाक प्रमुख का चुनाव चल रहा था दो दो कैन्डीडेट इनके बार बार जा करके हमारे क्षेत्र में डिस्टर्ब करने का काम कर रहे थे। चाहे वह सदर के कैन्डीडेट रहे हों या गोपालपुर के दोनों लोगों ने अपने अध्यक्ष जो जिला बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष था उसकी जमानत भी नहीं बचा सके। 84 वोट समाजवादी पार्टी को और 9 बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष पाये। उसमें भी मैं कहना चाहता हूं कि 10 वोट पाये। इतना घबरा गया इतना इनको सिखाया गया माननीय अध्यक्ष जी कि अपना वोट भी गलत देकर चला गया ऐसे इनके अध्यक्ष हैं। अपना वोट भी गलत किया, पहले हमारे रूदल प्रसाद सोनकर के सामने एक लिख दिया

फिर उसको काटकर दूसरा पर्चा मांगा। उसको यह भी जानकारी नहीं है ऐसे ऐसे तो अध्यक्ष हैं। यह क्या लड़ाने का काम करेंगें, इनके पास कोई कन्डीडेट है क्या ? इनके पास कोई नहीं है जिला पंचायत के उधार कंडीडेट आज डिक्लेयर किया है आजमगढ़ में। इनके पास उधार लेने के लिये है। आज इनके पास कोई चीज बची नहीं है कि लड़ाने का काम करे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सरेन्डर कर गई है बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और अभी कोई बोल रहा था अन्त्येष्टि स्थलों को नहीं देखा गया केवल कब्रिस्तानों को देखा गया। केवल मुसलमानों को देखा जा रहा है। इस पर नहीं बोले विधायक जी। कब्रिस्तानों के साथ साथ हमारे मुख्य मंत्री जी ने अन्त्येष्टि स्थलों को भी पैसा देने का काम किया गया है और बनवाने का काम किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा भेदभाव हमारी सरकार ने करने का काम नहीं किया। अगर हमने मदरसों को अनुदान में लेने का काम किया तो 77 संस्कृत स्कूलों को भी हमने अनुदान में लेने का काम किया। यह हमारी अखिलेश यादव जी की सरकार कहीं भेदभाव नहीं करती है। आप तो कहते हैं नल नहीं मिल रहा, सड़क नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही। बलिया के साथी बोल रहे थे। लखनऊ से आजमगढ़ फोर लेन बलिया उनके विधान सभा क्षेत्र तक जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करिये।

श्री वसीम अहमद–

उनको एहसास है इस बात का कि आज सड़कें बन रही हैं। बिजली की बात कर रहे थे मैं कहना चाहता हूं जितना काम हमारे मुख्य मंत्री जी ने बिजली के क्षेत्र में करने का काम किया है उतना आज तक हिन्दुस्तान की किसी सरकार ने करने का काम नहीं किया। इसलिये हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप कह रहे थे कि पांच घंटे बिजली, 6 घंटे बिजली भूल गये कि इसी दीवाली में धनतेरस से ले करके भईयादूज तक लगातार चौबीसों घंटे हमारी सरकार ने, माननीय अखिलेश जी की सरकार ने बिजली देने का काम किया और किसी क्षेत्र में चाहे वह गांव का क्षेत्र हो या शहर का क्षेत्र हो उन दोनों क्षेत्रों में बिजली 15 से 18 घंटे बिजली देने का काम किया। कह रहे थे कि मुबारकपुर में नहीं मिल रही। इस तरह से झूठ बोलने की, मान्यवर, मैं क्षमा चाहूंगा मैंने झूठ शब्द कह दिया, इस तरह से असत्य नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मुबारकपुर में 18 घंटे से लेकर 21 घंटे बिजली मिल रही है। इसलिये इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। इसलिये हम आपसे कहना चाहता हैं माननीय अध्यक्ष जी कि आपने हमें माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं उसका समर्थन करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

कांग्रेस से कोई बोलेगा ?

(श्री सुदेश शर्मा जी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे शर्मा जी रुक जाइये। कांग्रेस से वह माननीय सदस्य खड़े हैं पहले उनको बोल लेने दीजिये।

श्री राधे श्याम–

माननीय अध्यक्ष जी, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगदीशपुर विधान सभा अमेठी से आता हूं। सरकार के द्वारा बहुत से काम कराये भी गये हैं और बहुत सारे कार्य कराने की आवश्यकता भी है। मैं सीधे अपने क्षेत्र की कुछ बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे यहां की दो प्रमुख सड़कें हैं जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कें बनवायेंगे उसी क्रम में बाजार सुकुल से जगदीशपुर होते हुए अमेठी मुख्यालय तक जाने वाली सड़क जिसकी लम्बाई जगदीशपुर तक लगभग 24 किलोमीटर है बहुत ही डेमेज है बहुत ही खराब है मैं उसमें सरकार से चाहूंगा कि उसको रिन्यूवल करा दिया जाए। दूसरा बाजार सुकुल से ही देवकली होते हुए, रानीगंज होते हुए, वारिसगंज एन0ए0 56 तक आती है यह दो हमारी सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो ब्लाक से जिला मुख्यालय को टच करेंगी जिस पर क्षेत्र की जनता जनार्दन का आवागमन होता है आए दिन कोई न कोई क्षेत्रवासी दुर्घटना के शिकार होते हैं और उनको सड़क अच्छी न होने की वजह से अस्पताल तक भी पहुंचना पड़ता है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इन दो सड़कों पर कार्य कराया जाए। इसी के साथ–साथ सरकार के द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन 33/11 के उपकेन्द्र दिए गए हैं जिसमें ग्राम सभा के द्वारा डिपार्टमेंट को जमीन की लीज भी दे दी गई है और एक जनपद को 132 के0वी0ए0 का उपकेन्द्र भी दिया गया है तो यह सारे काम हैं जो होने हैं अगर काम की शुरूआत करा दी जाएगी तो उस क्षेत्र में, तो इससे सरकार की भी उपलब्धि हो जाएगी। मान्यवर, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सरकार की तरफ से उसमें कोई नीति बना दी जाए कि बच्चों को परीक्षा के दौरान विद्युत आपूर्ति उनके समय के अनुसार मिले सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुझे कहने में बड़ा अफसोस लग रहा है कि सरकार जितना गिनाती है कि हमने बड़े–बड़े काम कर डाले। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मेरे क्षेत्र में केरोसीन का तेल नहीं मिलता है और इसके लिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन उसमें कहीं न कहीं सत्ता के लोग इन्वाल्व हैं जिनकी वजह से तेल नहीं मिलता है और मैं चाहूँगा कि इसकी जांच करा ली जाए। मैंने मुख्य मंत्री जी को भी पत्र दिया था उसके बावजूद भी केरोसीन छः–छः महीने नहीं मिलता है और इसके बाद अहम चीज है कि अभी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था कानूनगो हलियापुर सर्किल को अमेठी जनपद में शामिल करने के लिए, इसकी घोषणा कर दी गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इसी के साथ सरकार के द्वारा मेरे पड़ोस में इसौली विधान सभा में एक नई तहसील देने का काम किया है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ–साथ एक अनुरोध और करना है सरकार से, हमारे क्षेत्र में टेल का एरिया होता है

जो बाराबंकी से नहरें होकर के हैदरगढ़ डिबाई है, उसके द्वारा सिंचाई के काम में पानी की आपूर्ति की जाती है। काफी लम्बे समय से उसकी शिकायत भी की गई पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुँच रहा जो आवश्यकता है पानी की। मेरा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है कि नहरों में पानी के लिए अपने स्तर से उचित कार्रवाई की जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो विरोध स्वरूप कहा गया है उस पर बल देने के लिए मुझे बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैंने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने और पढ़कर समझने का काफी प्रयास किया है। बड़ी अच्छी–अच्छी बातें उसमें कहीं गई हैं कहा गया है कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष दिल है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का का दिल तो है लेकिन वह दिल तार–तार हो चुका है और उसमें बहुत सारे छेद वर्तमान समय में किए जा रहे हैं।

(इस समय 03 बजकर 27 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनूप सण्डा पीठासीन हुए)

बड़ी बड़ी लम्बी बातें की जा रही हैं कि कानून–व्यवस्था दुरुस्त है तो आंकड़े देख लिए जाएं पिछले चार साल के पिछले 10 वर्षों के आंकड़े उठाकर उनका कम्परीजन कर लिया जाए लूट हत्या डकैती बलात्कार कितने अपराधों में कमी आई है या कितने अपराध बढ़े हैं। मैं अपनी विधान सभा का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में उस रोज भी माननीय नेता जी ने उठाया था एक ज्वैलर के यहां लूट हुई सोनू ज्वैलर्स के नाम से उसकी दुकान है और पुलिस ने उल्टे उसी के भाई के घर पर छापा मारकर उसी का अपना चार पांच लाख का माल बरामद करके उसी के माल को एक करोड़ का माल बताकर माल बरामद करने का काम किया। यह पुलिस का हाल है यह आपकी कानून–व्यवस्था का हाल है। आज नो इन्ट्री के नाम से ट्रकों से बसों से अवैध उगाही की जा रही है केवल एक धन्धा मिल गया है पुलिस वालों को कानून–व्यवस्था के नाम पर नो इंट्री के नाम पर खुले आम लूट की जा रही है। मान्यवर, बजट की शुरुआत किसानों से की गई किसान वर्ष मनाया जा रहा है सरकार के द्वारा लेकिन आज किसान का गन्ना किसान का जितना बुरा हाल है शायद इससे पहले कभी हुआ नहीं है। आज मेरे ही मोदीनगर विधान सभा क्षेत्र में मैंने नियम–56 में भी इसे डाला था तो आपने कहा था कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जब बोलेंगे तो चर्चा कर लेना मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष का बकाया आज तक भुगतान नहीं हुआ है सैकड़ों करोड़ रुपया अभी पिछले वर्ष का बकाया है माननीय अध्यक्ष जी और इस बर्ष का तो एक पैसा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। किस तरीके से प्रदेश सरकार यह किसान वर्ष मना रही है। क्या मोदीनगर विधान सभा क्षेत्र का किसान इस उत्तर प्रदेश

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

से अलग है इस हिन्दुस्तान से अलग है। किस तरीके से वहां का किसान अपना जीवन यापन कर रहा है उसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है मैं समझता हूं कि किसान वर्ष मनाना सरकार का बिल्कुल बेईमानी भरा कदम है। आज उन लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, फीस देने के लिए पैसा नहीं है। अपनी बेटियों की शादियॉ करने के लिए पैसा नहीं है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है फिर कब यह सरकार जागेगी और इस बात को कहेगी कि आओ किसान भाइयों हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि हम किसान वर्ष मना रहे हैं सरकार का यह कहना है। आपने बहुत नलकूप लगाए लेकिन अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज उन नलकूपों की हालत भी देख ली जाए जितना बोर करने के लिए स्पेशीफिकेशन के लिए कहा जाता है उतना नीचे बोर नहीं किया जाता और आज उनमें से आधे से ज्यादा नलों में पीले रंग का पानी आ रहा है जो कि दूषित है इस पर कोई भी कार्रवाई सरकार की ओर से या वहां के अधिकारियों की ओर से नहीं की जा रही है। जहां तक प्रदेश में शिक्षा की बात है तो शिक्षा विभाग में तो यह हाल है अध्यक्ष जी मैं सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि आखिर प्रदेश के अन्दर कितने सरकारी स्कूल हैं जिनको परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए सेन्टर नहीं बनाया जाता उनके केन्द्र नहीं दिए जाते प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा केन्द्र स्थापित किये जाते हैं परीक्षा देने के लिए जिससे कि खुली नकल चल सके वहां जो अधिकारी हैं जो स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं वह खुली लूट मचाकर नकल करवा सकें हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकें। यह शिक्षा के नाम पर हाल है। एक मान्यवर अभी आदेश हुआ है कि जो भी किसान खेत के अन्दर अपनी फसल को जलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले दो होमगार्ड मोटर साइकिल पर जाते हैं और अगर किसान ने थोड़ी पत्ती भी जला दी तो उससे उगाही करने का काम शुरू कर दिया है। कई जिलों में कर दिया है मेरे यहां तो कम से कम कर ही दिया है। मैं उसका खुद गवाह हूं जबकि कायदे में कम से कम किसानों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए उनको वह उपकरण देने चाहिए कि किस तरह से गन्ने की जो पत्ती है जो फसल होती है उसका किस तरह से निस्तारण किया जाय। लक्जरी कारों से भी प्रदूषण को हानि हो रही है और भी बहुत सारी चीजें हैं केवल किसान को बिना प्रशिक्षित किए उस पर जो यह कानून थोपा गया है मैं समझता हूं कि इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। मान्यवर, इस बजट के अन्दर मोदी नगर के अन्दर जाम लगता है। मोदीनगर को लोग जाम नगर के नाम से जानने लगे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपनी चुनावी सभाओं में घोषणा की थी कि हम मोदीनगर को जाम से निजात दिलायेंगे, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी योजना तैयार नहीं की गयी जिससे मोदीनगर के लोगों को कम से कम जाम से निजात मिल सके। (सदस्य श्री सतीश महाना जी द्वारा कुछ बोलने का प्रयास करने पर) महाना जी, गडकरी जी तो परभीशन दे दें वहीं बहुत है। गडकरी जी और मोदी जी के बारे में मत बुलवाओ, फिर दूसरी बात आ जायेगी। आज सरकार के खिलाफ बोलने दें तो ज्यादा अच्छा है। (सदस्य, श्री गुलाम मौहम्मद द्वारा कुछ बोलने का प्रयास करने पर) मा0 गुलाम मौहम्मद जी, आप हमारे बड़े

वरिष्ठ सदस्य हैं। आप कह रहे थे कि मा0 नेता जी के एक अदने से चेले ने राष्ट्रीय लोकदल को, जिसके लिये आप कह रहे थे। मा0 सदस्य जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस पार्टी के आप माननीय सदस्य हैं, यह समाजवादी पार्टी का भी उसी राष्ट्रीय लोकदल से निकली है और उनको भी मा0 मुलायम सिंह जी, जो नेता हैं जिनको हम भी नेता मानते हैं, लेकिन मा0 चौधरी साहब के बारे में आज तक उन्होंने भी ऐसे शब्द नहीं कहे और वह भी स्व0 चौधरी चरण सिंह जी को अपना नेता मानते हैं। केवल एक जाति विशेष या सांप्रदायिक माहौल बनाकर कुछ वोट हासिल कर लेने से आदमी नेता नहीं बन जाता है। उस सांप्रदायिक माहौल में हो सकता है कि चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव में आपसे पीछे रह गये हों, लेकिन चौधरी अजीत सिंह के सामने आपका कद बहुत छोटा है। वह किसानों की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं, वह मजदूरों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं। राष्ट्रीय लोक दल जो हमेशा मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ने वाला है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुये तो राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया ने उन दंगों में आग में घी डालने का काम नहीं किया। उन्होंने किसी की तरफ से न जाने का काम किया जिससे कि इन दंगों को और हवा न मिल सके। मा0 सदस्य जी, आप हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, मैं आपसे क्षमा के साथ इतना ही कहना चाहूंगा।

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि डार्क जोन के नाम पर पिछले चार वर्षों से हम लगातार सवाल लगा रहे हैं। एक नियम–51 में दिया था जिसका अब जवाब आया है। जवाब में आपकी सरकार ने लिखा है कि जो कृषकों के प्राईवेट ट्यूबवेल हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यहां पर सरकार के मंत्री बैठे हैं। हमारे और भी मा0 सदस्यों को जानकारी होगी कि जहां पर डार्क जोन हैं वहां के जो हायडिल के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वह उन किसानों को कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। मुझे सरकार का जवाब प्राप्त हुआ है कि यह प्रतिबंधित नहीं है। जब सरकार का यह जवाब है कि यह प्रतिबंधित नहीं है तो डार्क जोन में केवल जल दोहन से ही तो आपको समस्या हो सकती है और जब प्राईवेट बोरिंग पर प्रतिबंध नहीं है तो फिर उन पर बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं दिया जा सकता है या तो सरकार का जवाब झूठा है या सरकार सदन को गुमराह करने का काम कर रही है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, विधायक निधि में एक प्राविधान रखा गया है कि 25 लाख रुपये तक अपनी विधायक निधि से इलाज के लिये दे सकते हैं। यदि कोई दुर्घटना हो जाये, कोई एक्सीडेंट हो जाये तो यदि हम विधायक निधि से किसी को इलाज के लिये कोई पैसा देना चाहें तो सबसे पहले मरीज प्रयास करता है कि मैं नजदीक के अस्पताल में अपना इलाज करा सकूं, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि केवल उस हॉस्पिटल को पैसा दिया जा सकता है जो राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य योजना से एफिलियेटेड हो। मैं समझता हूं कि सरकार की यह योजना दो साल से बंद है। यह केन्द्र सरकार की यह योजना है, लेकिन दो साल से इसका रिन्यूवल नहीं हुआ है। ऐसे में अगर उसको सरकारी अस्पताल ले जाने का समय हो तो वह अपने आप ही इलाज

करा सकता है, उसको विधायक निधि से इलाज कराने का कोई औचित्य नहीं है। महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस संबंध में कोई संशोधन इस सरकार द्वारा नहीं किया गया है। मेरी मांग है कि कम से कम इसमें यह संशोधन किया जाये जिससे गरीबों और जरूरमंद लोगों का इलाज हो सके। दो साल से तो केन्द्र सरकार द्वारा यह योजना ही बन्द कर दी गयी है और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मांग करता हूं कि हमारी विधान सभा के अन्दर कम से कम युवाओं के खेलने के लिए स्टेडियम बनाये जायें। जब हम ट्रेन से उतर कर सुबह जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, उनके खेलने के लिए स्टेडियम आदि की व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से कब्रिस्तानों की चहारदीवारी के लिए प्रदेश के अन्दर पैसा दिया गया, मैं समझता हूं कि उसमें भी बहुत ज्यादा पक्षपात किया गया है। हमारे विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर में किसी कब्रिस्तान की चहारदीवारी के लिए अभी तक पैसा नहीं दिया गया है और मैं यह भी मांग करता हूं कि कब्रिस्तान के साथ–साथ जो श्मशान घाट हैं, उनके उद्धारीकरण के लिए भी पैसा दिया जाना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, जो बातें मैंने रखी हैं, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन में इनको भी जोड़ लिया जाए, बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है, उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए, मान्यवर, इस अभिभाषण को जब मैंने पढ़ा तो सरकार के द्वारा जो बातें अभिभाषण में कही गयी हैं कि सरकार के सभी वायदे पूरे हो गए हैं। मान्यवर, अगर सभी वायदे पूरे हो गए तो इसका मतलब है कि सरकार ने प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर लिया है। लेकिन मान्यवर, हमारे विपक्ष के तमाम साथी और सत्तापक्ष के लोग जब यहां अपनी बात कहते हैं तो अक्सर यह बात निकल कर आती है कि हमारे क्षेत्र में अभी यह नहीं हुआ, यह नहीं हुआ और हम लोग जब यहां प्रश्न लगाते हैं तो जवाब आता है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर विकास का कार्य कराया जायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह सरकार अपना अन्तिम बजट लेकर आयी है। एक वर्ष बचा है, सरकार को सत्ता या विपक्ष न बनकर सारे सदस्यों के साथ जो हम लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ना चाहिए और प्रदेश का तभी सर्वांगीण विकास हो सकता है। मान्यवर, पिछले वर्ष से यह सरकार किसान वर्ष मना रही है। किसानों की क्या दुर्दशा है, यह शायद सारे सदस्यों को पता है। अभी बेमौसम बरसात हुई, सूखा पड़ गया, तमाम दैवी आपदाएं आ रही हैं, सरकार की तरफ से आज तक ओलावृष्टि से प्रभावित तमाम ऐसे गांव हैं, जहां के किसानों को मुआवजा देने का काम नहीं किया गया और जहां भी थोड़ा–बहुत मिला है, उसमें जो लोग प्रभावी हैं या सीधे–सीधे कहिए कि पैसा देकर अपने हिसाब से चेक बनवा लेते हैं

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

लेकिन तमाम ऐसे गरीब लोग आज भी तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, उनको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और ओलावृष्टि के कारण हुए किसानों को हुए नुकसान की भरपाई का जो भी मुआवजा बकाया है, उसे देने के लिए इस अभिभाषण में जोड़ने का काम किया जाए। मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने वैसे तो इस किताब में कहा है कि हमारी सरकार की कानून–व्यवस्था अच्छी है। लेकिन यही राज्यपाल महोदय मीडिया के माध्यम से कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था अच्छी नहीं है और अभी हमारे सत्तापक्ष के साथी भी बता रहे थे कि लखनऊ के अन्दर एक लड़की का अपहरण हुआ, उसकी हत्या हो गई और अभी तक उसके जो हत्यारे हैं, वह गिरफ्तार नहीं हुए हैं। राजधानी के अन्दर अभी कुछ दिनों पहले एक रिटायर आई0ए0एस0 अफसर के घर पर हमला किया गया, दूसरे दिन एक जज के यहां हमला किया गया। आज जब राजधानी के अंदर अपराध बढ़े हुये हैं तो गांवों में, छोटे जिलों में क्या हाल है यह शायद सब लोग समझते हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार न तो चेत रही है और न ही वह सुझाव लेना चाहती है। केवल सत्तापक्ष के हमारे तमाम साथी जिनको यह लगता है कि हम यहॉ सरकार के पास बैठे हैं तो सरकार की वाहवाही कर दें इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं सभी सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कानून–व्यवस्था पर यहां एक ऐसी चर्चा होनी चाहिए जिसमें सुझाव निकलकर आयें और उत्तर प्रदेश को कानून का राज मिले और उत्तर प्रदेश के लोग अपने को सुरक्षित समझें। यह तभी संभव है जब सारे सदस्य और सरकार इस पर ध्यान देगी। सत्तापक्ष या विपक्ष की बात सड़कों पर होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए लेकिन सदन के अंदर सबको जनहित की बातें करनी चाहिए और जनसमस्याओं को हल करने के लिए हम यहां आते हैं लेकिन ऐसा यहां नहीं हो पा रहा है। विपक्ष के साथी चाहे सवाल लगाते हों या कोई समस्या लिखकर देते हैं उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, पेंशन की बात आयी। बार–बार यहां से यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पेंशन 45 लाख लोगों को दी जा रही है। आज भी जब कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में जाता है तो वहां तमाम वृद्ध, तमाम हमारी विधवा बहनें तमाम विकलांग हमें घेर लेते हैं कि अभी हमारी पेंशन नहीं बंधी है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सरकार गंभीरता से जिले पर यह आदेश भेजे कि एक सर्वे कराया जाये कि कितने लोगों को पेंशन देना है और जो लोग पेंशन के लिए पात्र हैं उनको फेजज में पेंशन देने की व्यवस्था बनायी जाये। आपको याद होगा कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो इसी सदन के अन्दर पहले यह पेंशन डेढ़ सौ रुपये हुआ करती थी इसको हमारी नेता मा0 बहन कु0 मायावती जी ने इसी सदन में घोषणा करके डेढ़ सौ से तीन सौ करने का काम किया था और आज इस सरकार के भी चार साल हो गये और पांच साल पहले घोषणा हुयी थी तो नौ साल के अन्दर महंगाई कितनी बढ़ गयी है लेकिन इस पेंशन को बढ़ाने के बारे में सरकार ने कोई विचार नहीं किया। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर जरूर विचार करे और यह तीन सौ रुपये पेंशन बहुत ही कम हैं इसको बढ़ाकर कम से एक हजार या पन्द्रह सौ रुपये के बीच में करने

का काम किया जाये। तभी पेंशन की यह जो योजना है, सार्थक होगी। नहीं तो इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। मान्यवर, अंत में मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर मण्डी बनी हुयी है जो कि किसानों के लिए होती है जहां पर किसान अपना अनाज और भी साधन लेकर आते हैं। आप किसान वर्ष मना रहे हैं। लेकिन मण्डी पर जाने का रास्ता इतना खराब है कि उस पर कई ट्रैक्टर ट्राली पलट गयी और अभी मैंने अपने प्रयासों से उस पर मिटटी डलवाने का काम किया। उस पर मैंने सरकार को कई बार लिखकर दिया लेकिन सरकार की तरफ से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और मुझे जवाब यह दिया गया कि वर्ष 2013 में एक अनुरक्षण नीति बनायी गयी है उस अनुरक्षण नीति में यह कहा गया है कि कोई मण्डी सड़क बनायेगी तो उसको हम 08 साल के बाद उसको मरम्मत करेंगे, अनुरक्षण करेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह सड़क जून, 2008 में बनायी गयी थी। आज जून, 2016 में उसके 08 साल पूरे हो जायेंगे। अगर अपनी अनुरक्षण नीति में ही सरकार काम करे तो सरकार को उसका इस्टीमेट मंगाकर उसको टेण्डर की प्रक्रिया में लाना चाहिए। तभी 08 साल के बाद आप उसका अनुरक्षण कर पायेंगे। उसमें किसानों के साथ दुर्घटनायें हुयी हैं, एक किसान की उसमें मौत भी हुयी है। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र जलालाबाद में मण्डी समिति है उसका जो सम्पर्क मार्ग है उसको मरम्मत कराकर उसको बनवाने का काम किया जाये ताकि आगे कोई दुर्घटना न हो और जो किसान वर्ष आप मना रहे हैं वह भी किसानों के लिए सड़क है, किसानों के लिए ही वह काम होगा। मान्यवर, आज बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है। सरकार ने वायदा किया था कि हम 2016 में 20–24 घण्टे बिजली देंगे। आज हमारे यहां कस्बे में 4–6 घण्टे भी बिजली निर्बाध गति से नहीं आ रही है। एक घण्टे आयी चली गयीं यह जो बिजली की व्यवस्था है इसको दुरुस्त करने का काम होना चाहिए। क्योंकि अगर बिजली ही नहीं मिलेगी तो आप विकास की बात सोच नहीं सकते। अगर हम किसी प्रदेश के विकास की बात करते हैं तो बिजली भी होनी चाहिए। सड़क भी होनी चाहिए। पानी भी होना चाहिए, आज गांव में बुरा हाल है पानी का, हैण्ड पम्प नहीं मिल रहे हैं चार साल से और गांवों मे स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, आज गांवों में जब हम लोग जाते हैं, तो लोग हैण्ड पम्प की मांग करते हैं, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार इस अभिभाषण में यह संशोधन करे कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से डेढ़ सौ, दो सौ हैण्ड पम्प भी लगवाने का काम सरकार करेगी।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त कर दें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, बस एक बात आपसे कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मान्यवर, यहां पर लखनऊ के अन्दर अंसल हाउसिंग ने एक कालोनी बनाई थी 1986 में, उस कालोनी को आज तक नगर निगम को हैण्ड ओवर नहीं किया गया, वहां पर आये–दिन वहां के जो रहने वाले लोग हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। कई बार हमारे पास

भी लोग आये, हमने उसमें पत्राचार के माध्यम से लिखा भी, उस कालोनी के अन्दर जितनी भी अवस्थापना की सुविधायें हैं, वह बिल्कुल नगण्य हैं, जीरो हैं और सरकार की तरफ से जो लाइसेन्स उस कम्पनी को दिया गया था अंसल हाउसिंग को, उसको भी न तो निरस्त किया गया और न ही उनके खिलाफ कोई एफ0आई0आर0 की गई। एल0डी0ए0 ने उनको लाईसेन्स दिया था, एल0डी0ए0 की जिम्मेदारी है कि ऐसी कालोनियां जहां लाखों लोग रहते हैं वहां पर सारी अवस्थापना सुविधायें हों और उस लाईसेन्स धारक को या तो उससे काम करवाया जाय या तो उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 करा कर उसको जेल भेजने का काम किया जाय। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव रखने का मुझे अवसर दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री श्याम बहादुर सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जनाब गुलाम मौहम्मद साहब द्वारा रखे गये, समर्थन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, हमारी सरकार की चर्चा चल रही थी, अभी हमारे मा0 मंत्री जी ने बोला, मैं भी कहना चाहता था, अभी मा0 नेता जी के व्यक्तित्व पर बात चल पड़ी, मुबारकपुर के मा0 विधायक जी ने कहा, हम भी आजमगढ़ के एम0एल0ए0 हैं, इसलिए कहना चाहते हैं मान्यवर कि सिर्फ मुबारकपुर विधान सभा क्षेत्र में ही अरबों रूपयों का काम हमारी सरकार ने किया है, जो चीनी मिल अभी स्थापित हुई है, एशिया के पैमाने पर सहकारी समिति से इतनी बड़ी चीनी मिल वह भी रिकार्ड समय में अभी एक साल नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि मिल मार्च, 15, 16 या 18 के बीच में चल जायेगी। यह मुबारकपुर से बिल्कुल सटी हुई सठियांव में लग रही है। मान्यवर, मुबारकपुर में 132 के0बी0 का बन कर के तैयार हो गया है, जो बिजली की वह बात कह रहे थे, हम भी छात्र राजनीति से आये हैं, मुबारकपुर बड़ा इलाका था हमारे सिबली कालेज के इलाके में, हजारों वोट वहां के थे, वहां से हमारा भी अच्छा लगाव है, वहां के बुनकरों की समस्या जब–जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, चाहे उनके बिजली बिल की माफी का मसला रहा हो, चाहे उन्हें बिजली देने की सुविधा का मसला रहा हो या और भी जो अवस्थापना सुविधायें देकर के मुबारकपुर को आगे बढ़ाने का हमारी सरकार ने तब–तब काम किया। मान्यवर, इसके पहले पी0जी0आई0 स्तर का जो अस्पताल बनाया आजमगढ़ में, वह भी उसी विधान सभा क्षेत्र में है और यहां पर हमारे नेता के खिलाफ उनके व्यक्तित्व के खिलाफ बात कर–कर के असली जो विकास हमारी पार्टी वहां पर कर रही है, उसको छुपा कर के यहां सदन में झूठा बयान देकर के मा0 विधायक जी चले गये हैं। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, पानी मुफ्त की बात अभी इधर से आ रही थी कि टेल तक पानी नहीं पहुंचा, ऐसा हो सकता है, बहुत बड़ा प्रदेश है, कहीं न पहुंचा हो, लेकिन जब–जब हाउस चलता

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

है, तभी–तभी यह असुविधा आती है, मा0 मंत्री हैं शिवपाल जी, आजतक ऐसा कहीं पर भी ऐसा पानी हम भी काफी समय से राजनीति में हैं, लेकिन कभी ऐसे टेल तक पानी पहुंचने का काम हमने नहरों में नहीं देखा और सिंचाई मुफ्त इधर से भी पाण्डेय जी बैठे हैं, जनपद से सटे हुए हैं बंट गया है, अब तो मान लीजिए जनपद दूसरा हो गया है, इन्होंने एक बात रखी कि खाद, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, लाठियां खाई किसानों ने, भूल से इन्होंने कह दिया, लाठियां तो किसानों ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में खाया, सोसाइटियों पर सैकड़ों की लाइन लगती थी, सिर फट जाते थे लोगों के और चार साल की सरकार में, कभी भी खाद, बीज के लिए किसानों को लाइन नहीं लगाना पड़ा और न ही लाठी और इस तरह की बात करने का कोई अवसर बन पाया, लेकिन झूठी बातों को कहने के लिए यहां पर हमारे विपक्ष के साथी बैठे रहते हैं, तो सरकार की किरकिरी करने के लिए बैठे रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर कि ऐसा नौजवान मुख्य मंत्री देश के पैमाने पर ही नहीं, दुनिया अगर कहूं तो बुरा नहीं होगा, जो गरीबों, मुसलमानों, किसानों, नौजवानों, छात्रों सबके लिए सोंचता हो और सबके लिए करता हो, ऐसा मुख्य मंत्री देश के इतिहास में मैंने कोई नहीं देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बैट्री के रिक्शे की बात इधर से आई थी। फिरोजाबाद के मनीष असीजा जी चले गए हैं बैट्री चालित रिक्शा की बात आयी थी वह बहुत सी जगहों पर दिया गया है। इसी तरह से एक समस्या लैपटाप के लिए भी दो साल पहले आयी थी। पंद्रह लाख की संख्या में लैपटाप देना था और इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश के अंदर कोई कंपनी लैपटाप बनाने के लिए तैयार नहीं थी। कैसे–कैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था बनाकर के इतनी बड़ी संख्या में लैपटाप उपलब्ध करा करके और इतनी ट्रांसपरेंसी से बांटने का काम किया। पूरे प्रदेश के पैमाने पर कि कहीं से भी एक पैसे की कोई शिकायत नहीं आयी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनको अपनी पॉलिसी के तहत बनाने का, उपलब्ध कराने का, पाने का और बांटने का उसमें थोड़ी असुविधा जरूर हो रही है लेकिन हमारी मंशा सही है। बार–बार यह आता है कि आपकी सरकार ने आपकी पार्टी ने एक घोषणा–पत्र छपवाया था हमने उस समय भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि जो पार्टी पीछे सरकार में थी उसका घोषणा–पत्र कहां है ? हमारे घोषणा–पत्र को यहां लहरा कर दिखाया जाता है और जिस पार्टी ने पीछे बहुमत की सरकार चलायी उसका घोषणा–पत्र कहीं रिकार्ड में है क्या ? क्या वह पार्टी के जो माननीय सदस्य या नेता प्रतिपक्ष है क्या वह सदन के अंदर पार्टी का घोषणा–पत्र दिखा सकते हैं कि हमने यह घोषणा की थी ? मान्यवर, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर हम लिखा–पढ़ी में वायदा करते हैं और हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया है और लोकतंत्र में अगर कुछ बाकी रह गया है तो अभी साल भर का समय है उस पर काम करने का और हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी दिन–रात लग कर उस पर काम करने का काम कर रहे हैं। अभी पेंशन की बात आयी थी। हमारे यहां उस जमाने में मनीष चौहान नाम के जिलाधिकारी थे। 17 करोड़ रूपया पेंशन का भेज दिया गया था अम्बेडकर पार्क बनवाये

जाने के लिए। न किसी विधवा महिला, न किसी विकलांग को, न किसी वृद्ध को, न किसी किसान को कोई पेंशन नहीं मिल पायी पूरे चार–पांच साल की सरकार में। आज हम 45 लाख लोगों को दे रहे हैं। यह हो सकता है, बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा सिस्टम है उसमें यह हो सकता है कि किसी अधिकारी के किसी कर्मचारी के स्तर पर किसी जांच में किसी सर्वे में कुछ गड़बड़ी की गयी हो लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि क्या 45 लाख लोगों को मिल रहा है, तो 45 लाख को फर्जी मिल रहा है। हम कहना चाहते हैं आज हमारे बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम 10 लाख और बढ़ायेंगे 55 लाख लोगों को देंगे तो क्या 55 लाख लोगों को फर्जी मिलेगा ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं त्रुटियां सिस्टम में है उसको भी सुधारने का हमारी सरकार, हमारे मुख्य मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह मैं कहना चाहता हूं कि नीति और नियत यह दोनों हमारे मुख्य मंत्री जी की, हमारी सरकार की साफ है इसलिए गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों के लिए हम काम कर पा रहे हैं। मान्यवर, मैंने बिजली, पानी की बात कर ली, माननीय मंत्री जी हमारे यहां से हमारे बड़े भाई, हमारे नेता हैं, बैठे हैं यह भी विभाग को देख रहे हैं। बिजली के लिए कभी भी ऐसा नहीं रहा है जैसा कि लोग अभी इसको महसूस कर रहे हैं कि सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है। लेकिन हम पीछे थोड़ा जाना चाहते हैं जब 4,200 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए दादरी परियोजना का शिलान्यास माननीय नेता जी ने अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में किया था। कितनी बड़ी साजिश बना करके, ट्रैक्टर चला करके उस योजना को विफल बनाने का काम किया गया था। इसलिए हम उस पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यह महसूस होना चाहिए कि कहां–कहां सरकार को रोड़े डाल करके काम नहीं करने दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षिप्त में कहें।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव–

मान्यवर, सिर्फ दो मिनट में खत्म करूंगा। हमारे विधान सभा में एक सड़क है आसूत मार्ग, जो बेलवाई से आजमगढ़ जनपद को जोड़ती है। बेलवाई जो आपके जिले का सटा हुआ किनारा है, सुल्तानपुर से सटा हुआ है। वहां से आजमगढ़ को आसूत–मिर्जापुर मार्ग करके इसका नाम है। यह 70 में बनी थी। पूरे प्रदेश के अंदर 17 सड़कें बनी थीं, सारी सड़कों का उच्चीकरण और चौड़ीकरण हो गया है। मैंने कई बार इस सड़क के लिए लिखा–पढ़ी की थी। इस पर 1 अरब 67 करोड़ रूपये की स्वीकृति भी हुयी थी। अपरिहार्य कारणों से वह क्यों रुक गया है। मैं विशेष तौर पर इसके लिए आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस पर सुचारु रूप से इस कार्य करा करके इसके चौड़ीकरण और उच्चीकरण का काम कराया जाये क्योंकि यह सड़क दो–तीन जिलों को आजमगढ़ जनपद से जोड़ती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि किथावें दुर्वासा ऋषि का धाम है वहां से लेकर के नहर की पटरी लालपुर एक जगह है वहां तक चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण किया जाना आवश्यक है। नित्तूपुर से दसनवल तक एक पीच का निर्माण

कराया जाना बहुत आवश्यक है। यह करीब तीन किलोमीटर का है। हमारी असनी नदी एक हमारे विधान सभा में है जो बीचों–बीच जाती है। उस नदी की वजह से पीने के पानी का बहुत संकट है। नदी के किनारे के गांवों के लिए वहां हैण्डपम्पों के लिए विशेष व्यवस्था बना दी जाये और उस नदी पर तीन–चार जगहों पर पैदल पुल बनाया जाना बड़ा आवश्यक है एक–दूसरे को जोड़ने के लिए। असनी नदी पर दशनवल में एक पुल बनाया जाना जरूरी है, सुलेमापुर में बनाया जाना आवश्यक है और छज्जोपटी एक गांव हैं, अमगिरियां हैं, ये तीन–चार पैदल पुलों का बनाया जाना बड़ा आवश्यक है। मान्यवर, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा जनपद से करीब 80 कि0मी0 दूर है और सुदूर विधान सभा में मैं चाहता हूं कि एक पॉलीटेक्निक कालेज खुल जाए। मैं आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पॉलीटेक्निक कालेज खोले जाने के लिए और एक छोटी डेरी खोले जाने के लिए प्रयास हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, आपने मुझे मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया जिससे मैं अपनी और अपने क्षेत्र की बात रख सका। आपका बहुत–बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

डा0 अरुण कुमार–

माननीय श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल एवं हमारे नेता श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में बताऊंगा। हमारे यहां बरेली महानगर के अन्दर यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत 28 करोड़ रुपये में 17 ओवर हेड टैंक बने। ये टैंक बन गए हैं, कुछ जगहों पर पाइप लाइन भी पड़ गई है। लोगों ने कनेक्शन भी ले लिए हैं। पानी कभी आता है लेकिन ये टंकियां सुचारु रूप से नहीं चल रही हैं। 78 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी आम जनता को कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। जल निगम कहता है कि हमने टंकियां बना दीं और चलाने का काम नगर निगम का है। नगर निगम कहता है कि हमें हैण्ड ओवर नहीं हुई हैं। जब तक हैण्ड ओवर नहीं होंगी तब तक हम नहीं चलाएँगे। इन दो विभागों के झगड़े में जनता पिस रही है। पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार अपने ही दो विभागों के झगड़े को तय करे और बरेली महानगर की जनता को पानी दिलाए ताकि आने वाले गर्मियों के दिनों में कम से कम शुद्ध पानी मिल सके। अभी तो न नल है, न पानी है। अधिष्ठाता महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपसे बिजली के बारे में भी कहना चाहूंगा। हमारा बरेली जब पहले नगर निगम नहीं था साधारण नगर पालिका थी। जब नगर निगम बना तो उसमें कुछ गांव जुड़े। उन गांवों को रूरल फीडर से बिजली मिलती थी। आज भी उन्हें रूरल फीडर से ही बिजली मिल रही है और उन्हें अरबन फीडर के मुकाबले में बिजली कम देर मिल रही है। मैं चाहता हूं कि उन क्षेत्रों को भी अरबन फीडर से जोड़ दिया जाए ताकि उन्हें भी सुचारु और सही किस्म की बिजली मिल सके। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां बिजली बहुत कम समय मिल पाती है। लगभग 30 साल महानगर से जुड़े हुए हो गए हैं लेकिन उनमें बिजली के मामले में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। शहर के

लिए जो योजनाएं आती हैं वे शहर में लगती हैं वहां पर इसलिए नहीं लग पातीं क्योंकि उनको अरबन फीडर से बिजली की सप्लाई होती है और देहात की जो योजनाएं आती हैं जैसे पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना या अन्य योजना वे वहां पर इसलिए लागू नहीं हो पातीं क्योंकि वे अब महानगर का हिस्सा हैं। वे क्षेत्र अब न इधर के रहे, न उधर के रहे। वहां पर बिजली का कोई विकास नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि वहां अरबन फीडर से बिजली दी जाए और वहां पर भी विकास किया जाए। अधिष्ठाता महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे बरेली महानगर के अन्दर हाउस टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। विशेषकर कामर्शियल भवनों पर 10 गुना टैक्स बढ़ाया गया है जो जबरन वसूला जाता है जिससे लॉ ऐण्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक दम से 10 गुना टैक्स बढ़ाना, यह किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से मैं चाहूंगा कि वहां पर ट्रैफिक के लिए श्यामगंज पर एक ओवर ब्रिज बनाया जाए जो थाना बारादरी से बरेली कॉलेज तक हो ताकि लोगों को चलने में आसानी हो सके। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति की जाए और एक डायलिसिस मशीन लगाई जाए। डायलिसिस मशीन गुर्दा रोगियों के लिए बहुत जरूरी है। पिछले लगभग 6–7 साल पहले एक डायलिसिस मशीन लगी थी लेकिन वहां पर कोई भी चिकित्सक नियुक्त नहीं किया गया है, टेक्नीशियन नियुक्त नहीं किया गया है, केमिकल्स नहीं भेजे गए जिसकी वजह से वह मशीन कूड़ेखाने में चली गई और किसी काम की नहीं रही। मैं यह चाहता हूं कि वहां पर एक नई दूसरी डायलिसिस मशीन जिसके लिए कई दफा सरकार ने कहा भी है कि जल्दी लगवाएंगे, जल्दी लगवाएँगे लेकिन अभी तक नहीं लगी है। उन गरीब गुर्दा मरीजों का ख्याल रखते हुए, मेहरबानी करके नई डायलिसिस की मशीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बरेली में जल्दी से जल्दी लगवा दें। इसके साथ ही विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन की राशि कम से कम 01 हजार रुपये प्रतिमाह की जाए। 300 रुपये में कुछ नहीं होता है, जब तीन सौ रुपये की गई होगी तब भी यह राशि बहुत कम रही होगी लेकिन आज के इस महंगाई के दौर में 300 रुपये देना सिर्फ मजाक करना है। मैं चाहता हूं इसे कम से कम 1000 रुपये किया जाए। बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र में हमारे यहां एक फायर ब्रिगेड की बहुत सख्त जरूरत है। वहां पर कोई फायर ब्रिग्रेड नहीं है, काफी दूर से फायर ब्रिगेड आती है और रास्ते में जाम मिलता है, जिससे फायर ब्रिगेड समय से नहीं आ पाती और बहुत ज्यादा जन–धन की हानि होती है। मैं चाहता हूं कि एक फायर ब्रिगेड वहां बनाई जाए। इसके साथ ही साथ सिविलियन इनक्लेव की आवश्यकता है, हमारे यहां जो मिलिट्री का हवाई अड्डा है, उसी में एक सिविलियन इनक्लेव बनाने की बात चल रही है। जमीन की काफी कुछ खरीदारी हो गई है, मैं चाहता हूं कि उसमें तेजी लाई जाए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी सिविलियन इनक्लेव की सहूलियत मिले और लोगों का आना–जाना हो सके। लगभग चार साल से हम लोग सुन रहे हैं कि ई–रिक्शा मिलेगा, ई–रिक्शा मिलेगा लेकिन आज तक तो बरेली को मिला नहीं। मैं चाहता हूं इस सरकार से कि बरेली के गरीब रिक्शा चालकों को ई रिक्शा दी जाए ताकि

वह मेहनतकश लोग कुछ सुकून महसूस कर सकें। उनके पास भी ई–रिक्शा हो, जो पसीना बहाते हैं, कुछ उन्हें भी थोड़ा आराम मिले। ई–रिक्शा आप जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दें। साथ–ही–साथ बरेली के अंदर गलियों की स्थिति बहुत ही खराब है। सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं और वहां पर जल निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं है। हल्की सी बारिश में ही सड़क नहर बन जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, लोगों को अपने कार्यालय आने–जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं चाहता हूं कि सड़कों को बनाया जाए। जब भी सड़कों को बनवाने के लिए नगर निगम से या विकास प्राधिकरण से कहा जाता है, तो वे कह देते हैं कि यह कॉलोनी वैध नहीं है। कॉलोनी अवैध है इसलिए उसमें काम नहीं हो सकता है। कॉलोनी वैध या अवैध हो सकती है लेकिन वहां भी इंसान रहते हैं और जब अवैध कॉलोनी बनती है वह खाली कॉलोनाइजर नहीं बनाता वह प्राधिकरण और प्रशासन के पूरे सहयोग से बनाता है। इसकी जिम्मेदारी जनता की नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है, उन प्राधिकरण के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है, जिन्होंने कॉलोनाइजर से सांठ–गांठ करके अवैध कॉलोनियां बसाईं और वहां पर लोगों को नारकीय जीवन मिल रहा है। वहां पर विकास कार्य नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और विकास कार्य कराने चाहिए। आज बरेली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है बेरोजगारी और खासतौर से नौजवानों में बेरोजगारी है। आज नौजवान हमारा बेरोजगार है। नौजवान कुण्ठाग्रस्त हो रहा है, नौजवान परेशान है। खासतौर से पढ़ा–लिखा नौजवान, पढ़ा–लिखा बरोजगार इसलिए मैं चाहता हूं कि बरेली में एक बड़ा उद्योग लगाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री राजेश त्रिपाठी–

धन्यवाद, माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष जी ने जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया है, नेता प्रतिपक्ष जी के समर्थन में हम अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए हैं। माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण के पहले पन्ने पर जो प्रमुख बात कही है, मैं वहीं तक अपने को सीमित रखना चाहता हूं। ''मेरी सरकार ने लगभग अपने सभी वायदे पूरे किये हैं और हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है।'' हो सकता है माननीय राज्यपाल जी ने जहां का देखा होगा, वहां का लिखा होगा। हमारे अपने क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, वहीं से शुरू करना चाहता हूं, चूंकि मेरे यहां तो कुछ नहीं हुआ है। वायदे जो कहे गए हैं, वह पूरे नहीं किये गये हैं। कथनी और करनी में फर्क दिखा है। मैं अपने को वहीं पर केन्द्रित करना चाहता हूं और इस विधान सभा में सरकार ने जो वायदे किये थे। इस विधान सभा में सदन के सदस्यों और आपके सामने किये गए वायदे तक पूरे नहीं किये गये हैं, इसलिए यह बात सत्य से परे लग रही है कि कथनी–करनी में फर्क नहीं है। इसी विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखित जवाब में कहा था कि चिल्लूपार क्षेत्र में जो राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज बन रहा है, वर्ष 2015–16 में वहां पढ़ाई शुरू हो जायेगी और ऐसा नहीं

हुआ अभी उसका निर्माण कार्य तक पूरा नहीं किया गया, पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस सरकार ने चुनाव के दौरान यह वादा किया था कि बंद चीनी मिलों को चलाया जायेगा। इस हाउस मे कई बार इस मामले को लेकर मैं आया कि चिल्लूपार क्षेत्र में धुरियापार सहकारी चीनी मिल है जो बन्द पड़ी है, उसे चलाया जाना चाहिए। आश्वासन मिला था कि ऐसा किया जायेगा मगर आज तक उस धुरियापार चीनी मिल को चलाने की कोई प्रक्रिया आरम्भ नही हुई। इस नाते मैं यह बात कहना चाह रहा था कि सरकार ने अपने ही किये वादे पूरे नहीं किये हमारे क्षेत्र में आई0टी0आई0 कालेज बन रहा है राजकीय आई0टी0आई0 कालेज, पिछले पांच वर्षों से उसका कार्य ठप पड़ा है और इस सदन में आश्वस्त किया गया था लिखित आश्वासन दिया गया था कि 2014 में आई0टी0आई0 कालेज को आरम्भ कराकर पढ़ाई शुरू की जायेगी परन्तु 2016 आ गया वह ज्यों का त्यों ठप पड़ा हुआ है। कैसे माना जाये कि सरकार ने जितने वादे किये हैं, वे पूरे किये हैं ? मान्यवर, सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, लोहिया ग्राम जिसके तहत सड़के बनाई जाती हैं, आवास देना होता और भी कई तरह से उसे संतृप्त करना होता है। मैं और जगहों की बात नही जानता सरकार कह रही है तो कहीं पर कार्य किया होगा। तभी राज्यपाल महोदय कह रहे होंगे। मगर हमारे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी लोहिया ग्राम चयन हुए 2013–14 में जो लोहिया ग्राम का चयन हुआ वह आज तक सन्तृप्त नहीं हुआ। सरकार के जवाब कुछ और आते हैं अधिकारियों के धरातल पर क्रियाकलाप कुछ और होते हैं। 2014–15 में जो लोहिया ग्राम का चयन हुआ था वहां अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। 2015–16 में जो लोहिया ग्राम का चयन हुआ था वहां भी अभी तक कार्य आरम्भ नही किया गया है। यह बात यह साबित कर रही है कि जब लोहिया गांव तो सरकार के प्रमुख एजेण्डे में है और यहां से घोषणा हो गयी और उसका तीन साल से मौके पर कार्य नही हो रहा है तो कैसे माना जाये कि सरकार ने जो वादा किया उसे निभाया है। इसके अलावा सरकार ने ओलावृष्टि पर अपनी बात रखी मैं इस बात को साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत क्विक डिसीजन लेते हुए भारत सरकार से तत्काल मदद न मिलने के बावजूद आपने किसानों को राहत देने का निर्णय लिया। मगर आपने कभी इस बात को जानने का प्रयास किया कि जो आपने धन दिया क्या वह किसानों तक पहुंचा। जिले में धन पड़ा है या बंट गया ? हालात यह है कि जानकारी के अनुसार आपके भेजे धन जिले में पड़े हुए हैं और सरकार के मुलाजिमों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा दे सकें यह सरकार की कथनी–करनी की स्थिति है। सूखावृष्टि का जहां तक सवाल है आपने वादा किया था कि सूखाग्रस्त किसानों को हम मुआवजा देंगे, उनको राहत पहुंचायेंगे, जब ओलावृष्टि की यह हालत हमने आपको बताई कि वह पैसा पड़ा है, नहीं बंटा तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आपने क्या किया होगा। आप हमसे बेहतर जानेंगे। इसके अलावा अभी हमारे साथी श्री उमेश पाण्डेय जी इस बात का जिक्र कर रहे थे और माननीय मंत्री जी इस पर सामने से काउण्टर लगा रहे थे। आपने वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे आपने एक पार्ट में उसको कहीं पर किया भूमि विकास बैंक का मगर वादे में

यह बात नहीं थी कि पश्चिम में आप किस बैंक का माफ करेंगे। हमने यह सोचा, किसानों ने यह सोचा, लोगों ने यह सोचा कि सरकार 50 हजार रुपये किसानों का कर्ज माफ करेगी अर्थात् जो भी किसान कर्ज लिया होगा, जहां से भी कर्ज लिया होगा, वह माफ करेगी आपकी सरकार। इस उम्मीद में किसानों ने आपकी सरकार बनवाई थी, मगर पूर्वान्चल का किसान तो अपने को ठगा महसूस कर रहा है, जब उसने यह पाया कि पूर्वान्चल में तो माफी ही नहीं मैं अपने यहां का बताऊं गोरखपुर जनपद में केवल एक भूमि विकास बैंक है वह भी बासगांव तहसील में है वह भी वहां बहुत नौमिनल लोगों के उपयोग में आता है। शायद ही वहां पर कोई लोन लेने जाता होगा। सरकार के वायदे का कोटा तो पूरा हो गया कि हमने कर्ज माफ किया केवल भूमि विकास बैंक का किया। मगर पूर्वान्चल का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि वादा तो किया गया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे उसने उम्मीद लगाई थी कि वह भी उसमे शामिल हैं मगर ऐसा नहीं हुआ। यह है आपके वादे की स्थिति एक वादे की स्थिति यह है कि जैसे ही सरकार बनी थी कहा था कि सभी सड़कों को एक वर्ष के अन्दर गड्ढा मुक्त कर दिया जाये और इसके अलावा सभी टूटी–फूटी जर्जर सड़कों की पूरी तरीके से मरम्मत करा दी जाये लगभग 60–65 सड़कों की सूची हमने स्वयं दिया लेकिन उनमें तमाम सड़के ज्यों की त्यों जर्जर पड़ी हुईं हैं। उस पर एक्सीडेन्ट हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, लगातार प्रमुख सचिव तक विभाग में सूचनायें दी जा रही हैं उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहे हैं, कैसे मानू कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं है। सरकार द्वारा यह बात कही जाती है कि बिजली विभाग द्वारा पूरी तरीके से गांव का विद्युतीकरण कराया जा रहा है जर्जर पोल तार बदले जा रहे हैं कितनी बार कहा गया, थक गये हम लोग कहते कहते अधिकारियों से विभाग की चिल्लूपार फलां–फलां गांव में विद्युत के पोल और तार जर्जर पड़े हैं उनको बदला जाय। जो कुछ है पड़े हुए हैं कैसे मान लूं कि जो वायदे किये गये थे वह पूरे हो गये हैं ?

मान्यवर, सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर आप जानते हैं डाक्टर साहब और माननीय मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं सच्चाई यह है कि स्वास्थ्य विभाग से आपकी दवायें जाती होंगी मगर मरीज बाहर से पर्चा लेकर के दवा ले रहा है। वहीं मेडिकल कालेज के लोग यही कर रहे हैं। अखबार में रोज छाप रहा है, रोज सदर अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक यह बाते आ रही हैं कि दवायें मरीजों को नहीं दी जा रही हैं। निजी मेडिकल स्टोर से मजबूरन जनता को लेना पड़ रहा है दवाओं की यह स्थिति है। मान्यवर, चूंकि अभी बजट की चर्चा नहीं हो रही है इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा लेकिन पिछले कई वर्षों से गरीब इंतजार कर रहा था चाहे वह किसी भी समाज का गरीब हो वह इंतजार कर रहा था कि सरकार गरीब बेटियों की शादी के लिए अनुदान देगी इस बार ऐसा किया गया लेकिन 4 साल वह परेशान रहा और तमाम फाइलें पड़ी रहीं अब तो अधिकारियों ने फाइल लेना भी बन्द कर दिया वे कहते हैं कि जब सरकार मदद दे ही नहीं रही तो तुम फाइल क्यों देते हो। यह बात एहसास करा रहा है कि अधिकारी कह रहा है कि क्यों देते हो फाइल, क्यों 50

रुपया, 100 रुपया खर्च करते हो सरकार तो नहीं देने जा रही है। यह सरकारी अनुदान की स्थितियां रही है विधवा, विकलांग, वृद्धा पेंशन की जो स्थिति है वह आप बेहतर जानते हैं कुछ सीमा तक भले आप दिये होंगे मगर गांवों में बहुत तड़पन है, बहुत पीड़ा है कि हम एक तरफ तो यश भारती पुरस्कार की घोषणा करते हैं उसके लिए पेंशन 50 हजार रुपया महीना देते हैं जो रुपये पैसे से भरा पड़ा है उसे भी हम 50 हजार रुपया महीना पेंशन दे रहे हैं और गांवों में 300 के लिए विधवा। हमारी माताएं हमारी तड़प रही हैं, विकलांग हमारा 300 के लिए परेशान हो और वहां पर हम नहीं दे पाते, दे पा रहे हैं। हम यशभारती पुरस्कार दे कोई बात नहीं मगर उन गांव की विधवाओं को, वृद्धा और विकलांग पेंशन की धनराशि बढ़ाई जाती हजार दो हजार की जाती तो मानक समझ में आता समझ में नहीं आता कि गरीबों की सरकार कहकर लोग आते हैं और 50 हजार पेंशन किसी और को दी जाती है और गरीब ज्यों का त्यों अपने को ठगे महसूस करते हैं। यश भारती सम्मान दे रहे हैं आप बिलकुल सम्मान प्रतिभाओं का होना चाहिए मगर एकेडमिक एवार्ड जो वर्षों से बन्द पड़ा था आपकी सरकार ने घोषणा किया था कि जैसे ही आयेंगे एकेडमी एवार्ड की शुरुआत करेंगे। एकेडमी एवार्ड अर्थात संगीत एकेडमी एवार्ड या अन्य एवार्ड। को दो यश भारती के पुरस्कार में रोक दिया जाय तो 10 साल तक लगातार एकेडमी एवार्ड दिये जा सकते हैं यह परिस्थितियां हैं कि एकेडमी एवार्डी हमारे तड़प रहे हैं। मांग कर रहे हैं अगर यश भारती पुरस्कार पाने वाले को पेंशन मिलना चाहिए तो फिर हमारे उर्दू एकेडमी या साहित्य एकेडमी या संगीत एकेडमी के जो हमारे एवार्डी हैं उन्हें पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए। हम यह निवेदन करेंगे कि काश यह राज्यपाल जी के अभिभाषण में अगर एकेडमी एवार्ड को देने की घोषणा की चर्चा की गयी होती, तो अच्छा होता घोषणा किया गया और एकेडमी एवार्ड नहीं दिया गया तो कैसे मान लें कि जो आपने कहा था उसको पूरा किया। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता था कि आपके द्वारा जो राजकीय ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं। उसकी स्थिति यह है कि कुछ दूर ले जाकर के कोलाबा बनाकर छोड़ दिया जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर आप सरकारी ट्यूबवेल लगा रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा दूरी तक निर्धारित दूरी से अधिक लेकर के उन किसानों के खेतों में कोलाबा बनाया जाना चाहिए। अगर पुराने कोलाबे टूट गये है तो उनका निर्माण कराया जाना चाहिए क्योंकि अगर आप बिल्डिंग को खड़ा कर देंगे मशीन लगा देंगे उस पर पावर लगा देंगे मगर अगर किसानों के खेतों तक पानी नहीं जायेगा तो वह बेकार होगा और कोलाबा के अभाव में आपके ट्यूबवेल बेकार पड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है कि कोलाबें को बढ़ाया जाय। इसी हाउस में यह आश्वस्त किया गया था कि हमारे क्षेत्र में दो जगह खखाइजातोर और खानपुरा में जो पावर स्टेशन बनाया 33 के0वी0ए0 का, पिछले 4 वर्षो से उसका काम ठप पड़ा हुआ है और इस हाउस में कहा गया था कि 2014 में दोनों सब–स्टेशन को पूरा करा दिया जायेगा मगर वह दोनों सब–स्टेशन ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं मेरा सरकार से आग्रह है आपके माध्यम से कि हमारे चिल्लूपार के जो अधूरे सब–स्टेशन हैं उसको पूरा कराया जाय ताकि विद्युत की आपूर्ति लोगों को बेहतर मिल

सके। पानी की टंकी के बारे में हमारे बीजेपी के साथी चर्चा कर रहे थे मैं भी अपने यहां की बात कहना चाहता हूं कि पानी की टंकियां तो खड़ी हैं मगर वह सफेद हाथी की तरह खड़ी हैं उनको बिजली नहीं मिल रही हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, वहां ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं विभाग दोनों विभाग आपस में उलझे हुए हैं पता नहीं क्या तकनीकी दिक्कत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपकी मंशा साफ हो सकता है कि सही हो मगर दिमाग से कोई संदेश आप देना चाहेंगे और हाथ पैर काम नहीं करे। दिमाग के निर्देश को नहीं माने तो केवल दिमाग के कहने से क्या होगा। हो सकता है राज्यपाल जी सही कह रहे हों, हो सकता है माननीय मुख्य मंत्री जी सही कह रहे हों, मगर धरातल के स्तर पर कार्य नहीं हो रहे हैं, सरकार की किरकिरी हो रही है और हम जैसे जनप्रतिनिधियों को जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। जनता सिर्फ यह जानती है कि विधान सभा में यह बैठे हैं, यह जो कहेंगे और वहां जब अपनी बात उठायेंगे तो कार्य होगा। हालात यह है कि न आपकी सुनी जा रही है, न हमारी सुनी जा रही है, कोई नहीं सुन रहा है, स्थिति बहुत दयनीय है। इस नाते यह कहना कि जो वादा किया है वह हम पूरा कर रहे हैं, या फिर यह कहना कि कथनी और करनी में अंतर नहीं है, धरातल पर बहुत फर्क है। कृपया आपसे निवेदन है कि सरकार अपनी कथनी और करनी के अंतर को मिटाये और ऊपर से जो निर्देश जा रहा है, वह धरातल तक पहुंचे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल जी ने अपने भाषण में यह बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही है और अपने घोषणा–पत्र में जो कुछ लिखा था उन सारे वायदे को सरकार ने पूरा किया है और राज्यपाल जी ने इस बात को साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी सरकार पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो सही ढंग से काम करके जनता के हितों पर विशेष ध्यान दे रही है। तमाम योजनायें जो लागू की गई हैं, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, कन्या विद्या धन हो, समाजवादी पेंशन हो, उन तमाम योजनाओं को जिस प्रकार से घोषणा किया था, उसी प्रकार से जनता के बीच में करके दिखाने का काम यदि किसी ने किया है, तो वह समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। विपक्ष में बैठे लोग हमारा विरोध करते हैं, बात सही है कि वह विपक्ष में हैं इसलिये उनको विरोध करना चाहिये, लेकिन विरोध सार्थक होना चाहिये। विरोध इस प्रकार का हो कि जो चीज सही हो उसको स्वीकारते हुए अन्य बातों पर विरोध करना चाहिये। इस तरह से गलत तरह से विरोध करके समाज को गुमराह करना नहीं चाहिये। जनता के बीच में गुमराह करने का यह काम करते हैं। कानून–व्यवस्था के ऊपर बसपा के कुछ लोगों ने बोला, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मायावती जी की सरकार थी, तो हमारे क्षेत्र में 27 ब्राम्हणों के ऊपर फर्जी एस0सी0/एस0टी0 का मुकदमा लगवाने का काम किया गया था, जो बड़ी

शर्मनाक बात रही। इस तरह से उस जमाने में तमाम लोग थर–थर कांप रहे थे कि बसपा के लोग कपड़ा फाड़कर झूठे मुकदमें कायम करवाने का काम कर सकते हैं। हमारे भाई मो0 गुलाम ने जो अभिभाषण का समर्थन किया है उनके पक्ष में मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता ने जो काम किये हैं उनकी हम लोग सराहना करते हैं। हम ज्यादा कुछ न कहते हुये यह कहना चाहते हैं कि ''यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ वर्क'' यह तीन चीजें ऐसी होती हैं, यह जिसके अंदर मौजूद हो, तो वह सरकार कभी असफल नहीं होती है। हमारी समाजवादी पार्टी के अंदर एक यूनिटी है, स्थान है, कार्य करने की क्षमता है। हमारे मंत्रीगण क्षेत्र में जाकर काम देखते हैं, काम करते हैं और कोई भी कार्यकर्ता निराश नहीं होने पाता है। आज पूरे प्रदेश का यूथ हमारे साथ इसलिये खड़ा है, क्योंकि हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर उनका काम करते हैं और उनको तरजीह देते हैं। जनता का जो भी काम होता है, वह आसानी से हो जाता है। इसलिये सरकार ने जो काम किये हैं, वह निश्चित ही बहुत अच्छे काम हैं। हम ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। हमारे भाई श्री श्याम बहादुर जी हमारे बगल के विधायक हैं, वहां पर एक स्थान है भेलारा। भेलारा से कलाफतपुर तक लगभग बीस वर्षों से एक नाला पड़ा हुआ है, जब वह खुद जायेगा तो उससे किसानों की हजारों बीघा जमीन को लाभ मिलेगा। वह नाला खुद जाने से पानी चला जायेगा और लोगों को सुविधा हो जायेगी। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में सूरापुर से लेकर इब्राहीमपुर तक जो पी0एम0जे0एस0वाई0 के अन्तर्गत सड़क थी, वह सड़क नहीं बन पायी है, उस सड़क को इब्राहीमपुर तक चौड़ीकरण होना चाहिये और उसके बाद विजयथुआ से मुदराघाट तक सड़क की विशेष मरम्मत होना चाहिये जो बीसों वर्ष से पड़ी है सरकार को हमने लिखकर दिया है, 224 सड़कें बन रही हैं लेकिन यह हमारी महत्वपूर्ण सड़क है इसको भी बनाने की आवश्यकता है और हमारे बांगरकलां से लेकर बांगरखुर्द तक बीच में एक हमारी सड़क बनी है उसमें एक छोटी सी पुलिया टूट गयी, उसको बनाने की आवश्यकता है, वह पुलिया हजारों लोगों के आने जाने का रास्ता है, तमाम गाड़ियां भी आती जाती है, इसके लिये भी हमने लिखकर दिया है, आश्वासन भी मिला है लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दी वह कार्य हो जाय ताकि समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों में यह सोच पैदा होगी कि समाजवादी पार्टी सरकार जो कहती है वह काम हो जायेगा और खन्डौरा से बिजेश्वा तक सड़क की विशेष मरम्मत भी होना है। अधिष्ठाता महोदय, पूर्वांचल विकास निगम द्वारा एक कादीपुर चीनी मिल चल रही थी, उस चीनी मिल को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह ने तोड़ दिया था, वह जमीन पड़ी हुयी है उस जमीन को अधिग्रहीत करके सरकार जो कोई कल कारखाना वहां लगवा दे तो निश्चित ही हजारों लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें रोजगार मिल जायेगा। उस जमीन पर घेरा बना हुआ है और बिल्डिंग बनी हुयी है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में इंटर कालेजों और महाविद्यालयों की कमी नहीं है लेकिन लड़कियों की शिक्षा हेतु एक राजकीय महाविद्यालय का होना नितान्त आवश्यक है इसके खुल जाने से

हमारे क्षेत्र की महिलाओं को शिक्षा में बहुत अधिक सहयोग मिलेगा और हमारी महिलाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दूसरी बात, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कादीपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दोस्तपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करदीकलां, यह तीन हमारे यहां हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि जो तहसील हेडक्वार्टर है कादीपुर में, वहां सामुदायिक केन्द्र को उच्चीकृत करके 100 बेड का हास्पिटल बनवाया जाय इससे जो तमाम मरीज दूर से आते हैं, उनको वहां पर सुविधा मिल सके। इस तरह से हमने अपने क्षेत्र की जो समस्यायें बतायी हैं वह बड़ी महत्वपूर्ण हैं इनके हो जाने से हमारे यहां जो पुल बन रहा है इमलियाघाट का गोमती नदी पर, वह पुल जल्दी बन जाये और अधिष्ठाता महोदय यह हमारा गुदराघाट का पुल स्वीकृत हुआ था उसके लिये मैनें माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखकर दिया था वहां पीपे का पुल लगना था वह किन्हीं कारणों से रोक दिया गया है उसको जल्द से जल्द बनवाया जाय, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, बहुत–बहुत धन्यवाद ।

'श्री रविन्द्र जायसवाल–

धन्यवाद महोदय, वाराणसी पर्यटन का बहुत बड़ा केन्द्र है इसे पूर्वांचल की राजधानी बोलते हैं आज बनारस पूरी तरह गड्ढों में तब्दील है वहां की योजनायें चाहे जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की हो चाहे जायका की हो यह सारी योजनायें फेल हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने 13 स्मार्ट सिटी दी थी, वह 13 स्मार्ट सिटी में से प्रदेश सरकार ने मात्र 12 का प्रस्ताव दिया था प्रदेश सरकार एक सिटी का नाम तय नहीं कर पाई थी। भारत सरकार ने बनारस को भी स्मार्ट सिटी में रखा था और दो करोड़ रुपया प्रति शहर यानि 24 करोड़ भारत सरकार ने एक सितम्बर को प्रदेश सरकार को दिया था पब्लिक की इसमें जन सहभागिता हो इस कारण से एक एग्जामिन कराया था, लोगों की राय लेनी थी। उस राय के लिए अलग–अलग शहर के लिए अलग–अलग कम्पनियां बनाई गई थीं जैसे कि बनारस के लिए बिल्डकॉन कम्पनी थी। इन्हें 5 नवम्बर तक ई–गवर्नेन्स के काम करने थे गवर्नेन्स के माध्यम से एक्जामिन किया जाता कि भारत सरकार के लिए 20 स्मार्ट सिटी कौन और इसके लिए इन्होंने 24 करोड़ रुपया दिया था। भारत सरकार से पैसा 1 सितम्बर को प्रदेश सरकार को मिल गया था लेकिन प्रदेश सरकार ने 5 नवम्बर छोड़ दीजिए, 5 दिसम्बर छोड़ दीजिए, 5 जनवरी, 5 फरवरी बीत गई लेकिन स्मार्ट सिटी का पैसा जिले तक भेजा ही नहीं गया। आज अगर उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी नहीं हो पाया है तो प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा भेजे गये पैसे को जिले तक भेजा ही नहीं इस कारण से प्रदेश का कोई भी सिटी स्मार्ट सिटी में नहीं आ पाया। स्मार्ट सिटी का जो मुख्य सिद्धान्त था प्रदेश सरकार के 5 सौ करोड़ रुपए और भारत सरकार के 5 सौ करोड़ रुपए से मिल करके सिटी बनाना था। प्रदेश सरकार ने 5 सौ करोड़ रुपए देने के बजाय जो दो करोड़ रुपए प्रति सिटी दिया गया था उसको भी

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

रख लिया, उसे जिले तक नहीं भेजा। आज बनारस शहर पूरा गड्ढे में तब्दील है, 4 हजार 7 करोड़ रुपए सीवर के लिए दिया था। वहां का जो विकास दर है सीवर की लाइन है 2009 की योजना थी वहॉ पर मात्र 37 प्रतिशत काम किया गया है। स्मार्ट सिटी में न आने के कारण से जो प्रदेश की कार्य योजनाएं हैं जो कल्चर है उसका फेल होना था। वहां 2009 का सीवर पड़ना था इसके लिए 450 करोड़ रुपया जापान ने एक परसेंट के ऋण पर पैसा दिया था उसका भी विकास मात्र 48 प्रतिशत हुआ है। इस कारण से पूरे प्रदेश में स्मार्ट सिटी फेल हुआ क्योंकि कल्चर खराब है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के कल्चर में हमें सुधार करना चाहिए, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वह डी0एम0 हों, चाहे नगर आयुक्त हों, चाहे कमिश्नर हों, चाहे किसी विभाग का ए0सी0 और एक्स0ई0एन0 हो, जब योजना फेल होती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये अपना प्रमोशन लेते हैं और जब योजनाएं फेल होती हैं तो इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई योजना फेल होती है, धीमी गति से होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए। जिस दिन यह ऐक्शन का काम हो जायेगा तो उत्तर प्रदेश के कल्चर में वृद्धि होगी और कल्चर में परिवर्तन होगा और कार्य योजनाएं ठीक होंगी लेकिन ये ब्यूरोक्रेट विधायिका को बदनाम करने के लिए कहते रहते हैं सरकारें आती जाती रहती हैं, ये सरकार फेल है वह सरकार फेल है, यह नहीं किया वह नहीं किया। मैं मांग करता हूं कि कहीं न कहीं इनको भी कटघरे में घेरना चाहिए अगर योजनाएं फेल होती हैं तो उसका डी0पी0आर0 किसने बनाया था, अधिकारी कौन था इंचार्ज कौन था उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके प्रमोशन रुकने चाहिए। मान्यवर, पूर्वांचल शिक्षा की राजधानी कही जाती थी लेकिन प्राईवेट सेक्टर में आज पूरे उत्तर प्रदेश में 19 प्राईवेट विश्वविद्यालय खोले गये हैं लेकिन पूर्वांचल में एक भी नहीं है। प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि आपने बीच में प्राईवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए भूमि का मानक 100 एकड़ से 25 एकड़ किया और 25 एकड़ से 10 एकड़ कर दिया था लेकिन दो ही महीने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज आपने पास करा दिया उसके बाद 100 एकड़ फिर से कर दिया। मान्यवर, 100 एकड़ भूमि चाहे गोरखपुर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो या बनारस हो 100 एकड़ भूमि नहीं मिल सकती है। मेरी मांग है कि इसके मानक में पूर्वांचल के लिए ढील दी जाए जिससे कि वहां पर भी प्राईवेट यूनिवर्सिटीज खुल सकें। सारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट हों, उद्योगपति हों, पॉलीटीशियन हों इनके सारे बच्चे यू0पी0 के बाहर पूने में, बंगलौर में, हैदराबाद में या देश के बाहर ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उत्तर प्रदेश का कोई भी यूनिवर्सिटी 1 लेबिल के 100 के रेंज में नहीं है, 200 के रेंज में नहीं है, 300 के रेंज में नहीं है, उत्तर प्रदेश का कोई भी युनिवर्सिटी 500 रेंज के पहले नहीं आता है, हमें इन्हें कहीं न कहीं बदलना चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि युनिवर्सिटीज के अन्दर 11–11 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। एक युनिवर्सिटी में यदि 11 लाख बच्चे एग्जाम देंगे तो सिर्फ उनके पास एक प्रिन्टिंग मशीन होगी जहां डिग्री छाप कर दी जाती है। मेरी मांग है कि किसी भी युनिवर्सिटी में 100 से ऊपर कॉलेज न हों, किसी भी

युनिवर्सिटी के अन्दर एक लाख से अधिक बच्चे न हो। अगर बच्चे एक लाख से अधिक होंगे तो वहां प्रिन्टिंग मशीन के कारखाने के रूप में ही काम होगा। ऐसी स्थिति में सारे लोग अपने बच्चों को यू0पी0 से बाहर पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मान्यवर, मैं बनारस से बिलॉग करता हूं, मेरी विधान सभा वाराणसी उत्तरी है। वरुणा नदी है, वरुणा नदी पर पुल बनना चाहिए, दो ही पुल वहां पर हैं जहां जाम लगती है, वहां पर एक पुल बनना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी आयुर्वेद का विश्वविद्यालय नहीं है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, बनारस में सम्पूर्णानन्द आयुर्वेद कॉलेज है। मेरी मांग है कि उसे विश्वविद्यालय बनाया जाए, विश्वविद्यालय बनाये जाने का प्रस्ताव भी वहां से पूर्व सरकार में आया था मेरी मांग है कि उसे आयुर्वेद का विश्वविद्यालय बनाया जाए। मान्यवर, शहरों के लिए अवस्थापना निधि होती है, दो प्रतिशत एक्स्ट्रा स्टाम्प से ये निधि बनाये जाते हैं। बनारस में पिछली बार 84 करोड़ रुपया अवस्थापना निधि में आया था उस निधि में कमिश्नर चेयरमैन होते हैं और जिलाधिकारी, नगर आयुक्त मेम्बर होते हैं। पूरी तरह से अगर इस पैसे का सदुपयोग किया जाए तो कोई शहर ऐसा नहीं है जो शहर गड्ढे से मुक्त न हो जाये। कोई शहर हो, सारे शहर गड्ढे में तब्दील हैं मेरा सुझाव है कि वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अवस्थापना निधि की कमेटी में उनको रखा जाय। कोई भी ब्योरोक्रेट किसी भी शहर में 6 महीने या साल भर के लिए आता है, जो अधिकारी साल भर या 6 महीने के लिए आता है तो उस शहर की जो बेसिक प्राब्लम है उसको समझता व जानता नहीं है लेकिन चेयरमैन वह रहेगा, मेम्बर वह रहेगा, इस कारण से पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग होता है। बनारस में अवस्थापना निधि में पिछले साल 84 करोड़ रुपये था, उसके पहले 76 करोड़ रुपये था। अगर पैसे प्रापर ढंग से यूज किये गये होते तो बनारस आज गड्ढे से मुक्त हो जाता लेकिन आज पूरा शहर गड्ढे में तब्दील है। इसी प्रकार से 11वां वित्त, 13वां वित्त, 14वां वित्त आयोग आने वाला है उस पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग करते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करिये।

श्री रविन्द्र जायसवाल–

और नाली के ऊपर नाली बनाकर उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। 14वां वित्त आयोग का पैसा अभी आने वाला है नगर निगम ने अभी तक योजना बनायी नहीं है और अगर बनायेगी महीने भर में तो केवल उसका दुरुपयोग करेगी। मेरी मांग है कि उसमें जो लोकल विधायक होते हैं उनको कमेटी में रखा जाए, उनसे राय लिया जाए उस शहर के कुछ लोग आर्किटेक्ट होंगे, शहर के सम्भ्रान्त लोग होंगे उनको रखा जाए और उनकी राय ली जाए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री राजकुमार रावत–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय नेता विरोधी दल द्वारा अभिभाषण पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मथुरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन, जो भगवान कृष्ण की क्रीड़ास्थली, जन्मस्थली, लीलाधाम से मैं सदन का प्रतिनिधित्व करता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में अगर कहीं कानून–व्यवस्था के नाम पर, अगर कहीं छोटी सी भी घटना होती है तो वहां पर सम्पूर्ण प्रदेश और देश ही नहीं, विश्वभर के लोग यहां पर आते हैं और उस छोटी सी घटना को बहुत बड़े रूप में ले करके सरकार को, हमारे प्रदेश को बहुत बड़ी बेइज्जती और शर्मिन्दगी झेलने का काम होता है और वहां पर कानून–व्यवस्था के नाम पर बहुत बड़ा नाकामी है। पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती है इस कारण से पर्यटन पर आने वाले लाखों लोग इस सब चीज को झेल करके प्रदेश सरकार को, वहां के जनप्रतिनिधियों को इस बात से धिक्कार करके जाते हैं कि यहां की कोई व्यवस्था किसी प्रकार की ठीक नहीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान इस सबकी ओर आकर्षित करते हुए मैं विशेष रूप से इस बात का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां गोकुल बैराज का प्रकरण चला, उस प्रकरण में हाईकोर्ट ने आदेश किया कि सभी पीड़ितों को मुआवजा दिया जाये। हाईकोर्ट का आदेश हुआ मगर जो यहां बैठे अधिकारी हैं उन्होंने 28 वर्षों से उन अभिलेखों का परीक्षण नहीं किया अब वह अभिलेखों का परीक्षण करने के नाम पर वसूली का काम कर रहे हैं। किसी के खाते को सीज कर देते हैं, किसी के खाते को बढ़ा देते हैं, किसी के खाते को कम कर देते हैं जिससे वसूली हो जाती है उसको वह मुआवजे का चेक देने का काम करते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस सब पर विशेष रूप से ध्यान देकर इस प्रकरण को निश्चित रूप से देखा जाय और सरकार इस पर ध्यान दे। दूसरा मथुरा शहर के किनारे यमुना जी बहती हैं। आज करीब 25 नाले, सीवरेज के गन्दे नाले यमुना जी में गिरते हैं। यह बड़ी शर्म की बात है कि आज यमुना का पानी उन दर्शनार्थियों के लिये आचमन के लायक भी नहीं रह गया है। केन्द्र में बैठी सरकार ने यमुना को शुद्ध करने के लिये बड़े लम्बे चौड़े वायदे किये और मंत्रालय भी बनाया मगर मथुरा में यमुना को साफ करने के लिये केन्द्र की बैठी गूंगी बहरी सरकार ने यमुना के शुद्धीकरण के नाम पर एक भी पैसा देने का काम नहीं किया है। मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यमुना में गिरने वाले गन्दे नालों को टेप करने के लिये अनुरोध करता हूं कि उन नालों को टेप किया जाय और यमुना को आचमन के लायक बनाया जाय। वहां पर हम लोगों की जो धार्मिक आस्थाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की आरब्ध श्री यमुना महारानी, कालिन्दी जो भगवान कृष्ण की पटरानी के रूप में हम लोग उन्हें मानते हैं, आज उनका जल इतना दूषित हो चुका है कि आचमन के लायक भी नहीं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उन नालों को टेप करके यमुना की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2011 में हमारे विधान सभा क्षेत्र में करीब 60 करोड़ रुपये की लागत से 40 पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई थीं और

उनका निर्माण वर्ष 2014–2015 तक हुआ है। आज पूर्ण होने से पहले वह सारी टंकियां बन्द हो चुकी हैं। करोड़ों रुपया खर्च हुआ है सरकार का, और आज उनके बंद होने से जनता को उनका पानी नहीं मिल पा रहा है इसलिये इस पर विशेष ध्यान देते हुए इसकी जांच कराई जाय और वह पानी की टंकियां और पेयजल जनता को मुहैया कराया जाय। मेरा आपसे अनुरोध है कि गोवर्धन में सात कोस की परिक्रमा लगती है, सप्तकोसी परिक्रमा। इस सप्तकोसी परिक्रमा में विद्युतीकरण हुआ, लाइट लगी लेकिन अधिकांश लाइटें खराब पड़ी हुई हैं उस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ लाइटें जलती भी हैं तो वहां बिजली नहीं पहुंच पाती है इस सबके लिये हमने पहले भी आग्रह किया था कि गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग के लिये अलग से एक सीधा फीडर बना करके एक बिजलीघर वहां पर स्थापित किया जाय मेरा आपसे अनुरोध है अधिष्ठाता महोदय कि वहां पर एक अलग से बिजलीघर होना चाहिए। परिक्रमा मार्ग को चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाय जिससे आने वाले देश–विदेश के श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कष्ट पीड़ा न हो। हमारे विधान सभा क्षेत्र में तहसील स्वीकृत हुई। तहसील बनी लेकिन उसका कोई भवन नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। इस सबके लिये भी मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां पर प्रस्तावित स्थल पर तहसील भवन का पैसा दिया जाय और भवन बने और उसमें अच्छे स्टाफ की भर्ती का काम हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां की महत्ता को देखते हुए वहां पर फायर स्टेशन की व्यवस्था की जाय। फायर स्टेशन मथुरा से करीब 25 किलोमीटर दूर है। जब कोई घटना दुर्घटना घटती है तो 25 किलोमीटर दूर से फायर बिग्रेड जाती है तब तक वहां का काम तमाम हो जाता है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि इस ओर ध्यान देकर फायर स्टेशन की भी स्थापना की जाय। हमारा सम्पूर्ण क्षेत्र राजस्थान से लगा हुआ है राजस्थान से आने वाली सभी सड़कें फोर लेन हैं मगर हमारी यू0पी0 की सड़कें वही पुरानी 3 मीटर की हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि राजस्थान से आने वाली फोर लेन की सड़कों को जोड़ने वाली सड़कों को फोर लेन मार्ग किया जाय। जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान की सीमा की सड़क खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं किसी गांव देहात की ओर जा रहे हैं। वहां से मार्ग समाप्त हो जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे यहां एक और प्रकरण चल रहा है जनपद मथुरा में बॉके बिहारी मंदिर को अधिग्रहण करने का मंदिर का अधिग्रहण न किया जाए। वहां के तीर्थ पुरोहित, पंडा, गोस्वामी समाज के हितों की रक्षा की जाए। वहां के मंदिर में आने–जाने के मार्ग की व्यवस्था सही की जाए, वहां प्रकाश व्यवस्था की जाए। मंदिर के हमारे गोस्वामी समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज के लोग हैं, उनकी जन भावनाओं से खिलवाड़ न किया जाए। सरकार से हम आग्रह करते हैं कि सरकार इस मंदिर के अधिग्रहण की बात को छोड़ करके मंदिर के विकास की बात करे, वहां के विनाश की बात न सोचे। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक और बात रखना चाहता हूं कि वृन्दावन में आज जाम की स्थिति को देखते हुए वहां पर एक ट्रैफिक प्लान लगाया गया है, उस ट्रैफिक प्लान से उस पूरे वृन्दावन को और गोबर्धन को उजाला जा रहा है वहां

की व्यवस्था को सुचारु किया जाए वहां की व्यवस्था को सुचारु करने के लिए सकराया आरस मार्ग पर यमुना नदी पर पुल बना करके मार्ग को एकरूपित किया जाए। एक पुल बनने से वहां की सारी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु रूप से सम्पन्न हो जाएगी। किसी भी तरह से आने–जाने वाले लोगों को, रोकने की आवश्यकता, चार किलोमीटर दूर वृन्दावन आने–जाने वाले लोगों को रोक दिया जाता है, लोग अपनी गाड़ी लेकर आते हैं कि अपने परिवार के साथ मंदिर दर्शन करके आएंगे और उन्हें चार किलोमीटर दूर रोककर उनका उत्पीड़न किया जाता है जिससे हमारे पर्यटन को, आने वाले तीर्थ यात्रियों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अन्त में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं प्रदेश में कानून–व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है मैं अपने जनपद का उदाहरण देना चाहता हूं मेरे जनपद में बीस थाने हैं और बीस थाने में से 18 थाने में ऐसे थानाध्यक्ष, कोतवाल एक ही समुदाय के बैठे हैं इन सारी चीजों को देखते हुए आप कैसे अन्दाजा लगा सकते हैं कि कानून–व्यवस्था की स्थिति कैसे सुदृढ़ हो सकती है।मैं एक बात कहना चाहता हूं अभी की बात है थाना गोबर्धन के कोतवाल के पास वायरलेस आया कि डी0आई0जी0 महोदय आने वाली हैं। डी0आई0जी0 महोदय का आने का कार्यक्रम हुआ तो सिपाही अपनी प्राइवेट ड्रेस में घूम रहे थे, कोतवाल ने कहा कि आप लोग बा–वर्दी हो जाओ डी0आई0जी0 साहब आने वाली हैं। उस सिपाही का कोतवाल साहब को जबाव था कोतवाल साहब आप थाना चलाइए हम सरकार चलाते हैं। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाकर के कानून–व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने की जरूरत है। जहां पर देश–विदेश के करोड़ों लोग आते हों उनकी भावनाओं को देखते हुए वहां की कानून–व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करते हुए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा जो मैंने आपके सामने बात रखी है इन सबका समुचित ध्यान रखा जाए। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री राजीव गुम्बर–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के संशोधन पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं सहारनपुर से विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं। सहारनपुर एक ऐसा शहर है जो वास्तविकता में एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। शिवालय की पहाड़ियों से घिरा मां शाकम्भरी देवी का मेला और मंदिर जो पर्यटन के रूप में अपने आप में पूरे देश में विख्यात है। जहां पर वुड कारविंग का उद्योग होता है। जो पूरे विश्व का एक अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित उद्योग है और पूरे विश्व के अन्दर वुड कारविंग का सप्लाई होता है। परन्तु आज सहारनपुर की दशा बहुत गम्भीर होती जा रही है सहारनपुर के अन्दर जो प्रमुख रूप से वुड कारविंग का उद्योग था वह आज बिजली की कमी की वजह से और सरकारी विभागों के उत्पीड़न की वजह से बिल्कुल नष्ट हो गया है। उस व्यवसाय की इतनी बुरी हालत है कि व्यवसाय में लगे हुए लोग आज गम्भीर रूप से अपनी आजीविका चलाने के लिए पीड़ित

हैं उन्हें आजीविका का साधन नहीं मिल रहा है। मान्यवर, मैं सहारनपुर के बारे में आपसे बताना चाहूंगा सहारनपुर के अन्दर डूडा के माध्यम से जो विकास कार्य कराये जाते रहे हैं डूडा का काम पहले केवल मलिन बस्तियों का विकास करना था किन्तु उसके बाद अब उसमें अल्पसंख्यक बस्तियों को जोड़ दिया गया। इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत डूडा के विभाग के द्वारा 90 प्रतिशत काम केवल अल्पसंख्यक बस्तियों में कराए गए और मात्र 10 प्रतिशत से भी कम काम मलिन बस्तियों में कराए गए। इसी प्रकार से सहारनपुर में आठ साल से नगर निगम के चुनाव नहीं हुए आठ साल से वहां पर अफसरशाही हावी है और इस अफसरशाही के हावी होने से नगर निगम का हाल बिल्कुल बेहाल है। अधिकारियों पर कोई भी कंट्रोल नहीं है चाहे सत्ता पक्ष के लोगों का हो चाहे हम लोगों का हो। अधिकारी इतना लूटने में लगे हुए हैं कि नगर निगम के अन्दर जो भी काम होते हैं अपनी मनमर्जी से हो रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है। नगर निगम के कामों की गुणवत्ता का हाल यह है मैंने अभी प्रमुख सचिव को भी लिखकर दिया सहारनपुर के मण्डलायुक्त को भी लिखकर दिया कि सहारनपुर के कामों की जांच कराई जाए कुछ कामों को मैंने प्रमुख रूप से उल्लेख करके भी लिखकर दिया कि वह सड़कें मात्र दो महीने के अन्दर उखड़ गईं गुणवत्ता का इतना बुरा हाल है। सहारनपुर एक ऐसा शहर है जिसके बीचों–बीच होकर सड़क निकलती है। यह जो पंजाब हरियाणा और जम्मू–कश्मीर और उत्तरांचल को जोड़ती है। सहारनपुर में आज तक बाई पास न होने के कारण पूरा का पूरा ट्रैफिक सहारनपुर के बीच से होकर गुजरता है जिससे हर समय वहां जाम की स्थिति रहती है उस जाम के कारण रोजाना घटनाएं हो रही हैं अब से 15 दिन पहले दो बच्चे आज उनकी रश्म पगड़ी भी थी दो बच्चे एक ट्रक से कुचल दिए गए उससे 10 दिन पहले एक नवयुवक जिसकी शादी को एक साल भी नहीं हुआ था वह ट्रक से कुचल गया। प्रतिदिन वहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं ऐसी बुरी स्थिति है। मान्यवर, सहारनपुर से होकर पंचकुला–हरिद्वार बाई पास का निर्माण होना है जो कि नेशनल हाई–वे पंचकुला से जाकर हरिद्वार तक बनना है। मान्यवर, बड़े खेद का विषय है उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं है सहारनपुर का प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है जहां इस बाई पास के अन्दर हरियाणा के अन्दर यमुनानगर से आगे का जितना भी इलाका है वहां पर सड़क का निर्माण शुरू हो गया है गड्ढों के पटान हो गए हैं वहीं सहारनपुर के प्रशासन ने अभी तक जमीनों के अधिग्रहण की भी कार्रवाई कम्प्लीट नहीं की। अधिग्रहण की फाइलें एक–एक अधिकारी के पास महीनों तक लम्बित हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जिससे सहारनपुर की एक प्रमुख समस्या से हमको लाभ मिल सकता। सहारनपुर खनन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सहारनपुर से लगातार रोजाना हजारों ट्रक खनन के अवैध रूप से जाते हैं जिसमें सत्तापक्ष के लोग भी शामिल हैं सरकार का इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का रोजाना लाखों करोड़ों रुपए इस अवैध रूप से खनन के अन्तर्गत बरबाद हो रहा है चोरी हो रही है सरकार के लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे यहां अब से कुछ समय पहले कांशीराम के नाम से एक मेडिकल कालेज का निर्माण किया गया था जब बहुजन

समाज पार्टी की सरकार थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई इन्होंने उसका नाम तो परिवर्तित कर दिया मौलाना हिन्द मेडिकल कालेज के नाम से कर दिया परन्तु यह खेद का विषय है कि आज वह मेडिकल कालेज एक सफेद हाथी के रूप में खड़ा है वहां पर उस मेडिकल कालेज के अन्दर न तो कोई भर्ती की सुविधा है न डाक्टर्स हैं वह पूरा का पूरा मेडिकल कालेज केवल नाम का मेडिकल कालेज रह गया है वहां पर कोई कक्षाओं का प्राविधान नहीं है आज पूरे सहारनपुर के अन्दर नगर निगम की उपेक्षा के कारण सीवर लाइनें ठप्प पड़ी हैं ऐसी स्थिति बन गई है कि सहारनपुर नगर निगम न होकर नरक निगम बन गया है। बिजली की स्थिति ठीक नहीं है पानी की स्थिति खराब है हमारे सहारनपुर के अन्दर एक शारदा नगर खलासी लाइन का क्षेत्र है जो शहर का सबसे सघन क्षेत्र है शहरी क्षेत्र है परन्तु वहां पर अभी भी मानक नगर बिजली घर से बिजली की आपूर्ति की जा रही है केवल देहात क्षेत्र की आपूर्ति मिलने से शहर के एक बहुत बड़े हिस्से को लगभग पांच से छह घण्टे ही बिजली मिल पा रही है। मान्यवर, सहारनपुर नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही देखिए आज सहारनपुर में हाउस टैक्स में लगभग 10 गुना की वृद्धि कर दी गई है किसी भी क्षेत्र में इतनी वृद्धि नहीं हुई होगी सहारनपुर क्योंकि नगर निगम गठित नहीं है वहां जनप्रतिनिधियों का दखल नहीं है तो वहां पर यह स्थिति है कि कामर्शियल हो या रेजीडेंसियल हो सभी लोगों को भवनों पर बड़े गलत तरीके से 10–10 गुना टैक्स कर दिए गए हैं। सहारनपुर में हैण्डपम्पों की स्थिति यह है कि रि–बोर नहीं हो पा रहे हैं लोग पानी के लिए तरस रहे हैं पानी की पाइन लाइन नहीं है और विकास कार्य बिल्कुल ठप्प पड़े हैं। जहां पर हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं सहारनपुर में बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम है परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके लिए कोई बजट का प्राविधान नहीं किया जा रहा है जिसके कारण स्टेडियम में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है बच्चों को खेलने के लिए सही प्रकार से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मान्यवर, केवल विकास कार्य हो रहे हैं तो धर्म के आधार पर बांटकर हो रहे हैं। उत्तरांचल बनने से सहारनपुर एक टापू बनकर रह गया है। एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ हिमांचल प्रदेश और एक तरफ उत्तरांचल है, जिससे सहारनपुर का व्यापारी वर्ग अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ सा महसूस करता है। सहारनपुर जो कि पूरे उत्तरांचल का एक केन्द्र होता था, आज उत्तरांचल बनने के बाद एक टापू बनकर रह गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सहारनपुर के व्यापारियों को एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिये और व्यापार कर में छूट मिलनी चाहिये। मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत–बहुत आभार, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने आपको विपक्ष के नेता मा0 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से सम्बद्ध करते हुये कहना चाहूंगा कि महामहिम श्री राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ, उसमें जो चीजें बोली गयीं और पूरे प्रदेश के बारे में उसमें

दर्शाया गया कि किसान को, मजदूर को आगे बढ़ाने की बात तो कही गयी है, लेकिन वर्तमान में इस प्रदेश में किसान की जो दुर्दशा है, पूर्व में ओलावृष्टि से किसानों की जो फसल मारी गयी थी, उसका मुआवजा अभी तक किसानों को न मिलने से किसान भुखमरी की कगार पर चला गया है। मैं खासकर अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के चारो ब्लाकों में लखावटी, अगौता, बुलन्दशहर, जहांगीराबाद और हमारा जो आधा ब्लाक अनूपशहर लगता है, उसमें एक बूथ से लेकर 354 बूथ के गांवों तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है और गन्ना किसानों की दशा यह हो गयी है कि उनका पिछला पेमेण्ट तो मिला ही नहीं था। चीनी मिल लेट शुरू हुयीं और उसमें भी पेमेण्ट की यह दशा है कि वर्तमान में किसानों ने जो गन्ना डाला है उसका चीनी मिल पेमेण्ट नहीं कर रही हैं। चीनी मिलों द्वारा तीन–तीन बार में चालीस रुपये रोककर पेमेण्ट की बात की जा रही है। ऐसे में जब इस प्रदेश का किसान दुखी है तो फिर सरकार किसान वर्ष मनाने की बात कैसे कर रही है ?

प्रदेश सरकार एक तरफ किसानों की बात करती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने किसानों को आगे बढ़ाने के जोर–जोर से नारे दिये, उन्होंने किसानों के साथ छल किया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार दोनों अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं और अपने आप अपनी तारीफ करने से नहीं थक रहे हैं। वह कहते हैं कि हम किसानों के लिये कर रहे हैं और केन्द्र सरकार कहती है कि हम किसानों के लिये कर रहे हैं। आज किसान की दशा यह हो गयी है कि किसान आज अपने बच्चों की बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहा है। उसे न तो प्रदेश सरकार से कोई राहत मिल पा रही है और न ही केन्द्र सरकार से कोई राहत मिल पा रही है। ऐसे में अपने बच्चों के इलाज के लिये भी किसान मोहताज है। आज किसान कर्ज लेकर, जमीन बेचकर अपनी बेटियों की शादी करने को मजबूर है। आज दोनों सरकारों की तरफ किसान देख रहा है और दोनों सरकारें किसानों की अनदेखी कर रही हैं।

इसी के साथ–साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनूपशहर जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, जहां बीच शहर से होकर गंगा नदी निकलती है, वहां पर पूर्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में गंगा पर घाट बनने के जो काम हुये थे और जो काम स्वीकृत हुये थे, वर्तमान सरकार में वह काम जहां के तहां रोक दिये गये। केन्द्र की सरकार गंगा का नाम लेकर जो बड़े–बड़े नारे, बड़े–बड़े वायदे करने का काम करती है, उन्होंने भी वहां पर एक रुपया लगाने का कोई काम नहीं किया है।

(इसी मध्य 04 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

ऐसे में जनता दोनों सरकारों को देख रही है और समय आने पर जवाब देगी क्योंकि झूठे नारों और झूठे वायदों से किसी का पेट नहीं भरता और खासकर मेरी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की दशा यह है कि जो सड़क गांव से शहर को जोड़ती है और गांव का किसान अपनी फसल शहर या चीनी मिल लेकर जाता है, सारी सड़कें टूट गयी हैं, चाहे वह हमारे यहां की अगौता चीनी मिल से जुड़ी हुई सड़कें हों जो औरंगाबाद से लेकर विअरा तक और जमालपुर तक जाती हैं, उस सड़क के लिए एक बार नहीं अनेक बार सरकार

को क्विशचनों के माध्यम से विधान सभा में उठाकर याद दिलाने का काम किया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि वह सड़क कृपया गन्ना किसानों की है, आए दिन वहां पर भैंसा बुग्गी और ट्रैक्टर ट्राली पलट जाते हैं, अनेक किसानों की मौत हो गयी है, रोज वहां से भैंसा बुग्गी लाने वालों के भैंसों की टांगें टूट जाती हैं, उस सड़क की तत्काल मरम्मत कराने का काम सरकार कराये। मान्यवर, इसी के साथ–साथ दूसरी चीनी मिल, अनूप शहर चीनी मिल है, उससे जुड़ी हुई जो सड़क है, जगपुरा से चीनी मिल और जहांगीराबाद से चीनी मिल होते हुए डूंगरा तक, तौली तक और दूसरी सड़क है अनूप शहर–बुलन्दशहर मार्ग से डूंगरा से होते हुए जटपुरा तक, यह चीनी मिल के मार्ग हैं, इनका बहुत जल्दी रिपेयर होना आवश्यक है क्योंकि वहां का किसान बहुत परेशान है और वर्तमान में हमारे यहां एक गांव है, दौलताबाद, उस गांव में आज तक बिजली के खम्भे नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सरकार उस गांव में क्योंकि वह गांव मेरे क्षेत्र में नया आया है, बाकी गांवों में हमने पिछली सरकार में अपने पूरे क्षेत्र में विद्युतीकरण का काम कराया था, आज इस सरकार में एक गांव के विद्युतीकरण के लिए मैंने एक बार नहीं अनेक बार आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध किया है, लेकिन दौलताबाद और रामगढ़ जो एक ही ग्राम सभा है और दो गांव लगते हैं, उन दोनों गांवों में बिजली का काम नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि उन दोनों गांवों में बिजली का काम करा दिया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो टूटी हुई सड़कें हैं, उनका निर्माण करा दिया जाए और हमारे यहां जो मुख्य मार्ग है, जो जिला सम्पर्क मार्ग है, लगभग 08 कि0मी0 बुलन्दशहर से अनूपशहर रोड जो जटवाल से लेकर हमारे सडगवां तक जाता है, उसकी हालत ऐसी है कि उस पर पैदल नहीं चल सकते हैं, उसे भी बनवाने का काम करें। मान्यवर, आज हम सब लोग किसान के लिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप किसान का ध्यान दें, उनकी फसल का जो मुआवजा है, उनकी जो फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो गयी थी, खासकर मेरी विधान सभा क्षेत्र में, उसे बंटवाने का काम करें, जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके और हमारे यहां जो तीन नगर लगते हैं, उनमें बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करायी जाए।

श्री गजेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने शुरू किया है, केवल 05 मिनट हुए हैं, अध्यक्ष जी, मुझे मौका दीजिए क्योंकि हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। अध्यक्ष जी, छोटी काशी जो अनूपशहर है, उसकी समस्या विकट है, मान्यवर, यदि आपके माध्यम से वह समस्याएं सरकार के सामने नहीं जायेंगी तो कैसे उनका समाधान हो पाएगा। वहां का किसान आज मायूस है, जब से नयी सरकर बनी है, नलों का लगना बन्द हो गया है, बड़ी समस्या है, इसलिए हमारे क्षेत्र में नल लगवाये जायें और इसी के साथ–साथ हमारे यहां गंगा पर घाटों का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था, उसे सरकार दोबारा शुरू करा दे। इन्ही शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, मैं हृदय की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र की राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो चीजें आनी चाहिए थीं, वह नहीं आ पायीं, उसको मैं सूचीबद्ध करते हुए बताना चाहता हूं कि खानपुर नहर से सत्तूनगली मुकाम तक साढ़े तीन कि0मी0 की सड़क, खानपुर–बसंतपुर नरावली मार्ग से देहराबिलन्दी तक डेढ़ कि0मी0 सड़क। आलमपुरी–हिरनपुरा मार्ग में से हमानगली गन्ना सेंटर तक 500 मीटर तक की सड़क, अनीसा नगली नहर के पुल से रतनपुरा होते हुए दौलतबाद भट्टे तक लगभग ढाई किमी0 की सड़क, गल्ला खेड़ी से पैंतिया होते हुऐ रामखेड़ा तालाब तक लगभग दो किमी0 की सड़क, सत्वाई से मुण्डाखेड़ी तक डेढ़ किमी0 की सड़क, हमानगली से किवाड़ तक डेढ़ किमी0 की सड़क, स्योहरा नूरपुर मार्ग में से गढ़ी सदाफल होते हुये वदुपुरा ग्राम तक साढ़े चार किमी0 की सड़क, खानपुर पुल से नहर–नहर पटरी पर कडूला (संदूकवाला) पुल तक तीन किमी0 की सड़क, रबाना सिकारपुर से गल्लाखेड़ी होते हुये संदूकवाला पुल भट्टा तक ढाई किमी0 की सड़क। इसी प्रकार सहसपुर–किवाड मार्ग से आलमपुरी गन्ना क्रय केंद्र की ओर से आलमपुरी बाल्मीकियों के घर तक लगभग एक किमी0 की सड़क, स्योहारा–मुरादाबाद मार्ग से सुल्तानपुर होते हुये अनीसा नगली तक 05 किमी0 की सड़क, नहटौर–पैजनिया मार्ग से भवानीपुर शकुन्तला देवी जूनियर हाई स्कूल से महमदाबाद आबादी तक लगभग डेढ़ किमी0 की सड़क, ओमड़ी से गाजीपुर तक की 02 किमी0 की सड़क, खजूरी से दवखेड़ी तक ढाई किमी0 की सड़क, धामपुर नूरपुर मार्ग से मोरना होते हुए पौटी तक 03 किमी0 की सड़क, फैतिहाबाद, झीरन चौराहे से पुरैना अब्दुलरहमान गांव की आबादी तक डेढ़ किमी0 की सड़क, स्योहारा–ताजपुर मार्ग से ताजपुर के पुल से ग्राम पडिया तक दो किमी0 की सड़क, पौटा ताजपुर मार्ग से कन्हेड़ी तक 700 मी0 की सड़क, शिवाला कला रोड से नैनू नागल रोड लगभग 700 मी0 की सड़क, दौलतपुर नूरपुर मुरादाबाद से नहर–नहर बिजनौर जनपद की सीमा तक 6 किमी0 की सड़क, ग्राम मालवा के नहर के पुल से मालवा गांव तक लगभग 500 मीटर की सड़क का निर्माण कराया जाना। अध्यक्ष जी, यह सब चीजें राज्यपाल जी के अभिभाषण में सम्मिलित की जायें। लेकिन इसके साथ–साथ जो समाजवादी पार्टी एक लोहिया विचारधारा को लेकर चली थी आज मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी उनके विचारों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए और उत्तर प्रदेश के अंदर एक अराजकता का वातावरण उत्पन्न है। जिस प्रकार जिला पंचायत के चुनाव में प्रमुखी के चुनाव में एक तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकारियों के माध्यम से पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को कुचलने का काम किया और केवल और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बिजनौर जिले के अंदर जो समाजवादी पार्टी की विधायक थीं उन्होंने इस कारण वहां टिकट मांगा था, ऐसा नहीं है कि हम अनुसूचित जाति के समाज के रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। लेकिन जो संविधान में व्यवस्था दी है, डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने, उसको हम सब देशवासियों को मानने की आवश्यकता है। जब आपने

रामपुर सीट रिजर्व की, आयोग ने मुरादाबाद की सीट रिजर्व की, आपने सम्भल की सीट रिजर्व की, बदायूं की सीट रिजर्व की, आपने हापुड़ की सीट रिजर्व की, आपने सहारनपुर की सीट रिजर्व की, मेरे आस–पास के जिलों में जनपद बिजनौर की सामान्य सीट केवल वही थी। उस सामान्य सीट पर भी आपकी समाजवादी पार्टी ने वहां पर अनुसूचित समाज को टिकट देने का काम किया। जब आपके दल में इस बात को उठाया गया और यह साक्ष्य है, इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने इसे देश और दुनिया में दिखाया। जब उन्होंने कहा कि टिकट मांगा तो उनको आपने पार्टी से निकाला और यही नहीं उसके घर पर जिला पंचायत जो सदस्य थे जो भट्ठा चलाते थे, एक–एक भट्ठा स्वामी पर एक–एक दिन में तीन–तीन केस दर्ज किये गये। मा0 अध्यक्ष जी, प्रदूषण विभाग के लोग जाते हैं, कहते हैं कि ऐ इदरीस, तुम्हारा भट्ठा है, इस भट्ठे के अंदर से यह धूंआ कैसे निकल रहा है। यानी प्रदूषण डिपार्टमेंट का उस पर एक मुकदमा दर्ज होता है। फिर वन विभाग का आदमी जाता है और कहता है कि ये लकड़ी कैसे पड़ी हुई हैं, वन की लकड़ी चोरी कर के आप लाये हो, फिर उस पर दूसरा मुकदमा वन विभाग का दर्ज होता है, तीसरा जाता है आपका खनन इन्स्पेक्टर, वह कहता है कि ईंट कहां से पाथी, मिट्टी कहां से उठाई आपने, तीसरा मुकदमा खनन इन्स्पेक्टर उस पर दर्ज करता है, उस इदरीश नाम के व्यक्ति पर जिसके तीन भटठे थे, एक ही दिन में तीन घण्टे के अन्दर 9–9 मुकदमें आपके इशारे पर लगवाये गये, बिजनौर जिले के अन्दर और आपके ही विधायक के यहां चूंकि हम उनका समर्थन कर रहे थे और हमने उन्हें जिताया भी और उनके घर पर 22 थानों के एस0एच0ओ0, 05 इन्सपेक्टर, 05 सी0ओ0, एडीशनल एस0पी0, एस0पी0 सिटी पूरा अमला, आपकी पुलिस जो रिजर्व में रहती है, लाईन में रहती है, 400 पुलिसकर्मी, डेढ़ से दो हजार लोग उनके घर के गेट को उजाड़ने का और तोड़ने का काम करें, मा0 अध्यक्ष जी सही मायने में अगर लोहिया के सिद्धान्तों को माना और न्याय दिलाने का काम किया तो वह काम हमारे जैसे लोगों ने वहां पर खड़े होकर वहां की जनता ने किया, इसको रोकने का काम किया। मा0 अध्यक्ष जी यही नहीं, गन्ना किसानों के लिए, यह बात ठीक है कि मा0 मुख्य मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भावना है कि हम प्रदेश को आगे ले जाये, उनकी अच्छी सोच है, नौजवान हैं, हम भी उनके प्रति एक अच्छा भाव अपने हृदय में रखते हैं, कभी जाते हैं, काम को मना नहीं करते हैं, उनके प्रति कोई नाराजगी नहीं, लेकिन उनके साथ में जो नहला और दहला हैं, जो शुक्र और शनीश्चर के रूप में कार्य कर रहे हैं, मुख्य मंत्री जी को पता नहीं होता है और निर्णय कुछ के कुछ हो जाते हैं नीचे। मा0 अध्यक्ष जी, उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अन्दर किसानों का हाहाकार है कि आज गन्ना भुगतान नहीं होता है, आपने, आपकी सरकार ने चार वर्षों से गन्ने का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, किसान वहां बीज लेने जाता है तो कमीशन, खाद लेने जाता है तो बिना पैसे दिए सोसाइटी से कट्टा नहीं मिलता है, अगर गन्ने के क्रय केन्द्र पर जाता है, तो घटतौली होती है, मिल में जाता है तो घट तौली होती है। तहसीलों में जाता है आया प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र बनवाने के लिए, वह दाखिल खारिज करवाने के लिए

बैनामा करवाने के लिए अगर वह जाता है, बिना पैसे से उसका काम नहीं होता है। जो लोग ये करते थे पास में बैठे हुए बसपा के लोग, वही आप कर रहे हो, आप में और इनमें कोई अन्तर नहीं है, यह भी एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है तो दूसरा टेल है। इनके समय में भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, आपके समय मे भी उत्तर प्रदेश के अन्दर रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। मा0 अध्यक्ष जी, यही नही पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लगवाये जा रहे हैं, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया अगर छापती है तो उन पर झूठे मुकदमें लगवाये जाते हैं। एक डी0एम0 ने केवल सेल्फी मात्र खींचने पर उसको जेल भिजवा दिया।

श्री अध्यक्ष–

बैठ जायें, अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, दो मिनट में अपनी कह दूंगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, एक मिनट बोल लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कल बोल लीजिएगा। अब नियम–56 की सूचना लेते हैं।

ख05.05, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 15–02–2016 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम सूचना को अग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना (1) श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री उमेश पाण्डेय, श्री लोकेश दीक्षित, श्रीमती पूजा पाल, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री मो0 आसिफ, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री सुनील कुमार सिंह यादव, श्री मो0 इकबाल, श्री ममतेश शाक्य, श्री वहाब चौधरी, चौ0 गजेन्द्र सिंह, श्री ओम कुमार, डा0 अरूण कुमार, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री नूर सलीम राणा, (2) श्री प्रदीप माथुर, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री विजय कुमार दुबे, श्री गयदीन अनुरागी, श्री दिलनवाज खां, श्रीमती उमाकान्ती, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री राधेश्याम, श्रीमती अराधना मिश्र 'मोना' की प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की समस्या के निराकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

उक्त सूचना के सम्बन्ध में मा0 नेता विरोधी दल यह बता गये थे, उनसे बात हुई थी तो कह रहे थे, इसको दूसरे दिन ले लीजिए।

दूसरी सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती में चीनी मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह खुद ही इतने इन्ट्रेस्टेड हैं कि वह कभी रहते ही नहीं हैं, 301 में दे दें तो गायब, इसमें भी गायब, पता नहीं इतना इन्ट्रेस्ट इनका है, इस पर ध्यान आकृष्ट है।

तीसरी सूचना श्री उमाशंकर की यू0पी0 स्टेट एग्रो इ0का0लि0 सेवा केन्द्र रामपुर, उदयभान में बलिया के स्व0 श्याम नारायण के मृतक आश्रित को नौकरी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर मैंने ध्यान आकृष्ट कर लिया है, इस पर बोलने की जरूरत नहीं है।

चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में अवमुक्त धनराशि के उपरान्त भी लोक निर्माण विभाग द्वारा गोरखपुर–सोनौली मार्ग पर पुल का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं :–

श्री जय प्रताप सिंह, श्री लोकेश दीक्षित, श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री संतराम कुशवाहा एवं श्री श्री सुरेश राणा ।

ख05.06, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाये।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है और सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है आप देख रहे हैं, जो मंत्री विभाग के हैं वह भी गायब हैं। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वह भी गायब हैं अब यह परिवहन मंत्री हैं तो अब सरकार इसको ले करके कितनी गंभीर रही होगी लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो संज्ञान में आनी चाहिए। भारत सरकार ने एक योजना ली है जो पूरे देश में लागू हुयी है 'इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग' जिसके पांच आयाम हैं और इन पांच आयामों के प्रथम चरण में यह परिवर्तन आया है। पांच आयाम जो लिए गए हैं उसमें एक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि विपणन अवस्थापना सुविधाएं, दूसरा मार्केटिंग रिसर्च और

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

इंफार्मेशन नेटवर्क, विपणन शोध एवं सूचना तंत्र, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एगमार्क ग्रेडिंग फैसिलिटीज, एगमार्क ग्रेडिंग फैसिलिटीज को मजबूत करना, एग्री बिजनेस डेवलपमेण्ट प्रूवेंचर कैपिटल एसिसटेंस एण्ड प्रोजेक्ट डेवलेपमेण्ट फैसिलिटीज और चौधरी चरण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें दो क्लॉज इसके ऑब्जेक्टिव में बताए गए हैं मैं सिर्फ दूसरा जो महत्वपूर्ण है उसे पढ़ दे रहा हूं 'टू प्रोमोट कम्पीटीटिव एल्टरनेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाई इन्करेजिंग प्राइवेट एण्ड को–आपरेटिव सेक्टर इंवेस्टमेण्ट'। अर्थात् निजी और सहकारिता क्षेत्र के निवेश के द्वारा प्रतियोगितात्मक विकल्प कृषि विपणन अवस्थापना सुविधाओं में पैदा करना। मैं इसी बिंदु को विशेष रूप से चर्चा में लाना चाहता था जो मूल परिवर्तन ई–मार्केटिंग की दृष्टि से किया गया है वह सब तो भारत सरकार की रणनीति और नियमों के अंतर्गत है इससे कोई असहमति नहीं हो सकती। मुख्य असंतोष इसकी धारा नौ और दस के जो पैनाल्टी क्लॉज है उसके संदर्भ में है। एक बार जब हमने यही सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि हम निजी और सहकारिता क्षेत्र के निवेश को एक वैकल्पिक कृषि विपणन की व्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो जो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधेयक, 2014 था सैद्धांतिक रूप से इसका आर्टिकल नौ और दस समाप्त हो जाना चाहिए था। यह आर्टिकल नौ और दस मूलतः उन लोगों के लिए है जो किसी मण्डी समिति में मण्डी समिति के प्रावधानों के बावजूद अलग से अपना व्यापार खड़ा करते हैं तो जब आपने वैकल्पिक व्यापार व्यवस्था को स्वीकार किया तो या तो आप इस मुद्दे पर चुप रहते या इसे समाप्त करते लेकिन बावजूद इसके उल्टा किया गया है कि जो लोग इस प्रकार के स्वतंत्र व्यापार करेंगे उनके लिए दण्ड बढ़ा दिया गया है। 500 रुपये से बढ़ाकर के 5 हजार रुपये, एक हजार से दस हजार रुपये और दस हजार से बढ़ा करके एक लाख रूपये। यह अत्यन्त आपत्तिजनक लाभ है और यह लगता है कि जो छोटे–छोटे व्यवसायी क्षेत्र में अपना निजी व्यापार करते हैं यह कहीं न कहीं उनके व्यापार को प्रभावित करने की दृष्टि से लाया गया है तथा ई–मार्केटिंग के इस दौर में एक बार जब ई–मार्केटिंग का पंजीकरण हो जायेगा और सारा व्यापार ई–मार्केटिंग के माध्यम से होने लगेगा तो इन दण्डात्मक प्राविधानों की जो करीब–करीब छोटे व्यापारियों के लिए शोषण का प्राविधान है और वस्तुतः यही वे व्यापारी हैं जो किसानों को उनकी उपज का दाम दे पाते हैं या ई–व्यापार से आने वाली बड़ी–बड़ी संस्थाएं किसानों को अभी उपज का दाम दे पाएंगी ये तय नहीं है क्योंकि किसान पहले दाम लेने की कला तो सीख ले। उसको बाजार का उपयोग करना तो आ जाए। अभी नेट के प्रयोग से जो बड़ी संस्थाएं हैं वे तो किसान की चीजें निकाल सकती हैं लेकिन किसान अभी इस योग्य नहीं है कि अपनी चीजों का सही दाम पूरे देश के अन्दर ले सके। यह एक प्रशिक्षण का काम है जो आने वाले कई सालों में धीरे–धीरे दसियों सालों की प्रक्रिया में होने वाला है। इसलिए हम लोगों की यह मान्यता है कि यह जो दण्डात्मक प्राविधान है यह एक प्रकार से शोषणात्मक प्राविधान होंगे जो छोटे व्यापारियों को दण्डित करेंगे और उनके दण्डित होने के नाते किसानों को उनके मूल्य का सही दाम नहीं मिल पाएगा। हम लोगों का मूल

विरोध यही है और इसीलिए मैं आग्रह करूंगा कि इसे प्रवर समिति के अधीन सुपुर्द किया जाए।

'नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने इस बिल से किसानों पर आने वाले भार और साथ ही साथ किसानों के साथ होने वाले उत्पीड़न के विषय में विस्तार से बताया। मा0 अध्यक्ष जी, यह विधेयक ऐसे समय लाया जा रहा है जिस समय सरकार किसान वर्ष मना रही है और किसान वर्ष के ऊपर इस विधेयक के माध्यम से गाज गिरा रही है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, किसान वर्ष के अवसर पर किसानों को मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए सरकार सहूलियत प्रदान करती है लेकिन यह विधेयक उनके ऊपर ठीक वज्रपात जैसा होगा क्योंकि जो मूल अधिनियम की धारा–37 की उप धारा–1 में, 2 में, 3 में तथा ख उपधारा–2 में इन्होंने खण्ड–क में शब्द 5000 रुपये के स्थान पर शब्द 50,000 रुपये रख दिए जाएंगे। खण्ड–ख में शब्द 10,000 रुपये के स्थान पर शब्द 1,00,000 रुपये और 1000 रुपये के स्थान पर 10,000 रुपये। इसी प्रकार से 3 खण्ड–ख के परन्तुक शब्द में 250 रुपये के स्थान पर शब्द 2500 रुपये और शब्द 500 रुपये के स्थान पर 5000 रुपये, इसी प्रकार ख उपधारा–2 में शब्द 2000 रुपये के स्थान पर 20,000 रुपये, शब्द 200 रुपये के स्थान पर शब्द 2000 रुपये। यानी सीधे–सीधे 10 गुना, यह एक तरीके से किसानों पर अतिरिक्त भार के रूप में विधेयक के माध्यम से किसान वर्ष के पर्व पर सरकार उनको यह तोहफा देने जा रही है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, सरकार कहती है कि हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है लेकिन यह सरकार जो कहती है उसका ठीक उल्टा करती है। किसान वर्ष के नाम पर जिस तरीके से उनकी भावनाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है तो हम समझते हैं कि यह विधेयक किसान विरोधी है और स्वाभाविक रूप से इससे जो ग्रामीण क्षेत्र के छोटे किसान हैं, जो अपने खेतों के उत्पादन को लेकर वहां जाते हैं, यह भार अप्रत्यक्ष रूप से सीधे उन पर आएगा, वे सीधे प्रभावित होंगे। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, यह विधेयक किसान विरोधी भी है और इस विधेयक से सरकार की नियत भी स्पष्ट हो रही है कि विपक्ष जो उस पर आरोप लगाता रहा कि किसान विरोधी होने का दम तो सरकार भरती जरूर है लेकिन इसके क्रिया–कलाप किसान विरोधी हैं। इस विधेयक से भी वह स्पष्ट हो रहा है, इसलिए मान्यवर, राधा मोहन जी ने जो यह संसोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष–

संशोधन आपका है, प्रस्तुत उन्होंने किया है। हालांकि हमने अलाऊ कर दिया था, आप नहीं थे, हालांकि उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

माननीय अध्यक्ष जी, जब संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाता है, भले ही वह संशोधन प्रस्ताव मेरा था, लेकिन वह सदन की सम्पत्ति हो जाती है। विपक्ष का कोई भी सदस्य उस संशोधन को मेरी गैरहाजिरी में या मेरी मौजूदगी में...

श्री अध्यक्ष–

नियम है कि जब आप उसे भारसाधक बना देंगे, तो प्रस्तुत करेंगे लेकिन बोलने की पूरे सदन को आजादी है। विधेयक जब विचार के लिए प्रस्तुत हुआ तो कोई भी बोल सकता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपकी अनुकम्पा होती है तो क्या–क्या नहीं हो जाता है। आप भी ऐसी बात करते हैं, क्या बात है मान्यवर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो मेरी अनुपस्थिति में मेरा संशोधन प्रस्ताव माननीय अग्रवाल जी ने रखा, उस पर मैं बल देता हूं और साथ ही साथ इस किसान विरोधी विधेयक को मान्यवर, प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, जो अपनी रिपोर्ट तीन महीने में दे, उसके बाद उस पर विचार किया जाए।

'समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण तथा सैनिक कल्याण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक किसानों के हित में है, विपक्ष का पता नहीं विधान सभा में सही बात बोलने की कब आदत पड़ेगी। ठीक उल्टी बात कह रहे हैं। यह विधेयक किसानों के हित के लिए लिया गया है, उस बात को अपने भाषण में माननीय नेता विरोधी दल ने भी, माननीय नेता भाजपा राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने भी कहा। ये जो व्यापारी लोग हैं, ज्यूं ही फसल तैयार होती है, ये किसानों के यहां जाते हैं, सस्ते में उनका माल खरीद लेते हैं, उनको जरूरत होती है, कपड़े की, नमक की, मसाले की और सरकार चाहती है कि छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो उसको मण्डी की समिति से उचित मूल्य मिले। इसलिए बड़ी–बड़ी मण्डी समितियों का निर्माण तो सरकार करा ही रही है, देहात के इलाकों में छोटी–छोटी मण्डियां भी स्थापित की जा रही हैं, ताकि किसानों का शोषण न हो। माननीय नेता विरोधी दल इतने बड़े विद्वान आदमी है, कैसे इनके झांसे में आ गए हैं। शुरू से इन पर यही आरोप ही है कि समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारी पार्टी के ये लोग टेढ़ीमार पार्टी हैं। ये हमेशा केवल व्यापारियों के पक्ष की बात क्यों करते हैं। किसान की बात इनके मुंह से कभी अच्छी नहीं हो सकती। ये किसानों को लूटने वालों की बात कह रहे हैं कि किसानों का प्रताड़ना हो रहा है। किसानों की प्रताड़ना हो रही है कि जो किसानों को लूटने जा रहा है उसका प्रताड़ना हो रहा है। जो किसानों को लूटने जा रहे हैं, उन पर दण्ड का प्राविधान किया गया है। किसान को उसके अनाज का उचित मूल्य मण्डी समिति देती है। आपको याद होगा अध्यक्ष जी, पिछली बार जब धान की खरीददारी हुई तब मण्डी समिति को सरकार ने

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

कड़ा निर्देश दिया था कि किसानों की धान की उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए, कहीं कमी नहीं होनी चाहिए चाहे वह व्यापारी खरीदे, चाहे मण्डी समिति खरीदे। व्यापारियों पर इतना नकेल कसी मण्डी समिति ने कि धान का दाम उचित मूल्य पर व्यापारी लोगों को भी देना पड़ा जितना मण्डी समिति दे रही है, तो यह व्यापारी के हित की बातें कर रहे हैं। सरकार किसान की बात कर रही है, किसान वर्ष हम मना रहे हैं और किसानों की मूलभूत सुविधाओं को यह सरकार दे रही है। उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है, सिंचाई हमने मुफ्त की, किसान बीमा दुर्घटना बीमा योजना को लागू किया, किसान फसल बीमा योजना को लागू किया, हम सूखा राहत बांटने जा रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, ओला, अतिवृष्टि, बाढ़ आपको याद होगा माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली दफा जब किसानों का गांव और घर नदी में कट के गिरा तो पक्का मकान का पक्का मुआवजा, कच्चा मकान का कच्चा मुआवजा और जिन किसानों का नदी में खेत गिरा उसका भी मुआवजा समाजवादी की सरकार नेता जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जब भी सरकार में आई है, हमेश अतिवृष्टि हुई है, ओला पड़ा है, सूखा पड़ा है क्या कभी इन्होंने किसानों को एक पैसा भी दिया है ? समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है, किसानों की मदद करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तभी जब गांव, गरीब और किसान जमकर समाजवादी पार्टी को वोट देता है। किसान को हर सहयोग, हर सहायता देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। यह विधेयक किसानों के हित में लाया गया है इसलिए इसे पास कराने की कृपा करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, कुछ बातें यहां बहुत स्पष्ट आईं हैं, एक शब्द का प्रयोग किया गया है, टेढ़ी मार। समाजवादी पार्टी इस सदन में सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रही है इस प्रदेश के सारे व्यापारी टेढ़ी मार हैं। मैं इनको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं और मैं समझता हूं कि प्रदेश के नागरिकों को यह पता होना चाहिए। जानकारी के अभाव मे जब व्यक्ति पुराने जमाने की बातों को लेकर बोलता है तो वह इसी प्रकार से बोलता है। अध्यक्ष जी दूसरी चीज माननीय मंत्री जी को यह भी नहीं पता है कि यह जो किसानों के मूल्य वितरण की बात कर रहे हैं यह सारी योजना 23 नवम्बर, 2014 को भारत सरकार ने बनाई, इन्टीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यह उसी योजना का एक हिस्सा है जिसके तहत यह मण्डी समिति के धारा मे परिवर्तन करके ई–मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं जिसे वह वैसे ही छिपाते हैं जैसे बजट में भारत सरकार के सारे पैसे को छिपा कर बैठ जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं आपत्ति इस बात की नहीं है कि ई–मार्केटिंग का तो दौर आ गया आप इसे कैसे रोक लेंगे। भारत सरकार की योजना न होती तो भी आता योजना है तो आप ला रहे हैं क्योंकि उसके बाद आपको चार फायदे मिलने वाले हैं, भारत सरकार से सब्सिडी पर बहुत पैसा मिलने वाला है उसी को स्वीकार कर लेते लेकिन स्वीकार करने के लिए जानकारी चाहिए वह तो है नहीं। अध्यक्ष

महोदय हमारी और नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति दूसरी है, जब आपने वैकल्पिक व्यापार व्यवस्था को स्वीकार कर लिया तब इस पैनालटी को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था हमारी आपत्ति इस पर है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी पहले कांग्रेस पार्टी के लोग केन्द्र का बखान करते थे अब जब बैठते हैं यह लोग केन्द्र पैसा दे रही है, केन्द्र को मना कर दीजिये, केन्द्र बहुत पैसा नहीं दे रही है, हम काम करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–25 सन् 1964 की धारा–2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–2 में,–

(क) खण्ड (ज–2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया

जायेगा, अर्थात् :–

''(ज–3) 'ई–व्यापार' का तात्पर्य उस व्यापार से है जिसमें बिल बनाना, बुकिंग करना, करार करना, वार्ता करना, सूचना का आदान–प्रदान करना, अभिलेख रखना और अन्य जुड़ी गतिविधियां, कम्प्यूटर नेटवर्क/इण्टरनेट पर इलेक्ट्रानिकली की जाती हैं;''

(ख) (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(ट–1) 'मुख्य मण्डी समिति' का तात्पर्य उस मण्डी समिति से है, जो एकीकृत लाइसेन्स निर्गत करने के लिये प्राधिकृत हो;''

(ग) खण्ड (म) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(म–1) 'एकीकृत लाइसेन्स' का तात्पर्य अधिनियम की धारा–9–क के अधीन स्वीकृत लाइसेन्स से है।''

नई धारा–9–क का बढ़ाया जाना

3–मूल अधिनियम की धारा–9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

''9–क (1) परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई भी मुख्य मण्डी समिति कृषकों में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादनों का क्रय करने के लिये, यथाविहित रीति में, निदेशक से लिखित पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिये एकीकृत लाइसेन्स स्वीकृत कर सकती है :–

कतिपय प्रयोजनों के लिये एकीकृत लाइसेन्स

(क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादनों का प्रसंस्करण;

(ख) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादनों का व्यापार;

(ग) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन का मूल्य सम्वर्धन करके अन्य रीति से ग्रेडिंग, पैकिंग और सौदा।

(2) सभी मण्डी क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के क्रय और विक्रय पर अधिनियम में यथा उपबन्धित मण्डी शुल्क और विकास उपकर मुख्य मण्डी समिति को देय होगा।

(3) परिषद् इस सम्बन्ध में राज्य में एक या अधिक मण्डी समिति को प्राधिकृत कर सकती है और इस प्रकार प्राधिकृत मण्डी

समितियां मुख्य मण्डी समितियां कहलायेंगी।''

4–मूल अधिनियम की धारा–37 में,– धारा–37 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) खण्ड (क) में, शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पचास हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख रुपये'' और शब्द ''एक हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ख) के परन्तुक में शब्द ''दो सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार पांच सौ रुपये'' और शब्द ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''बीस हजार रुपये'' और शब्द ''दौ सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मान्यवर मै आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संधोधन) विधेयक, 2016 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संधोधन) विधेयक, 2016 को पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख5.29, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर व्यवस्था

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, एक अनुरोध है कार्य–स्थगन प्रस्ताव पर आपने अपनी व्यवस्था दे दिया ?

श्री अध्यक्ष–

आपने कहा न कि इसको कल ले लिया जाय तो कल ले लेंगे। हम इसको कह दिये थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपने उसे चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया था।

श्री अध्यक्ष–

हां, हां। कार्य–स्थगन पर आप बोलेंगे तब चर्चा होगी। आप कह गये थे तो मैंने आपकी बात को रख करके दूसरे कार्य–स्थगन पर ध्यान आकृष्ट कर लिया था।

ख5.30, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 15–02–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री रविदास महरोत्रा की जन सन्देश टाइम्स दैनिक समाचार–पत्र अम्बेडकर नगर के ब्यूरो चीफ श्री करुण मिश्र की 13 फरवरी, 2016 को हुई क्रूर एवं निर्मम हत्या के सम्बन्ध में वक्तब्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद गोरखपुर के थाना चौरी–चौरा अन्तर्गत पार्टी कार्यालय पर हमला किये जाने के संबंध में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–0466/2015 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तब्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड ईसानगर अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल से निकलने वाले प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, यह रहते नहीं हैं इनका लिखकर देता कौन है। नेता विरोधी दल इनका पता लगाइये इनका रोज आता है यह रहते नहीं हैं। चौथी सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया की जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा अन्तर्गत ग्राम सिंगावर से जेठरा होते हुए सरैया तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे की जनपद कुशीनगर स्थित नवनिर्मित खड्डा नगर तहसील को यथास्थान रखे जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठी सूचना श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुरादाबाद के ब्लाब छजलैट को डार्क श्रेणी से हटाकर ग्रे श्रेणी में परिवर्तित किये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री उमाशंकर की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के कतिपय ग्रामों के घरों के ऊपर से खींचें 11000 वोल्ट हाई टेन्सन विद्युत लाइन को हटाये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्रीमती अराधना मिश्र 'मोना' की प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परिसर तक उ0प्र0 सरकार द्वारा अपने खर्चे पर एक निश्चित सीमा तक बिजली उपलब्ध कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, नवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की जनपद वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कोनिया क्षेत्र में कोनिया घाट के सामने वरुणा नदी पर पूर्वांचल राज्यांश अथवा अन्य किसी मद से पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना डा0 अरूण कुमार की बरेली महानगर में 78 करोड़ से अधिक यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत बने 17 ओवर टैंकों द्वारा शीघ्र पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में केवल

वक्तव्य हेतु स्वीकृत, ग्यारहवीं सूचना श्री अविनाश कुशवाहा की स्वास्थ्य महानिदेशालय उ0प्र0 में तैनात संयुक्त निदेशक क्षय/राज्य क्षय नियंत्रण अधिकारी द्वारा बी0सी0जी0 टेक्नीशियन के साथ की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, बारहवीं सूचना श्री गजराज सिंह की प्रदेश के बन्द पड़े लगभग 17000 ईंट भट्ठों को चालू कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

श्री दलजीत सिंह, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री दिलनवाज खां, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री मनीष असीजा, डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री ममतेश शाक्य, श्री संजय कपूर, श्री रामचन्द्र यादव, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री रविन्द्र जायसवाल, श्री जय प्रकाश अंचल, मो जासमीर अन्सारी, श्री पूरन प्रकाश, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री सुरेश बंसल, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री काली चरन सुमन, श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री प्रदीप माथुर, श्री गुलाब चन्द्र सरोज, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री सन्तराम कुशवाहा, श्री गयादीन अनुरागी एवं श्री जियाउद्दीन रिजवी।

जनपद महोबा समेत सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे के कारण अकाल की स्थिति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

परिवहन राज्य मंत्री (श्री यासर शाह)–

माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि पिछले कई वर्षों की तरह ...

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री यासर शाह–

ख्इस वर्ष भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बारिश न होने से भयंकर सूखे की स्थिति के कारण किसान बुरी तरह बर्बाद हो गया है। विशेष कर जनपद महोबा में सबसे अधिक किसान प्रभावित हैं, जहां पर 90 प्रतिशत खेत खाली पड़े हुए हैं। सिंचाई का कोई अन्य साधन न होने के कारण बुवाई नहीं हो सकी है, जिन किसानों ने किसी प्रकार बुवाई की थी उसको आवारा पशुओं ने उजाड़ दी अथवा समय पर पानी न लगने के कारण सूख चुकी है। लोगों के सामने खाने के लाले पड़े हुए हैं, पशुओं को चारा तथा पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण कोई रोजगार न होने से लोग तेजी से

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

पलायन कर रहे हैं, किसान आक्रोशित एवं आन्दोलित है, सूखा राहत राशि का वितरण समय पर नहीं हो रहा है। उसमें भी भयंकर धांधली हो रही है। राजस्व कर्मी किसानों का शोषण कर रहे हैं। आन्दोलित किसानों की मांग है कि बुन्देलखण्ड को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, सम्पूर्ण कर्ज माफ कर बुन्देलखण्ड को अकालग्रस्त घोषित करने, काला हांडी की तर्ज पर किसानों को सुविधायें प्रदान करने, राहत राशि छोटे–बड़े किसानों को देने, किसानों को मुफ्त बोरिंग कराये जाने तथा बुन्देलखण्ड पैकेज में हुए भारी भ्रष्टाचार की सी0बी0आई0 से जांच अविलम्ब कराई जाए तथा बैंक अधिकारियों, राजस्व कर्मियों, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग द्वारा अनेक तरह के शोषण पर रोक लगाई जाए।

क्षेत्र में पशु चारे की कोई व्यवस्था आज तक न्याय पंचायत स्तर पर नहीं हो सकी है। शासन के अधिकारियों में कोई तालमेल नहीं है, सरकार झूठे आश्वासन व घोषणायें कर रही है, क्षेत्र में भयंकर अकाल की स्थिति बन चुकी है। किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं अथवा सदमें में मर रहे हैं, सर्दी लगने से भी अनेकों लोग मारे जा चुके हैं। अब भूख से मर रहे हैं, पशुओं की मौतें चारा–पानी न मिलने से लगातार हो रही हैं, सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने दौरा कर स्थिति को अत्यन्त दयनीय बताया है।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की विशेष समस्या के निराकरण के बिन्दु पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 24–12–2015 को सम्बन्धित विभागों के साथ मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगणों के साथ बैठक की गयी। जिलाधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि कम वर्षों की वजह से फसलों की बुवाई 50 प्रतिशत से भी कम हो पायी है, जिसमें सबसे न्यूनतम महोबा जनपद में 15 प्रतिशत के आस–पास बुवाई हो पायी है। प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई ने अवगत कराया कि उन्होंने उपलब्ध पानी को पलेवां हेतु नहरों में उपलब्ध कराया है लेकिन अब जलाशयों में पानी उपलब्ध नहीं है। पीने के पानी की भी समस्या बतायी गयी और सरकारी एवं प्राइवेट ट्यूबवेल बिजली की पर्याप्त आपूर्ति न होने, लो–वोल्टेज की समस्या बतायी गयी। किसानों के घरों में खाद्यान्न की समस्या बतायी गयी। जिलाधिकारीगण द्वारा यह अवगत कराया गया कि भूख से किसी की मृत्यु नहीं हुयी है। एक महीने के बाद चारे की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

3–बुन्देलखण्ड में सूखे की समस्या से निपटने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की समीक्षा के उपरान्त मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा भी मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण के साथ बैठक/समीक्षा की गयी। तत्पश्चात् विभागों/जिलाधिकारीगणों को निम्न निर्देश दिये गये हैं :–

1–बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

2–मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार दिवसों को 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस किये जायं।

3–मनरेगा के अन्तर्गत बड़े तालाबों की खुदाई वृहद् स्तर पर कराये जाने के निर्देश दिये गये एवं यह भी निर्देश दिये गये कि मनरेगा के अन्तर्गत धनराशि समय से जनपदों को उपलब्ध करायी जाय। आवश्यकता होने पर राज्य सरकार से भी धनराशि उपलब्ध करायी जाये।

4–झांसी मण्डल में 01 जनवरी, 2016 से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो रहा है। अतः झांसी मण्डल में अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय। चित्रकूटधाम मण्डल में भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न एफ0एस0ए0 रेट से उपलब्ध कराया जाये।

5–पशुओं को चारा उपलब्ध कराये जाने के लिये काम्पैक्ट फूड ब्लाक्स तैयार रखे जाने के निर्देश दिये गये एवं आवश्यकता होने पर किसानों को तत्काल मुहैया कराया जाय।

6–पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिये खराब हैण्डपम्पों को रि–बोर/मरम्मत किये जाने एवं नये हैण्डपम्प लगवाये जायें।

7–बुन्देलखण्ड क्षेत्र को समाजवादी पेंशन योजना से शत–प्रतिशत आच्छादित किये जाये।

8–बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बकरी पालन बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है, अतः बकरी पालन कार्यक्रम में गति लायी जाये।

9–खराब ट्रांसफार्मर को अतिशीघ्र बदला जाय एवं इसके लिये ट्रांसफार्मर का बफर स्टाक बनाया जाय। विद्युत दोषों का तत्काल निवारण किया जाय। लो–वोल्टेज की समस्या का निराकरण किया जाय।

10–यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की भुखमरी से मृत्यु न होने पावे। इसके लिये समस्त प्रकार की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। भुखमरी से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जिलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

11–सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग के प्रदेश स्तरीय अधिकारी संयुक्त रूप से 03 दिन दोनों मण्डलों के जिलों का भ्रमण कर जिलाधिकारियों से सम्पर्क कर बतायी गयी सिंचाई एवं बिजली की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

12–हैण्डपम्पों के रि–बोर एवं मरम्मत की कार्यवाही युद्ध स्तर पर की जाय ताकि पीने के पानी की समस्या हल हो जाय।

4–मुख्य सचिव द्वारा बुन्देलखण्ड में सूखे की समस्या के निराकरण के बिन्दु पर पुनः दिनांक 09–02–2016 को सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव एवं मण्डलायुक्त चित्रकूट एवं झांसी मण्डल के साथ समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान पानी, बिजली, खाद्यान्न, सिंचाई एवं पशुओं के चारे आदि के निराकरण के सम्बन्ध में पुनः निर्देश दिये गये।

बुन्देलखण्ड के सातों जनपदों को आपदा से तत्काल राहत हेतु विभिन्न मदों में निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत की गयी है :–

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	सामान्य आपदाओं के लिये दी गई धनराशि (वर्ष 2014–15)	ओलावृष्टि 2014	सूखा 2014	सामान्य आपदाओं के लिये दी गई धनराशि (वर्ष 2015–16)	ओलावृष्टि 2015	सूखा 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बांदा	889.88	249.31	4670.19	132.5	22988.07	200.00 लाख खाद्यान्न हेतु 100.00 लाख पशु चारे हेतु 450.00 लाख कृषि निवेश अनुदान हेतु
2	चित्रकूट	59	620	561.21	132	13690.94	200.00 लाख खाद्यान्न हेतु 100.00 लाख पशु चारे हेतु 450.00 लाख कृषि निवेश अनुदान हेतु
3	हमीरपुर	67.5	4868.14	1610.84	47	18469.04	200.00 लाख खाद्यान्न हेतु 100.00 लाख पशु चारे हेतु 450.00 लाख कृषि निवेश अनुदान हेतु
4	महोबा	43	2991.76	2741.93	96.5	20114.11	200.00 लाख खाद्यान्न हेतु 100.00 लाख पशु चारे हेतु 450.00 लाख कृषि निवेश अनुदान हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
5	झांसी	254.97	13166.04	1935.33	222.5	27840.97	200.00 लाख खाद्यान्न हेतु

							100.00 लाख पशु चारे हेतु 450.00 लाख कृषि निवेश अनुदान हेतु
6	ललितपुर	108	1060.39	——	87.5	17270.6	200.00 लाख खाद्यान्न हेतु 100.00 लाख पशु चारे हेतु 450.00 लाख कृषि निवेश अनुदान हेतु
7	जालौन	97.5	250	1109.14	52.5	20115.95	200.00 लाख खाद्यान्न हेतु 100.00 लाख पशु चारे हेतु 450.00 लाख कृषि निवेश अनुदान हेतु

सूखा मेमोरेण्डम–2015 धनराशि रु0 2057.79 करोड़ के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा रु0 934.32 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी है, जिसे जनपदों को शीघ्र स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है।,

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला में सूखा राहत राशि का वितरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके विधान सभा क्षेत्र रामकोला अन्तर्गत ब्लाक कप्तानगंज...

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री यासर शाह–

ख्ब्लाक रामकोला और ब्लाक मोतीचक्र का आंशिक ग्राम मधोली बाजार, लक्ष्मीपुर नरायनपुर व चन्दरपुर, इन्दरपुर, खबराभार, उस्मा, खोटही सहित सपहा, मोरजन, देवरिया बाबू ग्रामों का सूखा राहत राशि का अब तक वितरण नहीं किया गया जिससे किसानों में निराशा व्याप्त है। अतः ग्रामों में सूखा राहत धनराशि का शीघ्र वितरण किये जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

2–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सामान्य के सापेक्ष 60 प्रतिशत से कम वर्षा होने एवं 33 प्रतिशत या उससे अधिक कृषि फसलों की क्षति होने के आधार पर शासनादेश संख्या–453/1–11–2014–7 (जी)/2015, दिनांक 19–11–2015 द्वारा प्रदेश के 50 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखाग्रस्त जनपदों में हुई कृषि फसलों को क्षति तथा इसके निराकरण के लिये रु0 2057.79 करोड़ का सूखा मेमोरेण्डम भारत सरकार को दिनांक 23–11–2015 को प्रेषित किया गया था जिसमें जनपद कुशीनगर के रु0 43.49 करोड़ की कृषि फसलों की क्षति का प्रस्ताव भी सम्मिलित है।

3–प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं के दृष्टिगत जनपद कुशीनगर को रु0 4.50 करोड़ की धनराशि दिनांक 15–01–2016 को कृषि निवेश अनुदान हेतु स्वीकृत की जा चुकी है, जिसे जिलाधिकारी द्वारा जनपदीय कोषागार से सीधे किसान/लाभार्थी के खाते में ई–पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान किये जाने के लिये तहसील के ग्रामवार पीड़ित किसानों के खातों को एकत्रित किया जा रहा है। सम्बन्धित कृषकों के खाते में धनराशि शीघ्र भेज दी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के आदेश दिनांक 22–01–2016 द्वारा रु0 934.32 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसे जनपदों को स्वीकृत किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।,

जनपद वाराणसी के बादशाह बाग में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत पानी की टंकियों के निर्माण में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र जायसवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

श्री रविन्द्र जायसवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09–02–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में जनपद वाराणसी के बादशाह बाग में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत पानी की टंकियों के निर्माण में की गई अनियमितताओं ....

श्री जगतम्बा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्री यासर शाह–

ख्के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गई है।

2–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वाराणसी नगर के सिस वरुणा क्षेत्र में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 17 शिरोपरि जलाशयों का निर्माण कराया गया है। इन सभी जलाशयों को निर्मित कर अगस्त, 2014 में इनकी टेस्टिंग भी कर ली गयी थी और इनमें से 7 शिरोपरि जलाशयों से जलापूर्ति भी चालू कर दी गयी थी। वर्तमान में इन 17 जलाशयों में से कुल 13 जलाशयों से लगभग 260 कि0मी0 वितरण प्रणाली के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

3–दिनांक 06 फरवरी, 2016 को शिरोपरि जलाशय को भरने के पश्चात् ठेकेदार के पम्प आपरेटर की त्रुटि के कारण जलाशय भर जाने के पश्चात् भी पम्प चलाना बन्द नहीं किया गया, जिसके कारण शिरोपरि जलाशय से ओवर फ्लो करके पानी नीचे गिरने लगा और जमीन एवं निकटवर्ती सड़कों पर फैल गया। पम्प आपरेटर की लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। पम्प आपरेटर को ठेकेदार द्वारा हटा दिया गया है। उस समय वितरण प्रणाली के स्लूस वाल्व भी बन्द थे, जिसके कारण वितरण प्रणाली के माध्यम से भी शिरोपरि जलाशय खाली नहीं हो रहा था। उस समय शिरोपरि जलाशय से जो पानी बाहर निकल रहा था वह ओवर फ्लो के कारण था न कि टंकी में लीकेज के कारण।

4–कार्य स्थल की जांच करने पर यह पाया गया कि शिरोपरि जलाशय के ओवर फ्लो एवं वाश आउट के पाइप को निकटवर्ती पिशाच मोचन तालाब में ले जाने के स्थान पर उन्हें वितरण प्रणाली से जोड़ दिया गया था। कार्य स्थल पर उपस्थित जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ता ने अवगत कराया कि वहां के निवासियों ने ओवर फ्लो एवं वाश आउट के पाइप को पिशाच मोचन तालाब तक ले जाने के लिये आपत्ति की थी जिसके कारण ओवर फ्लो हो रहे पानी को तुरन्त जलाशय से नहीं निकाला जा सका और जलाशय में पानी भरने के पश्चात् ऊपर से पानी ओवर फ्लो करने लगा। शिरोपरि जलाशय के निर्माण में कोई खराबी नहीं है। ओवर फ्लो एवं वाश आउट के पाइप को पिशाच मोचन तालाब तक ले जाने के लिये पुनः प्रयास किया जा रहा है।,

श्री रविन्द्र जायसवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर बनारस में 17 टंकी बनाई गई थी। उस समय लगभग ढाई सौ किलोमीटर पाइप लाइन डालनी थी, वहां एक पाइप भी सही नहीं है। जहां–जहां टेस्टिंग हो रही थी, वहां पर ब्लास्ट कर जा रहे हैं और पूरी की पूरी योजना में एक अरब इक्यानवे करोड़ रुपये में आपने क्लीयर नहीं किया है कि हम टेस्टिंग के खिलाफ क्या करेंगे। उस कालोनी का रोड डैमेज हो गया है, वहां पर क्या मुआवजा देंगे, उसके अलावा पूरी योजना में जो सड़क खोदते हैं और सड़क खोदने के बाद वापस उस कंपनी को बनाना था, लेकिन उस कंपनी ने सड़क खोदने के बाद कहीं पर सड़क नहीं

---

uksV %&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

बनाई है। उस कंपनी के खिलाफ आप क्या करने वाले हैं, यह भी उत्तर में स्पष्ट नहीं है।

श्री यासर शाह–

माननीय अध्यक्ष जी, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें पुनः प्रयास किया जा रहा है, टेक्निकल डिफकल्टीज थी सरकार उसको देख रही है और उसको दूर करेगी।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद ईंट भट्ठों को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती सीमा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर अवगत कराना है कि ईंट भट्ठों.....

श्री मो0 रेहान–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री यासर शाह–

ख्के लिये मिट्टी खनन हेतु पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु पर्यावरण निदेशालय, उ0 प्र0 में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पूर्व से गठित है जिनसे पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेना होता था। 5 हेक्टेयर से कम या उसके बराबर लघु खनिज (जिसमें साधारण मिट्टी भी सम्मिलित है) के खनन से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिये पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–125, दिनांक 15–01–2016 एवं अधिसूचना संख्या–166, दिनांक 20–01–2016 द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) एवं जिला विशेषज्ञ निर्धारण समिति (डी0ई0ए0सी0) का गठन कर दिया गया है जिस पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश पर्यावरण विभाग के पत्र दिनांक 25–01–2016 द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को दे दिये गये हैं तथा पत्र दिनांक 04–02–2016 एवं दिनांक 11–02–2016 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को पुनः अनुस्मरण कराते हुए तत्काल अनुपालन करते हुए कृत कार्रवाई से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

जनपद स्तर पर उक्त प्राधिकरण व समिति के गठन के परिणामस्वरूप ईंट भट्ठों के लिये मिट्टी खनन हेतु (5 हेक्टेयर से कम या उसके बराबर) पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिये अब पर्यावरण निदेशालय उ0 प्र0 में गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति से अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह गयी है। उक्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति जनपद स्तर पर ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

प्राप्त हो जायेगा। उपरोक्त व्यवस्था से ईंट भट्ठों के लिये मिट्टी खनन हेतु पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने में भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है।,

जनपद सीतापुर के नगर क्षेत्र में 2013–14 में कम्पोजिट विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रण में बनाये जाने में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि सीतापुर नगर क्षेत्र में वर्ष 2013–14 में .....

श्री मो0 रेहान–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री यासर शाह–

ख्दो कम्पोजिट विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रण में बनाये गये थे। उक्त विद्यालय के संचालन का कार्य अस्थायी रूप से सम्बद्ध शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण मूल रूप से शिक्षकों की तैनाती उक्त विद्यालयों में नहीं की गयी है और न ही उन सम्बद्ध शिक्षकों को स्थायी किया गया। वर्ष 2015–16 में नगर क्षेत्र के विद्यालयों में पदोन्नति के समय उक्त विद्यालयों को समायोजन के समय सांठ–गांठ कर पद सृजन कर शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां की गई। यही नहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय बी0आर0सी0 में कई शिक्षक अनियमित रूप से सम्बद्ध होकर लिपिकीय कार्य कर रहे हैं जो आर0टी0ई0 ऐक्ट का खुला उल्लंघन है इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। बड़े पैमाने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर ने सम्बद्धता किया है और अनियमिततायें करके शासन की छवि धूमिल कर रहा है। शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर नियमों के विरुद्ध सारे कार्य कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों के समायोजन आदि में अनियमिततायें हुई हैं। आर0टी0ई0 ऐक्ट का उल्लंघन कर सम्बद्धता करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस पर वक्तव्य दिये जाने एवं अनियमितता करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित किये जाने की मांग की गयी है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर की शिक्षकों के अनियमित पदस्थापन एवं सम्बद्धता आदि किये जाने की शिकायत की गई है जिसकी जांच कराया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, उप शिक्षा निदेशक (सेवायें–2), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0 प्र0 लखनऊ ने अपने कार्यालय आदेश दिनांक 12–2–2016 द्वारा जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है। जांच अधिकारी को जांच आख्या एक माह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।,

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की .....

श्री मो0 रेहान–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री यासर शाह–

ख्ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस तहसील का क्षेत्रफल जिला मुख्यालय से लगभग 60 कि0मी0 की दूरी तक फैला है। जिसके कारण सरकार का जनता को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने का वादा पूरा नहीं होता है। गरीब जनता का धन भी अधिक खर्च होता है तथा समय भी अधिक लगता है। यह तहसील उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर स्थित है। यहां पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना करने के लिये काफी लम्बे समय से धरने–प्रदर्शन व हड़ताल हो रही है। सम्बन्ध में मेरे द्वारा पिछले लगभग 5 वर्ष से मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की मांग बराबर विधान सभा में की जाती रही है जिसके फलस्वरूप इसका स्थलीय निरीक्षण व जगह का चयन होकर मा0 जिला जज द्वारा मा0 उच्च न्यायालय को भेजा जा चुका है मगर अभी तक सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सार्थक कार्रवाई सामने नहीं आयी है। जिसके कारण गरीब जनता व वकीलों में भारी रोष और नाराजगी व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

---

uksV %&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

मान्यवर, अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–25/2015/1462/सात–न्याय–2–2015– 216जी/2007, दिनांक 24–11–2015 द्वारा जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दी गयी है।,

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद की ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में पानी की टूटी हुई पाइपों को पुनः डलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

श्री अमर पाल शर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09.02.2016 को दी गई सूचना में अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के .....

श्री मो0 रेहान–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री यासर शाह–

ख्ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में पानी की लाइनें डाली गयी थीं जो पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल की गम्भीर समस्या बन गयी है। ऐसी परिस्थिति में ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में पानी की लाइनें अतिशीघ्र डाला जाना आवश्यक है।

2–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में पेयजलापूर्ति हेतु कोई भी पाइप लाइन पूर्णतः क्षतिग्रस्त एवं बदलने योग्य नहीं है। यदि किसी पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलती है तो उसकी मरम्मत करा दी जाती है।

3–यह भी अवगत कराया जाना है कि नागर निकायों के अन्तर्गग्त सृजित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव एवं संचालन का दायित्व नागर निकायों का है और उक्त के आलोक में ही विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में पेयजलापूर्ति से सम्बन्धित पाइप लाइन के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा किया जा रहा है।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद आगरा में नारायण नगर वासन फैक्ट्री के सामने बिचपुरी रोड वोदला पर दो वर्ष से नाले टूटे होने से जलभराव के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

श्री जगन प्रसाद गर्ग, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना .....

श्री मो0 रेहान–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री यासर शाह–

खदिनांक 09–02–2016 निम्नवत् है :–

''जनपद आगरा में नारायण नगर वासन फैक्ट्री के सामने विचपुरी रोड वोदला आगरा में विचपुरी रोड पर लगभग दो साल से नाला टूटा पड़ा है। नारायण नगर के दोनों नालों का पानी रोड पर बह रहा है जिसमें से एक नाली का पानी नाला चोक होने के कारण बन्द पड़ा है। इस कारण दोनों नालों का पानी एक नाले से निकल कर सड़कों पर बह रहा है। रोड के पास एक गड्ढा बनाया गया था वह खुला पड़ा है, जिससे वहां पर आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। इस सम्बन्ध में ए0डी0ए0 के अधिकारियों को अवगत कराया गया परन्तु कोई कार्रवाई न होने से जनमानस में आक्रोश एवं रोष व्याप्त है। जनहित में उक्त नाले की मरम्मत कराकर जल निकासी का समुचित व्यवस्था किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त नाले की मरम्मत कराकर जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2–उक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि आगरा में नारायण नगर वासन फैक्ट्री के सामने विचपुरी रोड वोदला आगरा का निरीक्षण कराया गया। नारायण नगर वासन फैक्ट्री के सामने नालों की सफाई का कार्य कराया जा रहा है तथा वर्तमान में स्थल पर किसी भी प्रकार का जलभराव नहीं है। उक्त मार्ग पर बने चैम्बर (गड्ढा) की मरम्मत का आगणन धनांक रु0 55,000.00 का तैयार कराया गया है। शीघ्र ही चैम्बर की मरम्मत का कार्य करवा दिया जायेगा।,

जनपद देवरिया के नगरपालिका परिषद् को पदेन सदस्य होने के बाद भी बैठक में न बुलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जन्मेजय सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

श्री जन्मेजय सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09–02–2016 को नियम–51 ....

श्री मो0 रेहान–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री यासर शाह–

ख्के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद्, देवरिया में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद्, देवरिया का पदेन सदस्य होने के बावजूद उन्हें बैठकों में नहीं बुलाया जाता है और न ही बैठकों की कोई सूचना दी जाती है। अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, ठेकेदार, जे0ई0 व कुछ सभासदों के द्वारा निर्माण कार्यों के नाम से ओवर स्टीमेट बनाकर नगर के विकास के पैसे की लूट व अपहरण किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 में नगर पालिका बोर्ड देवरिया का गठन हुआ और वर्ष 2012–13, 2013–14 में कोटेशन के नाम पर सैकड़ों फर्जी तौर से दिखाकर लाखों–लाख रुपया के बंदरबांट आपस में मिलकर कर दिया। जिसकी शिकायत करने के बाद भी अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। वार्ड नं0–6 देवरिया खास और वार्ड नं0–13 भुजौली कालोनी में सैकड़ों कोटेशन सभासद व अन्य जिम्मेदार को मिलाकर लाखों–लाख रुपया लूट लिया गया। इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की मांग की गयी है।

2–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी, देवरिया से आख्या प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी देवरिया के पत्र दिनांक 12–02–2016 के अनुसार नगर पालिका परिषद्, देवरिया की प्रत्येक बोर्ड बैठक में स्थानीय मा0 सांसद, मा0 सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद् को प्रतिभाग किये जाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा की गयी अन्य शिकायतों में उल्लिखित बिन्दु वित्तीय एवं तकनीकी होने के कारण उक्त बिन्दुओं पर जांच कराये जाने में लगभग दो माह का समय लगने की सम्भावना है। मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र में उल्लिखित

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

बिन्दुओं पर जिलाधिकारी, देवरिया से जांच आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।,

यमुना एक्सप्रेस–वे के लिये जनपद आगरा व मथुरा के किसानों से अधिग्रहीत की गयी भूमि का 64.7 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान अभी तक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

डा0 धर्मपाल सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा मा0 सदन में दिनांक 09–02–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत .....

श्री मो0 रेहान–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री यासर शाह–

ख्दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि आगरा से नोएडा तक यमुना एक्सप्रेस–वे के लिये जो जमीन जनपद आगरा व मथुरा के जिन किसानों की अधिग्रहीत की गयी थी उन प्रभावित किसानों को यमुना प्राधिकरण बोर्ड की सितम्बर, 2014 में हुई 51वीं बोर्ड बैठक में 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया गया था लेकिन अभी तक सितम्बर, 2014 से इतना समय गुजर जाने के बावजूद जनपद आगरा व मथुरा के किसी भी किसान को उक्त मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। जिसकी वजह से किसानों में भारी आक्रोश पनपता जा रहा है और किसान कभी भी आन्दोलित हो सकता है। यह एक अति गम्भीर विषय है जिसका निदान सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

2–इस विषय में अवगत कराना है कि जनपद आगरा व मथुरा में अर्जित की गयी भूमि कन्सेशन एग्रीमेन्ट दिनांक 07–02–2003 के अन्तर्गत कन्सेशनायर मै0 जेपी इन्फ्राटैक लि0 को हस्तान्तरित हुई है। यमुना एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण बोर्ड की 51वीं बैठक दिनांक 15–09–2014 में प्राधिकरण द्वारा अर्जित/क्रय भूमि के भू–स्वामियों को अतिरिक्त प्रतिकर राशि जनपद मथुरा एवं आगरा हेतु क्रमशः अंकन रु0 251.00 एवं 274.30 रुपये

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

प्रति वर्ग मीटर की दर पर विवाद निस्तारण भत्ता (नो लिटिगेशन इन्सेन्टिव) के रूप में भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली धनराशि की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण अपने आवंटियों से अथवा जो अर्जित भूमि आवंटन हेतु शेष है उसकी आवंटन दर बढ़ा कर करेगा। आवंटियों से इसको 04 छमाही किस्तों में लिया जायेगा जिसमें प्रथम किश्त आदेश निर्गत होने के 03 माह बाद शुरू होगी।

3–कन्सेशन एग्रीमेन्ट दिनांक 07–02–2003 के अन्तर्गत कन्सेशनायर मै0 जेपी इन्फ्राटैक लि0 को हस्तान्तरित की गयी भूमि के सापेक्ष 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर राशि की मांग प्राधिकरण द्वारा कन्सेशनायर को प्रेषित की गयी थी लेकिन अभी तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है बल्कि कन्सेशनायर द्वारा पत्र के माध्यम से प्राधिकरण को अवगत कराया गया है कि ''प्रश्नगत भूमि के अर्जन की सम्पूर्ण कार्यवाही वर्ष 2008 से 2010 में पूर्ण हो गयी थी तथा प्रश्नगत अर्जित भूमि उन्हें पट्टा प्रलेख पद्धति के आधार पर हस्तान्तरित हुई है यमुना एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण द्वारा अर्जित एवं हस्तान्तरित की गयी भूमि की सम्पूर्ण भू–अर्जन लागत कन्सेशनायर द्वारा जमा कर दी गयी थी वर्तमान में अतिरिक्त प्रतिकर की यह मांग कन्सेशन एग्रीमेन्ट तथा पट्टा प्रलेख/लीज डीड की शर्तों से बाहर है।''

4–कन्सेशनायर द्वारा उठाये गये उक्त बिन्दु पर यमुना प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण बोर्ड की 53वीं बैठक दिनांक 25–05–2015 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में कन्सेशनायर से अतिरिक्त प्रतिकर लिये जाने के सम्बन्ध में विधिक परीक्षण कराकर समुचित निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।,

ख5.31, नियम–56 की सूचना पर वक्तव्य की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, एक अनुरोध है कि नियम–56 में श्री संत राम कुशवाहा जी की एक सूचना है, कृपया आप इस पर सरकार से वक्तव्य मांग लें।

श्री अध्यक्ष–

आप इसको कल दे दीजियेगा। हम इस पर वक्तव्य मांग लेंगे।

अब हम उठते हैं। कल दिनांक 16–02–2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 32 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 15 फरवरी, 2016 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–04 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

पुष्टाहार वितरण प्रणाली को प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने हेतु विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही निम्नवत् है :–

- परियोजना कार्यालय पर आपूर्तित पुष्टाहार का भौतिक सत्यापन 48 घण्टे के अन्दर उप जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पुष्टाहार की नियमित उपलब्धता तथा लाभार्थियों में इसके समुचित वितरण हेतु स्थानीय स्तर पर ग्राम समुदाय से जुड़ी हुई महिलाओं का सहयोग प्राप्त करते हुए सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मातृ समितियां गठित हैं। मातृ समिति का मुख्य दायित्व यह होता है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र नियमित रूप से खुलें व प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर नियमित रूप से पोषाहार का वितरण हो। समिति के सदस्य समय–समय पर पोषाहार के स्टाक की चेकिंग एवं सत्यापन कार्य करते हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चलाये जा रहे अन्य कार्यक्रम यथा–टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, प्री–स्कूल शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि में भी मातृ समिति अपना सहयोग प्रदान करती है।
- लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर पोषाहार का समुचित रूप से वितरण करने के लिये वितरण से एक दिन पूर्व गांव में डुग्गी पिटवाकर अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रचार माध्यम से इसकी जानकारी ग्रामवासियों को दिये जाने की व्यवस्था है।
- पोषाहार का वितरण आंगनबाड़ी केन्द्र पर गठित मातृ समिति की अध्यक्षा/सदस्य/स्वास्थ्य कल्याण समिति/ग्राम प्रधान/उप ग्राम प्रधान/स्थानीय जन प्रतिनिधियों से कराये जाने की व्यवस्था है।
- अनुपूरक पोषाहार के वितरण की विशेष व्यवस्था की गयी है। आंगनबाड़ी केन्द्र पर आपूर्ति होने वाले पोषाहार की प्रत्येक बोरी तथा पैकेट पर जनपद एवं परियोजना का नाम अंकित रहता है। परियोजना कार्यालय से पोषाहार आंगनबाड़ी कार्यकत्री को उपलब्ध कराते समय बोरी पर आंगनबाड़ी केन्द्र का कोड नं0 लिखना सुनिश्चित किया जाता है।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों को टी0एच0आर0 के रूप में अनुपूरक पोषाहार वितरण की तिथि प्रत्येक माह की 05, 15 एवं 25 तारीख निर्धारित की गयी है। यदि उपरोक्त में से किसी निर्धारित तिथि को रविवार अथवा आंगनबाड़ी केन्द्र का अवकाश पड़ता है तो पोषाहार का वितरण आगामी कार्यदिवस पर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने एवं उसकी प्रगति की समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ब्लाक स्तर पर उप

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तथा आंगनबाड़ी स्तर पर ग्राम पंचायत/वार्ड मेम्बर की अध्यक्षता में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समितियां गठित हैं जो आंगनबाड़ी केन्द्रों के कार्य प्रणाली का निरीक्षण करने सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने, कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन एवं उनके पोषण में सुधार की निगरानी करने तथा केन्द्र पर साफ–सफाई, शौचालय एवं सुलभ पेयजल आदि व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने सुझाव देती है।

- विभाग से सम्बन्धित शिकायतों/समस्याओं के समाधान हेतु निदेशालय में समाधान/शिकायत निवारण प्रकोष्ठ गठित है। किसी भी प्रकार की शिकायत/समस्या टोल फ्री नं0–1800–180–5599 पर निःशुल्क दर्ज करायी जा सकती है। टोल फ्री नं0 पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण कराकर शिकायतकर्ता को सूचित किया जाता है।
- विभाग में भ्रष्टाचार अथवा अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच करायी जाती है और गुण–दोष के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही की जाती है। विभिन्न प्रकरणों की जांच में दोषी पाये गये 62 कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक/विभागीय कार्रवाई की गयी है।

————————

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2016 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री रामचन्द्र यादव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–35 का संलग्नक।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत जनपद फैजाबाद में वर्ष 2015–16 में चयनित ग्रामों में कार्यक्रमवार आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

कार्यक्रम का नाम	चयनित ग्राम का नाम एवं आवंटित धनराशि
सम्पर्क मार्ग	समग्र ग्राम हरिहरपुर कायस्थान में रु0 49.09 लाख एवं रतनपुर में रु0 15.51 लाख धनराशि आवंटित हुई है।
ग्रामीण विद्युतीकरण	समग्र ग्राम टाण्डा खुलासा में रु0 21.71 लाख, रानीमऊ में रु0 13.60 लाख, दशरथमऊ में रु0 13.67, रतनपुर में रु0 20.61 लाख एवं हरिहरपुर कायस्थान में रु0 7.98 लाख आवंटित हुई है।
आन्तरिक गलियों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण	ग्राम टाण्डा खुलासा में रु0 20.00 लाख, रानीमऊ में रु0 40.00 लाख, दशरथमऊ में रु0 20.00, रतनपुर में रु0 20.00 लाख एवं हरिहरपुर कायस्थान में रु0 20.00 लाख आवंटित हुई है।
स्वच्छ पेयजल हेतु हैण्डपम्प की स्थापना	टाण्डा खुलासा में 4, रानीमऊ में 9 व दशरथमऊ में 8 हैण्डपम्प स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। इस कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं हुई हैं
आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण	ग्राम टाण्डा खुलासा एवं हरिहरपुर कायस्थान में 01–01 आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कराया जाना है। इस कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं हुई है।
सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना	ग्राम टाण्डा खुलासा में रु0 3.04 लाख, रानीमऊ में रु0 8.41 लाख, दशरथमऊ में रु0 2.80 लाख, रतनपुर में रु0 2.34 लाख एवं हरिहरपुर कायस्थान में रु0 1.40 लाख धनराशि आवंटित हुई है।
स्वच्छ शौचालय का निर्माण	ग्राम टाण्डा खुलासा में रु0 14.64 लाख, रानीमऊ में रु0 39.60 लाख, दशरथमऊ में रु0 15.60, रतनपुर में रु0 17.10 लाख एवं हरिहरपुर कायस्थान में रु0 8.40 लाख आवंटित हुई है।
इन्दिरा आवास	ग्राम टाण्डा खुलासा में रु0 4.55 लाख, रानीमऊ में रु0 16.80 लाख, दशरथमऊ में रु0 2.10, रतनपुर में

कार्यक्रम का नाम	चयनित ग्राम का नाम एवं आवंटित धनराशि
	रु0 1.40 लाख एवं हरिहरपुर कायस्थान में रु0 3.85 लाख आवंटित हुई है।
लोहिया ग्रामीण आवास	ग्राम टाण्डा खुलासा में रु0 44.00 लाख, दशरथमऊ में रु0 71.50, लाख, रतनपुर में रु0 68.75 लाख एवं हरिहरपुर कायस्थान में रु0 60.85 लाख धनराशि आवंटित हुई है। ग्राम रानीमऊ के लाभार्थियों के चयन की कार्रवाई की जा रही है।

पी0एस0यू0पी0–एल0 86 विधान सभा (131) 28–07–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।